हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 मार्च, 2018

खण्ड–1, अंक–09

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 14 मार्च, 2018

	पृष्ठ संख्या
विधान परिषद जम्मू एवं कश्मीर के सदस्य का अभिनंदन	5
इंडियन नेशनल लोकदल के निलंबित सदस्यों को वापिस बुलाने का अनुरोध	5
इंडियन नेशनल लोकदल के निलंबित सदस्यगण पर निर्णय का निरसन	6
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	6
नार्वे के राजूदत का अभिनंदन	25
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	25
राजकीय महिला महाविद्यालय, रेवाड़ी के प्रोफैसर्ज एवं विद्यार्थियों का अभिनंदन	29
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	29
मंत्रियों द्वारा सम्पत्तियों की घोषणा से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 2279 का उत्तर न मिलने के संबंध में मामला उठाना	35
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	36

नियम 45(1) अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	46
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	54
कटौती प्रस्तावों से संबंधित मामला उठाना	71
शोक प्रस्ताव	71
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएँ/विभिन्न मामले उठाना	72
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	86
प्रदेश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शराब, अफीम, भुक्की, गांजा, स्मैक ड्रग की तेजी से अवैध बिक्री बारे	
वक्तव्य–	88
शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना/विभिन्न मामले उठाना	100
सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र	103
वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर	104
बहादुरगढ़ में भूमि घोटाले का मामला उठाना	112
वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर	118
बैठक का समय बढ़ाना	147
वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर	147
बैठक का समय बढ़ाना	174
वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर	175
बैठक का समय बढ़ाना	201
वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर	201
बैठक का समय बढ़ाना	216
वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर	216
बैठक का समय बढ़ाना	233
वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर	233

बैठक का समय बढ़ाना 261

वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ) 261

बैठक का समय बढ़ाना 268

वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ) 268

वर्ष 2018–19 के बजट के अनुदानों की मागों पर चर्चा तथा मतदान 271

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 14 मार्च, 2018

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

विधान परिषद्, जम्मू एवं कश्मीर के सदस्य का अभिनन्दन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, आज सरदार चरणजीत सिंह खालसा एम.एल.सी. विधान परिष्द, जम्मू कश्मीर सदन की कार्यवाही देखने हेतु हरियाणा विधान सभा के सदन में बैठे हैं। मैं सदन की तरफ से उनका स्वागत करता है।

इण्डियन नेशनल लोकदल के निलम्बित सदस्यों को वापिस बुलाने का अनुरोध

श्री परमेन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी पार्टी के माननीय सदस्यों को बजट की बहस में हिस्सा लेने के लिए बुला लिया जाए। हमारे माननीय सदस्यों के प्रश्न भी लगे हुए हैं। हमारा इतना बड़ा अपराध भी नहीं था, माननीय सदस्यों ने तो केवल एक भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। माननीय सदस्यों के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न सदन में लगे हुए हैं और माननीय सदस्यों को अपने हल्के की बात भी रखनी है। माननीय सदस्यों को उनके हल्के की मांगों को सदन में रखने से वंचित न किया जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्षः ढुल जी, पहले प्रश्नकाल पूरा हो जाने दें।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय सदस्यों को प्रश्नकाल से पहले ही बुला लिया जाए।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि विपक्ष के माननीय सदस्यों के बिना सदन चलाना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप माननीय सदस्यों को सदन में बुला लें।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा को बनाये रखना सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेवारी बनती है।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जिम्मेवारी लेकर आया हूं।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य जिम्मेवारी लेकर आए हैं तो यह बात लिखकर दें दे कि माननीय सदस्य सदन में कोई हंगामा नहीं करेंगे।

इण्डियन नेशनल लोकदल के निलम्बित सदस्यगण पर निर्णय का निरसन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, आप जैसे शालीन व्यक्तित्व का धनी कोई बिरला ही अध्यक्ष की चेयर पर बैठता है। हमारे माननीय सदस्य श्री परमेन्द्र सिंह ढुल ने कहा है कि वे अपनी पार्टी के सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेवारी लेकर आए हैं। माननीय सदस्य भी विपक्ष के जिम्मेवार सदस्य हैं और सी.एल.पी. लीडर माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी ने भी माननीय सदस्यों को सदन में बुलाने के लिए अनुरोध है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने भी महसूस किया है और यह बजट सत्र चल रहा है। माननीय सदस्यों ने कल भी 10 बार वेल में आकर हंगामा किया था लेकिन आपने कभी भी कोई कठोर निर्णय नहीं लिया है। इसलिए माननीय सदस्य श्री परमेन्द्र सिंह ढुल की बात पर विश्वास करते हुए माननीय सदस्यों को सदन में बुला लेना चाहिए।

श्री अध्यक्षः ठीक है, अगर हाउस की सहमति है तो इंडियन नेशनल लोकदल के निलम्बित सभी माननीय सदस्यों को सदन में बुला लिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, निलम्बित सदस्यों को सदन में वापिस बुला लिया जाए।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

To Set Up Solid Waste Management Plant

***2621 Shri Subhash Sudha** : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a solid waste management plant in of District Kurukshetra; if so, the details thereof ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री कविता जैन) : नहीं, श्रीमान जी। परन्तु 3 नगर पालिकाएं नामतः शाहबाद, थानेसर व पिहोवा अंबाला–कुरूक्षेत्र–करनाल कलस्टर का अंग हैं जबकि 4जी नगर पालिका लाडवा ठोस कचरा प्रबंधन स्थापना हेतु यमुनानगर कलस्टर का अंग है।

श्री सुभाष सुधाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कुरूक्षेत्र जिले से डेली 70 टन कचरा निकलता है यह हमारे जिले की बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम लीज पर जमीन लेकर कचरा डालने का प्रबन्ध करते हैं तो कचरे के कारण वहां पर रहने वाले लोगों में बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए जल्दी से जल्दी टैंडर प्रक्रिया पूरी करके काम शुरू करवाया जाए।

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है और सरकार भी इस स्वच्छता को लेकर प्रतिबद्ध है। कुरूक्षेत्र जिले का एरिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुरूक्षेत्र जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा गीता जयंती महोत्वसव बहुत धूम–धाम से मनाया जाता है और देश–विदेशों से लाखों लोग हर साल कुरूक्षेत्र जिले में विजिट करते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि विभाग द्वारा 2 बार टैंडर काल किये जा चुके हैं परन्तु सिंगल bid आयी है और कोई भी टैंडर रिसिव नहीं हुआ है। जिसके कारण विभाग इस काम को नहीं कर पाया। इसके लिए फिर से विभाग द्वारा 15 अप्रैल को नये टैंडर लगाए जाएंगे और उसके टैंडर्ज रिसीव होने के बाद हम इसका काम जल्दी ही पूरा करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगी कि हमने अम्बाला में क्लस्टर प्लांट स्थापित किया है। अध्यक्ष महोदय, यह एक वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट है। इस प्लांट में कूड़े को इकट्ठा किया जाएगा और उससे एनर्जी पैदा की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगी कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 265 करोड रुपए है और उस प्लांट की कैपेसिटी 600 टन प्रति दिन की होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगी कि हमने पूरे हरियाणा प्रदेश को 14 क्लस्टर्ज में बांटा है और हमने कोई भी ऐसी अर्बन लोकल बॉडी नहीं छोड़ी है जो किसी क्लस्टर का पार्ट न हो। पूरे हरियाणा प्रदेश में हम इन 14 क्लस्टर्ज में प्लांट लगाने वाले हैं।

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, अभी जो क्वैश्चन श्री सुभाष सुधा जी का आया है उसी से संबंधित मेरा फतेहाबाद जिला का क्वैश्चन है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, भूना ये कुछ नगर ऐसे हैं जहां पर कूड़े के निपटान की बड़ी भारी समस्या है और उस समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा की थी कि भूना में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि भूना में जो सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया जाना था, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और क्या उसमें भी कोई ऊर्जा पैदा करने वाला संयंत्र साथ में लगाया जाएगा ?

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मानित साथी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अध्यक्ष महोदय, जैसा हमने पहले बताया था कि हमने पूरे हरियाणा प्रदेश को 14 क्लस्टर्ज में बांटा है और उनमें फतेहाबाद और भूना कलस्टर को भी जोड़ा गया है और इसके अंदर फतेहाबाद, भूना, रतिया, टोहाना और उकलाना मंडी ये जो 5 अर्बन लोकल बॉडीज हैं वे इस क्लस्टर में शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगी कि वहां पर वेस्ट ऑन एनर्जी का प्लांट नहीं लगेगा, बल्कि वेस्ट टू कम्पोस्ट का प्लांट लगेगा, क्योंकि यहां कचरे का प्रतिदिन उत्पादन 112 टन है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह भी बताना चाहूंगी कि यहां पर 45.65 करोड रुपए की लागत से प्लांट लगाया जाएगा और इसके लिए हमने 5 जनवरी, 2018 को टैंडर कॉल किया था, जिसकी अंतिम तिथि 6 मार्च, 2018 थी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगी कि जब उस टैंडर को खोला गया तो हमें सिर्फ 1 ही टैंडर रिसीव हुआ इसलिए हम अब दोबारा से टैंडर कॉल कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जून, 2018 तक टैंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद इसका काम आरंभ हो जाएगा और अगस्त, 2019 तक यह काम पूर्ण हो जाएगा।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया को बताना चाहूंगी कि भिवानी जिला भी गंदगी का डम्प बन गया है। अध्यक्ष महोदय, श्रीमती श्रुति चौधरी जो वहां की पूर्व सांसद रही हैं, उन्होंने कांग्रेस रिजीम के समय वहां पर एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी करवाई थी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि वहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लगाया जाएगा या नहीं ?

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय सदस्या पिछली सरकार में मंत्री भी रही हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारी माननीय सदस्या बता रही हैं कि भिवानी का एरिया कूड़े का डम्प बन चुका है तो मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि कहीं न कहीं इसमें उनका भी योगदान रहा है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने भिवानी में क्या काम किया है, उसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के दौरान यमुनानगर, करनाल, सिरसा, अम्बाला, रोहतक और

फतेहाबाद के अंदर प्लांट लगाए गए थे और उनकी स्थिति क्या है ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी जो वर्तमान की सरकार है वह सबका साथ–सबका विकास के भाव को लेकर आगे बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, यह जो स्वच्छ भारत अभियान है यह न केवल हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का है, बल्कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं भिवानी के बारे में माननीय सदस्या को बताना चाहूंगी कि भिवानी के अंदर बवानी खेड़ा, भिवानी, चरखी दादरी और लोहारू ये 4 अर्बन लोकल बॉडीज इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित साथी को यह भी बताना चाहूंगी कि हमें भिवानी क्लस्टर के लिए टैंडर रिसीव्ड हो गए हैं और वह इवैल्युएशन में चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगी कि उसका 15 दिनों के अंदर मूल्यांकन होने के बाद उसका टेंडर दे दिया जाएगा और उसके बाद यहां का काम प्रारंभ हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद है कि जून, 2018 तक इसका एग्रीमेंट हो जाएगा और अगस्त, 2019 तक यह काम पूर्ण हो जाएगा।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय में भिवानी में सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट लगाने के लिए 3 करोड रुपये मंजूर हो गये थे और मंत्री जी जवाब में कह रही हैं कि वहां पर इस तरह की कोई योजना थी उसकी इन्हें कोई जानकारी नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार को बने हुए तीन साल से ज्यादा का समय हो गया है मंजूर किए हुए कार्य को भी नहीं करवा जा रहा और यह कह रहे हैं कि अब ये इस कार्य पर आगे बढ़ेंगे ।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या सदन में गलत ब्यानी कर रही हैं । हम जिस प्रोजैक्ट पर कार्य कर रहे हैं यह हमारी सरकार का प्रोजैक्ट है, कोई पुराना प्रोजैक्ट नहीं है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपके सवाल का मंत्री जी ने जवाब दे दिया है । आपकी सरकार भी दस साल तक रही और दस साल किसी भी प्रोजैक्ट को पूरा करने के लिए बहुत समय होता है । उस समय तो आपने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करवाई ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय में भिवानी के लिए वेस्ट मैनेजमैंट का प्रोजैक्ट मंजूर हुआ था । उसके सारे लैटर मेरे पास हैं । यदि आप अनुमति देते हैं तो वह सारा रिकार्ड मैं सदन के पटल पर रख देती हूं ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, प्लीज आप बैठें । मंत्री जी ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है ।

.....

Job Provided to the Dependents of Martyrs

***2632. Shri Bismamber Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state the year wise details of total number of Government jobs provided to the dependents of Army and Paramilitary Martyrs from 2000 to 2017?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी। वर्ष 2010 से 2013 के दौरान कोई सरकारी नौकरी प्रदान नही की गई। वर्श 2014 से 2017 के दौरान 170 सैनिक व अर्ध सैनिक बलों के शहीदों के आश्रितों को नौकरी प्रदान की गई। जिसका व्यक्तिगत ब्यौरा विधानसभा पटल पर रखा जाता है।

ब्यौरा

Year 2014 (Total-10)					
1	Martyr Dharmesh Sangwan, VPO-Kheri Batar, Distt. Bhiwani, Army-19-12-2013	Kapil Dev, Brother	Clerk 01-08-2014	Army	Brother
2	Martyr Rajesh Kumar, VPO-Gorakhpur, Distt. Fatehabad Army	Dharambir Singh, Brother	Clerk 01-08-2014	Army	Brother
3	Martyr Krishan Kumar, # 42, Model Town, Hisar Army 3-7-2009	Kavita Devi, Wife	Clerk 01-08-2014	Army	Wife
4	Martyr Surender Kumar, VPO-Kablana, Jhajjar Army 11-12-95	Geeta, Wife	Peon 15-12-2014	Army	Wife
5	Martyr Ram Pal, VPO-Chhochhi, Jhajjar BSF 03-01-2004	Ashwani, Son	JBT Teacher 11-12-2014	BSF	Son
6	Martyr Harvinder Singh, VPO-Dubaldhan, Jhajjar Army 14-06-2012	Sushma, Wife	Peon 01-08-2014	Army	Wife
7	Martyr Dalbir # 1030/34, Vijay Nagar, Rohtak, Army 24-05-2013	Meenakshi, Wife	Clerk 02-09-2014	Army	Wife
8	Martyr Pawan Jeet Dahiya, VPO-Rohna, Distt. Sonepat, Army	Pawan Dahiya, Son	Clerk 17-11-2014	Army	Son
9	Martyr Dalbir, VPO-Pipli, Distt. Sonepat, Army 24-05-2013	Meenakshi, Daughter	Clerk 17-11-2014	Army	Daughter
10	Martyr Kanwar Pal, Vill-	Anjali,	Clerk	Army	Daughter

	Bhondsi Distt. Gurgaon, Army	Daughter	1-08-2014		
Year 2015 (Total-25)					
1	Martyr Jagdish Rai, VPO-Sanwar, Distt. Bhiwani, BSF-04-12-1971	Sadhu Ram Son	Clerk 24-08-2015	BSF	Son
2	Martyr Maha Singh, VPO-Kharkkalan, Distt. Bhiwani Army 22-04-1971	Sajjan Kumar Son	Clerk 30-11-2015	Army	Son
3	Martyr Satyabir, VPO-Mankwas, Bhiwani Army 22-03-1986	Pawan Son	Clerk 05-11-2015	Army	Son
4	Martyr Bijender, VPO-Badhra, Bhiwani Army 28-11-2001	Naveen Son	Clerk 04-11-2015	Army	Son
5	Martyr Rajpal, VPO-Sangha, Bhiwani Army 16-11-2007	Naresh wife	Peon 05-11-2015	Army	Wife
6	Martyr Satish, VPO-Manheru, Bhiwani Army 31-07-1991	Deepak Son	Clerk 01-12-2015	Army	Son
7	Martyr Ashok, VPO-Gokulpura, Bhiwani Army 22-12-2000	Shakuntla wife	Peon 04-12-2015	Army	wife
8	Martyr Vikash, Ward No.-7 Gandhi Nagar, Charkhi Dadri, Bhiwani Army 19-05-2007	Mandeep Wife	Peon 04-12-2015	Army	Wife
9	Martyr Surender, # 293/2, Ward No. 1, Loharu Road, Charkhi Dadri, Bhiwani Army 20-09-2004	Monu Son	Clerk 08-10-2015	Army	Son
10	Martyr Satyabir, VPO-Thuwa, Jind Army 08-03-2009	Sandeep Brother	Clerk 17-09-2015	Army	Brother
11	Martyr Pankaj Kumar, VPO-Dhakla,Jhajjar Army 28-05-2002	Satish Kumar Brother	Clerk 15-10-2015	Army	Brother
12	Martyr Rajesh Kumar, VPO-Jhanswa, Jhajjar Army 17-07-1999	Yatender Son	Clerk 18-12-2015	Army	Son
13	Martyr Jagbir Singh, VPO-Silana, Jhajjar BSF 19-09-1990	Seema Daughter	Clerk 20-07-2015	BSF	Daughter
14	Martyr Satyinder, VPO-Kheri, Hosdarpur, Jhajjar CRPF 18-02-2009	Rinki Wife	Clerk 10-06-2015	CRPF	Wife
15	Martyr Surender Singh, VPO-Silani, Jhajjar Army 02-03-1989	Vikash Son	Clerk 30-06-2015	Army	Son
16	Martyr Randhir Singh, VPO-Sulodha, Jhajjar CRPF 13-04-1987	Santosh Daughter in Law	Peon 15-10-2015	CRPF	Daughter in Law

17	Martyr Naresh, VPO-Ladhot, Rohtak Army 05-04-2000	Anita Wife	Peon 06-10-2015	Army	Wife
18	Martyr Dharam Singh, VPO-Hasangarh, Rohtak BSF 03-01-2004	Amar Singh Son	Clerk 30-10-2015	BSF	Son
19	Martyr Kuldeep, VPO-Ladhot, Rohtak Army 02-10-2000	Sunita Wife	Peon 01-10-2015	Army	Wife
20	Martyr Dharambir, VPO-Khidwali, Rohtak Army 14-11-1987	Pravesh Son	Clerk 31-12-2015	Army	Son
21	Martyr Yashpal, VPO-Rohna, Sonepat Army 05-07-2012	Meena Kumari Wife	Clerk 15-07-2015	Army	Wife
22	Martyr Mannu Ram, # 262, Shiv Colony, Near Railway Station, Rewari BSF 26-02-2013	Raksha Daughter	Clerk 28-10-2015	BSF	Daughter
23	Martyr Raghu Nath, VPO-Padli, Rewari. Army 05-07-1988	Sunil Kumar Son	Clerk 08-12-2015	Army	Son
24	Martyr Nasrudin, Vill. Hinganpur, PO-Pinagwan, Mewat Army 13-10-2000	Irshad Ali Son	Clerk 20-05-2015	Army	Son
25	Martyr Hoshiyar Singh, VPO-Jatusana, Rewari CRPF 12-11-2013	Keshav Son	Clerk 07-08-2015	CRPF	Son
Year 2016 (Total-75)					
1	Martyr Naresh Kumar, VPO-Haluwas, Distt. Bhiwani, Army 28-12-1994	Raj Bai Wife	Peon 26-02-2016	Army	Wife
2	Martyr Rakesh, VPO-Khoth, Distt. Bhiwani Army 16-08-2003	Suman Devi Wife	Clerk 29-1-2016	Army	Wife
3	Martyr Dharam Singh, VPO-Haluwas, Distt. Bhiwani, Army 20-01-1989	Surender Son	Clerk 03-03-2016	Army	Son
4	Martyr Kartar Singh, VPO-Sankror, Distt. Bhiwani, Army 28-04-1989	Sanjay Kumar Son	Clerk 29-01-2016	Army	Son
5	Martyr Hawa Singh, VPO-Barela, Distt. Bhiwani, Army 13-09-2001	Vikash Son	Clerk 10-02-2016	Army	Son
6	Martyr Fateh Singh, VPO-Badesara, Distt. Bhiwani, Army 22-03-1986	Anand Son	Clerk 26-04-2016	Army	Son
7	Martyr Ramesh Chander, Vill-Dhani Rai Singh, Sarai Chopta, Distt. Bhiwani Army 18-07-2002	Rekha Yadav Wife	Clerk 25-03-2016	Army	Wife
8	Martyr Rajbir, VPO-Kakroli Sardara, Distt. Bhiwani,	Mukesh Devi Wife	Peon 19-02-2016	Army	Wife

	Army 30-12-2001				
9	Martyr Lal Singh, VPO-Ramwas, Distt. Bhiwani, Army 07-07-1998	Vijay Son	Clerk 19-02-2016	Army	Son
10	Martyr Surya Parkash, # 417, D.C. Colony, Bhiwani Army 19-12-2001	Vijesh Wife	Peon 25-03-2016	Army	Wife
11	Martyr Sandeep Kumar, R.O.-Shanti Nagar, Bhiwani Army 03-08-2005	Kusum Lata, Wife	Peon 21-04-2016	Army	Wife
12	Martyr Babu Lal, VPO-Manheru Distt. Bhiwani, CRPF 15-12-1991	Rupinder Son	Clerk 22-04-2016	CRPF	Son
13	Martyr Mahabir Singh, VPO-Rewari Khera, Bhiwani Army 02-10-2002	Neeraj Son	Clerk 12-05-2016	Army	Son
14	Martyr Rameshwar, VPO-Berla, Distt. Bhiwani, Army 07-07-2000	Akash Son	Clerk	Army	Son
15	Martyr Satya Parkash, VPO-Mandhola, Distt. Bhiwani, Army 08-06-1989	Neelam Daughter	Clerk 30-05-2016	Army	Daughter
16	Martyr Rajbir, VPO-Sidhan, Distt. Bhiwani, Army 01-07-2000	Poonam Daughter	Clerk 21-12-2016	Army	Daughter
17	Martyr Krishan Kumar, VPO-Char, Distt. Bhiwani, BSF 03-05-1993	Sushil Kumar Son	Clerk 14-12-2016	BSF	Son
18	Martyr Bharat Singh, VPO-Khanda Kheri, Distt. Hisar, Army 05-04-1990	Sandeep Son	Clerk 27-04-2016	Army	Son
19	Martyr Ram Mehar, VPO-Khedar, Distt. Hisar, Army 01-07-2002	Reena Daughter	Clerk 27-04-2016	Army	Daughter
20	Martyr Ram Mehar, VPO-Badla, Distt. Hisar, Army 03-03-1996	Sumit Son	Clerk 28-04-2016	Army	Son
21	Martyr Om Parkash, VPO-Litani, Distt. Hisar, Army 08-08-1989	Suman Rani Daughter	Clerk 28-04-2016	Army	Daughter
22	Martyr Raj Kumar, VPO-Kharbala, Distt. Hisar, Army 15-06-1997	Vinod Kumar Son	Clerk 28-04-2016	Army	Son
23	Martyr Ram Phal, VPO-Bass, Distt. Hisar, Army 27-04-1995	Shyam Sunder Son	Clerk 12-05-2016	Army	Son
24	Martyr Bharat Singh, VPO-Khanda Kheri, Distt. Hisar, Army 05-04-1990	Sandeep Son	Clerk 27-04-2016	Army	Son
25	Martyr Sarwan Kumar, VPO-Sandol, Distt. Hisar, Army 10-10-2002	Sudesh Kumari Daughter	Clerk 14-10-2016	Army	Daughter

26	Martyr Baljeet Singh, # 698/18, Advocate Colony, Hansi Hisar, Army 16-06-2000	Pritti Sherawat Daughter	Clerk 28-11-2016	Army	Daughter
27	Martyr Suresh Kumar, VPO-Dhakal, Distt. Jind, Army 16-12-2001	Madhu Daughter	Clerk 16-12-2016	Army	Daughter
28	Martyr Suraj Bhan, VPO-Chhatar, Distt. Jind, Army 11-11-1989	Balinder Son	Clerk 15-11-2016	Army	Son
29	Martyr Kuldeep, VPO-Kheri Bulan, Distt. Jind, Army 5-12-2014	Rekha Wife	Clerk 15-11-2016	Army	Wife
30	Martyr Ishwar Singh, Vill.-Chandpur, P.O. Dadanpur, Distt. Jhajjar Army 08-08-1989	Raj Hans Son	Clerk 29-1-2016	Army	Son
31	Martyr Ram Kishan, V.P.O-Khanpur Khurd, Distt. Jhajjar Army 19-05-2004	Pooja Daughter	Clerk 11-11-2016	Army	Daughter
32	Martyr Bani Singh, Vill.-Jatwara, P.O. Dadanpur, Distt. Jhajjar BSF 12-09-2004	Seema Daughter	Clerk 16-1-2016	BSF	Daughter
33	Martyr Ramesh Kumar, Silani Gate-Delhi Road, Ward No. 7 Jhajjar. Army 04-03-1989	Sunil Rani Daughter	Clerk 09-02-2016	Army	Daughter
34	Martyr Surender Kumar, V.P.O. Subna, Distt. Jhajjar Army 09-09-2013	Vijay Son	Clerk 2-6-2016	Army	Son
35	Martyr Balganand, V.P.O. Dhigar, Distt. Jhajjar Army 13-03-1986	Het Ram Son	Peon 25-4-2016	Army	Son
36	Martyr Shiv Narayan, V.P.O. Kablana, Distt. Jhajjar Army	Shashi Prasar Daughter	Clerk 19-12-2016	Army	Daughter
37	Martyr Krishan Singh, V.P.O. Lahli, Distt. Rohtak Army 10-05-1998	Pawan Son	Peon 4-1-2016	Army	Son
38	Martyr Jaswant Singh, V.P.O. Makroli Kalan, Distt. Rohtak Army 09-05-2003	Kavita Wife	Peon 17-2-2016	Army	Wife
39	Martyr Sunil Kumar, V.P.O. MaKroli Khurd, Distt. Rohtak Army 28-01-2007	Satwanti Wife	Peon 21-4-2016	Army	Wife
40	Martyr Partap Singh, V.P.O. Pakshma, Distt. Rohtak Army 14-09-2003	Amit Son	Clerk 21-4-2016	Army	Son
41	Martyr Ram Niwas, V.P.O. Ishmila, Distt. Rohtak Army 07-03-1993	Rakesh Son	Clerk 18-5-2016	Army	Son
42	Martyr Krishan Kumar, V.P.O.	Vivek Malik	Clerk	Army	Son

	Mokhra Khas, Distt. Rohtak Army 03-07-2008	Son	18-5-2016		
43	Martyr Ravinder Kumar, # 1234/31, Kamla Nagar, Rohtak Army 10-07-2012	Naveen Brother	Clerk 08-07-2016	Army	Brother
44	Martyr Rajesh Kumar, V.P.O. Ghirol Kalan, Distt. Rohtak Army 19-06-2012	Babli Wife	Clerk 26-7-2016	Army	Wife
45	Martyr Suresh Kumar, V.P.O. Sampal, Distt. Rohtak Army 19-06-2012	Neeraj Kumar Son	Clerk 15-12-2016	Army	Son
46	Martyr Rajbir, V.P.O. Kasandi, Distt. Sonepat Army 11-11-1993	Anjali Daughter	Clerk 26-07-2016	Army	Daughter
47	Martyr Lakshman Singh, Vill-Mehlana, Distt. Sonepat Army 09-06-1999	Pawan Kumar Son	Peon 17-10-2016	Army	Son
48	Martyr Dilbag Singh, V.P.O. Ahulana, Distt. Sonepat Army 04-10-1997	Geeta Daughter	Clerk 13-10-2016	Army	Daughter
49	Martyr Hushan Lal, VPO-Baras, Distt. Karnal Army 23-05-2010	Shalu Wife	Clerk 11-10-2016	Army	Wife
50	Martyr Om Parkash, VPO-Satondi, Distt. Karnal Army 23-05-2010	Hans Raj Son	Clerk 11-10-2016	Army	Son
51	Martyr Raj Kumar, VPO-Baras, Distt. Karnal Army 07-05-1990	Shashi Bhushan Son	Clerk 13-10-2016	Army	Son
52	Martyr Raki, Vill.-Ramgarh Majra, PO-Fatehjarh Tumbi Distt. Y. Nagar BSF 05-08-2015	Rohit Kumar Brother	Clerk 18-03-2016	BSF	Brother
53	Martyr Gurshewak, Vill-Garnalal, PO-Dhankhor, Ambala Army 2-01-2016	Jaspreet Kaur Wife	Clerk 27-05-2016	Army	Wife
54	Martyr Surender Singh VPO Kakar Majra Distt Kaithal 20.09.2000.	Jitender son	Clerk	Army	son
55	Martyr Rishi pal VPO Titaram Distt Kaithal Army 12.02.1995	Mandeep Son	Peon 06.2016.	Army	son
56	Martyr Raghbir Singh VPO Kolekhan Distt Kaithal	Deepak son	Peon 06.2016	Army	son
57	Martyr Radheshyam ward no.1 Distt Gurugram	Rohit Kumar son	Clerk 06-2016	Army	Son
58	Martyr Naresh Kumar, VPO-Lokra, Tehsil & Distt. Gurugram Army 16.04.2006	Suresh Devi Wife	Peon 31-08-2016	Army	Wife
59	Martyr Anil Kumar, VPO-Pahari, Tehsil-Patodi, Distt. Gurugram Army 12-11-2007	Sunila Wife	Clerk 27-10-2016	Army	Wife

60	Martyr Lala Ram VPO Sahore Distt Mahendergarh, Army 21-07-1994	Ajay Pal son	Clerk 04-02-2016	Army	Son
61	Martyr Babu Lal VPO Guwani Distt Mahendergarh 12-10-1987	Pardeep son	Clerk 25-04-2016	Army	son
62	Martyr Mahabir Singjh, Vill. Mohanpur, P.O.-Doharkalan, Distt Mahendergarh 31-05-1989	Amit Kumar son	Peon 23-06-2016	Army	son
63	Martyr Murari Lal, VPO Bihali, Distt Mahendergarh 25-12-2008 BSF 25-12-2008	Dinesh son	Clerk 29-06-2016	BSF	son
64	Martyr Inderjeet, Mohala Miyan Ki Sarai, Narnaul, Distt Mahendergarh 16-09-2004	Baljeet Singh son	Clerk 03-08-2016	Army	Son
65	Martyr Pala Ram Lamba, Vill.-Chindaliya, PO-Mangal Katha Distt Mahendergarh BSF 14-03-2011	Shakti Singh son	Clerk 25-07-2016	BSF	Son
66	Martyr Khushi Ram VPO Nangal Choudhary Distt Mahendergarh Army 04-03-2005	Aarti Daughter	Clerk 03-08-2016	Army	Daughter
67	Martyr Mahabir Singh, Vill-Mohanpur, PO-Dholkalan Distt Mahendergarh Army 31-05-1989	Amit Kumar son	Peon 23-06-2016	Army	Son
68	Martyr Anup Singh, # 1613, Subhash Nagar, Jhajjar Road, Rewari, Army 26-08-1997	Jitin Yadav son	Clerk 13-10-2016	Army	Son
69	Martyr Suresh Kumar, VPO-Haluhera, Distt. Rewari Army 26-08-1997	Jitender Yadav Son	Clerk 10-10-2016	Army	Son
70	Martyr Deen Mohammad, Vill-Laherwari, PO-Punana, Distt. Mewat Army 14-10-1990	Sabir Ahmed Son	Clerk 27-05-2016	Army	Son
71	Martyr Vikram Singh, VPO-Khurthala, Distt. Mewat Army 15-04-2005	Inder Singh Son	Clerk 26-09-2016	Army	Son
72	Martyr Ahmad Ali, Vill-Gudi, PO-Kalawadi, Distt. Mewat Army 02-07-1999	Rukmina Daughter	Clerk 03-10-2016	Army	Daughter
73	Martyr Mohammad Nishar, VPO-Imam Nagar, Distt. Mewat CRPF-16-04-2011	Abdullah Son	Clerk 25-07-2016	CRPF	Son
74	Martyr Raghubir Singh, Vill.-Sotaya, PO-Fatehpur Biloch, Faridabad Army-15-03-2000	Naresh Kumar Son	Peon 29-07-2016	Army	Son
75	Martyr Pardeep Chauhan, Vill-Ratanthal, Tehsil-Kosli, Distt. Rewari Army-23-02-2002	Dal Singh Brother	Peon 17-02-2016	Army	Son

Year 2017 (Total-60)					
1	Martyr Rajpal Village- Gopal Was, Post Office- Badrai. Tehsil- Badra, District- Bhiwani	Takdeer (Son)	Clerk/ 06.07.2017	Army	Son
2	Martyr Manjeet Village & Post Office- Bigaawa Tehsil- Badra , District- Bhiwani Army/27.09.2001	Kavita Devi (Wife)	Clerk/ 06.07.2017	Army	Wife
3	Martyr Gopal Village & Post Office- Ranila Tehsil- Charkhi Dadri , District- Bhiwani Army/10.05.1998	Jitender Panwar (Son)	Clerk/ 17.07.2017	Army	Son
4	Martyr Surender Singh H. No. 104, Village- Bardu Dhirja Tehsil- Loharu, District- Bhiwani Army/ 07.07.1999	Radha (Daughter)	Clerk/ 31.08.2017	Army	Daughter
5	Martyr Sunil Kumar Village & Post Office- Bond Kalan Tehsil- Charkhi Dadri , District- Bhiwani Army/26.08.2009	Urmila Devi (Wife)	Sewadar/ 04.09.2017	Army	Wife
6	Martyr Umed Singh Village- Jhhoju Khurd, Post Office- Jhhoju Kalan Tehsil- Charkhi Dadri , District- Bhiwani Army/27.03.1993	Ravinder Kumar (Son)	Clerk/ 04.09.2017	Army	Son
7	Martyr Partap Singh. Village & Post Office- Bapora, Tehsil & District- Bhiwani	Anita Devi (Wife)	Sewadar/ 25.11.2017	Army	Wife
8	Martyr Balwantrai. Village- Jhadli Khurd, Tehsil & District- Fatehabad Army/27.03.1991	Kuldeep (Son)	Clerk/ 19.04.2017	Army	Son
9	Martyr Dalbir Singh. H. No. 620, Ward No. 20, Behind Puran Market, District- Charkhi Dadri. Army/15.02.2000	Meenakshi (Daughter)	Clerk/ 06.09.2017	Army	Daughter
10	Martyr Attar Singh. Ward No. 14,Behind Uddham Singh Jain Hospital, Tehsil & District- Charkhi Dadri.	Mohit (Adopted Son)	Clerk/ 01.12.2017	Army	Adopted Son
11	Martyr Vijay Singh. H. No. 647, sector-13, District- Hisar	Maneeta (Daughter)	Clerk/ 08.03.2017	Army	Daughter

	Army/07.07.1997				
12	Martyr balbir Singh. H. No. 338, Village- Kharkhari, District- Hisar. Army/25.07.2001	Anil Kumar (Son)	Clerk/ 31.08.2017	Army	Son
13	Martyr Subhash Chander Dalal. Village & Post Office- Naagura, Tehsil- Alewa, District- Jind CRPF/11.03.2014	Deepak Dalal (Son)	Clerk/ 03.08.2017	CRPF	Son
14	Martyr Dharambir Singh. Village- Dariyawala, Tehsil & District- Jind. BSF/08.12.2009	Manisha (Daughter)	Clerk/ 31.08.2017	BSF	Daughter
15	Martyr Aashish Kumar. H. No. 376, Chmala Colony, Narwana, District- Jind. Army/15.06.1999	Jyoti (Daughter)	Seweadar/ 31.08.2017	Army	Daughter
16	Martyr Mahabir Singh, VPO-Khatkar, Distt. Jind CRPF	Anil Son	Clerk 26-11-2017	CRPF	Son
17	Martyr Jasbir Singh, Vill. Barhana, Distt. Jhajjar Army 18-01-1995	Jyoti Daughter	Clerk 01-08-2017	Army	Daughter
18	Martyr Dilbagh Singh, Vill. & PO Barhana, Distt. Jhajjar BSF 30-10-2014	Aashish Singh Son	Clerk 08-09-2017	Army	Son
19	Martyr Rohtash Singh, VPO-Mohanbari, Tehsil-Matanhail, Jhajjar Army14-05-1989	Jaswanti Devi Daughter	Clerk/ 23-09-2017	Army	Daughter
20	Martyr Dalbir Singh, VPO-Kharari, Tehsil-Kalanaur, Rohtak BSF 07-06-2000	Parambir Singh Son	Peon 08-09-2017	BSF	Son
21	Martyr Partap Singh, VPO-Jasia, Rohtak CRPF 03-05-2011	Gulab Singh Son	Clerk 08-09-2017	CRPF	Son
22	Martyr Hari Om, VPO-Bhalouth, Tehsil & Distt. Rohtak	Manju Bala Wife	Clerk 04-12-2017	Army	Wife
23	Martyr Randhir Singh, VPO-Sardana, Sonepat Army 20-10-1988	Rakesh Kumar Son	Clerk 08-07-2017	Army	Son
24	Martyr Jagmohinder Singh, VPO-Mehlana, Sonepat Army 02-11-1994	Prince Kumar Son	Clerk 20-07-2017	Army	Son

25	Martyr RajPal Singh, VPO-Barwala, Panchkula Army	Ajay Singh Son	Clerk 08-09-2017	Army	Son
26	Martyr Mandeep Singh, Vill-Antheri, PO-Bodla, Tehsil-Thanesar, Kurukshetra Army 28-10-2016	Sandeep Brother	Clerk 07-06-2017	Army	Brother
27	Martyr Sushil kumar, R/o Fancy Colony, Pehwa, Kurukshetra BSF 24-10-2016	Sunita Wife	Peon 12-10-2017	BSF	Wife
28	Martyr Surender Singh, Vill-Garoli Khurd, PO-Basai, Gurugram Army 21-05-2004	Kumari Anjali Daughter	Clerk 06-07-2017	Army	Daughter
29	Martyr Kaptan Singh, VPO-Bilaspur,Gurugram Army 13-09-2005	Mithun Son	Clerk 16-06-2017	Army	Son
30	Martyr Suresh Chand, VPO-Ghungola, Gurugram Army 25-08-1997	Naresh Kumar Son	Clerk 14-09-2017	Army	Son
31	Martyr Mursalim, VPO-Khudana, Tehsil & Distt. Mahindergarh Army 05-08-2010	Rajbala Wife	Peon 15-05-2017	Army	Wife
32	Martyr Dharam Pal, VPO-Kheri Talwana, Mahindergarh Army 16-07-2011	Sombir Son	Clerk 18-05-2017	Army	Son
33	Martyr Rawat Singh, VPO-Minadpur, Mahindergarh Army	Anil Kumar Son	Peon 03-06-2017	Army	Son
34	Martyr Jai Dayal, VPO-Bucholi, Mahindergarh Army	Dharmender Son	Peon 03-06-2017	Army	Son
35	Martyr Neki Ram, VPO-Beri, Mahindergarh Army 20-05-2011	Yogesh Kumar Son	Clerk 08-09-2017	Army	Son
36	Martyr Satpal Singh, Vill-Gealhi, PO-Hamidpur, Mahindergarh Army 02-11-1998	Deepak Kumar Son	Clerk 03-11-2017	Army	Son
37	Martyr Heera Lal Yadav, VPO-Rasulpur, Mahindergarh Army 13-09-1988	Mehar Singh Son	Peon 27-10-2017	Army	Son
38	Martyr Mahabir Parshad, VPO-Dongar Ahir, Mahindergarh	Pawan Kumar	Clerk 24-12-2017	Army	Son

	Army	Son			
39	Martyr Pardeep Yadav, VPO-Naya Gaon, Rewari CRPF 07-01-2013	Poonam wife	Peon 30-05-2017	CRPF	Wife
40	Martyr Ram Kishan, VPO-Mamriyahri, PO-Kohri, Rewari Army 20-07-2005	Ravinder Son	Peon 09-05-2017	Army	Son
41	Martyr Raj bir Singh, VPO-Pithrawas, Rewari CRPF 20-07-2001	Sangeeta Daughter	Clerk 27-07-2017	CRPF	Daughter
42	Martyr Rajneesh Kumar, VPO-Pawali, Rewari CRPF 20-07-2015	Meena Bai wife	Clerk 01-03-2017	CRPF	Wife
43	Martyr Rajinder Singh, VPO-Jant, Rewari BSF 05-08-2013	Uttam Singh Son	Peon 04-03-2017	BSF	Son
44	Martyr Harkesh Singh, VPO-Gudhiyani, Rewari Army	Ravinder Kumar Son	Clerk 19-05-2017	Army	Son
45	Martyr Bijender, # 215, Vijay Nagar, Konsiwal Road, Rewari Army	Vijay Lata wife	Clerk 24-12-2017	Army	Wife
46	Martyr Mohammad Sadik, VPO-Bijopur, Faridabad Army 27-07-2000	Nasib Ahmad Son	Clerk 04-04-2017	Army	Son
47	Martyr Diwan Singh, VPO-Chajju Nagar, Distt. Palwal	Gajinder Son	Clerk 18-01-2017	Army	Son
48	Martyr Sarwan Kumar, VPO-Raipur, Palwal Army 21-10-1998	Ravi Kumar Son	Clerk 08-03-2017	Army	Son
49	Martyr Shamsher Singh, VPO-Bhulwana, Palwal Army 28-12-2001	Dinesh Son	Clerk 03-03-2017	Army	Son
50	Martyr Deep Chand, VPO-Banchari, Palwal Army 31-12-2001	Jatinder Kumar Son	Clerk 01-03-2017	Army	Son
51	Martyr Ram Babu, Vill-Bidawali, PO-Chhayasa, Palwal Army 18-10-1998	Bharat Pal Son	Clerk 01-03-2017	Army	Son
52	Martyr Fateh Singh, VPO-Saroli, Palwal Army 19-11-1995	Manoj Kumar Son	Peon 07-03-2017	Army	Son
53	Martyr Dharambir, VPO-Meerpur, Karali, Palwal Army 22-08-2003	Adarsh Kumar Son	Clerk 22-03-2017	Army	Son
54	Martyr Birbal, VPO-Banchari, Palwal Army 30-11-1998	Gajinder Singh Son	Clerk 27-04-2017	Army	Son
55	Martyr Amarchand, Aadarsh Colony, In front of Bansal Nursing Home, Gali No. 7, Palwal Army 20-04-2010	Kusum Lata Wife	Peon 24-04-2017	Army	Wife

56	Martyr Subhash Chand, VPO-Chandhat, Palwal Army 24-11-2000	Kuldeep Son	Clerk 30-05-2017	Army	Son
57	Martyr Nepal Singh, VPO-Phulwari, Palwal Army 10-06-1996	Ram Niwas Son	Peon 20-05-2017	Army	Son
58	Martyr Asgar Ali, VPO-Buraka, Palwal Army 08-12-1992	Aashif Son	Clerk 20-05-2017	Army	Son
59	Martyr Badan Singh, VPO-Mitrol, Palwal Army 27-09-2001	Sunita Wife	Clerk 31-08-2017	Army	Wife
60	Martyr Ram Dev Singh, Vill. Balai,PO-Amarpur, Palwal BSF	Lokesh Kumar Son	Clerk 21-11-2017	BSF	Son

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से 2014 में 10, 2015 में 25, 2016 में 75, 2017 में 60, 2018 में 25 लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं जो शहीद सैनिक/अर्धसैनिक बलों के आश्रित परिवार से संबंध रखते हैं। हमारी सरकार आने के बाद टोटल 195 लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं जो शहीद सैनिक/अर्धसैनिक बलों के आश्रित परिवार से संबंध रखते हैं । अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहूंगा कि 1998 के कारगिल युद्ध से पहले जो सैनिक सीमा पर देश की रक्षा में शहीद हो जाते थे उनके अंतिम संस्कार का कोई अता–पता नहीं होता था । श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधान मंत्री थे वे कारगिल युद्ध की 14 हजार फिट की उंचाई पर गये और हमारे देश के राष्ट्रपति ने मना किया था कि इतने बड़े देश के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान जैसा बेईमान देश सामने हो मोर्चे पर नहीं जाना चाहिए । लेकिन श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी मोर्चे पर गये थे । जिस पण्डाल में वाजपेयी जी सैनिकों को सम्बोधित कर रहे थे उस पण्डाल का आधा हिस्सा गिर गया था । उस दौरान वाजपेयी जी ने मोर्चे पर कहा था कि भारत माता के वीर लालो हमारे जो शहीद सैनिक हैं उनका अंतिम संस्कार तिरंगे में लपेट कर तोपों की सलामी के साथ जिस गांव की मिट्टी के वे बने हैं उसी गांव की मिट्टी में उनका अंतिम संस्कार करवायेंगे। इसके साथ–साथ वाजपेयी जी ने यह भी कहा था कि हमारे शहीदों के मॉ–बाप, विधवाओं और बच्चों की रक्षा/सुरक्षा सरकार करेगी । यही कारण है कि वाजपेयी जी की सरकार के समय में जितनी गैस एजैंसीज/पैट्रोल पम्प दिए गए थे वे शहीदों के परिवारों को दिए गए थे ।

श्री बिशम्बर सिंह बालमीकि : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शहीदों के आश्रितों के कितने पद रिक्त हैं और उन्हें कब तक भरा जायेगा ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 में हमारी सरकार आने के बाद कैबिनेट ने चीफ सक्रेटरी जी की अध्यक्षता में शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने के लिए सैनिक कल्याण के लिए अलग से विभाग बनाया है । हमारी सरकार ने शहीदों की तीसरी पीढ़ी को नौकरी देने का काम किया है । यह हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि आफिसर्ज ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई में पास होने वाले अधिकारियों में प्रीती चौधरी और वीरती शर्मा हमारे प्रदेश की बेटियां हैं । अध्यक्ष महोदय, यह बात सारा जहां जानता है कि हमारी प्रदेश की आबादी देश की आबादी का 2 प्रतिशत है । But our contribution to the country in the Army is 11 percent. जरनल दीपक कपूर, जरनल वी.के. सिंह व जनरल दलबीर सुहाग तीन चीफ हमारे हरियाणा प्रदेश से रहे हैं और वर्तमान नेवी का चीफ एडमिरल सुनील लाम्बा भी हमारे प्रदेश के पलवल जिला से हैं । अध्यक्ष महोदय, हमने शहीदों के लिए जो कार्य किए हैं इससे उन पर किसी तरह का एहसान नहीं किया है, it is our duty. पहले शहीदों के परिवारों को 5 लाख रुपये की राशि मिलती थी और बहन किरण चौधरी जी की सरकार के समय में अगस्त 2014 में यह राशि 20 लाख रुपये की गई । उसके तुरंत बाद हमारी सरकार आ गई थी । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सैनिक की बेटी हूं । एक बात कहना चाहूंगी कि इस तरह से मंत्री जी को सैनिकों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, प्लीज आप बैठें । मंत्री जी सैनिकों के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे बल्कि आपकी सरकार की बात कर रहे हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं फौजी की बेटी हूं और मंत्री जी ने मेरा नाम लेकर बात कही है ।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज के बाद मैं कांग्रेस पार्टी के साथ बहन किरण चौधरी जी का नाम नहीं जोड़ूंगा क्योंकि उनका मन बदल रहा है ।

बहन किरण चौधरी जी कांग्रेस विधायक दल की नेता हैं । हम इनको सम्मान देते हैं । अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने अगस्त, 2014 में शहीदों के परिवारों को 20 लाख रुपये देने की घोषणा की थी परंतु उस रिजीम में अगस्त के बात विधान सभा के चुनाव डिकलेयर हो गये । उसके बाद प्रदेश में हमारी सरकार आ गई और हमारी सरकार आने के तुरंत बाद शहीदों के आश्रितों के लिए हमने 50 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान किया ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, आतंकवादी हमले में सुबेदार मेजर रणबीर सिंह शहीद हो गये थे । उनकी बेटी को नौकरी देने के लिए दरखास्त दी हुई है लेकिन सरकार की तरफ से कह दिया गया कि लड़कियों को नौकरियां नहीं दी जाती परंतु दूसरे शहीद की लड़की जयवंती को सरकार ने नौकरी दी है । सरकार किस आधार पर यह पिक एंड चूज करके नौकरियां दे रही है ? शहीद सुबेदार मेजर रणबीर की लड़की सुनीता देवी को नौकरी देने बारे क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया था कि हमारी सरकार आने के बाद हमने शहीदों की तीसरी पीढ़ी को कैबिनेट से विशेष अनुमति देकर नौकरी देने का काम किया है और अब तक हमारी सरकार 195 शहीदों के आश्रितों को नौकरी दे चुकी है । माननीय सदस्य जगबीर मलिक जी ने जिस शहीद की बेटी को नौकरी देने का विषय उठाया है वह अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, अब आप बैठें । मंत्री जी ने जवाब दे दिया है कि यह विषय उनके विचाराधीन है ।

श्रीमती प्रेम लता : अध्यक्ष महोदय, हमारे जींद जिले के कैप्टन पवन खटकड़ जी तीन साल पहले देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गये थे । वे अपने माता–पिता के इकलौते बेटे थे । उस समय जाट आरक्षण का मुद्दा चल रहा था जिसके कारण मुख्यमंत्री जी ने हमें हैलीकोप्टर प्रोवाईड करवाया था ताकि हम शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हो सकें । कैप्टन अभिमन्यु जी, सुभाष बराला जी और मैं वहां पर गये थे और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उस शहीद के नाम से कोई न कोई संस्था बनाई जायेगी जिसके लिए 50 करोड रुपये भी एनाउंस किए गए थे ।

तीन साल का समय हो गया उस शहीद के नाम से जो संस्था बनाई जानी है उस पर कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बहन प्रेम लता जी ने शहीद कैप्टन पवन खटकड़ के नाम पर किसी संस्था का नाम रखने का सवाल उठाया है । इस बारे में मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि कैप्टन पवन खटकड़ के नाम से सरकार होर्टीकल्चर का बहुत बड़ा रीजनल सैंटर बनाने जा रही है जिसका बहुत जल्द कार्य शुरू हो जायेगा ।

.....

Construction of PHC Building

***2295. Shri Jaswinder Singh Sandhu** : Will the Health Minister be pleased to state :-

(a) whether it is a fact that the building of P.H.C. in Ismailabad town is in dilapidated condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new building of the above said P.H.C; togetherwith the details thereof?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) यद्यपि, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इस्माईलाबाद के एक अतिरिक्त भवन का निर्माण किया जा रहा है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी पेहवा में एक जनसभा को सम्बोधित करने के लिए गये थे और वहां पर उन्होंने पेहवा में 100 बैड का एक हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की थी। इसी प्रकार से इस्माईलाबाद का जो प्राइमरी हैल्थ सैन्टर है वह बहुत ही जर्जर हालत में है। सरकार जिस प्रकार से नये डॉक्टर्स की भर्ती कर रही है और लोगों के स्वास्थ्य संबंधी बड़े बलंगबांग दावे किये जा रहे हैं इसलिए इस्माईलाबाद की पी.एच.सी. के भवन का भी पुनर्निमाण किया जाये। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि

पेहवा में जो 100 बैड के हॉस्पिटल की मुख्यमंत्री जी की घोषणा है वह हॉस्पिटल तो बन जायेगा या नहीं? वह एक पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां पर हॉस्पिटल बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, जिस पी.एच.सी. की बिल्डिंग का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं उसको हमने पी.डब्ल्यू.डी. से इग्जामिन करवाया था जिसके बारे में उनका कहना है कि अभी वह बिल्डिंग ठीक है तथा और चल सकती है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उसी भवन में एक दूसरे ब्लॉक के निर्माण के लिए 3 करोड 60 लाख रुपये की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दी जा चुकी है और रिवाइज्ड ड्राइंग एप्रूव करके बी.एण्ड आर. विभाग को भेज दी गई है कि वहां पर नया ब्लॉक बनाया जाये।

.....

नार्वे के राजदूत का अभिनन्दन

Parliamentary Affairs Minister (Shri Ram Bilas Sharma): Hon'ble Speaker Sir, His Excellency, Shri Nils Ragnar Camsvaag, Ambassdor of Narway is sitting in our VIP Gallery to watch the proceedings of the House. This House welcome him.

तरांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna

***2638 Smt Latika Sharma** : Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the time by which the Pardhan Mantri Krishi Sinchai Yojna is likely to be implemented in Haryana together with the number of Districts likely to be benefitted under the scheme along with the targets fixed for implementing the scheme and the details thereof?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड) : श्रीमान् जी, सूचना सदन के पटल पर रखी है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू करने बारे श्रीमती लतिका शर्मा, एम0एल0ए0, द्वारा पूछे गये ताराकिंत विधानसभा प्रश्न संख्या '2638 के उत्तर के सन्दर्भ में सूचना ।

सूचना

राज्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015–16 से लागू की जा रही है । सूक्ष्म सिंचाई तथा अन्य जल सिंचाई दक्षता प्रणालियों की क्रियान्वित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के सभी 22 जिलों को शामिल किया गया है । छः वर्ष (2016–17 से 2021–22) की अवधि के लिए 1736396.99 लाख रूपये की एक व्यापक राज्य सिंचाई योजना को क्रियान्वित करने का अनुमोदन राज्य स्तरीय संस्तुति समिति (एस0एल0एस0सी0) द्वारा किया जा चुका है । जिलावार तथा मदवार कार्यान्वयन योजनांए क्रमशः अनुलग्नक क तथा ख में दी गई हैं ।

अनुलग्नक–क

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिलावार तथा वर्षवार योजना

रूपये लाख में

जिला	वर्षवार आबंटन						
	2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**कुल**
अम्बाला	2447.93	4323.23	3776.44	3064.57	3303.23	3494.24	20009.64
भिवानी	8498.71	62503.48	58629.26	42089.51	38822.52	34015.58	244559.06
फरीदाबाद	1869.03	4873.78	3221.29	2325.99	1412.72	1149.72	14852.53
फतेहाबाद	1553.35	19460.63	22125.34	21956.46	17942.26	16673.86	99691.90
गुरूग्राम	1299.71	3082.32	2349.91	1828.36	1634.02	1605.51	11799.83
हिसार	21425.23	46192.15	35401.79	30318.29	30441.96	34346.60	198126.02
झज्जर	648.39	26998.29	18635.81	13672.06	13293.53	13607.42	86855.50
जीन्द	821.56	36454.88	20211.07	17323.43	16483.38	16010.11	107304.43
कैथल	8731.73	8196.14	10148.90	9673.60	8933.10	7630.99	53314.46
करनाल	3254.79	20320.74	39472.39	50367.68	11605.54	12011.35	137032.49
कुरूक्षेत्र	1490.44	5765.03	8094.55	7230.05	4452.84.	3130.09	30163.00
महेन्द्रगढ	4347.47	22036.56	19727.44	19455.51	19343.99	18192.94	103103.88
नूँह	5136.90	17230.10	17355.45	12671.39	4019.73	3867.11	60280.68
पलवल	2338.30	11440.44	9009.76	8048.79	6754.08	4839.63	42431.00
पंचकूला	1905.60	2398.80	2499.20	2546.60	2591.99	2664.26	14606.45
पानीपत	2088.31	44660.62	8226.26	16334.80	18645.29	9711.27	99666.55
रिवाडी	4144.31	13057.51	12646.84	11550.07	11204.04	11330.85	63933.62
रोहतक	4533.99	9728.88	6858.88	5682.38	5385.58	3623.68	35813.39
सिरसा	10444.82	31921.87	21719.90	18360.31	19165.56	19560.21	121172.67
सोनीपत	2371.50	19053.04	11141.90	12962.77	14288.49	14030.13	73847.83
यमुनानगर	557.30	40756.12	57029.47	6086.08	6394.48	7008.61	117832.06
कुल	**89889.30**	**450454.60**	**387881.85**	**313548.7**	**256118.33**	**238504.16**	**1736396.99**

अनुलग्नक–ख

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मदवार तथा वर्षवार योजना

रूपये लाख में

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल लागत
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	21888.99	209308.28	167914.01	98719.27	44372.16	28505.24	**570707.95**
हर खेत को पानी	22293.59	164135.40	155990.60	151787.13	149579.28	147475.82	**791261.82**
प्रति बूंद अधिक फसल	14503.79	27305.42	25773.06	26150.06	25600.85	28706.25	**148039.43**
पनधारा विकास	25046.62	42688.34	31185.39	30733.70	30080.56	27856.80	**187591.41**
मनरेगा के साथ रूपान्तरण	6156.37	7017.16	7018.79	6158.54	6485.47	5960.05	**38796.38**
कुल	**89889.36**	**450454.60**	**387881.85**	**313548.70**	**256118.32**	**238504.16**	**1736396.99**

श्रीमती लतिका शर्माः अध्यक्ष महोदय, यह जो हर खेत को पानी का पायलट प्रोजैक्ट है यह बहुत अच्छा प्रोजैक्ट है और इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बहुत अच्छी योजना है। इस योजना से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनको अधिक से अधिक आगे बढ़ाया जाना चाहिए, उनको इम्पलीमैंट किया जाना चाहिए। यह योजना जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए और पूरा हो भी रहा है इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारा कालका क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और इसमें लगभग 190 गांव हैं और वे सिंचाई के लिए कूल, डैम तथा ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं। हमारे क्षेत्र में ट्यूबवैल ज्यादा नहीं लग पाते हैं। जो ट्यूबवैल्स लगे हैं वे एम.आई. टी.सी. के द्वारा शिवालिक विकास बोर्ड के माध्यम से लगाये गये हैं। वहां पर बोर ज्यादा गहरे करने पड़ते हैं और अब वे अच्छी हालत में नहीं हैं, वे लगभग खत्म ही हो गये हैं। मैं कहना चाहूंगी कि सबसे अच्छी नर्सरी हमारे क्षेत्र में है। हमारे क्षेत्र में टमाटर, मक्का, अदरक, चावल, हरड़, आंवला, हल्दी, उड़द, सब्जियां तथा फूलों की खेती सबसे अच्छी होती है। हमारे एरिया में सरसा नदी है जो दून एरिया में पड़ती है तथा घग्गर और छामला भी हैं जो कि मोरनी और रायतन एरिया में पड़ती हैं। हमारे एरिया में सिंचाई के अपार साधन हैं इसलिए मैं चाहूंगी कि हमें इस योजना से जोड़ा जाये ताकि किसानों को इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। हमारे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि हमें नौकरी मिले न मिले लेकिन सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाये तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि यह योजना हमारे कालका क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कालका के लिए शिवालिक विकास बोर्ड के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा इम्पलीमैंट किया जाये।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत अलग–अलग विभागों की 4 योजनाएं आती हैं। इनमें से एक है नहरों का पुनर्निर्माण और नहर विभाग ही इसको कार्यान्वित करता है। नहरों के पुनर्निर्माण के लिए 23 करोड रुपये का प्रावधान रखा हुआ है तथा बाकी 368 करोड रुपये की मांग हमने की हुई है। जैसे–जैसे हमें पैसा मिलता रहेगा हम उसी हिसाब से इस पर पैसा लगाते रहेंगे। मैंने कल भी एक लम्बी लिस्ट पढ़ी थी कि कैसे हम नहरों का पुनर्वास कर रहे हैं उसी प्रकार इसका भी एक हिस्सा हमारे अन्तर्गत आता है तथा हम नहरों का पुनर्वास कर रहे हैं । इसका दूसरा हिस्सा (सी.ए.डी.ए.) काडा में है और काडा में जहां हम खालों की मरम्मत कर रहे हैं उसके साथ–साथ सरकार ने एक नया प्रोजैक्ट भी शुरू किया है 'हर खेत को पानी ।' हर खेत को पानी' के बारे में माननीय सदस्य ने भी चर्चा की है । उस संबंध में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने इसके लिए 14 पॉयलट प्रोजैक्ट शुरू किये हैं । कल श्री जसविन्द्र सिंह संधू जी ने भी बताया था कि इनके इलाके में भी एक अच्छा पॉयलट प्रोजैक्ट बना है । हम जो ये ऐसे पॉयलट प्रोजैक्ट्स बना रहे हैं वह अब जो इस बजट सत्र में बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें इस वितीय वर्ष में 140 पॉयलट प्रोजैक्ट्स बनाए जाएंगे । हम हर ब्लॉक में एक ऐसा पॉयलट प्रोजैक्ट लगाने जा रहे हैं ताकि इसके माध्यम से अधिक से अधिक खेतों तक माईक्रो ईरीगेशन सिस्टम से पानी पहुंचाया जा सके । इसमें जो तीसरा काम है वह हम हॉर्टीकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए करते हैं । इसमें हमारे पास किसानों को सब्सिडी देने के लिए लगभग 60 करोड रूपये है । जिसमें हम 36 ब्लॉक में 85 प्रतिशत सब्सिडी दे रहे हैं । इसमें एस.सी. कैटेगरी के किसान को भी हम 85 प्रतिशत ही सब्सिडी दे रहे हैं और मार्जिनल किसानों को 70 प्रतिशत और बाकी के किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी दे रहे हैं । इसमें हम लगभग 27 हजार किसानों को लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। हमारे पास उन किसानों की एप्लीकेशंज आई हुई हैं । जिस वाटर शैड मैनेजमैंट की चर्चा माननीय सदस्या ने की कि इनके क्षेत्र में ऐसे छोटे–छोटे तालाब हैं । उस पर भी इसी प्रोजैक्ट के माध्यम से काम होता है । जो जिले वाटर शैड मैनेजमैंट के हैं उनमें इनका जिला पंचकूला भी है । मैं बताना

चाहता हूं कि आज हरियाणा भवन में पानी के 434 स्ट्रक्चर हैं जिन पर यह वाटर शैड मैनेजमैंट काम कर रहा है जिसके लिए 9 करोड 61 लाख रूपये खर्च किये गये हैं । बाकी भी जो पुराने पानी के स्ट्रक्चर थे उनकी मुरम्मत पर भी 21 करोड 22 लाख रूपये खर्च किये गये हैं । इन सभी में प्रधान मंत्री सिंचाई योजना के तहत काम होता है । जैसे माननीय विधायिका का पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार का काम वाटर शैड मैनेजमैंट का होता है । जिसके माध्यम से पानी के छोटे–छोटे स्ट्रक्चर बनाकर पानी को रोका जा सकता है । इनका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इसलिए जैसे भी इनके क्षेत्र की योजना आएंगी तो वहां पर हम इसमें काम करेंगे ।

.....

राजकीय महिला महाविद्यालय रेवाड़ी के प्रोफैसर्ज एवं विद्यार्थियों का अभिनंदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज रिवाड़ी राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राएं और उनके साथ प्रोफेसर्ज दर्शक दीर्घा में सदन की कार्यवाही को देखने के लिए आए हैं । हम उनका स्वागत करते हैं ।

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्रीमती बिमला चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं । आपके माध्यम से मेरा कृषि मंत्री जी से सवाल है कि जिन किसानों के पास दो या तीन एकड़ जमीन है और उनके पास टयूबवेल नहीं हैं । वे दूसरे किसान के टयूबवैल से पानी लेते हैं । जिससे उनका पानी पर बहुत पैसा खर्च होता है । उनके खेत में इतने रूपये की तो फसल भी नहीं होती है जितने रूपये का पानी वे दूसरे किसान से खरीदते हैं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि उन किसानों के लिए भी पानी का कोई प्रावधान किया जाए जिससे उन दो–तीन एकड़ के किसानों को भी पानी मिल सके । इसके साथ ही मैं मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि पटौदी की एक नहर में 18 साल के बाद अब पानी आया है । इसके साथ ही मैं मंत्री जी को एक बात बताना चाहती हूं कि नहर के पानी को पटौदी से पहले ही रोक लिया जाता है । वहां के किसान उस पानी को पटौदी की तरफ नहीं आने देते हैं । उसकी

तरफ भी ध्यान दिया जाए । उस पर या तो कोई पुलिस का प्रबंन्ध किया जाए या कोई ऐसी चैकिंग की जाए जिसमें यह चैक किया जाए कि आगे पटौदी तक पानी क्यों नहीं जा रहा है । अगर उस पर कार्रवाई हो जाए तो पटौदी हल्के के किसानों को भी बराबर का पानी मिल जाएगा ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने बहुत ही मार्मिक बात कही है । यह सही है कि हमारी लगभग आधी सिंचाई नहरी पानी से की जाती है और किसान को उस पानी की बहुत कम कीमत 70 रूपये आबियाना के रूप में देनी पड़ती है। इसमें दूसरा बड़ा स्ट्रैक्चर टयूबवैल्ज का है और उसमें भी बिजली के टयूबवैल्ज का है जिस पर सरकार पूरे प्रदेश में 7700 करोड रूपये की एक बहुत भारी भरकम सब्सिडी देती है । जिस कारण से बिजली के टयूबवैल वाले किसानों को भी पानी उतना महंगा नहीं पड़ता है । तीसरी श्रेणी डीजल के टयूबवैल से पानी देने वाले किसानों की है जिनको सिंचाई महंगी पड़ती है । उससे अगली जो कैटेगरी है जिसका मुद्दा माननीय सदस्या ने उठाया है कि जो किसान पड़ोसी के टयूबवैल से पानी लेते हैं उनको डीजल भी देना पड़ता है और पानी के पैसे भी देने पड़ते हैं जिससे उनकी फसल बहुत महंगी हो जाती है । इसलिए ऐसे सभी किसानों की चिन्ता करते हुए जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी माईक्रो ईरीगेशन की स्कीमें चलाई गई हैं जिनको हम सब्सिडी दे रहे हैं । दूसरा उसमें हम एक काम और कर रहे हैं । मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए 14 पायलेट प्रोजेक्ट्स इस साल में शुरू किए गए हैं और अगले साल 140 पॉयलेट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे और इसके साथ ही हमारा नहरी विभाग अर्थात काडा, ऐसी योजना बनाने जा रहा है कि जिससे कई गांव के किसान मिलकर पहले 200, 300 या फिर 400 एकड़ जमीन की जोत को इकट्ठा करेंगे और तब इस जमीन पर हर खेत को पानी पहुंचाने वाला प्रोजेक्ट लगाया जायेगा। जो यह प्रोजेक्ट लगेगा, इस प्रोजेक्ट पर कुछ पैसा किसान का लगेगा और कुछ पैसा सरकार की तरफ से सहायता के रूप में दिया जायेगा। हमारी सरकार इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर निरंतर आगे बढ़ती जा रही है और हमारा विभाग भी इस तरह के कार्यों में पूरी गम्भीरता के साथ काम कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम इस योजना को अमलीजामा पहना देंगे और कम कीमत पर हरियाणा प्रदेश के हर खेत को पानी पहुंचाने के लक्ष्य के सपने को साकार करने का काम करेंगे। जहां तक नहरों की एफिशिएंसी का विषय है, इस

विषय का आज के सवाल से कोई संबंध नहीं है लेकिन मैं सदन के समक्ष इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा विभाग हरियाणा प्रदेश की नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने के कार्य में पूरी गम्भीरता के साथ लगा हुआ है और इसके साथ ही मुझे उम्मीद थी कि बिमला जी ने जो आज सदन में प्रश्न लगाया है, वह इस प्रश्न के साथ इनके क्षेत्र में स्थित उंचा मांजरा गांव में जो अभी हमने क्रॉप कलस्टर का उद्घाटन किया है, उसके लिए भी धन्यवाद करती लेकिन शायद बिमला जी प्रश्न करते हुए इस विषय को भूल गई है, पर कोई बात नहीं, मैं बिमला जी को आश्वस्त करता हूँ कि हमारी सरकार हर खेत को पानी पहुंचाने की दिशा में पूरी तरह से गम्भीर है।

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि वैसे तो मेरे क्षेत्र टोहाना को नहरों की नगरी कहा जाता है लेकिन बावजूद इसके पिछले काफी सालों से यह एरिया डार्क जोन में आ गया है। यहां के किसानों को ट्यूबवैल लगाने की अनुमति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पृथला माइनर, चंदर माइनर व दूसरी कई माइनर्ज की रिमॉडलिंग का काम शुरू किया गया है जिसके कारण किसान के खेत में अच्छी तरह से पानी लगना शुरू हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, हमारे टोहाना से जो भाखड़ा मेन नहर निकलती है, वह काफी जर्जर हालत में है। इस नहर का कुछ पानी पंजाब में जाता है बाकि पानी फतेहाबाद से लेकर सिरसा तक जाता है। यदि भाखड़ा नहर और समैन माइनर को दूसरी नहरों की तरह पक्का करवा दिया जाये तो इन एरियॉज में सिंचाई का पानी अंतिम छोर तक पहुंच जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या इस तरह की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है और साथ ही मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि जैसेकि माना जाता है कि हमारा टोहाना क्षेत्र नहरों का क्षेत्र है इसलिए यहां पर पानी बहुत ज्यादा है और सिंचाई के लिए पानी की कोई किल्लत नहीं है लेकिन असलियत में यहां पर भी कहीं न कहीं पानी की किल्लत है, अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू करने की भी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने कहा है कि इनका क्षेत्र टोहाना डॉर्क जोन में है, बिल्कुल सही है और निःसंदेह जो 36 डार्क जोन के ब्लॉक हैं, उनमें टोहाना भी शामिल है और इनमें 85 प्रतिशत माइक्रो इरीगेशन के

माध्यम से खेती करने की शुरूआत की गई है। यही नहीं वाटर शैड मैनेजमैंट वालों ने भी इन ब्लॉक्स में से 22 ब्लॉक्स अलग से छांटे है, उनकी भी पूरी कोशिश है कि कैसे इन ब्लॉक्स में ज्यादा से ज्यादा पानी देने का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाये और जहां तक समैन डिस्ट्रीब्यूटरी की रिहेबिलिटेशन की बात है तो यह कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में शामिल है और निश्चित रूप से इस काम को हर हाल में किया जायेगा लेकिन जैसाकि माननीय सदस्य के सवाल का दायरा बढ़ा है तो उस परिपेक्ष्य में मैं बताना चाहूंगा कि सरकार डॉर्क जोन की दोनों सूचियों पर अधिक से अधिक खर्च कर रही है और आगे भी करेंगी और सबसिडी देकर समुचित सिंचाई के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी तथा भाखड़ा नहर के पुनर्निर्माण का कार्य भी हमारी योजना में शामिल है।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दो महत्वपूर्ण विषयों की ओर दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मेरे क्षेत्र के साथ की जा रही अन्यायपूर्ण विसंगति की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। सदन में बार बार माइक्रो इरीगेशन व दूसरी चीजों के संदर्भ में सबसिडी दिए जाने बारे जिक्र किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के 8–10 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनको बैकवर्ड मानते हुए वहां पर माइक्रो इरीगेशन तथा पोली हाउसिज वगैरह पर 85 प्रतिशत सबसिडी दी जाती है लेकिन दूसरी तरफ जिला नूंह जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के कुल 115 जिलों की बैकवर्ड लिस्ट में शामिल किया है, बावजूद इसके यहां पर माइक्रो इरीगेशन व पोली हाउसिज वगैरह पर 65 परसेंट सबसिडी दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस विसंगती को दूर करने का सदन में आश्वासन देंगे ताकि और क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र में भी 85 परसेंट सबसिडी दी जा सके। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत ही अच्छी योजना है लेकिन यह योजना जिला नूंह, फरीदाबाद, पलवल या सोहना में केवल इसलिए लागू नहीं हो सकती क्योंकि यहां की नहरों में इंडस्ट्रियल वेस्ट्स का पानी आता है, जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है और इस पानी से माइक्रो इरीगेशन पद्धति संभव नहीं हो सकती, तो क्या माननीय मंत्री जी सदन में यह बतायेंगे कि हमारे क्षेत्र की नहरों में कब तक साफ पानी आयेगा ताकी यहां पर माइक्रो इरीगेशन पद्धति का प्रयोग करते हुए खेती की जा सके। हमारा एरिया दिल्ली के बहुत ही नजदीक है। दिल्ली की मार्किट में फलों व सब्जियों की बहुत मांग है लेकिन साफ पानी न सुलभ होने की वजह से हम

माइक्रो इरीगेशन पद्धति का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और इस प्रकार हमारे क्षेत्र के किसान दिल्ली की मार्किट में फलों व सब्जियों के माध्यम से जो मुनाफा कमा सकते है, उससे हमारे किसान काफी दूर हैं। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल वेस्ट की जगह साफ पानी कब तक मुहैया हो जायेगा?

प्रो. रविन्द्र बलियाला : आदरणीय अध्यक्ष जी, जब बाढ़ आती है तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र रतिया के साथ–साथ रानियां और डबवाली के इलाके में काफी पानी भर जाता है । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उसके निदान के लिए एक नया चैनल बनाया जाए और प्रोपर युटीलाइजेशन किया जाए । (विघ्न)

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं भी सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूँ। . ..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बलवान सिंह जी, इस तरह से अगर एक ही क्वैश्चन पर कई सप्लीमैंट्रीज पूछी जाएंगी तो बाकी क्वैश्चन पूछने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा । अतः आप बैठ जाइये । (विघ्न)

श्री परमेन्द्र सिंह ढ़ुल : आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकार की 'प्रधानमंत्री सिंचाई योजना' एक बहुत ही अच्छी योजना है । मैंने अपने इलाके के लोगों को इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए कहा है । माननीय मंत्री जी मेरे क्षेत्र के गांव बहबलपुर में इसकी शुरूआत करके आये हैं । इस योजना के कार्यान्वयन में एक पेंच फंस गया है और वहां पर अब रामकली माइनर की टेल पर पानी नहीं जा रहा है । एम.आई.टी.सी. ने काफी समय पहले वहां पर पक्के खाल बनाए थे । अब उन पक्के खालों की 'काडा' द्वार रिमोल्डिंग करना बहुत जरूरी हो गया है । वर्ष 2000 से पहले इन पक्के खालों को नाबार्ड की सहायता से बनवाया जाता था । इन खालों पर होने वाले कुल खर्च का जो 10 प्रतिशत शेयर किसानों को देना होता था वह शेयर एच.आर.डी.एफ. से दिलवाया जाता था । मेरे विचार से आपने वर्ष 2017 से ऐसा नियम बनाया है कि इन खालों पर आने वाले खर्च का 10 परसैंट हिस्सा किसानों से लिया जाएगा । यह निर्णय गलत है । इससे पहले से ही कमजोर किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा । अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इन खालों के निर्माण के लिए होने वाले खर्च का किसानों से जो 10

प्रतिशत शेयर निर्धारित किया था उसको एच.आर.डी.एफ. से लिया जाए । इसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इन खालों को पक्के करने के लिए हम किसानों से पैसे नहीं लेंगे ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मंत्री जी ने किसान हित की बहुत अच्छी घोषणा की है । मैं माननीय मंत्री महोदय का इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । उनके इस निर्णय के लिए पूरे प्रदेश के किसान उनका धन्यवाद करेंगे ।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : आदरणीय अध्यक्ष जी, सिंचाई विभाग के नॉर्म के अनुसार एक एकड़ पर 24 फुट पक्का खाला बनता है । एक मोघे पर लगभग 700–1000 एकड़ जमीन होती है और उस मोघे की 1000 एकड़ जमीन पर 24 हजार फुट लम्बाई का पक्का खाला बनता है । पिछले दिनों माननीय मंत्री जी ने जब मेरे क्षेत्र का दौरा किया तो उन्होंने अपने अधिकारियों को इन मोघों की प्रति एकड़ लम्बाई 24 फुट की बजाय 40 फुट करने का आदेश दिया था । इस पर वहां पर मौजूद अधिकारियों ने कहा था कि हमें इसके लिए सैंटर गवर्नमैंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी । अतः मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि वे इनके नॉर्म्स को बदलकर मोघों की लम्बाई 24 हजार फुट से बढ़ाकर 40 हजार फुट कब तक कर देंगे ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य जाकिर हुसैन के सवाल का जवाब देना चाहूंगा । इनके मन में अपने क्षेत्र के लिए एक सपना है । इनके उस सपने का जिक्र इनके हर सवाल के साथ आता है । इनका सपना है इनके क्षेत्र में आगरा कैनाल के काले पानी की बजाय नीला पानी चले । मेरा कहना है कि आज के दिन माइक्रो इरिगेशन की तरह पानी को स्वच्छ करने की बहुत–सी अच्छी टैक्नोलॉजी आ चुकी हैं । हम आगरा कैनाल के पानी को स्वच्छ करके माइक्रो इरीगेशन के प्रोजैक्ट पर भी आगे बढ़ेंगे । इसके अतिरिक्त कल माननीय सदस्य ने वाटर लॉगिंग का भी सवाल लगाया था । मैं इनको बताना चाहता हूं कि इसके समाधान के लिए मैं अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दूंगा । (विघ्न) माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न के जवाब में मैं इनको बताना चाहता हूं कि पॉली हाउस वगैरह लगाने के लिए किसानों को जो 85 परसैंट डिस्काउंट

दिया जाता है उसके लिए हमने लगभग 36 ब्लॉक्स की एक लिस्ट तैयार की है । अगर उस लिस्ट में इनके क्षेत्र के कुछ ब्लॉक्स का नाम भी एड हो जाता है तो उनको इन चीजों के लिए 85 परसैंट डिस्काउंट तो अपने आप ही मिल जाएगा । मैं इसका अपने विभाग को निर्देश दे दूंगा कि वे इन ब्लॉक्स की जांच करें और इस लिस्ट के 36 नामों को 37–38 तक ले जाएं । (विघ्न) सूचि में अंकित इन 36 ब्लॉक्स में हम किसानों को 85 परसैंट डिस्काउंट दे रहे हैं । हम अनुसूचित जाति के ब्लॉक्स को 85 प्रतिशत छूट, जनरल ब्लॉक्स को 70 प्रतिशत छूट और बाकी को 60 प्रतिशत छूट दे रहे हैं । मेरा कहना है कि मैं अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दूंगा कि वे जांच करें कि मेवात के कौन–से ब्लॉक्स इस सूची में एड हो सकते हैं ताकि उनको 85 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त हो सके । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने विधान सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 2279 जोकि मंत्रियों की जायदाद से संबंधित था और 7 मार्च, 2018 को लिस्टेड था लेकिन सरकार मुझे मेरे प्रश्न का जवाब देने से घबरा रही है । मुझे कोई इंफर्मेशन नहीं दी जा रही है । (विघ्न)

.....

मंत्रियों द्वारा सम्पत्तियों की घोषणा से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 2279 का उत्तर न मिलने के संबंध में मामला उठाना

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, आपके प्रश्न का जवाब आपके घर भेज दिया गया है । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब सदन में चाहिए । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को इनके प्रश्न का जवाब एक उदाहरण के माध्यम से देना चाहूंगा । एक व्यक्ति के घर में एक चोर घुस गया । उस व्यक्ति के पास कुछ खास संपत्ति नहीं थी । चोर घर के सामान और उस व्यक्ति को ढूंढता रहा । वह अपनी इज्जत बचाने के लिए चोर से बचकर इधर–उधर घूमता रहा । अतः मेरा कहना है कि हमारे पास कोई सम्पत्ति नहीं है । हम तो इनसे छिपते हुए घूम रहे हैं । (हंसी)

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

PradhanMantriFasalBimaYojna Scheme

***2616. Shri Ghanshyam Dass Arora :**Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state:-

(a) the number of farmers who are getting the benefits of PradhanMantriFasalBimaYojnatogetherwith the number of farmers, who have got the insurance through banks and the number of farmers who have got the insurance themselves; and

(b) thesteps taken by the Government to provide the benefits of the said Yojna to the Maximum number of farmers?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी,

(क) कुल 19,77,655 किसानों को वर्ष 2016–17 (खरीफ, रबी) तथा खरीफ 2017 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है। 19,73,477 किसानों ने बैंकों के माध्यम से बीमा करवाया है तथा 4178 किसानों ने स्वयं बीमा करवाया है।

(ख) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा हरियाणा किसान आयोग नें योजना मे अधिकांश किसानों को शामिल करने के लिए इलैक्ट्रोनिक्स मीड़िया, समाचार पत्रों, कैम्पों तथा अन्य साधानों के माध्यम से प्रभावशाली अभियान शुरु किया है।

श्री घनश्याम दास : आदरणीय अध्यक्ष जी, जब किसान कोई लोन लेता है तो बैंक उसकी जमीन की जमाबंदी और गिरदावरी अपने पास जमा कर लेता है । बैंक इसी को आधार मानकर किसान की अगले सालों की बीमा राशि काट लेता है जबकि इस दौरान किसान वास्तविक रूप में कोई अन्य फसल ले रहा होता है । कई बार किसान ऐसी फसल उगा लेता है जो योजना के तहत बीमित फसल में कवर नहीं होती है । अतः मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस विसंगति को दूर करने के लिए बैंक या राजस्व विभाग को निर्देश देंगे ? मेरे विचार से बैंकों को किसान द्वारा वास्तविक रूप में बोई गई फसल के अनुसार ही प्रीमियम काटा जाना चाहिए । अगर किसान ने ऐसी फसल बो ली जो

बीमित फसल में कवर नहीं होती है तो उसका प्रीमियम भी नहीं काटा जाना चाहिए ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को दो आंकड़े बताना चाहता हूं । वर्ष 2016 में कुल 7,38,795 किसानों की खरीफ की फसल का बीमा किया गया था । अगले वर्ष 2017 में कुल 6,41,562 किसानों की खरीफ की फसल का बीमा किया गया । अतः अगले साल में यह संख्या लगभग 1 लाख घट गई । माननीय सदस्य के सवाल का जवाब इन्हीं आंकड़ों में छिपा हुआ है । प्रदेश के जिस भी किसान ने बैंक में जाकर यह जानकारी दी कि मैंने बीमित फसल में कवर होने वाली फसल नहीं बोई है तो उस किसान का प्रीमियम नहीं काटा गया है । अतः किसानों को फसल बोने से पहले एक बार बैंक में जाकर अपनी फसल की जानकारी दे देनी चाहिए । बीमा का प्रीमियम किसान की फसल के बेस पर ही कटता है । अतः स्पष्ट है कि जिन किसानों ने बीमित फसल नहीं बोई है और उसकी जानकारी बैंक को दे दी है उनका प्रीमियम नहीं काटा जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में 33 लाख लोगों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है अगर बिना बीमा करवाये किसानों के खाते से पैसे काटते तो सभी किसानों के खातों से पैसे कट गये होते। इसलिए अगर कोई किसान फसल का बीमा करवाता है तो संबंधित किसान के खाते से ही बीमा की राशि काटी जाती है। हमारे प्रदेश में 33 लाख किसान क्रेडिट धारक हैं परन्तु सभी किसान हर साल बीमा नहीं करवाते हैं बल्कि सभी किसानों में से कुछ किसान बाकी रह जाते हैं जो अपनी फसल का बीमा नहीं करवा पाते हैं। केवल उन्हीं किसानों का फसल बीमा किया जा रहा है जो किसान अपनी फसल की ठीक जानकारी देते हैं। किसानों में फसल बीमा करवाने के लिए जागरूकता बढ़ रही है। फसल बीमा योजना शुरू करने के पहले साल के क्रॉप सीजन की तुलना में अगले वर्ष 1 लाख ज्यादा किसानों ने क्रॉप सीजन में फसल बीमा करवाया है और इन किसानों ने फसल की ठीक जानकारी दी है।

श्री घनश्याम दासः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हित में है। इसलिए विभाग की तरफ से फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए जो भी विधि अपना सकते हैं वह विधि अपनायी जानी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक किया जा सके ताकि अधिक से अधिक किसान इस फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकें।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के बारे जो इन्फार्मेशन पटल पर रखी गयी है उसमें केवल 4178 फारमर्ज ने फसल का इन्शयोरेंस लिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके फसल इन्शयोरेंस के मामले लम्बित पड़े हैं और उन्होंने इन्शयोरेंस कम्पनीज के खिलाफ एफ.आई.आर. भी दर्ज करवा दी है। माननीय मंत्री जी के क्षेत्र के गांवों के किसानों ने भी बीमा कम्पनियों से इन्शयोरेंस करवाया था परन्तु उन लोगों को बीमा कंपनीज की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला है। सरकार किसानों को फसल बीमा की जानकारी दे यह बात ठीक है, लेकिन आज किसान बहुत ज्यादा विजिलैंट हैं और किसानों के पास सारी जानकारियां हैं। इसमें तो केवल यही बताया है कि किसानों की मर्जी के बिना फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खातों में से पैसे काटे गये हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने लिखकर दिया था कि उन्होंने फसलों की बीजाई भी नहीं की थी परन्तु फसल इन्शयोरेंस के नाम पर उनके खातों में से अनुचित तरीके से पैसे काटे गये हैं। मेरे हल्के के अकेहड़ी मदनपुर, मातनहेल तथा छुछकवास गांवों के किसानों ने कम्पनीज के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवायी है।

श्री जसबीर देशवालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे सफीदों हल्के के डिडवाड़ा गांव में 300 एकड़ गेहूं की फसल जल गयी थी और सरकार ने 12,000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए एनाउंस किया था परन्तु अभी तक संबंधित किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि संबंधित किसानों को जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलवाया जाए। (शोर एवं व्यावधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि दिनांक 29.11.2016 को अखबार में खबर छपी थी कि किसानों से 63 करोड रूपये फसल बीमा योजना के नाम पर डबल लिये गये हैं। किसानों से फसल बीमा योजना के तहत 2–3 बार पैसे काटे गये हैं और यह खबर अखबारों में छपी थी। यह 63 करोड रूपये के भ्रष्टाचार का मामला है और सरकार द्वारा इस मामले की इन्कवायरी करवाकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार द्वारा 13 जून को फसल बीमा योजना के बारे में नोटिफिकेशन

जारी किया गया था जिसमें कहा गया है कि फसल बीमा योजना में सिर्फ किसानों का ही हिस्सा है, स्टेट गवर्नमैंट का हिस्सा नहीं है। फसल बीमा योजना के तहत जिन कंपनीज ने किसानों से 63 करोड रूपये डबल लिये थे, क्या सरकार ने संबंधित कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की है ? (शोर एवं व्यावधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत करवाना चाहूंगा कि मैंने पिछले सैशन के दौरान सदन में पूछा था कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी को शामिल किया जाए और माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इस बात पर विचार किया गया जाएगा। पिछले सैशन से आज के सैशन तक 6 महीने का समय व्यतीत हो चुका है और विचार करने के लिए 6 महीने का समय बहुत है। इसलिए माननीय मंत्री जी आज सदन में बता दें कि बागवानी को फसल बीमा योजना में शामिल किया जाएगा या नहीं (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, लगभग 2 लाख 7 हजार 506 किसानों को फसल बीमा योजना से बैनिफिट मिल चुका है। इन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ था जिसके कारण कंपनियों ने 2 लाख 7 हजार 506 किसानों को कम्पंसेशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 2172 किसान ऐसे हैं जिनको फसल बीमा योजना के तहत 1 लाख रुपए से ज्यादा कम्पंसेशन मिला है। 50526 ऐसे किसान हैं जिनको 50 हजार से 1 लाख रुपए तक कम्पंसेशन मिला है और 154808 ऐसे किसान हैं जिनको 50 हजार रुपए से कम कम्पंसेशन मिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि कुल बीमा कराने वाले किसानों में से एक बड़ी संख्या ऐसी है, जिनको इसका बैनीफिट मिल गया है। अध्यक्ष महोदय, किसानों के पक्ष में जो कुछ अफवाएं फैलाई गई थीं, किसान उन अफवाओं पर विचार नहीं करता है चाहे वे अफवायें कितनी ही जोर से क्यों न फैलाई गई हों।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि फिर इन्होंने किसानों के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज क्यों करवाई है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हमने ही किसानों के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गीता जी, मंत्री जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने ही किसानों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने किसानों के ऊपर जो एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है, क्या इन्हें उन किसानों की हालत का अंदाजा है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः करण जी, मैंने मान लिया है कि मैंने ही उन किसानों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मंत्री जी चाहते तो वे बीमा कम्पनियां उन किसानों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कर सकती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि बीमा कम्पनियों से सरकार की सांठ–गांठ है और इस तरह से किसानों को लूटा जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि किसानों के मैज्योरिटी ऑफ केसिज निपट चुके हैं, लेकिन कुछ–कुछ स्थानों पर ऐसे कसिज की संख्या है, जिनके मामले अभी लंबित हैं। अध्यक्ष महोदय, वे लंबित मामले ऐसे हैं, जिनमें किसी का नाम लिखने में गड़बड़ हो गयी, कहीं ब्लॉक लिखने में गड़बड़ हो गयी और कहीं पर लिस्ट नहीं पहुंची। अध्यक्ष महोदय, उन लंबित मामलों को हमारे डी.डी.ए. और स्टेट लैवल के डिपार्टमेंट ने उनको अच्छे से निपटाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, जब हमें ऐसा लगा कि कई जगहों पर निर्देश देने के बावजूद लापरवाही हो रही है और वह कम्पनी इस साल बीमा पॉलिसी के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि कम्पनी हर साल बदलती रहती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने ही कहा कि इस मामले का जल्दी निपटारा हो। अध्यक्ष महोदय, मैं भी कृषि मंत्री, हरियाणा सरकार के नाते इस बीमा का ग्राहक हूं और उसकी बड़ी राशि मैं देता हूं, इसलिए मैंने कहा कि इन पर एफ.आई.आर. दर्ज की जाए और इन किसानों का भुगतान जल्दी किया जाए।। अध्यक्ष महोदय, बीमा कम्पनियों का किसान एक मात्र अकेला ग्राहक नहीं है, केन्द्र सरकार भी ग्राहक है और मैं भी

ग्राहक हूं। अगर उसका निपटारा समय पर नहीं होगा तो मुझे जितने तरीके अपनाने पड़ेंगे, मैं अपनाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बताना चाहूंगा कि ये केवल अपने इलाके के किसानों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवा सकते हैं, बाकी हरियाणा के किसानों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवा सकते हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि किसी भी तरह से भुगतान करवाना सरकार की जिम्मेवारी है और जहां का भी विवादित मामला है और हमें किसी भी सीमा तक जाना पड़े तो हम उस सीमा तक जाएंगे और सभी का भुगतान करवाएंगे। एक आदमी को भी नहीं छोड़ेंगे। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मलिक जी ने यहां पर दो सवाल उठाए हैं। जिनमें इन्होंने एक सवाल एक खबर के बारे में उठाया है जिस खबर का कोई आधार या अस्तित्व ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कई बार खबरें किसी डाटा से ऐसे ही छप जाया करती हैं और यह ऐसी खबर है जिसका कोई अर्थ नहीं है और सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, जिसमें इस प्रकार कोई ऐसा हादसा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात माननीय सदस्य मलिक जी को बताना चाहूंगा कि गेहूं और रबी की फसल के लिए किसानों को बीमा पॉलिसी की राशि का केवल डेढ़ प्रतिशत देना पड़ता है और खरीफ के किसान को केवल 2 परसैंट देना पड़ता है। खरीफ सीजन में कपास के किसान को 5 परसैंट देना था लेकिन सरकार के प्रयासों से उसने भी 2 परसैंट दिया क्योंकि कपास के किसान का 37 करोड रूपया हरियाणा सरकार भरती है जिससे उसको यह महसूस नहीं हो कि धान वाले किसान ने 2 परसैंट दिया और मैं कपास का किसान हूं इसलिए मेरे से 5 परसैंट लिया जा रहा है। इसलिए कपास के किसान के प्रीमियम के रूप में 37 करोड रूपये सरकार की तरफ से भुगतान किये जा रहे हैं इसलिए किसी भी किसान को उसकी फसल का जितना बीमा हुआ है उससे डेढ़ परसैंट से अधिक नहीं देना पड़ता । बाकी का जितना भी पैसा है उसका टैण्डर होता है। मान लें कि टैण्डर 10 परसैंट में हुआ उसका जो बाकी 8 परसैंट बचा वह 4 परसैंट हरियाणा सरकार और 4 परसैंट केन्द्र सरकार देती है। इस प्रकार से किसान को खरीफ की फसल में 2 परसैंट और रबी की फसल में डेढ़ परसैंट प्रीमियम देना होता है। इससे अधिक प्रीमियम किसान को कहीं पर नहीं देना पड़ता। (विघ्न)

सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : स्पीकर सर, जगबीर मलिक जी को अब किसानों की इतनी चिंता हो रही है जब किसानों की जमीनों को इनकी सरकार के द्वारा लूटा जा रहा था उस समय ये कहां पर थे? ये उस समय कुछ भी नहीं बोले और आज ये किसान के हितैषी होने का दिखावा कर रहे हैं। जब किसानों की जमीनों के सैक्शन–4 और सैक्शन–6 के नोटिस करके किसानों की जमीनों को लूटा जा रहा था उस समय इनको किसानों के हित में अपनी आवाज उठानी चाहिए थी लेकिन उस समय इन्होंने इसकी कोई जरूरत नहीं समझी। न तो इन्होंने उस समय किसानों के लिए नहरी पानी के लिए आवाज़ उठाई और न ही उनको मिलने वाले खाद, बीज व दवाई के सम्बन्ध में कोई प्रयास किया। इनकी पार्टी ने अपने 10 साल के शासन काल के दौरान किसानों की सारी जमीन लूट ली गई लेकिन उस दौरान ये चुप बैठे रहे और किसानों की लुटाई का तमाशा देखते रहे। (विघ्न) अब ये बार–बार हाउस की कार्यवाही को डिस्टर्ब कर रहे है। ये बार–बार अपना ही राग अलाप रहे हैं और हाउस में किसी और को कोई बात नहीं करने दे रहे हैं। जो ये सवाल पूछ रहे हैं उनके ऊपर मंत्री जी को जवाब भी नहीं देने दे रहे हैं। (विघ्न) उस समय इन्होंने तो यही कोशिश की कि किसानों की जमीनों को लूट लो तो फिर उसको न तो खाद की जरूरत रहेगी और न ही बीज व दवाईयों की जरूरत होगी। (विघ्न) इस बात को तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीयर कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : जगबीर सिंह जी, आपने अपना सवाल पूछ लिया है इसलिए अब आप उस पर मंत्री जी का जवाब सुनें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, जगबीर मलिक जी जिस समाचार–पत्र को पढ़ रहे हैं ये उसके साथ मुझ से मिल लें मैं इनकी सारी की सारी शंकाओं का समाधान कर दूंगा। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं जो भी यहां पर कह रहा हूं वह as a Minister इस सदन में कह रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी किसान से रबी की फसल पर डेढ़ परसैंट से ज्यादा प्रीमियम नहीं लिया जाता है और इसी प्रकार से किसी भी किसान से खरीफ की फसल पर दो परसैंट से ज्यादा प्रीमियम नहीं लिया जाता है। मैं सदन में एक मंत्री के नाते उत्तर दे रहा हूं। अगर श्री जगबीर सिंह मलिक के पास कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो उसके बारे में मुझ से मिलकर बता दें। (विघ्न) जितना भी किसान का एक एकड़ का टोटल कम्पनसेशन है उसका केवल 2 परसैंट ही

प्रीमियम के रूप में लिया जाता है। जो भी किसान की बीमित राशि है उस बीमित राशि के ऊपर केवल डेढ़ परसैंट रबी की फसल में देना होता है और इसके अतिरिक्त अगर इनके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है तो उसके बारे में ये मुझ से मिलकर बात कर लें मैं इनको उसका भी विस्तृत उत्तर दे दूंगा।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, फसल बीमा के मामले में अत्यधिक धांधली के चलते किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाना बंद कर दिया है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इनके पास जो भी अतिरिक्त जानकारी है ये उसके साथ मुझ से मिल लें मैं इनकी सारी की सारी गलतफहमियों को दूर कर दूंगा। इस समय मुझे इनकी बात समझ में नहीं आ रही है कि वास्तव में ये क्या कहना और क्या पूछना चाहते हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह जानकारी भी देना चाहूंगा कि हमारी सरकार किसान कल्याण प्राधिकरण का विधेयक इसी विधान सभा सत्र में ला रही है। जहां तक बागवानी फसलों के प्रीमियम की बात है वह 5 परसैंट है। मेरे विचार में यह 5 परसैंट प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। सरकार इस विषय पर विचार कर रही है कि क्या इसको जो किसान कल्याण प्राधिकरण हम बना रहे हैं। क्या अपने तरीके से कोई सुरक्षा करेगा जैसे भावान्तर भरपाई सुरक्षा योजना हमने बाजार में दी है हम बागवानी फसलों को भी मौसम में सुरक्षा दें इस योजना पर सरकार विचार कर रही है। हमारी सरकार जो किसान कल्याण प्राधिकरण बना रही है उसके अंर्तगत हमने इस मामले को विचार करने के लिए रखा हुआ है। इस मामले में हमारी सरकार पूरी तरह से चिंतित है और हम जल्दी ही इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : जगबीर सिंह मलिक जी, आपने जो सवाल पूछा था उसका कम्पलीट जवाब मंत्री जी ने दे दिया है इसलिए अब आप कृपया करके बैठ जायें।

———————

To Re-Start Bus Service

***2419. Smt. Naina Singh Chautala** : Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to re-start bus service from Dabwali to Haridwar and Chautala to Chandigarh via Bhatinda; if so, the time by which above said bus service is likely to be re-started ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) :(क) व (ख) श्रीमान् जी,

डबवाली से हरिद्वार के लिए बस सेवा शुरू की जा चुकी है। यह बस प्रतिदिन प्रातः 04:50 बजे डबवाली से चलकर सांय 04:15 बजे हरिद्वार पहुंचती है। यह बस हरिद्वार से प्रातः 06:00 बजे चलकर सांय 05:00 बजे डबवाली पहुंचती है।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मंत्री जी जिस बस को चलाने की बात कह रहे हैं यह तो इन्होंने इस वर्तमान विधान सभा सैशन के शुरू होने के बाद शुरू की है। एक बस पहले चौटाला से चण्डीगढ़ चलती थी वह परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किये गये सारे के सारे नॉर्म्ज पूरे करती है। इस बस के यात्री बहुत ज्यादा हैं इसलिए मैं मंत्री जी से पुनः कहना चाहूंगी कि इस बस को जल्दी से जल्दी चलाया जाये। मेरी एक मांग यह है कि पाना नीलियावाली, हस्सू, हबवाना और पन्नीवाला रूल्दू इन गांवों में 12वीं कक्षा तक स्कूल नहीं है। इन चारों गांवों में सरकार द्वारा 12वीं कक्षा तक का स्कूल नहीं खोला गया है इसलिए इन गांवों की सभी लड़कियां अपने खर्चे पर बस हॉयर करके मांगेयाना गांव के सरकारी स्कूल में जाती हैं। मैंने इस बारे में मंत्री जी को चार से पांच बार लिखित में रिकवैस्ट दी है लेकिन इसके बावजूद भी इस रूट पर सरकारी बस नहीं चलाई गई है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, हमने शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा हुआ है । अगर कहीं से कोई भी प्रस्ताव आयेगा तो हम वहां पर बस चलायेंगे। बहन जी भी इस बारे में लिखकर दे दें हम वहां पर सरकारी बस चला देंगे। (विघ्न) अगर बहन जी यह कह रही हैं कि उन्होंने इस बारे में कई बार लिखकर दिया हुआ है तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि हम हाउस की यह प्रोसीडिग लेकर इस रूट पर बस जल्दी ही चलवा देंगे। दूसरे सवाल का मैं यह जवाब देना चाहूंगा कि संगरिया–चौटाला से हर पंद्रह मिनट में बस सर्विस है। सुबह 04.30 पर डब्वाली से पी.आर.टी.सी. की बस चलती है। जहां तक इंटर स्टेट बस चलवाने का सम्बन्ध है उस बारे में मेरा यही कहना है कि इंटर स्टेट बस चलाने के लिए हमारी दूसरी स्टेटस के साथ बराबर मीटिंग होती है। इस मामले में जो एम.ओ.यू. उत्तर प्रदेश के साथ हुआ है उसके तहत एक दिन में 66 हजार किलोमीटर हरियाणा प्रदेश की बस उत्तर प्रदेश में चलेगी और 50 हजार कलोमीटर उत्तर प्रदेश की बस हरियाणा प्रदेश में चलेगी। इसी प्रकार से जब पंजाब गवर्नमैंट के साथ मीटिंग होगी तो उस समय इस मामले पर भी विचार कर लिया

जायेगा। मैंने इस सम्बन्ध में हाउस के पटल पर पहले ही एशोरैंस दे रखा है। अभी तक पंजाब गवर्नमैंट के साथ हमारी सरकार की एम.ओ.यू. के लिए कोई मीटिंग नहीं हो पाई है। एक–दूसरी स्टेट में बस चलाने के लिए दोनों सम्बंधित स्टेटस के बीच एम.ओ.यू. होता है जिसके तहत परमिट लेने पड़ते हैं। अभी हमारी सरकार का पंजाब गवर्नमैंट के साथ कोई ऐसा टाई–अप नहीं हुआ है।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं इस बारे में पिछले साढ़े तीन साल से लगातार रिकवैस्ट कर रही हूं। मंत्री जी कृपया करके यह बतायें कि क्या इन साढ़े तीन सालों में अभी तक इस प्रकार की कोई मीटिंग मंत्री जी ने नहीं की है?

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, उत्तर प्रदेश के साथ वर्ष 2008 में एम.ओ.यू. साईन हुआ था उसके बाद एम.ओ.यू. हमारी सरकार आने के बाद साईन हुआ। इससे पहले वाली सरकारों ने उस एम.ओ.यू. को हाथ तक नहीं लगाया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करके यह एम.ओ.यू. जारी करवाया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, परिवहन मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं उसमें वे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी की माननीय सदस्या का जो सवाल है वह सवाल यह है कि चौटाला से चण्डीगढ़ जो बस चलती थी वह कब चलवाई जायेगी। इसके लिए पिछले साढ़े तीन साल से लगातार मंत्री जी को चिट्ठी लिखी जा रही है और लगातार इसके लिए रिकवैस्ट कर रहे हैं। मंत्री जी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि इसके लिए हमें पहले मीटिंग करनी पड़ेगी। मंत्री जी यह बतायें कि पिछले साढ़े तीन साल से क्या कर रहे थे? क्या मंत्री जी द्वारा उस चिट्ठी को कभी पढ़ा नहीं गया? सवाल चौटाला से चण्डीगढ़ बस चलाने के बारे में पूछा जा रहा है लेकिन मंत्री जी इसके जवाब में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। इसके साथ ये इसके लिए पिछली सरकार को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर मंत्री जी ने यू.पी. के साथ कोई एम.ओ.यू. साईन किया है और उसके तहत कोई बसें सरकार द्वारा चलाई जायेगी तो उससे लोगों को सहूलियत मिलेगी यह बहुत ही अच्छी बात है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इनके पास हमारी पार्टी की माननीय सदस्या द्वारा इस बाबत लिखी गई चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं था। क्या मंत्री जी उन चिट्ठियों का जवाब माननीय सदस्या को नहीं दे सकते थे? ये इन साढ़े तीन सालों के दौरान क्या कर रहे थे? जो इनसे सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल का ये जवाब नहीं दे रहे हैं।

मंत्री जी सवाल का सही उत्तर देने के बजाये बातों को इधर–उधर घुमाते रहते हैं और सदन का समय अनावश्यक रूप से बर्बाद करते हैं।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मंत्री जी ने जवाब तो चौटाला से चण्डीगढ़ बस चलवाने बारे ही दिया है। इन्होंने यू.पी. का जिक्र तो उदाहरणस्वरूप ही किया गया है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, इस सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं। मैं पुनः यह बताना चाहूंगा कि जो बस चौटाला से चलकर चण्डीगढ़ जायेगी वह पंजाब से होकर आयेगी। मैं यही कह रहा हूं कि इसके लिए हमें पंजाब गवर्नमैंट के साथ मीटिंग करनी होगी क्योंकि इसके लिए हमें पंजाब सरकार से परमिट लेना होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

————————

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Number of Schools Approved

***2573 Shri Balwant Singh :** Will the Education Minister be pleased to state:-

(a) the number of Government Middle Schools, Government High Schools and Government Senior Secondary Schools approved during the period from the year 2014 to 28.02.2018; and

(b) the number of Government Middle Schools, Government High Schools and Government Senior Secondary Schools approved during the period from the year 2004 to 2014?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) :श्रीमान,जी।

(क) वर्श 2014 से 28.02.2018 तक 63 राजकीय विद्यालय माध्यमिक स्तर तक, 383 राजकीय विद्यालय वरिश्ठ माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नति तथा 2 नए संस्कृति माध्यमिक विद्यालयों को अनुमोदित किया गया है।

(ख) 1427 राजकीय विद्यालयों को माध्यमिक स्तर तक, 375 राजकीय विद्यालयों को उच्च स्तर तक तथा 743 राजकीय विद्यालयों को स्तरोन्नति अनुमोदित

किया गया व कोई भी नया राजकीय वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय अनुमोदित नही किया गया।

.....

Repair of Water Works

***2557 Shri Makhan Lal Singla**: Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state :-

(a) whether it is a fact that the water works constructed in village Gadli is in very bad condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the above said water works togetherwith the details thereof?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डा0 बनवारी लाल) : (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न के इस भाग का सवाल ही नहीं उठता।

.....

Compensation to the Farmers

***2424. Shri Lalit Nagar** : Will the Chief Minister be pleased to state:

(a) Whether it is fact that the land of 19 Villages of Tigaon Assembly Constituency was acquired for Greater Faridabad but the amount of enhanced Compensation has not been paid to the farmers so far? and

(b) if so, the time by which the Enhanced amount of Compensation is likely to be paid together with the detail thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी,

(ए) तिगांव विधान सभा क्षेत्र के 19 गांवों की 1647.20 एकड भूमि अर्जित की गई तथा असल अवार्ड की अदायगी भूमि मालिकों को की जा चूकी है। रेफरन्स

कोर्ट मे अतिरिक्त जिला न्यायधीश द्वारा बढाये गये मुआवजे की कुल 882.63 करोड रूपये की राशि मे से 209.78 करोड रूपये की राशि भूमि मालिकों को अदा की जा चूकी है। रेफरन्स कोर्ट के आदेशों के विरूद्ध भूमि मालिकों तथा राज्य सरकार द्वारा फाईल की गई अपीलें माननीय उच्च न्यायालय में अन्तिम निर्णय के लिए अभी तक लम्बित है।

(बी) बढे हुए मुआवजे की बकाया राशि की अदायगी माननीय उच्च न्यायालय में इन केसों के अन्तिम निर्णय के बाद की जायेगी।

.....

To Upgrade Government Girls School

***2603 Shri Ravinder Baliala** : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the school of village Chimmo up to High School; if so, the time by which it is likely to be upgraded?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान जी।

.....

To Recognize The Degrees/Diplomas

***2301 Shri Balkaur Singh** : Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that the degrees/diplomas issued by Punjabi University Patiala are not recognized by the state Government for unemployment allowance and the benefits of “Saksham Yojna”; if so, whether there is any proposal to recognize the degree/diplomas of Punjabi University for unemployment allowance and “Saksham Yojna”?

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : श्रीमान, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला से प्राप्त डिप्लोमा/डिग्री धारक प्रार्थी ‘शिक्षित युवा भत्ता एवं मानदेय योजना–2016’ (सक्षम युवा योजना नाम से लोकप्रिय) के तहत बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र है किन्तु मानदेय के लाभ के लिए नहीं। वर्तमान में योजना के अन्तर्गत इन्हें मानदेय प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है।

To Open A 50 Beds Government Hospital

***2345 Shri Balwan Singh Daulatpuria** : Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a 50 beds Government hospital in village Gorakhpur of Fatehabad Constituency; if so, the time by which it is likely to be opened togetherwith the details thereof?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान् जी।

.....

To Supply Canal Water for Irrigation

***2373. Shri Ved Narang** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to supply canal water for irrigation for two weeks to the farmers of Barwala Assembly Constituency; if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं, श्रीमान् जी । इसलिए प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल ही नहीं उठता ।

.....

To open I.T.I.

*** 2387. Shri Jagbir Singh Malik** : Will the Skill Development and Industrial Training Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open I.T.I. at village Mohana and Bhatgaon of Gohana constituency ; if so, the details thereof ?

औद्योगिक एवं वाणिज्य मंत्री (श्री विपुल गोयल) : नहीं, श्रीमान जी ।

.....

Survey of B.P.L

***2513.Shri Anoop Dhanak :** Will the Rural Development Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the most of the population in village Kharkara and Gaibipur in Uklana Constituency is below the poverty line; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to identify B.P.L. families in the above said villages by conducting B.P.L. survey and to issue B.P.L. cards?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान् जी,

(क) नही श्रीमान जी, क्योंकि गांव खरकड़ा में कुल 827 परिवारों में से 409 और गांव गैबीपुर में 1127 परिवारों में से 641 बी.पी.एल हैं।

(ख) नही, श्रीमान् जी।

.....

To Control Private Pathology Labs

***2411. Shri Jasbir Singh** : Will the Health Minister be pleased to state: -

(a) whether it is a fact that Private Pathology Labs are facing the patients for conducting the test of Dengue, Chikungunya and other diseases; if so, the steps taken by the Government to regulate the functioning of above said labs; and

(b) the steps taken by the Government to constitute medical boards in each district to monitor the medical facilities in the State?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) दिनांक 21/09/2015 से सभी निजी हस्पतालों/प्रयोगशालाओं को डेंगू तथा चिकनगुनिया जो कि ऐलाईजा आधारित आई0जी0एम0 एंव एन0एस01 के प्रत्येक निर्धारित जांच के लिए 600/– रूपये

निश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी उल्लंघन के मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

(ख) चिकित्सा संस्थाओं व डाक्टरों के विरूद्व चिकित्सा लापरवाही के मामलों की जांच हेतु लापरवाही के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड है।

.....

Categories-wise backlog of the Employees

***2431. Shri Uday Bhan** : Will the Minister of State for Welfare of SC/BC be pleased to state:

(a) categories-wise backlog of the employees belonging to scheduled castes in the Government departments/Semi-Government departments/Boards/Corporations and local bodies; and

(b) the steps taken by the Government to fill up the above vacant posts?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कु मार बेदी) : श्रीमान जी,

बैकलॉग की स्थिति पूर्ण विवरण सहित विधान सभा के पटल पर रखी है।

विवरण

अनुसूचित जाति से सम्बन्धित कर्मचारियों का विभिन्न सरकारी विभागों, अर्ध–सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्थानीय निकाय में श्रेणीवार बैकलॉग दिनांक 31.03.2016 तक का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

श्रेणीवार बैकलॉग 31.03.2016 तक

	ग्रुप–ए0	ग्रुप–बी0	ग्रुप–सी0	ग्रुप–डी0
विभाग 75 जिसमें आयुक्त/उपायुक्त भी शामिल है।	2	268	2717	635
अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम 49	44	15	249	327
स्थानीय निकाय	0	0	102	33
कुल जोड़	**46**	**283**	**3068**	**995**

(2) बैकलॉग को भरने हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाये गये पग

राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति की रिक्तियां जो कि सामान्य भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत अक्टूबर, 2014 से अब तक भरी गई हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

ग्रुप–ए0	ग्रुप–बी0	ग्रुप–सी0
19	517	3016

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा उनके पत्र क्रमांक 22/31/89–3 जी0एस0–III दिनांक 07.07.1989, 13.04.1993, 30.09.1994, 14.09.1995, 12.09. 1997 तथा 25.09.1998 द्वारा सभी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों तथा विश्वविद्यालयों को अनुसूचित जाति का बैकलॉग विशेष भर्ती अभियान से भरने के लिए हिदायतें जारी की जा चुकी है। इसके साथ–2 बैकलॉग को भरने के लिए हिदायतें पत्र दिनांक 11.09.2015 जारी की गई है। उपरोक्त अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2017–2018 के दौरान अनुसूचित जातियों के लिये 266 पद विशेष भर्ती अभियान के तहत विज्ञापित किये हैं। राज्य सरकार के द्वारा पार्ट–2 के तहत कान्ट्रैक्ट आधार पर की जाने वाली भर्तीयों में भी आरक्षण नीति दिनांक 27.10.2017 जारी की गई है।

.....

Supply of Water in the Distributaries

***2492. Shri Ranbir Gangwa** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to supply water minimum for two weeks in a month in the distributaries of Balsamand and Devsar of district Hisar togetherwith the time by which said proposal is likely to be materialized?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं, श्रीमान् जी । इसलिए प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल ही नहीं उठता ।

.....

Repair of Drinking Water Pipeline

***2508. Smt. Kiran Choudhry** : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state :-

(a) whether it is fact that the drinking water pipe line of village Dab Dhani (Tosham) is lying broken for the last many months; and

(b) if so, the steps taken by the Government to repair the abovesaid pipeline togetherwith the time by which it is likely to be repaired?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डा0 बनवारी लाल) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी ।

(ख) यह भाग उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

.....

Shortage of Doctors And Other Staff

***2589. Smt Renuka Bishnoi** : Will the Health Minister be pleased to state :-

(a) whether it is a fact that there is shortage of doctors and other staff in the civil Hospital of Hansi; if so, the time by which shortage of doctors and other staff in above said Hospital is likely to be met out ; and

(b) the steps taken by the Government to improve the medical facilities in the above said Hospital ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री अनिल विज) : उप मंडल अस्पताल, हांसी में चिकित्सकों व अन्य अमले की कुछ कमी है। समय समय पर संबंधित सिविल सर्जन से प्राप्त मांग अनुसार आवश्यक अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

.....

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

To Set Up Fertilizer Plant

589. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Agriculture Minister be pleased to state whether it is a fact that permission in princip has been given to the private sector company namely Samparan Agriculture Pvt. Ltd. to set up five fertilizer and biogas plants based on paddy straw in the state; if so, the details thereof?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं साहब, राज्य मे पराली आधारित पांच उर्वरक तथा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की समर्पण एग्रीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड नामक कम्पनी को अनुमति नहीं प्रदान की गई है।

.....

Details of officers/Officials indicted

577. Shri Karan Singh Dalal: Will the Cooperation Minister be pleased to state the details of officers/officials indicted for discrepancies and short comings in transactions, detected in the Audit Reports of all District Central Cooperative Banks and all the Primary Agriculture Co-operative Societies in the State for the year 2012-13 to 2016-17 ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री मनीश कुमार ग्रोवर) : श्रीमान जी, सदन के पटल पर विवरण वर्श 2012–13 से 2016–17 के लिए राज्य में सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा सभी प्राथमिक कृशि सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में पाई गई लेन–देन में कमियों तथा विसंगतियों के लिए दोशी अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा सारणी 'क' व 'ख' पर रखा गया है।

ब्यौरा

सारणी–क

क0 संख्या	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के नाम	अवधि	आडिट रिर्पोट में दर्शाये गये दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों का ब्यौरा
	(क)	(ख)	(ग)
1	अम्बाला	2012-13 to 2016-17	शून्य
2	सिरसा	2012-13 to 2016-17	शून्य

3	महेन्द्रगढ़	2012-13 to 2016-17	शून्य
4	रेवाड़ी	2012-13 to 2016-17	शून्य
5	गुरुग्राम	2012-13 to 2016-17	शून्य
6	सोनीपत	2012-13 to 2016-17	शून्य
7	फरीदाबाद	2012-13 to 2016-17	शून्य
8	यमुनानगर	2012-13 to 2016-17	शून्य
9	जीन्द	2012-13 to 2016-17	शून्य
10	करनाल	2012-13 to 2016-17	शून्य
11	कैथल	2012-13 to 2016-17	शून्य
12	कुरुक्षेत्र	2012-13 to 2016-17	शून्य
13	पानीपत	2012-13 to 2016-17	शून्य
14	भिवानी	2012-13 to 2016-17	शून्य
15	रोहतक	2012-13 to 2016-17	शून्य
16	हिसार	2012-13	श्री कृष्ण लाल मलिक पूर्व कनिष्ठ लेखाकार व तत्कालीन शाखा प्रबन्धक
17	फतेहाबाद	2014-15	श्री हवा सिंह, लिपिक
18	झज्जर	2012-13	श्री दलजीत सिंह, पूर्व शाखा प्रबन्धक ब्लॉक कार्यालय छारा
19	पंचकूला	2014-15	1. श्री आनंद सक्सेना, पूर्व प्रबन्ध निदेशक 2. श्रीमती गुरप्रीत कौर, पूर्व महाप्रबन्ध्क 3. श्री राजीव माथुर पूर्व परियोजना अधिकारी

सारणी– ख

क्रं0 सं0	**प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ का नाम**	**अवधि 2012–13 से 2016–17**	**प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ की आडिट रिर्पोटों में हुई विसंगितियों और कमियों के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा**
	(क)	**(ख)**	**(ग)**
लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां, करनाल जिला–करनाल			
1	गढी जाट्ान पैक्स	2014.15	श्री रमेश चंद लिपिक और सतपाल प्रबंधक
2	सालवन पैक्स	2015.16	श्री भीम सिंह लिपिक और पैक्स प्रबंधक
	जिला–पानीपत		
1	गढ़ी बेसक पैक्स	2012.13	श्री गयूर अली, विक्रेता, सुरेन्द्र लिपिक और पैक्स प्रबंधक
2	पानीपत पैक्स	2013.14	श्री कुलदीप प्रबंधक
3	खोतपूरा पैक्स	2013.14	श्री सुन्दर सिंह विक्रेता, महेन्द्र सिंह, रति राम, बलकार और राम कुमार पैक्स प्रबंधक
4	लोहारी पैक्स	2014.15	श्री मेहर सिंह विक्रेता, कृष्ण कुमार लिपिक, पैक्स प्रबंधक और केन्द्रीय बैंक कर्मचारी सतनारायण प्रबंधक, अजमेर सिंह, रणधीर सिंह, विजय सिंह
5	नारायणा पैक्स	2015.16	श्री रूलिया राम विक्रेता

लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां, रोहतक			
1	दी भैंसवाल पैक्स लि.	2012.16	श्री अमरजीत विक्रेता, रामपाल चौकीदार, सुभाष विक्रेता व समिति प्रबंधक तथा श्री रणबीर सिंह ब्रांच मैनेजर सी.बी.
2	दी बजाना कलां पैक्स लि.	2013.14	श्री समुन्दर सिंह, समिति प्रबंधक
3	दी भैंसवाल पैक्स लि.	2014.15	श्री होशियार सिंह, समिति प्रबंधक
4	दी बुटाना कुण्डू पैक्स लि.	2014.15	श्री चांदीराम, समिति प्रबंधक
5	दी लाखनमाजरा पैक्स लि.	2014.15	श्री राजबीर, समिति प्रबंधक
6	दी बलम्बा पैक्स लि.	2015.16	श्री कृष्ण कुमार, समिति प्रबंधक
7	दी खानपुर कलां पैक्स लि.	2015.16	श्री सतपाल सिंह, अतिरिक्त कार्यभार समिति प्रबंधक
8	दी बड़ोता पैक्स लि.	2015.16	श्री जयभगवान, समिति प्रबंधक
9	दी आहूलाना पैक्स लि.	2015.16	श्री जगदीश, समिति प्रबंधक
10	दी बुटाना कुण्डू पैक्स लि.	2015.16	श्री चांदीराम, राजपाल व सतपाल समिति प्रबंधक
11	दी गन्नौर पैक्स लि.	2015.16	श्री सुलतान सिंह सेवादार
12	दी बजाना कलां पैक्स लि.	2016.17	श्री सुभाष सचिव, जयभगवान चौकीदार, राजेन्द्र सिंह कलर्क व रामकुमार प्रबंधक
13	दी दादरीतोय पैक्स लि.	2016.17	श्री प्रेम, समिति प्रबंधक
14	दी बड़ोता पैक्स लि.	2016.17	श्री रामकुमार, समिति प्रबंधक
लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां, भिवानी			
1	दी अलेवा पैक्स	2012.13	श्री महेन्द प्रबन्धक, श्री सही राम प्रबन्धक,श्री महाबीर प्रबन्धक ,श्री रामफल कुंडु प्रबन्धक
			श्री बलराज सेल्समैन
			श्री शिशनदत सेल्समैन
			श्री राजकुमार क्लर्क
2	दी मुढाल खुर्द पैक्स	2013.14	श्री जय भगवान प्रबन्धक
			श्री वीरेन्द्र मलिक प्रबन्धक
			श्री रविन्द्र चौकिदार
3	दी लोहारू पैक्स	2014.15	श्री मुंशी राम प्रबन्धक
4	दी ढीगावा पैक्स	2015.16	श्री राम अवतार प्रबन्धक
			श्री सज्जन कुमार प्रबन्धक
			श्री जय प्रकाश सैल्समैन

क्रं0 सं0	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ का नाम	अवधि 2012–13 से 2016–17	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ की आडिट रिर्पोटों में हुई विसंगितियों और कमियों के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा
	(क)	(ख)	(ग)
लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां, अम्बाला			
1	खोजकीपुर पैक्स	2012.13	श्री गुलाब सिंह, प्रबन्धक
2	नारायणगढ़ पैक्स	2012.13	श्री रंजोर सिंह, प्रबन्धक
3	शहजादपुर पैक्स	2012.13	श्री लखमीर सिंह, प्रबन्धक
4	लाहा पैक्स	2012.13	श्री माया राम, प्रबन्धक
5	धमौली पैक्स	2012.13	श्री लखमीर सिंह, श्री सुरजीत सिंह, श्री टीका सिंह, प्रबन्धक
6	जांडली पैक्स	2012.13	श्री गुरमेल सिंह, प्रबन्धक

7	अम्बली पैक्स	2012.13	श्री महेन्द्र पाल सैनी, प्रबन्धक
8	नागवान पैक्स	2012.13	श्री माया राम, प्रबन्धक
9	बकनौर पैक्स	2012.13	श्री बलकार सिंह, प्रबन्धक
10	सोन्टी पैकस	2012.13	श्री रिशपाल सिंह, प्रबन्धक व श्री हंसराज, प्रबन्धक
11	तेजा मोहरी पैक्स	2012.13	श्री महेश चन्द, प्रबन्धक
12	मंढौर पैक्स	2012.13	श्री गुरमेल सिंह, प्रबन्धक
13	चौरमस्तपुर पैक्स	2012.13	श्री रिशपाल सिंह, प्रबन्धक व श्री हंसराज, प्रबन्धक
14	आनंदपुर जलबेहरा पैक्स	2012.13	श्री महेश चन्द, प्रबन्धक
15	गेल पैक्स	2012.13	श्री महेश कुमार प्रबन्धक
16	ननियोला पैक्स	2012.13	श्री दयाल सिंह, प्रबन्धक
17	छपरा पैक्स	2012.13	श्री नजर सिंह, प्रबन्धक
18	माजरी पैक्स	2012.13	श्री निरंजन सिंह, प्रबन्धक
19	जोधपुर पैकस	2012.13	श्री मोहन लाल, प्रबन्धक
20	बबयाल पैक्स	2012.13	श्री सुरिन्द्र कुमार, प्रबन्धक
21	पटवी पैक्स	2012.13	श्री रमेश कुमार, प्रबन्धक
22	रायपुर रानी पैक्स	2012.13	श्री कृष्ण लाल प्रबन्धक
23	रसूलपुर पैक्स	2012.13	श्री धर्मपाल, प्रबन्धक
24	सढौरा पैक्स	2012.13	श्री धर्मपाल, प्रबन्धक व श्री सुखबीर सिंह, प्रबन्धक
25	सरवाना पैक्स	2012.13	श्री जगमल सिंह, प्रबन्धक
26	जगाधरी कदीम पैक्स	2012.13	श्री जगमल सिंह, प्रबन्धक
27	नाहड़पुर पैक्स	2012.13	श्री बीरपाल, प्रबन्धक
28	ओढरी पैक्स	2012.13	श्री मोहन लाल, प्रबन्धक
29	मांधौर पैक्स	2013.14	श्री गुरमेल सिंह, प्रबन्धक
30	चौरमस्तपुर पैक्स	2013.14	श्री हंसराज, प्रबन्धक
31	अंबली पैक्स	2013.14	श्री महेन्द्र पाल, प्रबन्धक
32	नागवान पैक्स	2013.14	श्री माया राम, प्रबन्धक
33	जांडली पैक्स	2013.14	श्री गुरमेल सिंह, प्रबन्धक
34	शहजादपुर पैक्स	2013.14	श्री टीका सिंह, प्रबन्धक
35	तेजा मोहरी पैक्स	2013.14	श्री महेश चन्द, प्रबन्धक
36	लाहा पैक्स	2013.14	श्री माया राम, प्रबन्धक
37	उगाला पैक्स	2013.14	श्री नरेन्द्र शर्मा, प्रबन्धक
38	ककड़ माजरा पैक्स	2013.14	श्री अम्बरिश वालिया व श्री विकास कुमार, प्रबन्धक और श्री राज कुमार, सेवक
39	संधाली पैक्स	2013.14	श्री पूर्ण सिंह, प्रबन्धक
40	सौंटी पैक्स	2013.14	श्री मोहन लाल, प्रबन्धक
41	खोजकीपुर पैक्स	2013.14	श्री गुलाब सिंह, प्रबन्धक
42	धमौली पैक्स	2013.14	श्री टीका सिंह, प्रबन्धक
43	बुरीया पैक्स	2013.14	श्री जगमल सैनी, प्रबन्धक
44	बकनौर पैक्स	2013.14	श्री बलकार सिंह, प्रबन्धक
क्रं0 सं0	**प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ का नाम**	**अवधि 2012–13 से 2016–17**	**प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ की आडिट रिर्पोटों में हुई विसंगितियों और कमियों के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा**
	(क)	**(ख)**	**(ग)**
45	सढौरा पैक्स	2013.14	श्री धर्मपाल, प्रबन्धक
46	रसूलपुर पैक्स	2013.14	श्री देविन्द्र कुमार, प्रबन्धक
47	कटगढ़ पैक्स	2014.15	श्री सुरिन्द्र कुमार, प्रबन्धक
48	संधाई पैक्स	2014.15	श्री राज कुमार, प्रबन्धक
49	कपुरी कलां पैक्स	2014.15	श्री रमेश चन्द, प्रबन्धक

50	ककड़ माजरा पैक्स	2014.15	श्री अम्बरिश वालिया, प्रबन्धक
51	नाहड़पुर पैक्स	2014.15	श्री राम रतन, प्रबन्धक
52	खीजरेबाद पैक्स	2014.15	श्री सोहन सिंह मलिक, प्रबन्धक
53	सौंटी पैक्स	2014.15	श्री मोहन लाल, प्रबन्धक
54	बकनौर पैक्स	2014.15	श्री बलकार सिंह, श्री सीता राम व श्री निसान सिंह, प्रबन्धक
55	नबीपुर एफ.एस.एस.	2014.15	श्री रती राम, प्रबन्धक
56	खोजकीपुर पैक्स	2014.15	श्री गुलाब सिंह, श्री सुभाष चन्द और श्री सुरिन्द्र कुमार, प्रबन्धक
57	बुरीया पैक्स	2014.15	श्री सुरेश सैनी, प्रबन्धक
58	रामगढ़ पैक्स	2014.15	श्री अम्बरिश वालिया, प्रबन्धक
59	मानक टाबरा पैक्स	2014.15	श्रीराम मूरती, प्रबन्धक
60	कैल पैक्स	2014.15	श्री सुशील कुमार, प्रबन्धक
61	रतपुर पैक्स	2014.15	श्री विकास कुमार, प्रबन्धक
62	लाहा पैक्स	2014.15	श्री माया राम, प्रबन्धक
63	रायपुर रानी पैक्स	2014.15	श्री ईश्वर दास, प्रबन्धक
64	धोरांग पैक्स	2014.15	श्री पवन कुमार, प्रबन्धक
65	हरनौल पैक्स	2014.15	श्री सुरेश सैनी, प्रबन्धक
66	होली पैक्स	2014.15	श्री महावीर सिंह, प्रबन्धक
67	मंढौर पैक्स	2014.15	श्री गुरमेल सिंह, प्रबन्धक
68	धमौली पैक्स	2010.15	श्री लखमीर सिंह, श्री सुरजीत सिंह, श्री टीका सिंह, श्री सतीश शर्मा, श्री सुभाष चन्द्र, श्री गुलजार सिंह व श्री माहेन लाल, प्रबन्धक, प्रबन्धक और श्री चमन लाल, सेल्ज मैन
69	खडक मंगोली पैक्स	2015.16	श्री राज कुमार, प्रबन्धक
70	घेल पैक्स	2015.16	श्री महेश चन्द, प्रबन्धक
71	रसूलपुर पैक्स	2016.17	श्री राज पाल, प्रबन्धक
लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां, गुरुग्राम			
1	जटौली	2013.14	श्री चरणजीत सिंह व श्री मदन, प्रबन्धक
2	मानेसर	2015.16	श्री महावीर सिंह, प्रबन्धक
3	बिलासपुर	2013.14	श्री रामफल, प्रबन्धक
4	पटौदी	2013.14	श्री तेजवीर सिंह, प्रबन्धक
5	नूंह	2014.15	श्री गनी खा, प्रबन्धक
6	कामेडा	2012.15	श्री कमरूद्दीन, प्रबन्धक
7	मांडीखेडा	2011.14	श्री खुर्शीद अहमद, प्रबन्धक
8	रावली	2013.14	मो0 अशरफ, प्रबन्धक
9	नगीना	2014.15	श्री अकबर खां, प्रबन्धक
10	बिसरू	2011.14 2014.15	अखतर हुसन, सुशील, मुबीन व जुबेर, प्रबन्धक हनीफ, प्रबन्धक

क्रं0 सं0	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ का नाम	अवधि 2012–13 से 2016–17	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ की आडिट रिर्पोटों में हुई विसंगितियों और कमियों के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा
	(क)	(ख)	(ग)
11	सिकरावा	2014.15	अता मौ0 व महासिंह, प्रबन्धक
12	फिरोजपुरझिरका	2013.15	श्री इसलाम मौ0, प्रबन्धक
13	पुनहाना	2014.15	श्री कासम, प्रबन्धक
14	पिनंगवा	2014.15	श्री मुबीन प्रबन्धक
15	गहलब	2012.14	श्री बलराम सिंह, प्रबन्धक
		2014.15	श्री मुन्ना लाल, प्रबन्धक
16	बहीन	2012.15	श्री सहूद अहमद, प्रबन्धक
		2015.17	श्री सहूद अहमद, प्रबन्धक
17	हथीन	2010.14	श्री प्रेमलाल, प्रबन्धक
		2014.15	श्री पूर्णलाल, प्रबन्धक
18	जटौली	2014.15	श्री बलबीर सिंह व श्री कर्मबीर, प्रबन्धक
19	अहरंवा	2013.16	श्री विरेन्द्र सिंह, प्रबन्धक
		2016.17	श्री विरेन्द्र सिंह, प्रबन्धक
20	पृथला	2013.17	श्री लखीराम षर्मा, प्रबन्धक
21	अलावलपुर	2013.15	श्री धर्मचन्द, प्रबन्धक
22	धतीर	2013.14	श्री कंवलजीत सिंह, प्रबन्धक
23	अमरपुर	2013.15	श्री किषोर सिंह, प्रबन्धक
24	चान्दहट	2013.14 2012.13 2013.14	श्री लीलाराम, सुभाष चन्द्र, जयकिशन, प्रबन्धक । माननीय रजिस्ट्रार, स0स0, हरियाणा पंचकुला के आदेशानुसार स्पैशल आडिट जारी है ।
25	गुरवाडी	2013.15	श्री देवेन्द्र सिंह, प्रबन्धक, माननीय रजिस्ट्रार, स0स0, हरियाणा पंचकुला के आदेशानुसार स्पैशल आडिट जारी है।
26	सोंध	2013.14	श्री ज्ञानचन्द, प्रबन्धक
27	फतेहपुर चन्देला	2015.16	श्री दलीप सिंह प्रबन्धक
28	उंचागांव	2014.15	श्री रविन्द्रपाल,, प्रबन्धक
29	फतेहपुर बिलोच	2006.12	श्री चन्द्रपाल, प्रबन्धक
		2015.16	श्री चन्द्रपाल, प्रबन्धक
30	जवां	2014.15	श्री रमेश चन्द, प्रबन्धक
		2015.16	श्री सुरेश, प्रबन्धक
		2016.17	श्री सुरेश, प्रबन्धक
31	बींवा	2013.15	श्री फैज मो0 प्रबन्धक
लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां, हिसार			
1	दी खरक पूनियां	2012.13	श्री सुखपाल (प्रबंधक)
2	दी गोरखपूर	2012.13	श्री धर्मपाल (प्रबंधक)
3	दी खेडी लोहचब	2012.13	श्री अजीत सिंह (प्रबंधक
4	दी घिराये	2012.13	श्री राजेश कुमार लिपिक/सैल्जमैन, श्री शमशेर सिंह (प्रबंधक), श्री बलवान सिंह (प्रबंधक)

क्रं0 सं0	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ का नाम	अवधि 2012–13 से 2016–17	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ की आडिट रिर्पोटों में हुई विसंगितियों और कमियों के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा
	(क)	(ख)	(ग)
5	दी मैहन्दा गढी	2012.13	श्री औमप्रकाश (प्रबंधक), श्री सुरेश चन्द शर्मा शाखा प्रबंधक, श्री ईश्वर सिंह, लिपिक
6	दी सुचान	2012.13	श्री महेन्द्र सिंह, सैल्जमैन, श्री बलबीर सिंह सैल्जमैन, श्री हजुरा सिंह सैल्जमैन, श्री हरि सिंह सैल्जमैन, श्री सुभाष चन्द्र सैल्जमैन, श्री इन्द्र सिंह सेवादार
7	दी आर्य नगर	2014.15	श्री कुलदीप सिंह प्रबंधक व पैक्स प्रबंधक कमेटी
8	दी पंजुआना	2014.15	श्री धर्मपाल पैक्स प्रबंधक, व सी0बी0 सिरसा प्रबंधन
9	दी बरवाला	2014.15	श्री बलराज सिंह सैल्जमैन
10	दी नियाणा	2015.16	श्री जगदीश चन्द्र (प्रबंधक)
11	दी गैबीपुर	2015.16	श्री काजू राम, भू0पू0 प्रबंधक
12	दी पिरथला	2015.16	श्री श्याम सुन्दर व सुखवीर सुरा प्रबंधक, महेन्द्र कुमार भू0पू0 लिपिक, साहब राम सैल्जमैन
13	दी झालानियां	2016.17	श्री जगदीश चन्द्र (प्रबंधक)
लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां, कुरुक्षेत्र			
	सी.बी. कैथल	**2012.13**	
1	दि पुण्डरी पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री सतबीर सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
2	दि हाबरी पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री चन्द्र भान प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
3	दि बरसाना पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन,ओम प्रकाश प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
4	दि डाण्ड पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री रिषीपाल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
5	दि पाई पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री कुलदीप नैन प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
6	दि कौल पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री पवन कुमार प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
7	दि रसीना पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन श्री रणबीर सिंह प्रबन्धक एंव समस्त पैक्स व सीएस कर्मचारी
8	दि किठाना पैक्स	2012.13	पैक्सप्रबन्धन श्री जगदीश अरोडा प्रबन्धक एंव समस्त पैक्स व सीएस कर्मचारी
9	दि राजौन्द पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री सुभाष प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
10	दि सेरधा पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री सतपाल सिंह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
11	दि जखौली पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री राम कर्ण प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
12	दि कलायत पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री कृष्ण दत प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
13	दि कुराड पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री दिलबाग सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
14	दि मटौर खडांलवा	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री बलबीर प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी

15	दि खुराना पैक्स	2012.13	पैक्स प्रब श्री राजेश प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
क्रं0 सं0	**प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ का नाम**	**अवधि 2012–13 से 2016–17**	**प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ की आडिट रिर्पोटों में हुई विसंगितियों और कमियों के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा**
	(क)	**(ख)**	**(ग)**
16	दि पाडला पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री धर्मबीर प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
17	दि नरड पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री बारू राम प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
18	दि तीतरम पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री भीम सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
19	दि क्योडक पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री रिषी पाल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
20	दि सीवन पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री महिन्द्र सिह राणा सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
21	दि मुन्दरी पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री कृष्ण कुमार प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
22	दि नौच पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री कृष्ण कुमार प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
23	दि अमरगढ पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री रणधीर सिह डांडा प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
24	दि बाबा लदाना पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री रणधीर सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
25	दि पटटी चौधरी पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री जगदीश ढुल, सतबीर सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
26	दि पटटी अफगान पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री राम कर्ण प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
27	दि टीक पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री जगपाल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
28	दि चीका पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री किरपाल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
29	दि कांगथली पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री सुरेन्द्र सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
30	दि गुहला पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री बलवन्त प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
31	दि उरलाना पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री ज्ञान चन्द प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
32	दि अगौन्ध पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री सुरेन्द्र सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
	सी.बी. कुरूक्षेत्र		
33	दि भौरख सी.एस.	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री अमरीक सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
34	दि रतनगढ ककराली पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री तरसेम लाल, श्री रणधीर, श्री निरजन, श्री प्रवेश प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
35	दि थाना पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री गजेन्द्र सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
36	दि छजजुपुर सी.एस.	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री निर्मल सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
37	दि मोरथी सी.एस.	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री निर्मल सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी

क्रं0 सं0	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ का नाम	अवधि 2012–13 से 2016–17	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ की आडिट रिर्पोटों में हुई विसंगितियों और कमियों के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा
	(क)	(ख)	(ग)
38	दि स्योसर पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री निरजन सिह, श्री तरेसम लाल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
39	दि मुर्तजापुर सी.एस.	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री रोहन लाल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
40	दि मलीकपुर सी.एस.	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री राम दयाल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
41	दि भैन्सी माजरी पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री रणबीर सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
42	दि कैन्थला खुर्द पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री बनारसी दास, लखविन्द्र बाजवा प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
43	दि पीपली पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री रामभूल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
44	दि उमरी पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री अशोक कुमार, चरणा राम, विजय कुमार व रामफल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
45	दि कौलापुर पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री हीरा सिह, श्री सुन्दर लाल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
46	दि अमीन पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री बलबीर सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
47	दि कमौदा पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री रणबीर सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
48	दि घराडसी पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री लखविन्द्र सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
49	दि बारना पैक्स	2012.13	पैक्स प्रबन्धन, श्री शीश पाल, जसबीर सिंह वकील सिंह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
	सी.बी. कैथल	**2013.14**	
1	दि पुण्डरी पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री कृष्ण गोपाल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
2	दि हाबरी पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री चन्द्रभान प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
3	दि बरसाना पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री ओम प्रकाश प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
4	दि डाण्ड पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्ध रिषी पाल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी. एस. कर्मचारी
5	दि पाई पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री कर्मबीर प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
6	दि कौल पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री करम सिंह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
7	दि रसीना पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री रणबीर सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
8	दि किठाना पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री जगदीश अरोडा प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
9	दि राजौन्द पैक्स	2013.14	पैकस प्रबन्धन सुभाष प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी. एस. कर्मचारी
10	दि सेरधा पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री पालाराम, श्री रामकर्ण प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी

क्रं0 सं0	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ का नाम	अवधि 2012–13 से 2016–17	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ की आडिट रिर्पोटों में हुई विसंगितियों और कमियों के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा
	(क)	(ख)	(ग)
11	दि जखौली पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री सत्यपाल सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
12	दि कलायत पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री कृष्ण दत प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
13	दि कुराड पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री दिलबाग प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
14	दि मटौर खडांलवा	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री कृष्ण दत्त प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
15	दि खुराना पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री परमानंद प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
16	दि पाडला पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री धर्मबीर सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
17	दि नरड पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री बारु राम प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
18	दि तीतरम पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री वासुदेव शर्मा, श्री रामफल ढूल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
19	दि क्योडक पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री ओम प्रकाश प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
20	दि सीवन पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री सतपाल सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
21	दि मुन्दरी पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री कृष्ण मुरारी प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
22	दि नौच पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री कृष्ण प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी. एस. कर्मचारी
23	दि अमरगढ पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री जगदीश ढूल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
24	दि बाबा लदाना पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री रणधीर सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
25	दि पटटी चौधरी पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री राम कर्ण प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
26	दि पटटी अफगान पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री राम कर्ण प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
27	दि टीक पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री जगपाल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
28	दि चीका पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री किरपाल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
29	दि कांगथली पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री सुरेन्द्र प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
30	दि गुहला पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री बलवन्त सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
31	दि उरलाना पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री गुरमीत सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
32	दि अगौन्ध पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री सुरेन्द्र सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी

क्रं0 सं0	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ का नाम	अवधि 2012–13 से 2016–17	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ की आडिट रिर्पोटों में हुई विसंगितियों और कमियों के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा
	(क)	(ख)	(ग)
	सी.बी. कुरूक्षेत्र		
33	दि भौरख सी.एस.	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री राम दयाल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
34	दि रतनगढ ककराली पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री निरजन, श्री तरसेम, श्री प्रवेश प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
35	दि थाना पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री गजेन्द्र सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
36	दि छजजुपुर सी.एस.	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री राम दयाल, श्री निर्मल सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
37	दि मोरथी सी.एस.	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री निर्मल सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
38	दि स्योसर पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री प्रवेश कुमार, तरसेम लाल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
39	दि मुर्तजापुर सी.एस.	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री बलविन्द्र, श्री राम दयाल, श्री रोशन लाल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
40	दि मलीकपुर सी.एस.	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री राम दयाल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
41	दि भैन्सी माजरी पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री रणबीर सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
42	दि कैन्थला खुर्द पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री रणबीर सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
43	दि पीपली पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री राम भूल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
44	दि उमरी पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री गुरनाम सिह, श्री अशोक कुमार, श्री सुशील कुमार प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
45	दि कौलापुर पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री विजय गुप्ता प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
46	दि अमीन पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री बलबीर सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
47	दि कमौदा पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री रणबीर सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
48	दि घराडसी पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री रणबीर सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
49	दि बारना पैक्स	2013.14	पैक्स प्रबन्धन, श्री शीश पाल, जसबीर सिंह वकील सिंह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
	सी.बी. कुरूक्षेत्र	**2014.15**	
1	दि भौरख सी.एस.	2014.15	पैक्स प्रबन्धन, श्री राम दयाल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
2	दि रतनगढ ककराली पैक्स	2014.15	पैक्स प्रबन्धन, श्री रणधीर सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
3	दि थाना पैक्स	2014.15	पैक्स प्रबन्धन, श्री बलबीर सिह प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
4	दि छजजुपुर सी.एस.	2014.15	पैक्स प्रबन्धन, श्री प्रवेश कुमार, श्री धर्मवीर चाहलीया प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी

क्रं0 सं0	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ का नाम	अवधि 2012–13 से 2016–17	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ की आडिट रिर्पोटों में हुई विसंगितियों और कमियों के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा
	(क)	(ख)	(ग)
5	दि मुर्तजापुर सी.एस.	2014.15	पैक्स प्रबन्धन, श्री बलविन्द्र, श्री धर्मवीर चाहलीय, अुनज कुमार प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
6	दि मलीकपुर सी.एस.	2014.15	पैक्स प्रबन्धन, श्री राम दयाल प्रबन्धक एंव समस्त पैकस व सी.एस. कर्मचारी
1	कुरूक्षेत्र मारकण्डा सी. एस.	2015.16	श्री जसबीर सिंह, प्रबन्धक
लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां, रेवाड़ी			
1	धारूहेड़ा पेक्स	2012.13	श्री विष्णु दत्त प्रबन्धक
2	ततारपुर पेक्स	2012.13	श्री मुंसी राम प्रबन्धक
3	सहारनवास पेक्स	2012.13	श्री अमरजीत प्रबन्धक
4	झारोदा पेक्स	2012.13	श्री राजेन्द्र सिंह प्रबन्धक
5	जोनावास पेक्स	2012.13	श्री सुरेश प्रबन्धक
6	कोसली पेक्स	2013.14	श्री सुरेश कुमार प्रबन्धक
7	जोनावास पेक्स	2013.14	श्री सुरेश प्रबन्धक
8	सहारनवास पेक्स	2013.14	श्री अमरजीत प्रबन्धक
9	रेवाड़ी पेक्स	2013.14	श्री अमरजीत प्रबन्धक
10	मनेठी पेक्स	2013.14	श्री तुलसी राम प्रबन्धक
11	मुंदी पेक्स	2013.14	श्री हुक्म चन्द प्रबन्धक
12	गुमिना पेक्स	2013.14	श्री मदन प्रबन्धक
13	खोरी पेक्स	2013.14	श्री मदन प्रबन्धक
14	धारूहेड़ा पेक्स	2013.14	श्री विष्णु दत्त प्रबन्धक
15	ततारपुर पेक्स	2013.14	श्री वीरेंद्र सिंह प्रबन्धक
16	भगवानपुर पेक्स	2013.14	श्री जगपाल प्रबन्धक
17	मूसेपुर	2013.14	श्री राजेन्द्र पैक्स प्रबन्धक
18	पाल्हावास पेक्स	2013.14	श्री वाशुकांत पैक्स प्रबन्धक
19	डहीना पेक्स	2013.14	श्री मनबीर पैक्स प्रबन्धक
20	नांगल तेजू पेक्स	2013.14	श्री चाँद सिंह प्रबन्धक
21	सुलखा पेक्स	2013.14	श्री ओम प्रकाश प्रबन्धक
22	नंगली पर्सापुर पेक्स	2013.14	श्री लख्खा सिंह प्रबन्धक
23	बावल पेक्स	2013.14	श्री प्रीतम प्रबन्धक
24	मोतला कलां पेक्स	2013.14	श्री राम सिंह प्रबन्धक
25	मांढइया खुर्द पेक्स	2013.14	श्री सुरेन प्रबन्धक
26	संगवारी पेक्स	2013.14	श्री धर्मवीर सेल्समेन प्रबन्धक
27	बोलनी पेक्स	2013.14	श्री पहलाद सिंह प्रबन्धक
28	काकोडिया पेक्स	2013.14	श्री विजय सिंह प्रबन्धक
29	झारोदा पेक्स	2013.14	श्री राजेन्द्रसिंह प्रबन्धक

30	गुढ़ा पेक्स	2012.13	श्री नेपाल सिंह प्रबन्धक
31	नांगल सिरोही पेक्स	2013.14	श्री बलवंत सिंह पैक्स प्रबन्धक
32	सतनाली पेक्स	2013.14	श्री सत्यप्रकाश प्रबन्धक
33	महेन्द्रगढ़ पेक्स	2013.14	श्री सत्यवीर सिंह पैक्स प्रबन्धक
34	नांगल सिरोही पेक्स	2013.14	श्री बलवंत सिंह पैक्स प्रबन्धक
35	सह्लांग पेक्स	2013.14	श्री कैलास प्रबन्धक
36	भोजावास पेक्स	2013.14	श्री दयाराम प्रबन्धक
37	गुढ़ा पेक्स	2013.14	श्री सतप्रकाश, समिति प्रबन्धक
38	डोंगरा अहीर पेक्स	2013.14	श्री बसंत लालए अमरसिंहए सतप्रकाश प्रबन्धक
		सारणी– ख	
क्रं0 सं0	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ का नाम	अवधि 2012–13 से 2016–17	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ की आडिट रिर्पोटों में हुई विसंगितियों और कमियों के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा
	(क)	(ख)	(ग)
39	कनीना पेक्स	2013.14	श्री सतप्रकाश और अशोक कुमार प्रबन्धक
40	बवानिया पेक्स	2013.14	श्री राजपाल प्रबन्धक
41	अकोदा पेक्स	2013.14	श्री वीरेन्द्र सिंह पैक्स प्रबन्धक
42	खाथोद्र पेक्स	2013.14	श्री महेश कुमार प्रबन्धक
43	नारनौल पेक्स	2013.14	श्री युधवीर सिंह प्रबन्धक
44	न दरगु पेक्स	2013.14	श्री दयाराम प्रबन्धक
45	भोजावास पेक्स	2013.14	श्री दया राम प्रबन्धक
46	ढाणी मामराज पेक्स	2013.14	श्री बसंत लाल प्रबन्धक
47	अटेली पेक्स	2013.14	श्री बसंत लाल प्रबन्धक
48	नांगल चौधरी	2013.14	श्री सुन्दर लाल प्रबन्धक
49	नसीबपुर पेक्स	2012.14	श्री महिपाल सिंह प्रबन्धक
50	बाला कलां पेक्स	2012.14	श्री रामकिशन कुमार प्रबन्धक
51	खातोती कलां पेक्स	2012.14	श्री विजय सिंह व श्री देशराज कुमार प्रबन्धक
52	निजामपुर पेक्स	2012.14	श्री ओमप्रकाश प्रबन्धक
53	बाछोद पेक्स	2012.14	श्री राकेश यादव बाछोदप्रबन्धक
54	सिह्मा पेक्स	2012.14	श्री सुरेन्द्र प्रबन्धक
55	अकोदा पेक्स	2014.15	श्री वीरेंदर सिंह प्रबन्धक
56	झारोदा पेक्स	2014.15	श्री राजेन्द्र सिंह प्रबन्धक
57	खोरी पेक्स	2014.15	श्री मदन प्रबन्धकए डॉ विनोद कुमार चेयरमैन पैक्स समिति
58	मनेठी पेक्स	2014.15	श्री सतपाल प्रबन्धक कोऑपरेटिव बैंक
59	रेवाड़ी पेक्स	2014.15	श्री धरमवीर और सतनारायण पैक्स प्रबन्धक
60	ततारपुर पेक्स	2014.15	श्री वीरेन्द्र प्रबन्धक
61	धारूहेड़ा पेक्स	2014.15	श्री विष्णु दत्त प्रबन्धक
62	सहारनवास पेक्स	2014.15	श्री अमरजीत प्रबन्धक
63	जोनावास पेक्स	2014.15	श्री सुनील कुमार प्रबन्धक

64	भगवानपुर पेक्स	2014.15	श्री जगपाल प्रबन्धक
65	काकोडिया पेक्स	2014.15	श्री विजय शर्मा और सुरेन सिंह पैक्स प्रबन्धक
66	बोलनी पेक्स	2014.15	श्री धरमवीर प्रबन्धक
67	सुलखा पेक्स	2014.15	श्री बलवान प्रबन्धक
68	बावल पेक्स	2014.15	श्री प्रीतम सिंह प्रबन्धक
69	नांगल तेजू पेक्स	2014.15	श्री चाँद सिंह प्रबन्धक
70	नंगली पर्सापुर पेक्स	2014.15	श्री लख्खा सिंह प्रबन्धक
71	संगवारी पेक्स	2014.15	श्री धरमबीर सिंह सेल्समेन अतिरिक्त चार्ज प्रबन्धक
72	मुंदी पेक्स	2014.15	श्री धरमवीर प्रबन्धक
73	गुमिना पेक्स	2014.15	श्री मदन पैक्स प्रबन्धक
74	सतनाली पेक्स	2014.15	श्री सत्यप्रकाश और राजकुमार पैक्स प्रबन्धक
75	नांगल सिरोही पेक्स	2014.15	श्री बलवंत प्रबन्धक
76	खाथोद्र पेक्स	2014.15	श्री महेश कुमार पैक्स प्रबन्धक रेवाड़ी
77	निजामपुर पेक्स	2014.15	श्री रामसिंह प्रबन्धक
78	भोजावास पेक्स	2014.15	श्री रामनिवास प्रबन्धक
79	नसीबपुर पेक्स	2014.15	श्री महिपाल प्रबन्धक
80	बाछोद पेक्स	2014.15	श्री राकेश प्रबन्धक
81	गुढ़ा पेक्स	2014.15	श्री रतन सिंह और सतप्रकाश प्रबन्धक
82	महेन्द्रगढ़ पेक्स	2014.15	श्री सतवीर सिंह और श्री सुरेन्द्र सिंह प्रबन्धक
83	संगवारी पेक्स	2015.16	श्री धरमवीर और तालेराम

क्रं0 सं0	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ का नाम	अवधि 2012–13 से 2016–17	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ/ऋण समितियाँ की आडिट रिर्पोटों में हुई विसंगितियों और कमियों के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा
	(क)	(ख)	(ग)
84	कनीना पेक्स	2015.16	श्री युधवीर सिंह और देशराज प्रबन्धक
85	भोजावास पेक्स ;ज्ञद्ध	2015.16	श्री देवेन्द्र कुमार प्रबन्धक
86	अकोदा पेक्स	2015.16	श्री वीरेंदर सिंह पैक्स प्रबन्धक
87	नांगल सिरोही पेक्स	2015.16	श्री होशियार सिंह पैक्सप्रबन्धक महेन्द्रगढ़
88	खोरी पेक्स	2015.16	श्री मदनए श्री धर्मवीर प्रबन्धक
89	झारोदा पेक्स	2015.16	श्री करन सिंह प्रबन्धक
90	बावल पेक्स	2015.16	श्री प्रीतम सिंह प्रबन्धक
91	ढाणी मामराज पेक्स	2015.16	श्री करमवीर प्रबन्धक
92	खाथोद्र पेक्स	2015.16	श्री महेश और अभय सिंह प्रबन्धक महेन्द्रगढ़
93	महेन्द्रगढ़ पेक्स	2015.16	श्री सुरेन्द्र सिंह प्रबन्धक महेन्द्रगढ़
94	सतनाली पेक्स	2015.16	श्री राजकुमार प्रबन्धक
95	डहीना पेक्स	2015.16	श्री मनवीर सिंह प्रबन्धक
96	पाल्हावास पेक्स	2015.16	श्री वाशुकांत प्रबन्धक

97	मांढइया खुर्द पेक्स	2015.16	श्री सुरेन यादव प्रबन्धक
98	रेवाड़ी पेक्स	2015.16	श्री धर्मवीर पैक्स प्रबन्धक
99	बोलनी पेक्स	2015.16	श्री सूरजभान सेल्समेनए पहलाद सिंह प्रबन्धक
100	गुढ़ा पेक्स	2015.16	श्री सत प्रकाश प्रबन्धक महेन्द्रगढ़
101	सह्लांग पेक्स	2015.16	श्री कैलाश चन्द प्रबन्धक महेन्द्रगढ़
102	बवानिया पेक्स	2015.16	श्री राजपाल प्रबन्धक महेन्द्रगढ़
103	डोंगरा अहीर पेक्स	2015.16	श्री बसंत लाल प्रबन्धक महेन्द्रगढ़
104	मनेठी पेक्स	2015.16	श्री सतपाल प्रबन्धक
105	नांगल चौधरी	2015.16	श्री सुंदर लाल प्रबन्धक
106	गुमिना पेक्स	2015.16	श्री मदन प्रबन्धक
107	नांगल तेजू पेक्स	2015.16	श्री चाँद सिंह प्रबन्धक
108	सह्लांग पेक्स	2016.17	श्री कैलाश चन्द प्रबन्धक
109	अकोदा पेक्स	2016.17	श्री वीरेंदर सिंह प्रबन्धक
110	मुंदी पेक्स	2016.17	श्री भुनेस कुमार पैक्स प्रबन्धक

Transfer Policy of Computer Teachers

635. Shri Ghanshyam Dass Arora : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any policy for the transfer of computer teachers in the state; if so, the time by which the said policy is likely to be implemented?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान् जी। कम्पयूटर शिक्षक अनुबंध के आधार पर नियुक्त हैं और उन्हें स्थानांतरण की अनुमति नहीं है। यद्यपि, नवविवाहित महिला कम्प्यूटर शिक्षकों और उन षिक्षकों, जो स्वंय या उनके जीवनसाथी किसी जानलेवा बीमारियों से पीडित हैंय को मामले दर मामले आधार पर उन स्कूलों मे समायोजित करने हेतु विचार किया जाता है, जहॉ पर कम्पयूटर लैब क्रियाशील हों और कोई कम्प्यूटर शिक्षक कार्यरत न हों।

.....

To Set-UP the solar Panels on the Tubewells

***590. Shri Parminder Singh Dhull :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the government to set up the solar panels on the tubewells of the farmers in the state; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां, श्रीमान जी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा किसानों को सौर ऊर्जा पम्प दिए जाने की एक योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में 750 सौर ऊर्जा पम्प लगाये गए है।

.....

To Set up Yoga Schools

591. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Sports and Youth Affairs Minister be pleased to State:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up ten Yoga schools in each assembly constituency in the state; and

(b) if so, the time by which the above said Yoga Schools are likely to be set up togetherwith the details thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) लागू नहीं।

.....

New C.N.G Buses in the State

593. Shri Parminder Singh Dhull: Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to purchase new C.N.G. Buses in the state; if so, the details thereof?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : नहीं श्रीमान जी।

सरकार द्वारा राज्य में नई सी.एन.जी. बसों को खरीदने का कोई प्रस्ताव विचाराधिन नहीं है।

राज्य परिवहन, हरियाणा ने वर्ष 2006 से 2010 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालन हेतू 250 बसों का अधिग्रहण किया था जो निम्न प्रकार से हैः –

क्र0सं0	अवधि		टाटा मोटॅर्स	अशोक लैलेंड	कुल संख्या
1	01.04.2006	31.03.2007	शुन्य	80	80
2	01.04.2007	31.03.2008	06	36	42
3	01.04.2008	31.03.2009	49	58	107
4	01.04.2009	31.03.2010	15	06	21

उपरोक्त के अतिरिक्त हरियाणा राज्य परिवहन, गुरूग्राम द्वारा वर्ष 2007–08 में शहरी बस सेवा संचालित करने हेतू 50 बसें टाटा मार्कोपोलो सी.एन.जी. वातानुकुलित ली गई थी।

इसके पश्चात राज्य परिवहन, हरियाणा द्वारा कोई भी सी.एन.जी. बस की खरीद नहीं की गई। हरियाणा राज्य परिवहन की आगारों में मौजूदा सी.एन.जी. बसों की संख्या निम्न प्रकार से हैः –

1. हरियाणा राज्य परिवहन, फरीदाबाद 34 बसें
2. हरियाणा राज्य परिवहन, दिल्ली 26 बसें
3. हरियाणा राज्य परिवहन, सोनीपत 20 बसें
4. हरियाणा राज्य परिवहन, पानीपत 16 बसें
5. हरियाणा राज्य परिवहन, रिवाड़ी 02 बसें

कुल संख्या 98 बसें

उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य परिवहन, हरियाणा द्वारा 150 बसें पूर्ण रूप से निर्मित भारत सरकार की जेएन एनयूआरएम योजना के तहत फरीदाबाद शहरी बस सेवा में संचालन हेतू खरीदी गई थी। इन बसों की प्राप्ती दिसम्बर, 2009 से प्रारम्भ होकर 2012 तक हुई। जेएन एनयूआरएम योजना के तहत खरीदी गई बसों का विवरण निम्न प्रकार से हैः –

1. अशोक लैलेंड़ लो फ्लोर सी.एन.जी. बसें जिसमें 30 बसें वातानुकुलित भी हैं। 115
2. लो फ्लोर वॉल्वो वातानुकुलित 15
3. स्वराज माज़दा अवातानुकुलित मीनी बसें (सी.एन.जी.) 20

कटौती प्रस्तावों से संबंधित मामला उठाना

11:00 बजे

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने और श्री कुलदीप शर्मा जी ने बजट ऐस्टीमेट्स पर अपने–अपने कट मोशंज़ दिए थे, उनका क्या फेट है यह हमें बताया जाये।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपके ये कट मोशंज़ डिस–अलाऊ कर दिये गये हैं क्योंकि नियमानुसार आपको इनको दो दिन पहले विधान सभा में देना चाहिए था लेकिन आपने इन्हें निर्धारित समय पर विधान सभा में नहीं दिया है।

———————

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, इस सत्र की अवधि के दौरान हमारे कुछ जवान शहीद हुये हैं। मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह सदन 13 मार्च, 2018 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले में शहीद हुये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 9 वीर जवानों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

इसी प्रकार से यह सदन 7 मार्च, 2018 को नक्सली हमे में शहीद हुए सहायक कमांडैंट गजेन्द्र सिंह, गांव खरक कलां, जिला भिवानी के दुःखद एवं असामयिक निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर इन्हें शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखे हैं मैं भी अपने आपको उनके साथ जोड़ता हूं तथा शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण किया जाये।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण किया।)

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं/विभिन्न मामले उठाना

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण इश्यूज पर कालिंग अटेंशन नोटिस दिये हुये हैं उनका क्या हुआ? आप उन पर चर्चा करवाएं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप इन बातों को बजट पर डिस्कशन के समय बोल लेना।

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने कट मोशन पर आपके पास लिखित में नोटिस दिया था जिसको आपने डिस्अलाऊ कर दिया है। इसी प्रकार से यह सरकार हरियाणा में नम्बरदारों को ठिकाने लगाने की साजिस कर रही है, सरकार हरियाणा में नम्बरदारों को हटाने का प्रयत्न कर रही है। हरियाणा में सरकार नम्बरदारों के लिए उम्र निर्धारित करने जा रही है कि कोई भी नम्बरदार 60 साल से ऊपर न हो। जब मंत्री 70–80 साल के हो सकते हैं तो नम्बरदार क्यों नही हो सकता है। नम्बरदार एक जिम्मेदार पद पर होता है और वह लोगों की तरह–तरह से सेवा करता है। नम्बरदार को समाज का एक जिम्मेदार आदमी माना जाता है। सरकार को नम्बरदारों को हटाने की बजाय उनका मानदेय बढ़ाना चाहिए तथा उनकी हिफाजत की जानी चाहिए। यह सरकार नम्बरदारों को हटाने की साजिश कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह नम्बरदारों के पीछे क्यों पड़ी हुई है? एक तरफ तो हुड्डा साहब के पीछे पड़ी हुई है और दूसरी तरफ नम्बरदारों के पीछे पड़ी हुई है।(हंसी)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं अतिथि अध्यापकों के बारे में बोलना चाहती हूं। सरकार ने अतिथि अध्यापकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का वायदा किया था लेकिन आज उनको सरकार के वायदे के मुताबिक वेतन नहीं दिया जा रहा है। जहां पर अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी उनको वहां से ट्रांसफर करके दूसरे जिलों में भेजा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि अतिथि अध्यापकों के साथ जो ज्यादती हो रही है वह न हो और उनको पूरा वेतन मिले।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कैंसर की बीमारी की रोकथाम के लिए एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया था लेकिन उसको आपने अलाउ नहीं किया जबकि कैंसर की बीमारी तो आज महामारी बन चुकी है ।

श्री अध्यक्ष : परमेन्द्र जी, जब आप बजट पर बोलेंगे तब आपके कालिंग अटैंशन मोशन को उस चर्चा में शामिल कर लेंगे । उस समय आप अपनी बात सरकार के सामने रख लेना ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी मेरा एक अलग मुद्दा है। हमारा एक मात्र कैंसर इंस्टीच्यूट रोहतक में है । सरकार उस इंस्टीच्यूट की तरफ ध्यान दें क्योंकि वह बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है । मैं उसको सदन के सामने हाई लाईट करना चाहता था क्योंकि कैंसर की बीमारी के लिए हरियाणा में वही एक मात्र इंस्टीच्युट है इसलिए सरकार को उसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए । इसके अलावा मैंने एक्सटैंशन लैक्चरर के बारे में भी कालिंग अटैंशन मोशन दिया था । जब एक्सटैंशन लेक्चररर्ज अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के पास आते हैं तो उनकी पिटाई की जाती है । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उनकी डंडों से पिटाई न करके उनको समान काम और समान वेतन दिया जाए । मैंने यह भी नोटिस दिया हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वह एक्सटैंशन लैक्चरर के लिए लागू किया जाए । इसी के साथ मैंने कर्मचारियों के लिए भी एक नोटिस दिया हुआ है । हमारे प्रदेश के जो पुलिस कर्मचारी हैं जिनके बारे में श्री अनिल विज जी जब हमारे साथ विपक्ष में बैठते थे तो वे भी बार–बार इनके बारे में आवाज उठाते थे लेकिन आज उन्हीं कर्मचारियों की बात सुनी नहीं जा रही है । आज हमारे कर्मचारियों की बड़ी दयनीय स्थिति है ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो रोहतक के कैंसर के सैंटर का मामला उठाया है । मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वहां पर वह सैंटर बड़ा दुरूस्त चल रहा है और उसको अपग्रेड करने की कोशिश भी की जा रही है । हम जल्दी ही वहां पर लीनयर एक्सीलेटर भी लगाने जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने फैसला किया है कि कैंसर के सभी रोगियों को जहां–जहां पर भी वे भर्ती हैं उन सभी अस्पतालों में उनको मुफ्त दवाई दी जाएगी । इसलिए उसकी टैस्टिंग के लिए और उसमें हम कहां–कहां, क्या–क्या सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं उसके लिए विभाग ने एक कमेटी बनाई है और वह कमेटी उस पर जल्दी ही विचार कर रही है । कैंसर के जो इतने केसिज बढ़ रहे हैं उसके बारे में हम खुद भी चिन्तित हैं ।

श्री अध्यक्ष : परमेन्द्र जी, आपकी बात का जवाब तो मंत्री जी ने दे दिया है ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप अपने प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन मान देकर उनका मान सम्मान बढ़ाएं क्योंकि उनकी स्थिति दयनीय है । उनकी हालत ये है कि दिल्ली में

तो पुलिस कर्मियों को 6500 रूपये एच.आर.ए. मिलता है और हमारे हरियाणा में पुलिस कर्मियों को 1200 रूपये एच.आर.ए. मिलता है । उनकी राशन मनी में भी काफी फर्क है । अध्यक्ष महोदय, आपसे भी मेरा निवेदन है कि जो हमारे विधान सभा के कर्मचारी हैं वे पंजाब विधान सभा के कर्मचारियों से कम वेतन ले रहे हैं । आप कह रहे हैं कि हमारा बजट पंजाब सरकार से अच्छा है तो कम से कम अपने विधान सभा के कर्मचारियों की हालत तो सुधार लीजिये । आप अपने कर्मचारियों की तरफ ध्यान देकर उनके लिए अपने बजट में प्रावधान कीजिये ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद । यहां सदन में हमारे सैनिकों से संबंधित बहुत जिक्र हुआ है । एक पूर्व सैनिक लैफटीनैंट जनरल डी.पी. वत्स जी को राज्य सभा का सदस्य बनाया गया है । मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव मातनहेल जोकि मेरा स्वयं का गांव है वहां तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैनिक स्कूल बनाने के लिए घोषणा भी की थी । उस समय की सरकार के समय में वर्ष 2002 में मातनहेल गांव द्वारा 273 एकड़ जमीन सैनिक स्कूल बनाने के लिए दी गई थी । उस समय वर्ष 2003 में डिफैंस मिनिस्टर और दि दैन चीफ मिनिस्टर ने वहां पर फाउंडेशन स्टॉन भी रखा था और बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5.8.2015 को यह घोषणा की थी कि मातनहेल गांव में एक सैनिक स्कूल खोला जाएगा । गांव मातनहेल यह नहीं है कि वह मेरा गांव है बल्कि वहां पर सैनिक व पूर्व सैनिक काफी रहते हैं और आस–पास के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा सैनिक हैं । इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी भी घोषणा कर चुके हैं । उसके बाद जनरल डॉ0 दलबीर सिंह सुहाग जी जब वे इण्डियन आर्मी के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में आए थे तब उन्होंने भी घोषणा की थी कि यहां पर सैनिक स्कूल खोला जाएगा । इसके बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वह हमें बताएं कि 14.12.2014 को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे मातनहेल गांव में जब मेरे विधान सभा क्षेत्र में जलसा किया गया था तो उस दौरान भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि मातनहेल में थर्ड सैनिक स्कूल खोल दिया जाएगा । उसके बाद 4.6.2016 को एक्स सर्विस मैंन की रैली में भी जनरल दलबीर सिंह सुहाग जी ने कहा कि हम इसी वर्ष से इस स्कूल में कक्षाएं शुरू करवा देंगे । उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23.7.2017 को घोषणा की कि इस सैनिक स्कूल की कक्षाएं इसी साल शुरू कर दी जाएंगी । अध्यक्ष महोदय, यहां पर जब सरकार की उपलब्धियों का पत्र

जारी किया तो उसमें भी यह लिखा गया कि मातनहेल में सैनिक स्कूल खोला जाएगा । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जो मामला तकरीबन 15 साल से पैंडिंग पड़ा है । उसके लिए हम लोगों ने 273 एकड़ से ज्यादा जमीन दे रखी है । वहां पर मिल्ट्री कैन्टीन भी है और इस समय हमारा गांव राष्ट्रीय स्तर पर पहले नं0 पर आया है । अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि उस स्कूल में कक्षाएं कब तक शुरू कर दी जाएंगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, आदरणीय बहन गीता जी भुक्कल ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि गांव मातनहेल में सैनिक स्कूल खोलने का मामला पिछले 15 सालों से लटका हुआ है, के सदर्भ में बताना चाहूंगा कि कल भारत सरकार की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई है, इस मीटिंग में हरियाणा सरकार की तरफ से मातनहेल गांव में सैनिक स्कूल खोलने की पैरवी करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।

श्रीमती नैना चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हमारे डबवाली शहर में एक अनाज मंडी है । हैफेड के चेयरमैन ने शायद आदेश जारी किए हुए है कि सरसों की फसल की खरीद डबवाली शहर की अनाज मंडी में नहीं होगी, जिसकी वजह से डबवाली के लोगों को बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करते हुए डबवाली के लोगों की समस्या को दूर किया जाये।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नैना जी का एक पत्र भी मुझे इस संदर्भ में पहले मिल चुका है और मैने पत्र मिलते ही डबवाली में सरसों की फसल की खरीद के आदेश कर दिए हैं।

श्री जय तीर्थ: अध्यक्ष महोदय, मेरा गांव बड़खालसा है और यह एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव है जिसने गुरू तेग बहादुर के लिए कुर्बानी देने का काम किया था और इस गांव के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी भी अच्छी तरह से जानते है। अध्यक्ष महोदय, पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस गांव में आए थे और लिंगानुपात के क्षेत्र में तथा लड़कियों के पालन पोषण में बेहतर परफोरमेंस के आधार पर इस गांव के प्रथम स्थान पर आने पर, गांव के नाम 11 लाख रूपये का इनाम देकर आए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के

नोटिस में लाना चाहूंगा कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से आए हैं, उस दिन से इस गांव का रास्ता बंद कर दिया गया है और अब इस गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं है और प्रशासन की तरफ से जो रास्ता प्रपोज किया जा रहा है वह कई किलोमीटर लंबा है और बहुत ही सुनसान है। इस सुनसान रास्ते से गांव की लड़कियां व महिलायें आने–जाने से डरती हैं। अतः बड़खालसा गांव की डिमांड है कि यहां पर जो के.जी.पी. का रास्ता बनाया जा रहा है उसमें से यदि इस गांव के लिए अंडर पास दे दिया जाये तो यह सरकार की तरफ से दी जाने वाली बहुत बड़ी राहत की बात होगी और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मेरे बढ़खालसा गांव की इस मांग को जरूर पूरा करेंगे।

श्री रणबीर गंगवाः अध्यक्ष महोदय, पिछले दो महीने से नहरी पानी के लिए हिसार के किसान धरने पर बैठे हुए है। आज सदन में मेरा प्रश्न लगा था लेकिन मेरे प्रश्न का नम्बर नहीं आया। कोई बात नहीं नम्बर नहीं आया लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन में यह जरूर बताना चाहूंगा कि नहरी पानी के लिए धरने पर बैठे इन किसानों से हमारे कृषि मंत्री महोदय का मिलना तो दूर की बात, यह इन किसानों से मिलने से बचने के लिए रात को 1 बजे यहां से होकर गुजरे। बाद में इन किसानों को यह आश्वासन दिया गया कि इनको महीने में दो बार नहरी पानी दिया जायेगा लेकिन जब मैंने इन किसानों के संबंध में सदन में प्रश्न लगाया तो सरकार की तरफ से जवाब प्राप्त हुआ है कि इस विषय पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे इन किसानों को पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से केवल मात्र किसानों को बहकाने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि किसानों की समस्या की तरफ उचित ध्यान दिया जाये।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि मैं रात को एक बजे गया और इसका कारण यह था कि कुछ लोगों ने षड़यंत्र किया था कि ओम प्रकाश धनखड़ जोकि किसानों को अपना देवता मानता है, का किसानों के साथ टकराव करवाओ और इसी षड़यंत्र के तहत हिसार में स्थित यूनिवसिर्टी के गेट पर योजनापूर्वक किसानों को धरने पर बिठाया गया। मुझे लगा कि किसान मेरा देवता है और मेरा और किसानों का टकराव नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैं वहां से रात को 1 बजे गुजरा। इसकी वजह से उन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई जिन्होंने यह सब षड़यंत्र रचा था। यह किसान बाद में मुझसे मिलने आये और बाद

में यह माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात की जानकारी है और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि यहां पर जो बरवाला लिंक नहर है उसके लिए 4 करोड 65 लाख रूपए दिए गए हैं। राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने फोन करके इस काम को रूकवा दिया था। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री महोदया से इस संबंध में बात की थी और पत्र भी लिखा था। उस लिंक में 1200 क्यूसिक पानी आ रहा है उसकी जगह 1400 क्यूसिक पानी आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की सोच है कि माननीय सदस्यों के इलाकों में ज्यादा से ज्यादा पानी आए, उसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से टकराने वाली सरकार नहीं है बल्कि किसानों की पूजा करने वाली सरकार है। यह किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है। किसानों को पानी ज्यादा कैसे मिले? इसके लिए काम कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेक चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक इशू है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण देव कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, पानी के लिए टकराव नहीं होने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेक चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पानी का इशू मेरे अकेले का ही नहीं अपित 14 माननीय सदस्यों का भी है। (शोर एवं व्यवधान) हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है, उसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह मेरे अकेले इलाके की बात नहीं है, इसमें चाहे सिरसा, रोहतक, यमुनानगर और हिसार वाले हों। सभी लोग 20 साल से पानी के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 20 साल से ही लगभग 14 विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लोग नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन पानी के लिए किसी भी सरकार ने कोई भी ठोस प्रबंध नहीं किए हैं। हर सैशन के अंदर यह आवाज उठती है कि हमें दिल्ली की तरफ से गंदा पानी मिल रहा है। लेकिन आज तक सदन की तरफ से कोई भी कम्पलीट जवाब नहीं दिय जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, दक्षिण हरियाणा के सभी माननीय सदस्यगण जो दिल्ली की तरफ से सीवरेज का गंदा पानी मिल रहा है उसके बारे में सदन से आश्वासन चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, हमें साफ पानी मिलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या दक्षिण हरियाणा, हरियाणा प्रदेश का हिस्सा नहीं है?

पंडित मूल चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यमुना नदी, जिसका पानी फरीदाबाद, पलवल, गुरूग्राम, मेवात आदि क्षेत्रों को मिलता है, उसके लिए बजट में एक भी पैसा नहीं रखा गया है। एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा भी हमेशा बना रहता है। आज पानी की जिन्स से फसल खाने से, सब्जी खाने से, दूध और पानी पीने से कैंसर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, वहां के एरिया में भी लोग ही बसते हैं। क्या सदन ने एस.वाई.एल. नहर की तरह यमुना नदी के बारे में भी कभी कोई बात सदन में गंभीरता से करी है? अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर का पानी तो पता नहीं कब मिलेगा लेकिन हमें इस गंदे पानी से छुटकारा दिलवाईए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेक चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमें कम्पलीट जवाब चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी की एक ही बात है। (शोर एवं व्यवधान)

पंडित मूल चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे 14 विधायक चाहे वे मेवात, गुरूग्राम या फरीदाबाद जिले के हैं, सभी माननीय सदस्यों की यही डिमाण्ड है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज सदन को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : केहर सिंह जी व शर्मा जी, आप अपनी–अपनी सीट पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बहुत ही मार्मिक सवाल है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल व नूंह जिले को जो पानी मिलता है उसका बी. ओ.डी./ सी.ओ.डी. लेवल बहुत ऊँचा है। दिल्ली सरकार ने कोई भी वादा नहीं निभाया है, चाहे उस मीटिंग में मैं गया या माननीय मुख्यमंत्री महोदय गए। हर बार ओखला बैराज से जो पानी की क्वालिटी को लेकर मुद्दा रहता है, उसका सवाल मीटिंग में उठाया जाता रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार के कान पर जूं तक नहीं

रेंगती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करता हूँ कि आगरा कैनाल के इशू को लेकर भी हम सबको मिलकर दिल्ली सरकार की तरफ मार्च निकालना चाहिए (शोर एवं व्यवधान) दिल्ली सरकार पानी के लिए जिम्मेवार है। दिल्ली सरकार ने ही पानी की सफाई करनी है। अध्यक्ष महोदय, गुरूग्राम, फरीदाबाद, पलवल व नूंह जिले के प्रतिनिधियों को साथ लेकर एक कमेटी गठित करके दिल्ली की तरफ निकाले गए मार्च में भाग लेकर दिल्ली सरकार को मजबूर करेंगे कि इस पानी को ठीक करें। पानी को ठीक करने का सिस्टम हरियाणा सरकार के हाथ में नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के हाथ में है और पानी को सफाई करने की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है । पानी को गंदा करने का काम दिल्ली सरकार कर रही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, पानी को साफ करने की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है और कंट्रोल उत्तर प्रदेश के हाथ में है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सीमा त्रिखा : अध्यक्ष महोदय, गंदे पानी से कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। (शोर एवं व्यवधान) दक्षिण हरियाणा का पानी सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से मिलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ललित नागर : अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके के साथ अन्याय हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सीमा त्रिखा : अध्यक्ष महोदय, पानी की व्यवस्था ठीक करनी ही पड़ेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, इस गंदे पानी को पीने से लोगों में तरह–तरह की बीमारियां फैल रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, पानी को साफ करने की जिम्मेवारी भी सरकार की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यगणों से निवेदन है कि एक–एक करके ही सदन में बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का 10 साल लगातार राज रहा है और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य इस मुद्दे पर कुछ भी काम नहीं करवा पायें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पानी के लिए लड़ाई लड़ रही है और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वासन देता हूँ कि दिल्ली की तरफ से जो गंदा पानी आ रहा है उस पानी को ठीक करवायेंगे। (शोर एवं व्यवधान) कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को तो इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत जरूरी बात सदन को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में थोड़ा सा पानी अमोनिया का चला गया था, इस ऐवज में दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार की पेशी लगवाई और मुलजिम के तौर पर हरियाणा सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर दिया था। दिल्ली सरकार 37 नालों का पानी बिना ट्रीट किए हुए नहर में डाल रही है। अध्यक्ष महोदय, आगरा कैनाल के माध्यम से गंदा पानी हमें मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, पहली बात यह है कि उसके National Green Tribunal (N.G.T) ट्रीटमैंट के लिए इंजीनियर ने बार–बार कहा हुआ है लेकिन वह आदेश लागू नहीं हो रहा है। दूसरी हम सब विधायकों की मांग यह है कि जब तक एस.वाई.एल. नहर का निर्माण नहीं होता तब तक वर्ष 1994 में जून के महीने में जो प्रदेश उपलब्ध पानी का दोबारा बंटवारा हरियाणा सरकार ने किया था, उसे लागू किया जाये। आज विधान सभा के द्वारा एक कमेटी बनाई जाने का भी आश्वासन दिया गया है। पानी के लिए हम यह नहीं कहते कि हमें पूरा हक मिले लेकिन प्रोरैटा बेसिज़ पर जितना पानी हमारे हक का है, वह हमें मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, क्या गुरूग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल आदि दक्षिण हरियाणा के लोग हरियाणा का हिस्सा नहीं है ? सर, गुरूग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिलों के लोग भी हरियाणा प्रदेश का ही हिस्सा है। मेरे पास हरियाणा सरकार की चिट्ठी है जिसमें हथिनी कुडं बैराज से गुड़गांव कैनाल के लिए 600 क्यूसिक पानी एलॉट है। मैं यह रिकार्ड प्लेस कर दूंगा और पहले भी मैंने यह रिकार्ड प्लेस किया है। हमारे जिले को हथिनी कुंड बैराज से एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा है। इसलिए विधान सभा की एक कमेटी बनाकर मामले की जांच करवायी जाए और हमारे हिस्से का पानी दिलवाया जाए या सरकार यह बात कह दे कि पानी नहीं मिलेगा। इस बात

को क्लीयर कर दें। हम अपने हिस्से के पानी के हक की लड़ाई सड़कों पर भी लड़ेंगे, दिल्ली में भी लड़ेगें और अपने हिस्से के पानी के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। (शोर एवं व्यावधान) सर, यदि आपकी सहमति हो तो मैं यह लैटर सदन के पटल पर रख देता हूं।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

(*इस समय श्री जाकिर हुसैन विधायक द्वारा संबंधित लैटर सदन के पटल पर रखा गया।)

From

Financial Commissioner & Secretary to Govt.
Haryana Irrigation & Power Department,
Chandigarh.

To

The Engineer-In-Chief,
Irrigation Department, Haryana,
Chandigarh.

Memo No. 22/9/94-W
Dated, the 13th June, 1994

Subject:- Distribution of Yamuna, Sutlej and Surplus Ravi-Beas waters amongst various Irrigation Projections in Haryana.

Ref:- Your U.O. No.101/Reg(Camp Delhi), dated-11.06.1994

Government approval is hereby accorded to the distribution of surface waters amongst various existing Canal command as tabulated below:-

Sr. No.	Name of the scheme	Water requirement	Proposed allocation of water			Total
			Sutlej	Yamuna	Ravi Beas	
1.	Bhakra Canal System	4.63	4.40	-	0.23	4.63
2.	WJC System	3.36	-	2.97	0.39	3.36
3.	JLN Lift Scheme	1.36	-	0.45	0.91	1.36
4.	Loharu Lift Scheme	0.66	-	0.22	0.44	0.66
5.	Sewani Lift Scheme	0.48	-	0.13	0.35	0.48
6.	Jui Lift Scheme	0.20	-	0.05	0.15	0.20
7.	Gurgaon Canal	0.49	-	0.37	0.12	0.49
8.	Nagale Lift Scheme	0.09	-	-	0.09	0.09
	Total	11.27	4.40	4.09	2.68	11.27

The above distribution is provisional for the purpose submission to Central Water Commission, Govt. of India to connection with sanction of water resources Consultation Project.

Sd/-
Joint Secretary/Irr. & Power,
Govt. of Haryana, Chandigarh

In 1961, 7.2 MAF surplus Ravi Beas water in Joint Punjab was approved for utilization for various schemes. In this Gurgaon Canal was allotted 0.307 and Sohna lift scheme–I was allotted 0.133 MAF. Thus, total 0.440 MAF water was allotted to Mewat region. Subsequently in 1966 Haryana was carved out of Punjab. But due to non-construction of SYL Canal this allotted water never reach Mewat. Somehow, the Govt. created irrigation facility in the Mewat region in the year 1962 by constructing Gurgaon Canal network and water was provided from Yamuna downstream Okhla Barrage from Agra Canal.

Thereafter, Govt. of Haryana distributed the Yamuna, Satluj and Surplus Ravi Beas water in 1994 and Gurgaon Canal was allocated 0.49 MAF out of which 0.37 MAF is allocated from Yamuna and balance 0.12 MAF from Ravi-Beas water. Mewat region is yet to get Ravi Beas water.

Hence, since inception Gurgaon Canal is getting water from Yamuna downstream Okhla in passage of time after 1980 Yamuna waters below Tajewala now Hathnikund has practically become Nil as water is utilized in Canals of Haryana and Uttar Pradesh. At Okhla what we received in Yamuna is practically sewage of Delhi except few days of rainy season when water is large quantity is released downstream Hathnikund which received Delhi.

From above it is conclusive that Mewat region is not getting fresh water from any river but is receiving highly polluted sewage of Delhi which neither can be used for drinking purpose (for human as well as for cattle) nor for agricultural purpose.

श्री टेक चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र की बात को नहीं सुना जा रहा है।

श्री अध्यक्षः जाकिर जी, आपकी बात पूरी हो गयी है और श्री टेकचन्द शर्मा जी का भी पानी को लेकर ही प्रश्न था। आप सभी माननीय सदस्य बैठ जाएं। टेकचन्द जी, आपकी बात का माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं (शोर एवं व्यावधान)।

श्री नसीम अहमद: अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में गन्दा पानी आ रहा है। (शोर एवं व्यावधान) हमारे हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा है (शोर एवं व्यावधान)।

श्री अध्यक्षः नसीम जी, आपका भी पानी का मुददा सेम है। इसलिए आपकी बात को भी जाकिर जी की बात के साथ जोड़ दिया जाएगा (शोर एवं व्यावधान)।

श्री उदयभानः अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें। (शोर एवं व्यावधान)

श्री अध्यक्षः उदयभान जी, प्लीज आप बैठ जाएं (शोर एवं व्यावधान)।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, उपलब्ध पानी के दोबारा बंटवारे के लिए सरकार ने जो सन् 1994 में फैसला किया था उस फैसले को लागू किया जाए। (शोर एवं व्यावधान)।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, हमारे फरीदाबाद जिले में सीवरेज का गंदा पानी आ रहा है (विघ्न)।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मेवात फीडर कैनाल बना दी जाए, जिससे पूरे इलाके को पानी मिल जाएगा (शोर एवं व्यावधान)।

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। अगर आप बैठेंगे नहीं तो माननीय मंत्री जी कैसे जवाब देंगे। क्या आप केवल अपनी बात नोट करवाना चाहते हैं या फिर उस समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं। आपका उददेश्य क्या है ? आप सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, सभी दलों के माननीय विधायक पानी के मुद्दे पर अपनी बात कर रहे हैं। आगरा कैनाल और यमुना कैनाल के पानी के बारे में एक ही मुद्दा उठाया है। माननीय मुख्य मंत्री जी को जवाब देना चाहिए (शोर एवं व्यावधान)।

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी ने पानी की समस्या के प्रश्न के बारे में पहले ही जवाब दे दिया है। दलाल साहब, आपकी बात मान ली है, माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का जवाब दें (शोर एवं व्यावधान)।

प्रोफेसर रविन्द्र बलियालाः अध्यक्ष महोदय, मेरे रतिया हल्के में पानी की समस्या है (शोर एवं व्यावधान)।

श्री अध्यक्षः प्रोफेसर साहब, माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। प्लीज आप बैठ जाएं।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, पानी का विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सदन को भी पानी की समस्या की चिन्ता है। खासकर उन क्षेत्रों को चिन्ता होना स्वाभाविक है जो पानी की समस्या से प्रभावित क्षेत्र हैं और पूरे सदन को भी इस बात की चिन्ता होना स्वाभाविक है कि हरियाणा के जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है उन संबंधित क्षेत्रों में पानी की कठिनाई को दूर किया जाए। यह पानी का विषय कई वर्षों से में लम्बित चला आ रहा है और सरकार इस मामले को सुलझाने के लिए लगातार प्रयासरत है। पानी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कृत्रिम तरीके से बना सकें बल्कि पानी तो प्राकृतिक रिर्सोसिज से ही आता है और इस तरह के पानी के मामले कोर्टस में चल रहे हैं। हम पानी की समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। पलवल, फरीदाबाद, मेवात और गुड़गांव जिले का कुछ हिस्सा भी पानी की समस्या से प्रभावित हैं। इस बारे में अगर सदन सहमत हो तो मेरा एक सुझाव है कि माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में इन जिलों के सभी विधायकों की एक कमेटी बना दी जाए और यह कमेटी पानी की समस्या का समाधान करेगी। यह पानी का मामला अन्तर्राज्यीय विषय है।

श्री जाकिर हुसैन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरे जिले का पानी का मामला अन्तर्राज्यीय नहीं है। हरियाणा के अन्दर का ही मामला है (शोर एवं व्यावधान)।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, कुछ पानी के मामले अन्तर्राज्यीय हैं तथा कुछ मामले प्रदेश के अन्दर के ही हैं। गन्दे पानी का मामला दिल्ली से साथ जुड़ा हुआ है।

श्री करण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद जिले में गन्दा पानी आता है। इसलिए दिल्ली सरकार के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवायी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, माननीय मुख्य मंत्री जी आपके जिले की ही बात कर रहे हैं। आप बैठ जाएं।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. दर्ज करवाने से पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए जल्दी ही एक मीटिंग की जाएगी और इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार को एक आवेदन करना पड़ेगा। यह विषय पहले से भी चल रहा है कि दिल्ली के गन्दे

पानी को कैसे ट्रीट करके यमुना में डाला जाए। इसके अतिरिक्त वृंदावन के लोगों का कहना है कि हमारी तरफ यमुना का गंदा पानी आता है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर उस गंदे पानी को साफ किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि यमुना में फरीदाबाद और दिल्ली का जो गंदा पानी जाता है, उस पानी को साफ करके यमुना में डाला जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, वह साफ पानी ओखला बैराज से आगरा नहर में आए, इसके लिए मैं श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करूंगा और उसके बाद एक मीटिंग करके उसके आधार पर आगे का काम किया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस कमेटी में जो वर्ष 1994 में उपलब्ध पानी का दोबारा बंटवारा हुआ था, का विषय भी कमेटी की मीटिंग में रखा जाए और 1994 के फैसले को इम्प्लीमैंट किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः ठीक है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

प्रदेश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शराब, अफीम, भुक्की, गांजा, स्मैक ड्रग की तेजी से अवैध बिक्री बारे

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री करण सिंह दलाल, विधायक द्वारा प्रदेश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शराब, अफीम, भुक्की, गांजा, स्मैक ड्रग की तेजी से अवैध बिक्री बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 27 प्राप्त हुई है, जिसे मैंने स्वीकार किया हैं। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक, श्री जसविन्द्र सिंह संधू, विधायक, श्री परमेंद्र सिंह ढुल, विधायक, श्री राम चन्द कम्बोज, विधायक, श्री बलवान सिंह, विधायक तथा श्री रविन्द्र बलियाला विधायक द्वारा भी इसी विषय से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 45 दी गई है जिसे मैंने समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 27 के साथ जोड़ दिया है। इसलिए ये सभी विधायक भी इस पर अपनी सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं। अब श्री करण सिंह दलाल विधायक जी अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें।

श्री करण सिंह दलालः स्पीकर सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे को उठाने का मौका दिया है। मैं अपनी कॉलिंग अटैंशन मोशन पढ़ रहा हूं:–

"Speaker Sir, I want to draw the kind attention of this august House towards a matter of great public importance that illegal sale of liquor/ Opium/ Bhukki/ Ganja /Smack drug is rampant in the State specifically in the rural areas and there is no check by the concerned authorities. Illicit and illegal liquor is openly sold even in small shops in villages all over the State which is spoiling the youth of the State due to which the youth is getting prone to these illegal activities for easy money and indulging in violence and other criminal activities like robbery, dacoity and sale of illicit weapons. The consumption of illegal and illicit liquor due to its easy availability is also effecting their health. The liquor mafia/ drug mafia product in connivance with concerned authorities are playing with the lives of young people which is jeopardizing the future of youth of State. It would not be surprising that the situation of youth of Haryana would get worse than of Punjab in case these illegal activities are allowed to go as is rampant now. I request the Government should make a statement in this regard in this august House."

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 45
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 27 के साथ संलग्न

श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक एवं पांच अन्य विधायकगणों ने इस महान सदन का ध्यान एक लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहा है कि आजकल हरियाणा के युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है । हमारे प्रदेश की सीमाएं कई प्रांतों से लगती है जैसे पंजाब, राजस्थान व यूपी । यहां के युवाओं में भूकी और दूसरी तरह के नशों का प्रचलन दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जा रहा है। इसका बड़ा कारण बेरोजगारी है, इससे युवाओं का भविष्य बिगड़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसी परिस्थितियों में प्रदेश के सदभाव, कानून व्यवस्था पर भी भारी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्रदेश सरकार को युवाओं के भविष्य के मध्यनजर तुरन्त प्रभावी कदम उठाकर उनको नशे की बीमारी से बचाएं और रोजगार प्रदान किया जाए जिससे कि लोगों का रोष और आक्रोश और अधिक न बढ़े । अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य देकर स्थिति स्पष्ट करे ।

वक्तव्य–

शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): स्पीकर सर, हमारे माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल, श्री अभय सिंह चौटाला और उनकी पार्टी के कई विधायकों ने इस संबंध में एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया है। स्पीकर सर, राज्य सरकार शराब, अफीम, चूरा पोस्त, गांजा, चरस, हिरोइन, स्मैक जैसे मादक पदार्थों की अवैध बिक्री तथा अवैध सेवन के मामले में अति गम्भीर है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि राज्य के सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा इन गम्भीर मामलों में उचित कार्यवाही नहीं की जाती। वास्तव में मादक पदार्थों की बिक्री तथा सेवन की राकथाम, अपराधियों की धर पकड़ और उन्हें दण्डित कराने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। युवा वर्ग को मादक पदार्थ से होने वाले नुकसान के बारे तथा उनकी ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए उन्हें शिक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके।

सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस तथ्य को अति महत्व दें कि मादक पदार्थों का प्रसार वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। सम्बन्धित विभाग किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की अवैध बिक्री, तस्करी और प्रयोग में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध त्वरित एवं अनुकरणीय कार्यवाही कर रहे हैं। प्राधिकारी वर्ग अवैध शराब और अवैध दवाइयों के उत्पादन पर सख्त निगरानी रख रहे हैं। अवैध उत्पादकों के खिलाफ विधि अनुसार सख्त कार्यवाही की जा रही है। सभी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को खत्म करने के लिए दिन–प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। इस सम्बन्ध में सभी जिलों को समय समय पर विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं। इसमें जो हमारे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के संलिप्त होने की बात है अभी दो केसिज में पुलिस स्टाफ को दस–दस साल की सजा हुई है।

इसके अतिरिक्त शराब तथा मादक पदार्थों की तस्करी को पकड़ने हेतु नियमित तौर पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। हाल ही में दिनांक 14–12–2017 से 15–01–2018 तक मादक पदार्थों के तस्करों, शराब की तस्करी, महिला विरुद्ध अपराधों की रोकथाम तथा धर–पकड़, सम्पत्ति विरुद्ध अपराधों की रोकथाम तथा धर–पकड़, तथा अतिवांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए एक

विशेष अभियान चलाया गया। इसी प्रकार मादक पदार्थों की धर–पकड़, अवैध हथियारों का पता लगाने, महिलाओं के साथ छेड़–छाड़ और यातायात नियमों की उल्लंघना, जैसे कि नशे की हालात में अथवा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना रोकने के लिए दिनांक 01–05–2017 से 15–05–2017 तक विशेष अभियान चलाया गया।

वर्ष 2017 के अन्तर्गत मादक शराब के व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ 14,668 आपराधिक मामले दर्ज करके तकरीबन सभी दोषियों को गिरफ्तार किया गया और तस्करी की शराब को कब्जे में लिया गया। इस समयावधि में तस्करी की 8,84,256 बोतल देशी शराब 38,702 बोतल अवैध शराब, 7,61,047 बोतल अंग्रेजी शराब, 73,910 बोतल बीयर बरामद की गई तथा अवैध शराब बनाने की 22 चालू भट्यिों को पकड़ा गया।

वर्ष 2017 के अन्तर्गत मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ 2247 आपराधिक मामले दर्ज किए गए जिनमें तकरीबन सभी दोषियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 86.28 किलो अफीम, 124.736 किलो चरस, 9549.65 किलो चूरा–पोस्त, 9.494 किलो स्मैक, 4367.881 किलो गांजा तथा 3.918 किलो हिरोइन बरामद की गई।

राज्य सरकार ने निम्नलिखित आपराधिक गतिविधियों के सघन अनुसंधान करने के लिए दिनांक 03–10–2017 को एक स्पैशल टास्क फोर्स स्थापित की है–

1. मादक पदार्थों और नशीली दवाई, अवैध हथियार और जाली मुद्रा के उत्पादन और आपूर्ति
2. छीना–झपटी, अपहरण और फिरौती के लिए अपहरण
3. अपराधियों के अन्दरुनी झगड़े/शूट आउट और ठेके पर हत्या
4. डकैती और लूट के संवेदनशील मामले
5. आतंकवाद और अन्तर्राज्यीय अपराध सम्बन्धित मामले।

एक पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को स्पैशल टास्क फोर्स का मुखिया बनाया गया है तथा इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थापित किया गया है।

प्राधिकारी वर्ग राज्य में मादक पदार्थों के विकार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न कर रहे हैं। जिन सरकारी कर्मचारियों की मादक

पदार्थों अथवा अवैध शराब के मामलों में संलिप्तता पाई जाती है उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य की युवा शक्ति को देश की उत्थान गतिविधियों में लगाने के उद्देश्य से एक नया प्रोग्राम 'पुलिस कैडिट कोर' आरम्भ किया जा रहा है। 'स्वस्थ शरीर–स्वस्थ दिमाग' के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले में सामुदायिक योजनाएं जैसे कि मैराथन दौड़, योग तथा राहगिरी का आयोजन किया जा रहा है। यह सभी कार्यक्रम युवा वर्ग द्वारा पसंद किये जा रहे हैं और वे अधिक से अधिक संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। राज्य सरकार अप्रैल माह में पुलिस विभाग में युवा वर्ग को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने के लिए जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी।

राज्य सरकार वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को लेकर अपनी जिम्मेवारी की ओर पूर्णतया सजग है और मादक पदार्थों और अवैध शराब के विकार को खत्म करने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। अपराधियों को हतोत्साहित करने तथा मादक पदार्थों और अवैध शराब की बिक्री, उत्पादन और तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले अपराधियों और शरारती तत्वों के खिलाफ सरकार नियमित प्रयत्न सुनिश्चित करती रहेगी। ऐसे तत्वों के खिलाफ अनुकरणीय, त्वरित, कठोर तथा विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। सरकार अवैध शराब और मादक पदार्थों से सम्बन्धित विकारों से युवा वर्ग को दूर रखने के लिए नियमित तौर पर शिक्षित करती रहेगी।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आज इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होने से हमारे प्रदेश में अच्छे नतीजे आयेंगे और हमारे युवाओं में जो नशे की लत बढ़ रही है उसको रोकने के लिए भी अच्छे सुझाव आयेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शराब पीने से शरीर खराब होता है और संस्कारों पर भी प्रभाव पड़ता है । शराब पीने से बहुत हानियां होती हैं । आज कल शराब पीकर गाड़ी चलाने का प्रचलन बहुत हो गया है । शराब पीकर गाड़ी चलाने से बहुत एक्सीडैंट होते हैं जिसमें कई–कई लोगों की मौत हो जाती है और गाड़ी चलाने वाले की खड़े–खड़े जमानत हो जाती है । मैंने इण्डियन मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के लिए प्राईवेट मैंबर बिल भी दिया था । इण्डियन मोटर व्हीकल एक्ट में धारा 304 ए में जमानत का प्रोविजन है जो कन्कैंट लिस्ट में आता

है । क्या स्टेट अपना कानून लाने का प्रावधान करेगी कि जो व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है और एक्सीडैंट करता है तो वह नॉन बेलेबल आफैंस होगा । यदि इस तरह के एक्सीडैंट में किसी की मौत हो जाये तो उसको ज्यादा संगीन अपराध माना जाये । यदि इस तरह का कानून बना दिया जायेगा तो इससे वाईड स्प्रैड असर पड़ेगा और लोग शराब पीकर गाड़ी चलाना छोड़ देंगे । हमारे प्रदेश के एक तरफ दिल्ली लगता है और दूसरी तरफ पंजाब लगता है । बड़े–बड़े शहरों में शराब पीकर गाड़ी चलाना आम रिवाज हो गया है इसलिए शराब पीकर एक्सीडैंट करने वालों के लिए नॉन बेलेबल आफैंस का कानून लाना जरूरी है । अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने स्वयं माना है कि नशे के कारोबार में पुलिस अधिकारी भी इनवोल्व रहते हैं । दिल्ली में शराब की होम डिलीवर पर कानून बना रखा है। हमारे प्रदेश में भी दो नम्बर में शराब की होम डिलीवरी होती है जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है क्योंकि जिन एल–1 और शराब के ठेकों में नार्म्ज से कम शराब बिकती है वहां पर चोरी से शराब होम डिलीवरी की जाती है और नशे के धन्धों में प्रदेश के नौजवान लिप्त हैं । कैप्टन अभिमन्यु जी बैठे हुए हैं मैं उनको कहना चाहूंगा कि जिन एल–1 और ठेकों पर शराब नार्म्ज से कम बिकती है उनकी जांच भी कराई जाये । इसमें हमारे प्रदेश के युवा और पुलिस स्टाफ भी शामिल है। क्या हमारे प्रदेश में भी दिल्ली की तर्ज पर होम डिलीवरी को लेकर स्पेशल कानून बनाया जायेगा ताकि शराब की चोरी रूक सके । इसके अतिरिक्त प्रदेश में आजकल बहुत सी ऐसी दवाईयां भी डाक्टर की प्रिसक्रीप्शन के बगैर बिकती हैं जिनका यूज स्कूली बच्चे नशे के रूप में करते है उसकी तरफ भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला सवाल यह है कि आज के दिन गांव–गांव में नौजवान बच्चों के हाथों में कंट्री मेड पिस्टल (कट्ट) बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है । इन कट्टों को दिखाकर राहगीरों को लूटा जा रहा है और जगह–जगह पर उत्पात किया जाता है। क्या सरकार पूलिस को हिदायतें जारी करेगी कि हर जिले में इन कंट्री मेड पिस्टल्ज (कट्टों) को पकड़ने के लिए कोई स्पेशल अभियान चलाया जायेगा । इललीगल शराब और इललीगल हथियार जो देशी कट्टे सप्लाई हो रहे हैं, जो आज गांवों के बच्चों के हाथों में पहुंच रहे हैं यह एक गम्भीर मामला है। इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि इसके लिए जिला स्तर पर एक अलग से कमेटी बना दी जाये जो

केवल इन्हीं मामलों की निगरानी करे। जो भी शिकायत आये उस पर उस कमेटी की राय ले ली जाये उसके बाद उसकी रिकमंडेशन के अनुसार कार्रवाई की जाये।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि शराब की तस्करी को लेकर हमारे विधायक साथी श्री करण सिंह दलाल ने जो चिन्ता जाहिर की है तथा शराब की वजह से एक्सीडैंट्स पर चिन्ता की है आज प्रदेश में यह एक गम्भीर प्रचलन बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाये जाने चाहिएं लेकिन आज प्रदेश में इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक विषय और है। हमारे क्षेत्र में स्मैक और चिट्टे की बहुत ज्यादा तस्करी होती है। हेरोइन भी बड़ी मात्रा में सप्लाई हो रही है। मेरी जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई तो मैंने उनके सामने इस बात का जिक्र किया था। मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात बताई थी। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में कुछ लोग गांवों में चिट्टा और स्मैक बेचने का काम करते हैं। मैंने उनको यह भी बताया था कि दड़बा गांव में तो 3 बच्चियां भी इस काम में संलिप्त हैं। मैंने उस घर का पता भी बताया था, उनके नाम भी बताये थे। मैंने एस.पी. के सामने भी जिक्र किया था, मैंने उनको यहां तक भी बताया था कि यह काम किन लोगों के माध्यम से होता है। आप उन लोगों पर शिकंजा कसो और उन लोगों को पकड़ो। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि जब कोई आदमी चिट्टा लेना शुरू कर देता है, वह इंजैक्ट करना शुरू कर देता है तो उसको होंशोहवाश नहीं रहता है। वह उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। किसी बच्चे ने अपने बाप को मार दिया तथा किसी बच्चे ने अपने भाई को मार दिया, आये दिन अखबारों में इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, जब तक इन मादक पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम नहीं होगी तब तक इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आज हमारे नौजवानों पर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। मुझे बताया गया है कि अगर किसी ने चिट्टे का इंजैक्शन एक–दो बार लगा लिया या स्मैक का सेवन दो–तीन बार कर लिया तो वह उसको छोड़ नहीं सकता है। अगर कोई उसकी इस आदत को छुड़वाना चाहे तो उसको रिहैबिलिटेशन सैन्टर में कई महीनों तक रखना पड़ता है और उसके बावजूद भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह उससे बाहर निकल पायेगा या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे गांव चौटाला का उदाहरण देना चाहूंगा।

मेरे गांव में इस प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन करने का कभी कोई प्रचलन नहीं था। लेकिन आज के दिन मेरे गांव में 15–16 साल से लेकर 25–26 साल तक के 60 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो इन मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। मैंने स्वयं पुलिस विभाग को इसकी जानकारी भी दी है कि मेरे गांव के बच्चे चिट्टा तथा स्मैक आदि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। आप अपने पुलिस विभाग से इसकी जानकारी ले सकते हैं। वहां पर पहले इस प्रकार के काम नहीं होते थे लेकिन अब आसपास के 20–30 गांवों में यह काम हो रहा है। यहां तक की संगरिया राजस्थान में जहां पहले यह काम होता था वे लोग राजस्थान को छोड़ कर अब हमारे गांवों की ढाणियों में आ कर बस गये हैं और वहीं से यह काम करते हैं। अब वहां पर इसका कारोबार शुरू कर दिया गया है। पिछले दिनों जब मैं अपने गांव में गया तो मैनें वहां उन तसकरों को देखा तो मेरे अपने गांव में पुलिस स्टेशन है जिसमें एक इंस्पेटर लेवल का अधिकारी बैठता है । उसके नीचे दो–चार एस.आई भी होंगे तथा ए.एस.आई भी होंगे । वहां पर प्रौपर एक थाना है। मैंने उन ऑफिसर्ज को बुलाकर कहा कि आप लोग इस थाने में बैठ कर करते क्या हो, जब पूरे गांव के सैकड़ों लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं तो आप उन लोगों को गिरफतार क्यों नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, बड़ी हैरानी की बात है कि जो इस तरह की तसकरी करने वाले लोग हैं वह थाने में जाकर के बैठते है और पुलिस उनको संरक्षण देती है। अगर ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता रहा तो आप मानकर चलो कि आप लोग यहां बैठकर के जिस देश के भविष्य के लिए चिन्ता करते हैं तो फिर आप उस भविष्य को 100 फीसदी बर्बादी की ओर ले जाने का काम कर रहे हो। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिन लोगों के बारे में मैंने एस.एस.पी. सिरसा से और आपसे से भी जिक्र किया है क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? क्या ये सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी ? अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर आप यह मानकर चलो कि आने वाले समय में इसके परिणाम और भी बुरे हो जाएगें। जो चैन स्नैचिंग के मामले हैं । वे मामले भी इसी से जुड़े हुए है क्योंकि जो नशा करने वाले बच्चे हैं जब उनको पैसा नहीं मिलता तो फिर वे ऐसे कामों को ही अन्जाम देते हैं जो मन्दिरों मे मूर्तियों की चोरी होती है, वह भी इसीलिए होती हैं क्योंकि जब उन्हें पैसा नहीं मिलता है तो फिर वे 100 फीसदी इस तरह का काम करते हैं । वे मन्दिरों की मूर्तियों को चोरी करके उन्हें बेचकर नशा खरीदने का काम करते हैं। क्या आप इसकी रोकथाम के लिए भी कोई कदम उठाओगे या अब

तक आपने इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं? यह ठीक है कि आपने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन यह मुद्दा पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है न कि केवल सिरसा जिले से, आप किसी भी जिले में जाओ और इस बात की पड़ताल करें तब आपको पता लगेगा कि हर जिले के अन्दर इस तरह के मुद्दे हैं। जिस प्रकार से पहले पंजाब नशे के लिए बदनाम हुआ करता था । आज हरियाणा प्रदेश इस मामले में उसी तरह से बदनाम है।

श्री अध्यक्ष : श्री जसविंद्र सिंह संधू जी, प्लीज शॉर्ट में अपनी बात कहना क्योंकि समय की कमी है ।

सरदार जसविंद्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, आज जिस नशाखोरी की बात को लेकर सदन में चर्चा हो रही है । यह किसी एक विधानसभा क्षेत्र या किसी एक जिले की बात नहीं है बल्कि इससे सारा प्रदेश और सारा सदन चिंतित है। अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरी यह प्रार्थना भी है और शिकायत भी है कि जिले के अधिकारियों के बिना यह कार्य संभव नहीं है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं मैंने बार–बार अपने जिले के पुलिस कप्तान के बारे में और अपने विधानसभा क्षेत्र के गांवों के बारे में और अपने समर्थक लोगों के बारे में व्यक्तिगत रूप से जाकर उनका नाम लेकर भी बताया है कि फलां–फलां गांव के फलां लोग यह काम कर रहे हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें । अध्यक्ष महोदय, उन लोगों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बात को लेकर के मेरा अपने पुलिस कप्तान से थोड़ा तनाजा भी हुआ है । जिसकी शिकायत मैंने आपके पास कर रखी है जिसका फैसला आपने करना है । अभी 2 महीने पहले हमारे पेहवा के दो एस.एच.ओ. बदले गए हैं। वहां जो पुराने एस.एच.ओ. थे वह हमारे जानकार भी थे, क्योंकि वह यहां पर पहले हवलदार भी रहे हैं, ए. एस. आई. भी रहे और आजकल इंस्पैक्टर हैं। जब वह मेरे पास आए तो मैंने उनको अपने गांव के लोगों की बकायदा नाम लेकर फिर शिकायत की कि यह वे लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। उन्होनें कहा ठीक है। उसके बाद वह उनको पकड़ने के लिए गये जिसमें उनके साथ लेडी पुलिस भी गई और उन्होंने वहां चलान भी किए हैं। जिस एक परिवार के एक व्यक्ति के बीसियों बार चालान हो चूके हैं फिर उसी एक व्यक्ति का चालान किया गया । लेडी पुलिस उस परिवार की महिलाओं को अपने साथ चौकी में लेकर गई तो वहां पर उनसे पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया गया । मैंने शाम को ही एस.एच.ओ. को फोन करके बता दिया कि फलां–फलां मामले में पैसे

लेकर लोगों को छोड़ दिया गया है । आप उनके खिलाफ लिखित कार्रवाई करके अपने पुलिस कप्तान को भेजिये लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरा अपना गांव गुमथला गढ़ू है, यहां का जो शराब का ठेकेदार था उसने एक्साईज डॅयूटी के पैसे नहीं भरे और इस प्रकार एक्साईज विभाग ने उनके ठेके रद्द कर दिए। इस बात को हुए दो महीने हो गए हैं लेकिन बावजूद इसके इस ठेकेदार की शराब की सभी दुकाने पहले की तरह चल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, एक शराब की दुकान जिसको गोदाम भी कह सकते हैं, जिसकी 50 फुट लंबाई और 50 फुट चौडाई है और जिसके अन्दर ट्रक भी सीधा चला जाता है वह पिहोवा पुलिस स्टेशन से महज 500 मीटर दूर है और इसी प्रकार गुमथला गढ़ू गांव में भी शराब की दुकानों से होर्डिंग तो हटा दिए गए हैं लेकिन वहां पर शराब लगातार बिक रही है और इन ठेकों में कारिंदे भी पहले की तरह ही काम कर रहे है। अगर सरकार की तरफ से यहां के पुलिस कप्तान या डी.सी. को सख्त हिदायतें दे दी जाये तो इन शराब की दुकानों पर अंकुश लग पायेगा अन्यथा यह ऐसे ही चलती रहेगी।

12:00 बजे

श्री परमेन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, मैं भी नशे के कारोबार विषय पर अपनी बात को आगे बढ़ाउंगा। आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सीनियर सैकेंडरी स्कूल्ज और कालेजिज के आस पास की दुकानों में नशे के विभिन्न प्रकार के आईटम्ज प्रचूर मात्रा में अवेलेबल हैं और नशा केवल मात्र शराब से ही किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है बल्कि दवाईयों के द्वारा भी नशा किया जाता है। आजकल तो स्कूल के बच्चे आयोडैक्स को ब्रैड के साथ मिलाकर भी खाते हैं जोकि शराब जितना ही नशा करती है और यही नहीं आजकल तो पैन की स्याही को मिटाने में प्रयोग किए जाने वाले सफेद कलर के कैमिकल को भी नशे में प्रयोग किया जाने लगा है। इसी प्रकार स्मैक जैसी चीज भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जींद में स्थित सीनियर सैकेडरी स्कूल्ज तथा गवर्नमैंट कालेजिज में स्मैक आसानी से उपलब्ध हो रही है। अध्यक्ष महोदय, जो अबेंडन सरकारी जमीन है या जो अर्बन एस्टेटस में अनडिवेलपड सैक्टर्ज हैं, वहां पर शाम को नौजवान प्रचूर मात्रा में नशे का सेवन करते हुए मिल जायेंगे और यही वे कारण हैं जिसकी वजह से अपराध बढ़ते जा रहे है या चैन स्नेचिंग की घटनायें घटित हो रही हैं। जुलाना में एक शादीपुर गांव है, इस गांव में कोई भी व्यक्ति जाकर स्मैक खरीद सकता है। यहां पर स्मैक सरेआम बिक रही है लेकिन सरकार की तरफ से इसकी रोकथाम के लिए कोई प्रयत्न नहीं

किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में नशा छुड़वाने के लिए जो एन.जी.ओज. बनाये गए है, वहां पर नशे की लत से छुटकारा पाने वाले लोगों के साथ पशुतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। इन एन.जी.ओज. पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ये एन.जी.ओज. सरकार से वित्तीय सहायता लेते हैं अतः मेरा अनुरोध है कि इनके लिए सरकार की तरफ से कुछ नार्म्ज फिक्स कर देने चाहिए ताकि ये नशे की लत के शिकार लोगों के साथ अमानवीय पशुतापूर्ण व्यवहार न कर सकें। ये एन.जी. ओज. नशा छुड़ाने के नाम पर नशा पीड़ित व्यक्ति को पीटना शुरू कर देते हैं। इस तरह से किसी भी सूरत में नशा नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार को बड़े होस्पिटल्ज में वार्ड बनाकर तथा कंसलटैंट की नियुक्ति करके कंसलटेशन के माध्यम से नशा छुड़वाने का कार्य करना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): स्पीकर सर, जिस तरह का सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, उस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मैंने इस संबंध में खासतौर से आदेश दे दिए हैं और यही कारण है कि हरियाणा प्रदेश के पंजाब तथा दूसरे प्रदेशों के बार्डर के साथ लगते एरियॉज के हस्पतालों में नशा मुक्ति केन्द्र बनाए गए है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, जिला जींद में स्थित हस्पतालों में ऐसे नशा मुक्ति केन्द्र नहीं बने हुए इसलिए मैंने सदन में यह बात उठाई है। (विघ्न)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, जिला जींद बार्डर के साथ नहीं लगता है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, जिला जींद की नरवाना तहसील के साथ पंजाब का बार्डर लगता है, लेकिन बावजूद इसके इस जिले में कोई नशा मुक्ति केन्द्र नहीं है। (विघ्न)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैने अपने उत्तर में खासतौर शब्द का भी प्रयोग किया है, माननीय सदस्य को उसका मतलब भी समझ लेना चाहिए।

प्रो0 रविन्द्र बलियालाः अध्यक्ष महोदय, नशा विषय पर बहुत सी बातें सदन में कही जा रही हैं। मैं भी नशे के विषय पर सदन में अपनी बात रखूंगा। आज नशे से समाज को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आज का युवा नशे की वजह से बहुत सी अपराधिक प्रवृतियों में लिप्त होता जा रहा है। अतः आज मैं सदन के माध्यम से

सरकार से आग्रह करता हूँ कि जैसाकि आजकल शादी समारोह में नशा करके गोलियां चलाने का फैशन बन गया है, क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनायेगी और उसमें प्रोविजन करेगी कि जिसके तहत नशा करने वाला व्यक्ति इस तरह का काम न कर सके। अध्यक्ष महोदय, एक चीज यह भी देखने में आती है कि शराब के ठेकों पर बहुत ही छोटी–छोटी उम्र के कारिंदे काम करते हैं। क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने का काम करेगी जिसमें निहित नियमों के आधार पर कोई भी छोटी उम्र का बच्चा शराब के ठेकों पर काम न कर सके और यदि ऐसा नियम पहले से बना है तो क्या सरकार उस नियम को अच्छी प्रकार से लागू करने की योजना बनायेगी। अध्यक्ष महोदय, एक चीज यह भी देखने को मिलती है कि लोग नशा करके रात को सड़क पर ही गाड़ियां खड़ी करके सोने लग जाते है और पीछे से कोई व्यक्ति जो स्पीड़ में गाड़ी चलाकर आ रहा होता है, वह सड़क के नज़दीक खड़ी गाड़ी को देख नहीं पाता जिसकी वजह से बिना नशा किए हुए व्यक्ति की गाड़ी की भी टक्कर हो जाती है और इस तरह से जिस आदमी ने कोई नशा ही नहीं किया होता है उसका भी नुकसान हो जाता है। क्या सरकार इसके लिए कोई विशेष कानून बनाने का काम करेगी ? इसके अतिरिक्त जो लोग नशा करते हैं सरकार को उनका सर्वे करवाना चाहिए । यह सरकार के लिए कोई बड़ा काम नहीं है । इसके अतिरिक्त मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार नशे के सप्लायर्स का पता करने का काम करेगी ? अगर यह पता चल जाएगा कि प्रदेश में कौन लोग नशे के सप्लायर्स हैं और कौन नशे के आदी हैं तभी हमारे पुलिस अधिकारी इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे ।

श्री राम चन्द कम्बोज : आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश को वर्ष 1947 में आजादी मिल गई थी लेकिन आज तक हमें नशे से आजादी नहीं मिल पाई है । मेरे क्षेत्र के पंजाब और राजस्थान से लगते हुए इलाके में चिट्टा नाम का नशा बहुत अधिक किया जाता है । इस नशे के कारोबार को पुलिस प्रशासन और सरकार रोकने में अब तक नाकामयाब रही हैं । यह नशा स्मैक टाइप का होता है । इस संबंध में मेरी वहां के एस.पी. से भी बात होती रहती है लेकिन उनको इसमें ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पा रही है । मेरे क्षेत्र के 16–16, 17–17 साल के जवान इस नशे की गिरफ्त में हैं । मेरा कहना है कि इन नशों की रोकथाम के लिए हरियाणा के बोर्डर पर योग्य अधिकारियों की ड्युटी लगाई जाए ताकि अन्य प्रदेशों से हरियाणा में नशे की एंट्री न हो सके । इसके लिए सरकार को नियम बनाना चाहिए । प्रदेश के नशे

की गिरफ्त में आये हुए लोगों को नशे से मुक्त करने के लिए जिला हैडक्वार्टर पर नशा मुक्ति केन्द्र खोलने चाहिए । जो प्राइवेट नशा मुक्ति केन्द्र खुले हुए हैं वे नशेड़ियों को प्रताड़ित करते हैं । इसके साथ–साथ वे अपने नशा मुक्ति केन्द्र को चलाने की आड़ में उनको नशा भी देते हैं । अतः मेरा पुनः कहना है कि सरकार को हर जिले में सरकारी नशा मुक्ति केन्द्र खोलना चाहिए ।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : आदरणीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष और अन्य साथियों ने नशे के विषय पर अपनी बात रखी है । मैं भी इनकी भावनाओं से अपने आप को संबद्ध करते हुए कहना चाहूंगा कि आज नशा कॉलेजिज तक पहुंच चुका है । यह चिट्टे का नशा बेचने का काम नाइजीरियन लोग करते हैं । ये लोग दिल्ली में रहते हैं । अतः सरकार को यह सप्लाई लाइन तोड़नी चाहिए । अभी दलाल साहब धारा 304 (1) लगाकर नॉन बेलेबल ऑफैंस बनाने की बात कर रहे थे । मेरा कहना है कि नशे के तस्कर 12 बजे पकड़े जाते हैं, 4 बजे उनकी बेल होती है और 6 बजे वे दोबारा नशा बेचना शुरू कर देते हैं । अतः इन नशा बेचने वालों पर भी यही धारा लगाकर इस गुनाह को नॉन बेलेबल ऑफैंस बनाया जाना चाहिए । ये 2 नंबर की दारू बेचने वाले लोग सीधे डिस्टिलरी से दारू लाकर बेचते हैं । अतः इन पर भी एक्साइज ऑफिसर की ड्युटी लगाई जानी चाहिए ताकि वे 2 नंबर में दारू न बेच पाएं । इसके साथ–साथ सरकार को शहर की कन्फैक्शनरी की दुकानों की भी चैकिंग करनी चाहिए । इन पर नशे की गोलियां बेची जाती हैं । मेरे क्षेत्र फतेहाबाद में टूरिजम डिपार्टमैंट का एक पार्क बना हुआ है । उस पार्क में स्कूल–कॉलेज के विद्यार्थी बैठे रहते हैं । सरकार को इस तरह से पार्कों में बैठने वाले विद्यार्थियों पर निगरानी रखनी चाहिए । इससे उनको कानून का भय रहेगा कि वहां पर किसी भी समय पुलिस आ सकती है और वे वहां पर व्यर्थ न बैठें । इसके अतिरिक्त सरकार को नशा छुड़वाने के लिए समय–समय पर सेमिनार आयोजित करने चाहिए । इनमें नशे से बचने के लिए अच्छी बातें बताने हेतु गांवों के मौजिज आदमियों जैसे सरपंच, नम्बरदार और सरकार की तरफ से ए.डी.ओ. स्तर के अधिकारियों को बुलाना चाहिए । इससे हमारे समाज में सुधार आयेगा ।

श्रीमती गीता भुक्कल : आदरणीय अध्यक्ष जी, सदन में इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय डिस्कश हो रहा है । ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार हमारे एजुकेशनल इंस्टीच्युट्स में बेटे और बेटियां भी नशे की चपेट में आ रही हैं । अतः सरकार को एंश्योर करना चाहिए कि एजुकेशनल इंस्टीच्युट्स में नशा नहीं किया जाएगा ।

ज्यादातर कॉलेजिज में खुद की अपनी कैंटीन्स हैं । इसके साथ ही एजुकेशनल इंस्टीच्युट्स में पढ़ने वाले हमारे बच्चे होस्टल्स में और होस्टल के बाहर भी रहते हैं । हमारा देश और प्रदेश यंगिस्तान है । मेरा कहना है कि सरकार को ट्राले जैसे हैवी व्हीकल्स चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए कुछ घंटो की टाइम लिमिट तय कर देनी चाहिए । ये ड्राइवर्स अधिक समय तक ट्राले चलाने के लिए ड्रिंक कर लेते हैं जिससे हादसे होते हैं । हमारे एरिया में थर्मल पावर प्लांट और कई अन्य बड़ी फैक्ट्रियां हैं । अतः वहां पर ट्राले जैसे हैवी व्हीकल्स काफी ज्यादा चलते हैं । पिछले दिनों वहां पर 17–18 एक्सिडैंट्स हुए हैं । जो मासूम इन हादसों का शिकार होते हैं उनकी कोई गलती नहीं होती । वे न तो नशा करते हैं और न ड्रग्स लेते हैं । ट्रैफिक पुलिस एक सिस्टम के तहत उनके चालान तो करती है लेकिन इन हादसों को रोकने के लिए उनके चालान करना नाकाफी है । ये ट्राले गांवों के बीच से भी गुजरते हैं । इसके लिए सरकार को अपने ट्रैफिक कंट्रोलर्स को डायरैक्शन देनी चाहिए कि वे इन पर चैक रखें । इसके साथ ही जिन ड्राइवर्स का बार–बार चालान होता है उनका लाइसैंस रद्द कर दिया जाना चाहिए । मैं एक सुझाव और देना चाहूंगी । वर्क प्लेस पर नशा करके आने वाले लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए ताकि वर्क प्लेस पर कोई इस तरह का काम न करे ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : आदरणीय अध्यक्ष जी, इस मुद्दे पर आज पूरे सदन की एक राय है । माननीय सदस्य करण सिंह दलाल, नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला जी, आदरणीय गीता भुक्कल जी, प्रो. रविन्द्र बलियाला जी, राम चन्द कम्बोज जी, बलवान सिंह दौलतपुरिया जी, सरदार जसविन्द्र सिंह संधू जी और परमेन्द्र सिंह ढुल जी ने इस मुद्दे पर एक मत से अपनी बात रखी है । माननीय सदस्य करण सिंह दलाल जी ने पूछा था कि whether this matter is under consideration of the Government? जो ड्राइवर शराब पीकर या नशा करके गाड़ी चलाते हैं और उनकी गाड़ी के नीचे आकर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसको नॉन बेलेबल ऑफैंस बनाना चाहिए । यह बात सही है लेकिन हमें इसका भारत सरकार से अनुमोदन करवाना पड़ता है । हम इस बात पर गहराई से विचार कर रहे हैं । हरियाणा प्रदेश में कुल 47 नशा मुक्ति केन्द्र हैं । इनमें से 12 नशा मुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं । बाकी के 35 नशा मुक्ति केन्द्र आर्य समाज, सनातन धर्म संस्था, गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसी विभिन्न सामाजिक

संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं । माननीय सदस्य अभय सिंह जी ने मुझसे इस बारे में सूचना मांगी थी । इसके लिए हमने एक स्पैशल टास्क फॉर्स बनाई है । इसमें एक ए.डी.जी.पी. रैंक का अधिकारी, एक एस.पी. रैंक का अधिकारी और 4 डी. एस.पी. होंगे । हम इसका जिलानुसार गठन करने जा रहे हैं । मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि हम नशे की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से एक एजेंसी बनाने जा रहे हैं । हम जनता को एक हैल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करायेंगे । उस नंबर पर कोई भी व्यक्ति दिन–रात किसी भी समय सूचना दे सकेगा कि फलां आदमी फलां धंधा करता है । यह काम हम अकेले नहीं कर सकते क्योंकि यह समस्या किसी एक विधान सभा क्षेत्र में नहीं है । आज यह वर्ल्डवाइड फिनोमिना बन चुका है । आज टीनेजर्स के दिमाग पर वायलैंस हावी हो रही है । अभी पिछले दिनों यमुनानगर में एक प्रिंसिपल ने एक स्टूडैंट को डांट दिया था । अगले ही दिन उस स्टूडैंट ने उस प्रिंसिपल को गोली मारकर मार दिया। जैसे दलाल साहब कह रहे थे कि देसी कट्टों की आवाज यू.पी. के रास्ते से आती है । पहले अलीगढ़ और किठवाड़ी के रास्ते से लोग देसी कट्टे ले आते थे लेकिन अब वहां से इनकी आवाजाही रुक गई है । अब यू.पी. में एक संत और सिपाही का राज है । अब यू.पी. के सी.एम. योगी आदित्यनाथ जी हैं । वे एक संत भी हैं और सिपाही भी हैं । जब गुरू गोविन्द सिंह जी ने खालसा सजाया तो लोग पूछने लगे कि खालसा तुम्हारा क्या करेगा तो उन्होंने कहा –

"जे समाज विज विछड़ेगा ते संत बनकर रहेगा,
ते मोर्चे ते लड़ेगा तो सिपाही बनकर रहेगा ।"

इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमने सब तरह का प्रबंध किया हुआ है । मैं पूरे सदन से विनती करना चाहता हूं कि इस संबंध में सभी माननीय सदस्य अपराधियों को पकड़वाने में सरकार का सहयोग करें । मेरे विचार से इस सदन में कोई नशे का आदी नहीं है । मेरा कहना है कि सभी सदस्य सरकार द्वारा नशे की रोकथाम के लिए शुरू किये जाने वाले हैल्पलाइन नंबर का खूब प्रचार–प्रसार करें । गुरू नानक देव जी ने कहा है –

माड़ा नशा शराब का, उतर जाए प्रभात ।
और नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे जगतार ।।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना/विभिन्न मामले उठाना

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, आजकल स्कूलों/कॉलेजों की परीक्षाओं का वक्त शुरू हो गया है और हमारे गांवों और शहरों में तेज साउंड में डी.जे. बजाए

जाते हैं जिसके कारण भयंकर आवाज पैदा होती है और उस साउंड से छोटे–छोटे पक्षी तो मर ही जाते हैं। इसके अतिरिक्त लोगों के दिल भी तेजी से धड़कने लग जाते हैं। कुछ नौजवान तो शराब के नशें में नाचना शुरू कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ? मैंने इस बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्षः करण सिंह जी, आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव डिसअलाउ हो चुका है फिर भी मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि जो डी.जे. बजाए जाते हैं इनका वॉल्यूम भी कम करवाने के लिए आदेश जारी कर दें।

श्री अध्यक्षः सरकार द्वारा डी.जे. की वॉल्यूम कम करवाने पर विचार किया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह निर्देश दें कि इसके लिए नियम बनाया जाए और उस नियम की अनुपालना सख्ती से करने के आदेश जारी किये जाएं।

श्री अध्यक्षः ठीक है, डी.जे. बजाने के लिए वॉल्यूम भी फिक्स की जानी चाहिए।

कैप्टन अभिमन्यु: अध्यक्ष महोदय, डी.जे. बजाने के लिए वॉल्यूम भी फिक्स होनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इतने डेसीमल से ज्यादा साउंड में डी.जे. नहीं बजना चाहिए। इस मामले में पूरे सदन की एक भावना है (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। यह जीरो ऑवर नहीं चल रहा है।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक निवेदन है कि हमारी विधान सभा में जो घंटी बजती है, उस घंटी से सांउड पॉल्यूशन ज्यादा होता है। इसलिए उस घंटी को ज्यादा देर तक न बजाया जाए और उस घंटी की साउंड भी अच्छी नहीं है। इसलिए इस घंटी की आवाज भी बदलवाकर मधुर घंटी लगायी जाए। इसलिए इस बारे विचार किया जाए ताकि साउंड पॉल्युशन न हो (विघ्न)।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, जब घंटी बजती है तो विपक्ष के माननीय सदस्यों के दिल की धड़कने तेज हो जाती हैं (विघ्न)।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ चण्डीगढ़ पुलिस के इंसपैक्टर श्री इकबाल सिंह ने जो हरियाणा विधान सभा परिसर में दुर्व्यवहार किया था। इस बारे में मैंने एक चिट्ठी जांच करवाने के लिए दी थी, उसके स्टेट्स के बारे में नहीं बताया गया है (विघ्न)। इस बारे में एक्शन होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: ढुल जी, आपने जो चिट्ठी दी थी उसके बारे में स्पष्टीकरण मांग लिया गया है (विघ्न) और आपको इसके बारे में जानकारी दे दी गयी थी (विघ्न)।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण मामले के बारे में अवगत करवाना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के एक माननीय सदस्य श्री परमेन्द्र सिंह ढुल के साथ विधान सभा परिसर में दुर्व्यवहार किया गया है (शोर एवं व्यावधान)।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, विधान सभा सचिवालय द्वारा आदेश दे रखा है कि विधान सभा परिसर में कोई भी माननीय सदस्य ढोल या दूसरी चीजें लेकर नहीं आ सकता है। इसके अतिरिक्त ढुल साहब ने जैसे ही इस बारे में शिकायत की तो मैंने संबंधित मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि आपने संबंधित चीजें विधान सभा परिसर में लाने के लिए बैन कर रखा है। अगर कोई माननीय सदस्य प्रतिबंधित चीज लेकर आ जाए तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाना उचित नहीं है (शोर एवं व्यावधान)।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, अगर किसी अधिकारी/कर्मचारी ने गले से ढोल निकालने का काम किया है तो वह अलग बात है। लेकिन माननीय सदस्य के साथ कोई दुर्व्यवहार किया होगा तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने इस मामले की जांच के आदेश दे दिये हैं। मैंने उसी टाईम ढुल साहब को बता दिया था कि मामले की जांच होने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। (शोर एवं व्यावधान)

.....

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

श्री अध्यक्षः अब संसदीय कार्य मंत्री सदन के पटल पर कागज–पत्र रखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज पत्र सदन के पटल पर रखता हूं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2012–2013 के लिए हरियाणा राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2013–2014 के लिए हरियाणा राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2014–2015 के लिए हरियाणा राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2015–2016 के लिए हरियाणा राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2016–2017 के लिए हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड पंचकूला की 43वीं वार्षिक रिपोर्ट।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2015–2016 के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट।

हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 की धारा 17 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2016–2017 के लिए हरियाणा लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के वर्ष 2016–2017 के लिए वित्तीय लेखे (भाग–I तथा II)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के वर्ष 2016–2017 के लिए विनियोग लेखे।

.....

वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ तथा वित्त मन्त्री द्वारा उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भ होगा।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात रखने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाए (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आपको कल अपनी बात रखने के लिए पूरा समय दिया गया था (शोर एवं व्यावधान)। प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, हमें गवर्नर एड्रैस पर भी बोलने के लिए समय नहीं दिया गया (विघ्न)। अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाए। (शोर एवं व्यावधान)

श्री हरिचन्द मिड्ढाः अध्यक्ष महोदय, मेरे जीन्द जिले में 20 दिनों से लोग धरने पर बैठें हैं परन्तु उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। (शोर एवं व्यावधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान (बेरी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने बजट में कंजर्वेशन ऑफ मुर्राह जर्मप्लाजम की बात की है। कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी सिंघवा के कैटल फेयर में भी गये थे। बजट में सरकार द्वारा नारनौंद में मुर्राह रिसर्च एण्ड स्किल डिवलैपमेंट सैंटर खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह बहुत अच्छी बात है। लगभग 30 साल पहले एक मुर्राह बुल फार्म बेरी हल्के के लकड़िया गांव में खोला गया था जो नेशनल हाईवे के साथ बनाया गया था और उस स्थान से एयर पोर्ट भी नजदीक है। वहां पर नेशनल और इन्टर नेशनल डिमांड मीट– आउट होती थी। इस फार्म की बिल्डिंग लगभग 7–8 एकड़ जमीन में बनी हुई थी परन्तु उस बिल्डिंग का डिमोलिशन कर दिया गया । इस बिल्डिंग का निर्माण लगभग 8–9 करोड रूपये की लागत से किया गया था। वहां पर फार्म खोलने के बाद मुर्राह बुल तो लाए नहीं गये, लेकिन अब वहां पर पुलिस चौकी खोल दी गयी है। आज भी संबंधित फार्म पर पुलिस चौकी खुली हुई है। यह नेशनल और इन्टरनेशनल लेवल का मुर्राह जर्म प्लाजम फार्म था जिसमें झज्जर, रोहतक, हिसार, भिवानी और जीन्द जिले मुर्राह जर्म प्लाजम के होम ट्रैक्ट थे और इन जिलों को मुर्राह जर्म प्लाज्म की सप्लाई इसी फार्म से होती थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि उस मुर्राह बुल फार्म को चालू किया जाए ताकि इससे पूरे प्रदेश को फायदा मिल सके। स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो मक्के की खरीद पर सरकार द्वारा गलत एफिडेविट देने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। अध्यक्ष महोदय, यह जो मक्के की फसल पिटी, जीरी की फसल पिटी और कपास की फसल पिटी है इसी प्रकार से यूरिया है, वह थानों के माध्यम से किसानों को मिल रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य कादियान जी को बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) इन्हें बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाजपा की सरकार में सब काम अच्छा चल रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण बात है तो कहें?(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने बदले की भावना की राजनीति की है, जिसकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह जो the feeling of revenge है यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में कुछ राजनीतिक लोगों के खिलाफ मुकदमें बनाए जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, किसके खिलाफ मुकदमे बन रहे हैं ?

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में हुड्डा साहब के खिलाफ मुकदमे बन रहे हैं।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, वह तो कोर्ट का फैसला है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब के कद को छोटा करने के लिए और उनके पॉलिटिकल कैरियर को बर्बाद करने के लिए जो राजनीति चलाई जा रही है। उसे हरियाणा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, कादियान जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, यह तो कोर्ट का फैसला है। (शोर एवं व्यवधान) कादियान जी, आप सिर्फ बजट के विषय पर बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह लॉ एण्ड आर्डर की बात। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था कि ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट में पटापेक्ष होगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के इस बयान से अहंकार की बू आ रही थी। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि 8 महीने बाद केवल हम यहां होंगे, वे यहां नहीं होंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, मुख्यमंत्री जी ने अहंकार की बात नहीं की है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री कादियान जी जो पटाक्षेप की बात कर रहे हैं, उसे मैं दुरुस्त कर देता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पटाक्षेप की बात कही थी और कादियान जी

पटापेक्ष की बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि बजट संबंधी चर्चा को आगे बढ़ाएं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार ने क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ की नौकरियां में जो इन्टरव्यू को कैंसिल किया है, यह शुरू में बहुत अच्छा लगता था। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, जो लड़के देहात से आते हैं उनकी सरकारी नौकरियों में इंट्री रुक गई है और वे चोरी और चालाकी का शिकार हो गए हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एच.एस. एस.सी. और एच.पी.एस.सी. से रिलेटेड बहुत सारे केसिज आज हाईकोर्ट में पैंडिंग पड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ की पोस्टों के लिए इंटरव्यू को शुरू किया जाए ताकि जो देहात के लड़के हैं उन्हें भी सरकारी नौकरियों में जगह मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मैं इवैंट मैनेजमेंट की बात करना चाहता हूं कि किस तरह से सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की बात करती रहती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप अपनी बात 2 मिनट में समाप्त करें।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी मेरे बेरी हल्के में गए थे और वहां पर घोषणाएं करके आए थे कि वे वहां के लिए ग्रांट देंगे और वहां पर एक महिला कॉलेज बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर न तो किसी गांव में ग्रांट दी गई और न ही महिला कॉलेज का फाउंडेशन रखा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे वहां पर जो घोषणाएं करके आए हैं उसे वे पूरा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि इन्होंने वहां पर एक पॉलिटैक्निक कॉलेज ऑफ वुमन का फाउंडेशन रखा था, उस पर भी आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मेरी कुछ डिमांड्स हैं जैसे– Round about (Four), Bus Stand (Out side near Mini Secretariat) on Beri-Jhajjar road, Sub-Depot of Haryana Roadways at Beri, Huda Sector, Bye Pass, Harbal Park in Chajjan Pana, Community Centre, Government College for Women और अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में जो रोड्स सैंक्शन्ड है और जिनका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है जैसे– Beri-Sheria road to Putlia Baba Ka Mandir, Chhara to Kultana, Chhara to

Rewari Khera (Straight way along with Drain), Beri-Dubaldhan road to Baba Tuta Ka Mandir, Bhadurgarh road to Mata Devi Ka Mandir (Chhara), Manala Pond to Shiv Mandir (Chhara), Beri-Dujana road to Nirachia Ka Mandir, From Matan Village to Chanderbhan Samadh (Freedom fighter).

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, यह हमारे हल्के के लोगों की डिमांड्स है। इन डिमांड्स को इस सदन में रखना मेरी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेवारी है, इसलिए मुझे अपनी डिमांड्स रखने दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है कादियान जी, आप जल्दी वाईंड–अप करें।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, इसी प्रकार से मेरे हल्क में एक सड़क मातन विलेज से दादा हिकमवाला मंदिर बनाई जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सड़क की लम्बाई मात्र दो मिलोमीटर है। ऐसे ही एक सड़क माजरा (डी.) पी. डब्ल्यू.डी. रोड से पीलियावाला पौंड तक है। मेरी मांग है कि सरकार इस सड़क का निर्माण भी जल्दी से जल्दी करवाये। इसी प्रकार से मेरी सरकार से यह डिमाण्ड है कि मेरे हल्के के गांव छारा में साऊथ साईड पर, गांव दूबलधन में नॉर्थ साईड पर और मातन विलेज में बहादुरगढ़–बेरी रोड पर बाई–पास का निर्माण करवाया जाये। इसी प्रकार से मेरे हल्के की इरीगेशन डिपार्टमैंट से सम्बंधित कुछ डिमाण्डज़ हैं। Extention of Rewari Khera Minor upto Kablana, Chhudani drain (Kharman, Chhudani to KCB drain), Bishan Minor (Allocation of time), Bhambewa Minor (Allocation of time), Drainage (Bhambewa, Diman Chliana to KCB drain, Drain from Rohad to Kharhar] Drainage for 250 acres land at Dhaur, Drain for flood water village Dharana, Bridge over KCB Drain for Bhaproda village, Dhigal Drainage for village flood water and Dabodha Sb-Minor abdononed time 10 years water supply restored. मेरी कुछ डिमाण्डज़ ग्रांट्स के सम्बन्ध में है। मेरी सरकार से यह रिकवैस्ट है कि मेरे हल्के के सभी गांवों को विकास के लिए ग्रांट्स दी जायें, एम. सी. बेरी को ग्रांट दी जाये, मेरे हल्के के जिन गांवं में विभिन्न समुदायों की चौपालें

नहीं हैं वहां पर चौपालों के निर्माण के लिए ग्रांट दी जाये। बेरी विधान सभा क्षेत्र के जिन गांवों में हरिजनों को 100 गज के प्लाट्स का आबंटन नहीं किया गया है उनको 100 गज के प्लॉट्स आबंटित किये जायें। जो विभिन्न गांवों में पीने के पानी के लिए पाईप्स डाले जाने हैं उनको जल्दी से जल्दी डलवाया जाये। मेरे हल्के के दो गांव दुजाना और भम्भेवा रेलवे स्टेशन बनाने के लिए निर्धारित क्राईटेरिया पूरा करते हैं इसलिए इन दोनों गांवों में रेलवे स्टेशन का निर्माण करवाया जाये। दुजाना से भम्भेवा तक रेलवे लाईन की वैस्ट साईड पर सड़क का निर्माण करवाया जाये। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में दो–तीन गांवों को छोड़कर जहां पर धनखड़ साहब के लड़के या दूसरे लोगों का ठेका है वहां पर ही ग्रांट दी जाती है और कहीं पर ग्रांट नहीं जाती। यह बात मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आपकी बात पूरी हो गई है। आपने अपनी सभी डिमाण्ड्ज़ को कल लिखित रूप में दे दिया था जिनको कल ही सदन की कार्यवाही में शामिल करवा दिया गया है। इसलिए अब आप कृपया करके बैठ जायें।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : ठीक है सर स्पीकर सर। सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : स्पीकर महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। वित्त मंत्री जी जब बजट प्रस्तुत कर रहे थे और बजट प्रस्तुत करते वक्त जिस ढंग से बार–बार अपने रूमाल से पसीना पोंछ रहे थे उसको सभी देख रहे थे। इस बारे में सभी ने चर्चा भी की थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस बजट में कुछ होता तो वित्त मंत्री जी द्वारा बजट के 51 पेज़ पढ़ते समय 51 बार रूमाल से अपना पसीना नहीं पोंछा जाता। यदि यह बजट अच्छा होता तो वित्त मंत्री के लिए ऐसी नौबत बिलकुल नहीं आती। मैं वित्त मंत्री जी को देख भी रहा था कि उनकी हालत बजट को पढ़ते समय कैसी हो रही थी। वित्त मंत्री जी बार–बार पसीना पोंछ रहे थे इस बारे में प्रैस के साथियों ने भी मुझ से जिक्र किया था कि वित्त मंत्री जी को बार–बार पसीना क्यों आ रहा था? इस पर मैंने उनको यह बताया कि उनका स्वास्थ्य तो ठीक था मेरी उनसे सुबह मुलाकात हुई थी। यह भी हो सकता है कि उनको पसीना बजट की किताब के कारण आ रहा हो क्योंकि हो सकता है कि

उनको इस बजट की किताब के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखकर दे दी हों जो शायद वे पढ़ना ही नहीं चाहते हों इसलिए हो सकता है कि उनको इस कारण से बार–बार पसीना आ रहा हो। (इस समय उपाध्यक्ष महोदया चेयर पर आसीन हुई) उपाध्यक्ष महोदया, वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट के अंदर जो सबसे पहली बात कहीं गई वह पर–कैपिटा इनकम के बारे में थी। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात कही गई थी कि हमारे प्रदेश की पर–कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है। इस बात पर सत्ता पक्ष द्वारा बड़े जोर–शोर से मेज़ों को भी थपथपाया गया था कि इस वर्ष पर–कैपिटा इनकम 1,96,982/– रूपये हो गई। पर–कैपिटा इनकम तो बढ़ी हुई दिखाई गई है लेकिन इसके साथ ही साथ यह नहीं बताया गया कि सरकार द्वारा कितना कर्ज़ा लिया गया है? सन् 2004 तक हरियाणा को बने 38 वर्ष हो चुके थे। इन 38 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के ऊपर लगभग 23 हज़ार करोड रूपये कर्ज़ था। वर्ष 2004 के बाद जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उसने अपने 10 साल के शासनकाल के दौरान इस कर्ज़ को बढ़ाकर 70,931 करोड रूपये कर दिया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साढ़े तीन वर्ष के अंदर लगभग 90 हज़ार करोड रूपये का कर्ज़ और ले लिया है। यह जो कर्ज़ लिया गया है इस कर्ज़ के ब्याज का जो भुगतान है वह कोई छोटा नहीं है बल्कि वह भी बहुत बड़ा है। वर्ष 2004 तक इस कर्ज़ पर 600 करोड रूपये सालाना ब्याज का भुगतान किया जाता था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के 10 साल के शासनकाल में इस ब्याज का भुगतान बढ़कर 7 हज़ार करोड रूपये सालाना के आसपास चला गया था। आज की तारीख में 14 हज़ार करोड रूपये से ज्यादा सालाना ब्याज के रूप में सरकार को वापिस करना पड़ेगा। इस किस्म के हालात भी प्रदेश में हुए है कि इस कर्ज़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए भी सरकार को कर्ज़ लेना पड़ा हो। जब कर्ज़ लेकर ही ब्याज चुकाना है तो फिर इस बजट के बारे में आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह बजट हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए हितकारी है। खास करके कृषि के क्षेत्र में, हैल्थ के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र सहित इन सभी क्षेत्रों के बारे में दिखाया गया है कि बजट में इन सभी क्षेत्रों के लिए राशि के प्रावधान को बढ़ा दिया गया है। अगर इस बजट की पिछले बजट से तुलना करते हुए आकलन किया जायेगा तो फिर सरकार को खुद को यह अहसास होगा कि यह बजट बढ़ा नहीं है बल्कि यह बजट घटा है। जो पिछले वर्ष वित्त मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था वह

लगभग एक लाख हजार करोड रूपये का था वर्तमान बजट को बढ़ाकर 1.15 लाख करोड रूपये किया गया है। अगर आप 2017–18 के बजट को देखेंगे तो आप पायेंगे कि आपके द्वारा कृषि क्षेत्र के ऊपर टोटल बजट का 12.49 प्रतिशत खर्च किया जा रहा था। इस बार जो कृषि क्षेत्र के लिए प्रस्तावित बजट है वह टोटल बजट का 12.22 प्रतिशत है। इस प्रकार से इस बार के बजट में .27 परसैंट खर्च कम हुआ है। अगर सरकार वास्तव में ही कृषि क्षेत्र के लिए बजट को बढ़ाती तो फिर ये 12.49 की बजाये बढ़कर 13 परसैंट हो जाना चाहिए था। सरकार कह रही है कि उसने कृषि क्षेत्र के बजट को 51 परसैंट बढ़ा दिया है। जब आंकडें निकालकर वर्ष 2017–18 के बजट की इस बजट से तुलना की जायेगी तो जो बात मैंने अभी कही है इसको ही सच पाया जायेगा। बिजली के क्षेत्र में एक तरफ तो यह कहा जाता है कि सरकार डिस्ट्रिक्टवाईज़ 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान करने जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 5–6 जिलों के नाम बताये और बताया कि इन 5–6 जिलों में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। वास्तव में बिजली की यह हालत है कि वर्ष 2017 के बजट में टोटल बजट का 6.31 प्रतिशत बिजली विभाग के लिए रखा गया था और इस बार के बजट में बिजली विभाग के लिए प्रस्तावित राशि टोटल बजट की 5.87 परसैंट है। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट के मामले में गवर्नर एड्रैस में तो यह कहा गया था कि सरकार द्वारा 550 नई बसों की खरीद की जायेगी लेकिन बजट में इस परपज़ के लिए किसी राशि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में यह नहीं कहा गया कि कितनी राशि बसों की खरीद के लिए रखी गई है। जो बातें मैं बता रहा हूं ये सारी की सारी बातें गवर्नर एड्रैस में बड़े स्पष्ट रूप में लिखी हुई हैं। मैं एक बार पुनः बताना चाहता हूं कि गवर्नर एड्रैस में इस बात का बाकायदा जिक्र किया गया है कि परिवहन विभाग के लिए 550 बसें खरीदी जायेंगी लेकिन बजट में इसके लिए किसी राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। इसी प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो डिवैल्पमैंट एण्ड पंचायत डिपार्टमैंट है उसमें वर्ष 2017–18 के लिए टोटल बजट की 4.85 प्रतिशत राशि रखी गई थी और इस बार की जो प्रस्तावित राशि रखी गई है वह टोटल बजट की 3.76 प्रतिशत है। इस प्रकार से इसमें भी कमी की गई है। इसी प्रकार से शिक्षा क्षेत्र के बजट को भी कम किया गया है। राम बिलास जी अभी यहां नहीं बैठे हैं वे बार–बार यह कह रहे थे कि हम इतने स्कूल्ज़ को नया अपग्रेड करने जा रहे हैं। जहां स्कूल्ज़ को अपग्रेड करने की बात हो रही थी वहां नये कॉलेजिज की

स्थापना की बात भी हो रही थी। शिक्षा के मामले में वास्तविक स्थिति यह है कि शिक्षा विभाग का बजट भी कम हुआ है। एक तरफ तो शिक्षा विभाग का बजट कम हुआ है लेकिन दूसरी तरफ सरकार द्वारा स्कूल्ज़ की संख्या बढ़ाने की भी बात की जाती है। सरकार को यह भी पता होना चाहिए कि जो स्कूल्ज़ में पढ़ाने वाला स्टॉफ है वह तो मोस्टली स्ट्राईक पर रहता है। वे इसलिए बारी–बारी से स्ट्राईक पर जाते हैं कि सरकार ने उन्हें सत्ता में आने से पहले तो उनको पक्का करने का विश्वास दिलाया था और अब जब वे सरकार से चुनावों से पहले उनके साथ किये गये वायदे को पूरा करने की बात कह रहे हैं तो सरकार उनकी जायज मांग को न मानकर उनको एजीटेशन करने के लिए मज़बूर कर रही है। सरकार के पास स्कूल्ज़ में टीचर्ज़ की 1,21,708 एक्चुअल सैंक्शंड पोस्ट्स हैं। जो आपके कॉलेज के एक्सटैंशन लैक्चरर्स हैं उनको आपने फिक्स पे पर रखा हुआ है, आपको उनको रेगूलर करना चाहिए। आप उनको रेगूलर करने की बजाय उनको मजबूर करते हैं कि वे सरकार के खिलाफ ऐजीटेशन करें। जब वे अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उनकी बात सुनने की बजाय उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उन पर पानी की बौछारें मार कर उनको भगाने की कोशिश की जाती है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अध्यापकों की कुल सैंक्शन पोस्ट 1,21,708 हैं जिसमें से आपकी 86654 रेगूलर पोस्ट भरी हुई हैं। इसी प्रकार से जो गैस्ट टीचर्स हैं उनको भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाये तो 13673 हैं। उसके बाद जो वैकेंट पोस्ट्स हैं वे भी बहुत ज्यादा बच जाती हैं वे 21381 हैं। इस प्रकार से हमारा शिक्षा का स्तर कैसे ठीक होगा? हमारे प्रदेश में टीचर्स की कमी है और अगर स्कूलों में अध्यापक ही नहीं होंगे तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? जब तक टीचर्स की भर्ती नहीं होती तब तक हाई स्कूल और 10+2 के स्कूल अपग्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। एक तरफ तो सरकार की ओर से यह ढोल पीटा जा रहा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में यह करेंगे, वह करेंगे और दूसरी तरफ शिक्षा की हालत यह है कि स्कूलों में टीचर्स ही नहीं हैं। इसी प्रकार से अब मैं कानून व्यवस्था पर अपनी बात रखना चाहता हूं। हालांकि कानून व्यवस्था पर सदन में पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है लेकिन मैं सरकार की जानकारी में एक बात अवश्य लाना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वे चाहें तो इसको नोट कर लें।

बहादुरगढ़ में भूमि घोटाले का मामला उठाना

श्री अभय सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहादुरगढ़ में पी.डब्ल्यू.डी. और नगर परिषद की जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। इसके लिए वहां के

स्थानीय लोगों ने तथा स्थानीय पूर्व विधायक ने इस इश्यू को लोगों के सामने उठाया लेकिन उनकी बात को किसी ने नहीं सुना। सुनने के बजाय उस के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर दी गई। मैं सरकार की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जिस जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है वह 5200 गज जमीन है। जब उसका रिवेन्यू रिकॉर्ड चैक किया गया तो पता चला कि रिकॉर्ड के अनुसार उस जमीन का खसरा नम्बर 2337 है। उस खसरा नम्बर के अनुसार वह जमीन बहादुरगढ़ नगर परिषद की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आप इसको चैक करवा लें कि यह जमीन किसके नाम पर है। आज की तारीख में भी वह खसरा नम्बर नगर परिषद के नाम पर है। इसी प्रकार से पी.डब्ल्यू.डी. की जमीन का खसरा नम्बर 2338 है उस पर भी अवैध निर्माण हो रहा है। एक तरफ सरकार की तरफ से बात की जाती है कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगायेंगे और दूसरी तरफ अवैध निर्माण हो रहे हैं। इन जमीनों पर अवैध कब्जे करने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके बहादुरगढ़ के नोमिनेटिड पार्षद है जो उन जमीनों पर कब्जा किये हुये है। उनको पुलिस का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। पुलिस के संरक्षण में खड़े हो कर वहां पर अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। इस बारे में मेरे पास तहसीलदार की 3 रिपोर्ट्स हैं अगर आप लेना चाहें तो ले लें। मैं आपको नक्शा भी दे सकता हूं जिससे आपको पता चल जायेगा कि जो बातें मैं सदन के सामने रख रहा हूं वे ठीक हैं या नहीं। पहली रिपोर्ट में तहसीलदार ने यह माना है कि यह जमीन नगर परिषद् की है और पी.डब्ल्यू.डी. की है लेकिन वे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरे ऊपर दबाव है इसलिए मैं इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूं।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, माननीय नेता प्रतिपक्ष अन्त्तोगत्वा बजट के प्रस्तुत करने के बाद सदन में बजट पर अपनी समीक्षा व टिप्पणी करने के लिए खड़े हुए हैं । मेरा निवेदन है कि इस पूरे मामले में सदन का समय बहुत जाया हुआ है । वास्तव में इस मामले में हम चाहते थे कि माननीय सदस्यों का बजट के प्रावधानों पर एक गम्भीर आंकलन उनकी समीक्षा के तौर पर व सुझाव के तौर पर मिले । उसके लिए हमने उनको बजट पर आलोचना करने का स्वागत करने को भी कहा है । मेरा निवेदन है कि बजट पर चर्चा करने की जो परम्परा है जैसे उन्होंने अपने सब्जैक्ट वाईज ट्रांस्पोर्ट पर, एजुकेशन पर और भी कई चीजों पर काफी अच्छी शुरूआत की है। । अगर वह उनको थोड़ा और

सारगर्भित रूप से रखेंगे तो उनके समय का बेहतर उपयोग हो सकेगा क्योंकि बजट के प्रावधानों पर चर्चा करने का पहले ही समय बहुत कम है । अपने यहां सदन में जैसी परम्परा पहले रही है । यह परम्परा कोई महीने भर सदन को लम्बा चलाने की नहीं है । उस नाते से मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को यह निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, आपको मैं यह दस्तावेज दे देता हूं । आप इसकी जानकारी ले लें । मैं आपको नक्शा भी देता हूं और मैं आपको तहसीलदार की रिपोर्ट भी दे देता हूं और वहां पर जो निर्माण हो रहा है आप उसके बारे में सरकार से उसकी जानकारी ले लें ।

श्री नरेश कौशिक : उपाध्यक्ष महोदया, मैं बहादुरगढ़ हल्के से विधायक हूं । वहां पर इस प्रकार का कोई अवैध निर्माण नहीं हो रहा है । हमने वहां सारे दस्तावेजों को वैरिफाई करवाया है । माननीय पूर्व विधायक जी वहां जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे । जबकि पिछले 20 सालों में वह 10 साल तक विधायक भी रहे हैं । उस समय माननीय चौटाला साहब की सरकार थी । उस समय की सरकार के दौरान वर्तमान पार्षद के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगाया गया था । जबकि वह जमीन पार्षद की पैदायशी अपनी जमीन है । वे उस जमीन का टैक्स भी भरते हैं क्योंकि वहां पर उनका सिनेमा हॉल चल रहा है। लेकिन उन पार्षद के साथ जबरदस्ती की गई जिसके बारे में उन्होंने बहादुरगढ़ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. भी दर्ज करवा रखी है । इसलिए उस पार्षद के खिलाफ माननीय सदस्य द्वारा लगाए गये सभी आरोप बिल्कुल झूठे और गलत हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, विधायक की तरफ से जो बातें कही गई हैं हो सकता विधायक जी का उसमें अपना कोई रोल हो ।

श्री नरेश कौशिक : उपाध्यक्ष महोदया, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने तो इनके बारे में कुछ कहा ही नहीं है । विधायक जी, मैंने आपको क्या कहा है ? उपाध्यक्ष महोदया, यह तो वही बात हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका ।

श्री नरेश कौशिक : उपाध्यक्ष महोदया, इन लोगों ने पहले प्रदेश में बहुत लूट मचाई है । हमने वहां का सारा रिकॉर्ड निकलवाया है और अगर आप चाहें तो वह रिकॉर्ड हम विधान सभा में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, आप विधायक जी को कहो कि वे उस रिकॉर्ड को विधान सभा में लेकर आएं । इनको यहां लाने से कौन रोक रहा है ? इनको वह रिकॉर्ड यहां लेकर आना चाहिए यह अच्छी बात है ।

श्री नरेश कौशिक : उपाध्यक्ष महोदया, पार्षद के खिलाफ श्री अशोक गुप्ता ने एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई हुई है क्योंकि उन्होंने श्री अशोक गुप्ता को दुकान खाली करने के लिए धमकी भी दी थी ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, यह प्रोपर्टी का जो मामला है उसमें विधायक को खड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह प्रोपर्टी विधायक की नहीं है । (शोर एवं व्यवधान) नरेश जी, आप अपनी जुबान पर लगाम लगाईये । उपाध्यक्ष महोदया, आप इनको बैठाईये । इससे ज्यादा भ्रष्टाचार के और क्या सबूत होंगे । विधायक जी का इस तरह का क्या तरीका है ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कौशिक : उपाध्यक्ष महोदया, आप मेरी बात सुनें ।(शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : नरेश जी, प्लीज आप बैठिए । (शोर एवं व्यवधान) जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा । नरेश जी, प्लीज आप बैठिए ।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा वित मंत्री जी से अनुरोध है (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, आप नेता प्रतिपक्ष को कहें कि उन्हें धमकी देने की जरूरत नहीं है । हम उनकी धमकी स्वीकार नहीं करेंगे । वह इस तरह से किसी सदस्य को धमका नहीं सकते । वे बात करें लेकिन इस तरह से सीधे किसी सदस्य से बात नहीं कर सकते । वे हमारे विधायक को धमका नहीं सकते । ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे इनको इस तरह नहीं धमका सकते । चौटाला जी, आप उपाध्यक्ष महोदया के माध्यम से बात कीजिए । हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं । हम किसी की धमकी से डरने वाले नहीं है । आप इनको धमकी के लिए वार्निंग दीजिये । वह इस प्रकार से धमकी नहीं दे सकते । वह चर्चा करें।(शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः उपाध्यक्ष महोदया, नेता प्रतिपक्ष बजट पर पूरे तथ्यों के साथ अपनी सारी बातें कह रहे हैं और वित्त मंत्री जी उसको नोट कर रहे हैं लेकिन सत्ता पक्ष का एक विधायक इंट्रप्ट करने लग जाता है। यह विधायक किस अधिकार से नेता प्रतिपक्ष को बोलने में इंट्रप्ट कर रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महिपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय साथी ने तो केवल यही कहा है कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा गलत तथ्य सदन में पेश किए जा रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष द्वारा हमारी पार्टी के इस सदस्य को धमकाया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष नरेश कौशिक जी के हल्के की बात कर रहे हैं, अगर सदन में कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य के हल्के के बारे गलत तथ्य पेश करेगा तो सीधी सी बात है कि जिस सदस्य के हल्के के बारे में गलत तथ्य पेश किए जा रहे होंगे, वह उस बात का विरोध जरूर करेगा। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, सदन में गलत तथ्य प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) इन लोगों के कारनामें जनता ने देखे हुए हैं।(शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी): उपाध्यक्ष महोदया, हम जो भी सदस्य इस सदन में बैठे हैं वह सारे जन प्रतिनिधि हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो धमकाने की कार्रवाई की जा रही है वह बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंहः उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो सरकार के कारनामों के बारे में सदन को बता रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महिपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदया, हम भी नेता प्रतिपक्ष के कारनामों की ही बात सदन में बता रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदीः उपाध्यक्ष महोदया, विपक्ष के नेता को अपनी गरिमा तक का भी ख्याल नहीं है? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. पवन सैनीः उपाध्यक्ष महोदया, नेता प्रतिपक्ष किसी भी सूरत में सदन के किसी भी सदस्य को धमका नहीं सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः पवन जी, आप प्लीज बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. पवन सैनीः उपाध्यक्ष महोदया, विपक्ष की तरफ से हमारे साथी सदस्य को धमकाया जा रहा है और आप मुझे ही चुप रहने के लिए कह रही हैं। (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के नेता अपनी गरिमा को भुलकर हमारे साथी सदस्य को धमकाने का काम कर रहे है। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, जिस दिन सदन के सदस्यों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया था उस दिन हमें सदन की न जाने कितनी ही प्रकार की मर्यादाओं के बारे में बताया गया था। जिस तरह का काम नेता प्रतिपक्ष द्वारा किया जा रहा है, क्या इस तरह से सदन की मर्यादाओं का पालन होता है? (शोर एवं व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन का कोई भी सदस्य क्यों न हो उसको सदन की मर्यादाओं को तोड़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः पवन जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाये, यह भी सदन की मर्यादाओं में शामिल है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से सदन में बहादुरगढ़ की नगर पालिका की जमीन व पी.डब्लयू.डी. की वह जमीन, जोकि अशोक गुप्ता नामक एक व्यक्ति के नाम है, के बारे में पूरे दस्तावेजों के साथ माननीय वित्त मंत्री के साथ बात कर रहा था लेकिन किसी विधायक को यह अधिकार नहीं है कि जब मैं चेयर की अनुमति से अपनी बात रख रहा हूँ तो वह मुझे इंट्रप्ट करे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कौशिकः उपाध्यक्ष महोदया, नेता प्रतिपक्ष को भी यह अधिकार नहीं है कि वह सदन में गलत आरोप लगाए। यह लोग खुद चोर हैं और आरोप लगाने का काम कर रहे है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं पूरे दस्तावेजों के साथ बात कर रहा हूँ। सदन में जब गवर्नर एड्रैस पर चर्चा होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसका रिप्लाई देते हैं या कोई कंसंर्ड मिनिस्टर है, वह प्वॉयंट आफ आर्डर लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की जगह जवाब दे सकते है। संबंधित मामले में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से बात कर रहा था क्योंकि मेरी बात का जवाब उन्होंने देना था तो जब मेरी बात का जवाब वित्त मंत्री जी ने देना है तो विधायक जी बीच में क्यों उठकर बोलने लग गए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना

चाहूंगा कि क्या देश की किसी विधान सभा में ऐसा कोई नियम है कि मंत्री की जगह विधायक जवाब दे। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, नेता प्रतिपक्ष इस सदन के बहुत ही सीनियर मैम्बर हैं और यह सदन ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा प्रदेश, बजट पर इनकी राय और विचार जानना चाहता है। नेता प्रतिपक्ष इस सदन के हमसे ज्यादा समय तक सदस्य रहे हैं। जहां तक नेता प्रतिपक्ष ने मुझसे पूछा है कि यदि वे चेयर की अनुमति लेकर कोई प्रश्न पूछते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर देने की जिम्मेदारी किसकी है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि ऐसी अवस्था में पूछे गए प्रश्न से संबंधित विभाग के मंत्री की जवाब देने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर किसी क्षेत्र विशेष के बारे में चर्चा हो रही हो और उस चर्चा में किसी सदस्य को लगता है कि कुछ गलत तथ्य पेश हो रहे है तो भी मर्यादा के साथ संवाद होना चाहिए लेकिन जब सरकार के मंत्री बात कर रहे होते हैं तो भी विपक्ष के कई विधायक साथी अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित किस विषय पर बीच में उठकर बोलने लग जाते है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूँ कि सदन की मर्यादा हर अवस्था में बनी रहनी चाहिए लेकिन अगर किसी विधायक साथी को उसके क्षेत्र के बारे में कही जा रही बात पर आपत्ति है तो किसी भी सूरत में उस विधायक को धमकाया नहीं जा सकता। उपाध्यक्ष महोदया, सदन का हर सदस्य बाकायदा तौर पर हर कसौटी पर तुलकर इस सदन में आया है। सदन के सभी सदस्य बराबर है। किसी भी सदस्य को धमकी नहीं दी जा सकती। अगर कोई बात बुरी लगती है तो चेयर के माध्यम से कहा जा सकता है, लेकिन सीधे सीधे धमकी देने की मर्यादा को यह सदन स्वीकार नहीं कर सकता।

वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, बजट के अंदर एस.वाई.एल. नहर का भी जिक्र आया है, दादूपुर नलवी नहर का भी जिक्र आया है और मेवात फीडर का भी जिक्र किया गया है। सदन के अंदर इन तीनों योजनाओं पर बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई हैं। मेवात फीडर के साथ जिन–जिन विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र आते हैं उन विधायकों ने अपने–अपने क्षेत्र में पानी लाने को लेकर एकमत होकर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी को बाध्य किया कि इसके लिए वे किसी कमेटी का गठन करें। इसके लिए मैं उन सभी विधायकों को बधाई देता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदया, हमें पानी मिले, इसके लिए हमें केन्द्र की सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। मैं फिर से उन सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या को सदन के अंदर रखा है। लेकिन मुझे अफसोस तब होता है जब एस.वाई.एल. नहर के बारे में जिक्र आता है, जिस क्षेत्र से उपाध्यक्ष महोदया आप भी जुड़ी हुई हैं और जिन जिलों में एस.वाई.एल. नहर का पानी आना है। उन जिलों का एक भी माननीय सदस्य अपनी–अपनी जिम्मेवारी सदन के अंदर निभाने का काम नहीं कर रहा है। इसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक दादूपुर नलवी नहर योजना का मामला है। यह हमारी जीवन रेखा है। जब पानी के बंटवारे की बात आती है और स्वच्छ पानी देने की बात आती है तो इस सदन में पानी को लेकर चर्चाएं होती हैं। दादूपुर नलवी नहर योजना जिसके ऊपर साढ़े तीन करोड रूपये खर्च हो चुके हैं लेकिन सरकार ने नहर बनाने की बजाय उस प्रोजैक्ट को रोकने का काम किया है। यह निंदनीय है। सरकार जिस ढंग से नहर के निर्माण को रोकना चाहती थी, उस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। सरकार ने अपनी तरफ से तो यह कह दिया कि हमने इस नहर को डिनोटीफाई कर दिया। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस नहर को सरकार डिनोटीफाई नहीं कर सकती है। आज भी वह नहर ज्यों की त्यों है। आने वाले समय में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय से इस नहर के लिए आदेश आ सकता है कि नहर निर्माण के लिए पैसे दिए जायें और इस प्रोजैक्ट को पूरा किया जाये। माननीय सुप्रीम कोर्ट का परसों का ही ताजा उदाहरण है कि जो 600 एकड़ जमीन जिसके लिए कल सदन में बहुत शोर मचा था, उसी जमीन के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि किसी भी किसान की जमीन का अगर उसको पूरा पैसा नहीं मिला है तो वह किसान कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अगर किसी किसान को 90 लाख रूपये मिले या किसी को 25 लाख रूपये मिले तो वह कोर्ट की शरण में आ सकता है। यह किसान का अधिकार है। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार उन किसानों को पैसा देने की बजाए नहर के निर्माण के प्रोजैक्ट को शुरू करें ताकि हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ धोखा न हो। इसी तरीके से जो बिजली का क्षेत्र है, जिसके ऊपर सदन में बहुत ज्यादा चर्चाएं हो चुकी हैं। इसलिए मैं और ज्यादा इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उपाध्यक्ष महोदया आप स्वयं कहती हैं कि मैं अपनी पार्टी के सदस्यों का बोलने का समय ले लेता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने

अपनी पार्टी के सदस्यों की एक लिस्ट सदन में बोलने के लिए दी हुई है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि उन सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दीजिए। अंत में उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी जगह पर लाला जी ने अपनी दुकान खोल दी और उस दुकान के सामने कोई बड़ा शोरूम खुल गया। जिसने बड़ा शोरूम खोला था उसने अपने सामान की रेट लिस्ट शोरूम के बहार लगा दी और उसमें फलां चीज की फलां कीमत लिख दी। उसमें देसी घी का रेट भी 300 रूपये लिखा हुआ था। सामने छोटे लाला की दुकान थी उसने भी सामान की रेट लिस्ट बाहर लगा दी और देसी घी का रेट 280 रूपये लिख दिया। अगले दिन शोरूम वाले ने देसी घी की कीमत 260 रूपये लिख दी और लाला ने भी 240 रूपये लिख दी। उपाध्यक्ष महोदया, उसके अगले दिन शोरूम वाले ने देसी घी की कीमत 220 रूपये लिख दी और लाला ने भी 200 रूपये कर दिया और बोर्ड पर लिख दिया। कुदरती ही लाला का कोई रिश्तेदार आ गया और लाला से कहने लगा कि लाला जी आप यह क्या कर रहे हैं। वह बड़ा शोरूम वाला है और तेरी छोटी दुकान को उजाड़ देगा। इस पर लाला जी ने कहा कि मैं उजडूगाँ तो तब जब मेरी दुकान में देसी घी होगा। (हंसी) उपाध्यक्ष महोदया, अगर इस बजट में कुछ होता तो माननीय वित्तमंत्री जी को पसीना नहीं आता ।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय प्रतिपक्ष के नेता यदि बजट से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेते तो, इस तरह की बात सदन में नहीं कहते।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बात सदन में कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने हरियाणा रोड़वेज के बारे में जिक्र किया था। (विघ्न) परिवहन विभाग में 4100 बसों का बेड़ा है। 600 बसें और हरियाणा सरकार परिवहन विभाग में ला रही है। इन बसों के लिए हाई पावर परचेज़ कमेटी से मंजूरी भी मिल चुकी हैं । 450 बसों की चेसिज भी आ चुकी हैं। 300 से ज्यादा बसें एच.आर.ई.सी. गुरूग्राम में बनकर हमने बस डिपों में दे दी हैं। उपाध्यक्ष महोदया, वर्ष 2018–19 में 150 मिनी बसें खरीदने का हमारा परपोज़ल है। क्योंकि किसी रूट पर या हिल एरिया में केवल 20–25 ही लड़कियां स्कूल के लिए आती हैं और हमें 52 सीट वाली बस भेजनी पड़ती है। वर्ष 2018–19 में परिवहन विभाग के लिए 2538.40 करोड रूपये के परिव्यय का प्रस्ताव है जोकि संशोधित अनुमान वर्ष 2017–18 के 2239.43 करोड रूपये की तुलना में

13.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2013–14 में 11.58 लाख किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से हरियाणा रोडवेज की बसें सफर तय करती थी और अब 12.61 लाख किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से हरियाणा रोडवेज की बसें सफर तय करती है।

श्री महीपाल ढांडा (पानीपत–ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय वित्तमंत्री जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक बहुत ही शानदार बजट, हरियाणा की जनता के हकों के लिए और हितों के लिए प्रस्तुत किया है । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, जो लोग अंधे होते हैं उनको तो रास्ता दिखाना पड़ता है लेकिन जो आँखें होने के बावजूद भी जानबूझ कर अंधे होते हैं, उनको कोई भी रास्ता नहीं दिखा सकता अर्थात् भैंस के आगे बीन बजाने का कोई भी लाभ नहीं है। विपक्ष में जितने माननीय सदस्यगण सदन में बैठे हुए हैं, उनकी बजट के बारे में इसी प्रकार की सोच है।

13:00 बजे

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री महिपाल ढांडा: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जितने रिकार्ड तोड़ कार्य किये हैं, पिछली सरकारों के कार्यकाल में उतने कार्य नहीं हुये।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे आरोप–प्रत्यारोप लगाने की बजाए अपनी बात पूरी करें क्योंकि अभी 26 माननीय सदस्यों को भी सदन में अपने हल्के की बात रखनी है। इसलिए वे बजट के बारे में अपनी बात पूरी करें ताकि दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का समय मिल सके। माननीय सदस्य हमारे बारे में कुछ कहेंगे तो हमारी पार्टी के माननीय सदस्य भी उस बात का जवाब देंगे। इससे कोई फायदा नहीं होगा बल्कि सदन का कीमती समय बर्बाद होगा (विघ्न)।

उपाध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, सदन में हैल्दी बात करें।

श्री महिपाल ढांडा: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने रिकार्ड तोड़ कार्य किये हैं और जो कार्य दूसरे दलों की सरकारें नहीं कर पायी थी, वे कार्य हमारी सरकार ने करके दिखाये हैं। पहले हमारी

माताएं/बहनें खाना पकाते समय धूएं से परेशान रहती थीं इस समस्या का समाधान हमारी सरकार ने प्रदेश को कैरोसीन मुक्त करके किया है। क्या यह बात किसी आंख वाले व्यक्ति को नजर आयी है ? सरकार ने प्रदेश को खुले में शौच मुक्त करवाया है। पूरे प्रदेश को ओ.डी.एफ. करवाया है जिसके कारण बीमारियां फैलने का खतरा हट गया है। हरियाणा प्रदेश में 22 कॉलेजों का निर्माण करवाया है जिसके कारण एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रान्ति आयी है। इसके बारे में विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कोई बात नहीं की है (विघ्न)।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपने मुंह मियां मिटठू हो रहे हैं।

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने 300 नहरों की टेलों तक पानी पहुंचाया है। पहली बार हरियाणा में कोई ऐसा मंत्री बना है जिसने कहा कि अगर किसी भी माननीय सदस्य के हल्के की सड़कें टूटी हुई हैं तो उन सड़कों के बारे में लिखकर दे दें, लेकिन किसी भी विधायक ने यह लिखकर नहीं दिया कि उनके हल्के की सड़के टूटी हुई हैं। हमारे एक माननीय सदस्य डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जी ने कहा है उनके हल्के में सड़के टूटी हुई हैं और किसी भी माननीय सदस्य ने टूटी हुई सड़कों की बात नहीं उठायी है। (शोर एवं व्यावधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, हमारे पास विभाग से आर.टी.आई. के माध्यम से ली गयी जानकारी है जिसमें टूटी हुई सड़कों के बारे में लिखा हुआ है। (शोर एवं व्यावधान)

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदया, अगर माननीय सदस्यों के हल्के की सड़के टूटी हुईं हैं तो आपने यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया ?

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कलैरिफाई करना चाहूंगा कि मैंने पहले बजट में टूटी हुई सड़कों की बात उठायी थी। उसके बाद दूसरे, तीसरे तथा चौथे बजट में भी टूटी हुई सड़कों की बात सदन में उठायी है। इन चारों बजट सत्रों के दौरान ही टूटी हुई सड़कों की बात उठायी है।

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदया, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हरियाणा नम्बर वन का झूठा नारा देते थे। इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए

कि पिछली सरकार द्वारा कुछ काम नहीं किया गया। इसलिए विपक्षी सदस्यों ने इतनी सारी डिमांडज सरकार के सामने रखी हैं (शोर एवं व्यावधान)।

श्री कुलदीप शर्माः उपाध्यक्ष महोदय, मैं करनाल में रहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी करनाल हल्के से विधायक हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि वहां की सभी सड़के टूटी पड़ी हैं। शायद इस बात के बारे में माननीय सदस्य को पता नहीं है।

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि करनाल की कोई भी सड़के टूटी हुई नहीं है (शोर एवं व्यावधान)।

श्री कुलदीप शर्माः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे हल्के की सड़के टूटी हुई हैं (विघ्न)।

उपाध्यक्ष महोदयः शर्मा जी, प्लीज आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी करने दें। (शोर एवं व्यावधान)

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए वह काम किया है। (शोर एवं व्यवधान) जो आज तक अपने आपको किसान नेता कहने वाले लोग काम को करना तो दूर की बात है, वे आज तक इस बारे में सोच ही नहीं पाए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं नकली किसान हितैषी लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि जब उन सब लोगों की सरकारें रहीं तो उन सरकारों ने किसानों के हक के लिए और उनके हितों के लिए कौन सी ऐसी योजनाएं बनाईं जिसमें सीधे तौर पर किसानों को लाभ मिला हो। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भावांतर भरपाई योजना एक ऐसी योजना लेकर आए हैं, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकार द्वारा किसी भी किसान को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदया, विपक्षी सदस्य कहते हैं कि वर्तमान सरकार किसान विरोधी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये हमें बताएं कि सरकार कैसे किसान विरोधी है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं खुद श्री अभय सिंह यादव जी के साथ हथनी कुंड बैराज पर गया था और हमने पूरी की पूरी नहर का दौरा किया था। उपाध्यक्ष महोदया, मैंने उस वक्त चीफ इंजीनियर से पूछा था कि आप यहां पर कब से हो तो उसने जवाब दिया था कि सर, मैं तो रिटायर होने वाला हूं। उपाध्यक्ष महोदया, उस समय हमने एस.डी.ओ. और एक्स.ई.एन. से पूछा कि आप यहां पर पहले कब आए थे तो सुनकर मुझे हैरानी हुई थी, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि सर, आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी विधायक ने

पूरी की पूरी नहर का दौरा किया है। उपाध्यक्ष महोदया, ये लोग पानी की बात करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि नकली किसान नेता पानी की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, वहां पर सारा का सारा सिस्टम खराब पड़ा हुआ है और उन खराब सिस्टमों को ठीक कराने के लिए इनके पास बजट में पैसा नहीं होता था। उपाध्यक्ष महोदया, जो लोग उधर बैठकर बार–बार बोलते हैं कि हमने विकास का काम किया, लेकिन उनके बजट में कुछ नहीं होता था। उपाध्यक्ष महोदया, मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि उसी बजट में से हरियाणा की सरकार ने 143 करोड रुपया देकर उस सिस्टम को ठीक करवाकर उसकी पूरी की पूरी रचना तैयार करवाई है। उपाध्यक्ष महोदया, ये लोग कह रहे हैं कि किसानों के हित के लिए इस बजट में कुछ नहीं हुआ है और कह रहे हैं कि हमारी सरकार किसान विरोधी है। उपाध्यक्ष महोदया, अगर हमारी सरकार किसान विरोधी सरकार है तो जो पहले किसान हितैषी सरकार थी, ये हमें एक भी उपलब्धि बताएं कि इनकी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है ? उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने केवल किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि उद्योग और इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। उपाध्यक्ष महोदया, यह जो इज ऑफ डूईंग बिजनेस है, जिसमें हम 14वें स्थान पर खड़े थे, लेकिन आज हमारी सरकार के प्रयास के कारण इस क्षेत्र में भी हम पहले स्थान पर आकर खड़े हो गए हैं। उपाध्यक्ष महोदया, जो हमारे पुराने औद्योगिक क्षेत्र थे उनको डैवल्प करने के लिए इस बजट में सरकार द्वारा 1400 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे हल्के में इंडस्ट्रियल एरिया बहुत है, इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिये को डैवल्प करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया है। उपाध्यक्ष महोदया, दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे मंत्री श्री विपुल गोयल जी हैं इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। उपाध्यक्ष महोदया, इन्होंने हमारे हर जिलों में रोजगार मेले लगाने शुरू कर दिये। (शोर एवंव्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, मैं कांग्रेस के सारे कारनामों को यही पर बताऊंगा। उपाध्यक्ष महोदया, ऐसा काम पहली बार हुआ है कि श्री विपुल गोयल जी ने हमारे हर जिलों में रोजगार मेले लगाने शुरू कर दिये। जब वह रोजगार मेले लगे तो उन्हीं रोजगार मेलों के अंदर 42 हजार से ज्यादा नौजवानों को नौकरी वहीं पर मिली है। उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने समाधान दिवस के माध्यम से इंडस्ट्रीज के लोगों के सामने किस प्रकार की समस्याएं हैं और उनको कैसे दूर

किया जा सकता है, इस प्रक्रिया को अपनाया है। उपाध्यक्ष महोदया, हम लोग यहां पर किसान, मजदूर और गरीब की बात करते हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने उनके लिए कोई काम नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इन्होंने इनके लिए क्या काम किया है ? उपाध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछले सारे रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो पता चल जाएगा कि इन्होंने किसानों या श्रमिकों के लिए कोई काम नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं पूर्ववर्ती सरकारों से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने पिछले 10 सालों में श्रमिकों के लिए कौन–सा ऐसा काम किया जिससे उनका उत्थान हुआ है ?

मैं बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के दस साल के कार्यकाल में 28 करोड रुपये का बेनिफिट 19 हजार श्रमिकों को दिया गया था जो कि बड़े शर्म की बात है । मैडम, जब हमारी सरकार बनी तो विपक्ष के साथी अनुभवहीन सरकार कहते थे लेकिन जिस तरह से इन्होंने 19 हजार श्रमिकों को दस साल में केवल 28 करोड रुपये का बेनिफिट दिया उससे तो ये लोग अनुभवहीन लगते हैं और पैसा भी इन्होंने कोर्ट के आदेश के बाद दिए थे । मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पीछे जो 10 साल सरकार चली और उससे पहले जो 5 साल सरकार चली वे राम भरोसे ही चल रही थी क्योंकि उस दौरान कोई विशेष योजनाएं प्रदेश की भलाई के लिए नहीं बनाई गई । श्रमिकों के लिए हमारी सरकार ने एक विशेष योजना बनाई जिसके तहत तीन साल में 328 करोड रुपये का बेनिफिट 3 लाख श्रमिकों को दिया गया है। क्या श्रमिकों को दिए गए 328 करोड रुपये का बेनिफिट विपक्ष के साथियों को दिखाई नहीं देता ? (विघ्न) मैडम, यदि विपक्ष के साथी कुछ बोलना चाहते हैं तो इन्हें बोलने दिया जाये क्योंकि मैं आंकड़ो के आधार पर फैक्ट्स की बात कर रहा हूं । विपक्ष के साथियों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदया : ढांडा साहब, आप कंकलूड करें ।

श्री महीपाल ढ़ांडा : मैडम, अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है और हमारी सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हुई हैं जिनसे आम लोगों को फायदा हुआ है । उनके बारे में मैंने कुछ बातें बोलनी हैं इसलिए मुझे थोड़ा समय और दिया जाये । मैडम, हमारी सरकार ने सक्षम योजना शुरू की है जिसके तहत पढ़े लिखे युवाओं को 100 घंटे रोजगार देना सुनिश्चित किया गया है । 7500 रुपये से लेकर 9 हजार रुपये तक का मानदेय देकर 20 हजार युवाओं को सक्षम योजना के तहत

रोजगार दिया गया है । यदि मैं पिछली सरकारों की बात करूं तो इन्हें मालूम ही नहीं था की सक्षम योजना भी कुछ होती है जिसके तहत पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके । (शोर एवं व्यवधान) मैडम, विपक्ष के साथियों को कोई जानकारी नहीं है । ये सदन में गलत तथ्य रखते हैं जो तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता की भलाई के लिए बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः गीता भुक्कल, जी प्लीज आप बैठें ।

श्रम रोजगार अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : मैडम, विपक्ष के साथियों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उनको हमारी बहुत सी योजनाओं की जानकारी ही नहीं है क्योंकि वे बिना तैयारी के यहां आते हैं। जो नौजवान सक्षम योजना के तहत काम कर रहे हैं उन्हें हमने 884300900 रुपये का अलाउंस दिया है और 526420194 रुपये का ऑनरेरियम दिया है । यदि गीता भुक्कल जी की जानकारी में कोई ऐसा पढ़ा–लिखा युवा है जिसको इस योजना के तहत 100 घंटे रोजगार नहीं मिला तो उसकी जानकारी ये हमें दे दें उन्हें घर से बुलाकर रोजगार दिया जायेगा । (विघ्न)

श्री महीपाल ढांडा : मैडम, इसी तरह से प्रेदश के युवाओं का स्किल डिवैल्प करने के लिए हर जिले में सिंगापुर और जर्मनी की तर्ज पर मॉडर्न आई.टी.आई. खोलने की योजना बनाई है । जिनमें हमारे प्रदेश के जो नौजवान तैयार होंगे उन्हें रोजगार के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा बल्कि प्रदेश में ही उनको रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे । इस योजना से प्रदेश के युवाओं में खुशी की लहर है क्योंकि अब उन्हें नौकरी के लिए कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी । (विघ्न) मैडम, इसी तरह से जब हम पहले सरकारी हास्पिटल्ज में जाते थे तो वहां पर मरहम पट्टी के अलावा दूसरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी यदि इसके अतिरिक्त कोई विशेष चिकित्सा सुविधाएं पहले दी जाती थी तो विपक्ष के साथी बता सकते हैं । मैडम, हमारी सरकार बनने के बाद हम चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आम जनता को बहुत सी नयी सुविधाएं दे रहे हैं । अब कुछ जिलों में एम.आर.आई., कैथ लैब, डायलिसिज, सिटी स्कैन आदि की सुविधाएं भी मुहैया करवाई जा रही हैं । जिसका फायदा जो गरीब तबके के मरीज हैं उनको मिल रहा है जबकि पहले वाली सरकारों के समय में गरीब के नाम पर

वोट लेकर लूट मचा रखी थी । हमारी सरकार गरीब और किसान हितैषी सरकार है जिसने सभी वर्गों के फायदे के लिए योजनाएं बनाई हैं । मैडम, अब मैं इण्डस्ट्रीज के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि पिछली सरकारों के समय में इण्डस्ट्रीज के नाम पर ठग्गी की जाती थी और बड़े–बड़े लोगों को बुलाकर योजनाएं बनती थी । हमारी सरकार आने के बाद हमने इण्डस्ट्रिज को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना बनाई हैं और मौके पर जाकर जो दिक्कतें इस क्षेत्र के लोगों को थी उनका हल किया है । विपक्ष के साथियों के पास कहने को कुछ नहीं होता और वे सदन में जिस तरह की अनाप–शनाप बातें करते हैं उनको देखते हुए उन्हें टाईम किल्लर कहा जाये तो गलत नहीं होगा लेकिन मैडम यदि कोई सही बात सदन में बोले तो उसे पूरा समय दिया जाना चाहिए । मैडम, अंत में मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातें मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों के ध्यान में लाना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में एनसल और अलडिगो दो रियल एस्टेट की कंपनीज हैं । इन कंपनीज ने जो क्षेत्र डिवैल्प किया है उनमें पिछले आठ–दस सालों से सड़कें नहीं बनी हैं जबकि लोगों ने वहां रहना शुरू कर दिया है । ये कालोनीज कारपोरेशन को भी हैंड ओवर नहीं हुई हैं । इन कंपनीज में आगे से आगे काम चल रहा है लेकिन जहां पर ये पोजैशन दे चुके हैं और लोग रह रहे हैं वहां पर अभी तक सड़कें नहीं बनवाई हैं । मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इन कंपनीज में जो आगे काम किया जा रहा है उसे तुरंत बंद करवाया जाये और जहां पहले लोग रह रहें हैं वहां पर रोड बनाने के इन्हें आदेश दिए जायें ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े । ये कंपनीज पहले रोड बनायें उसके बाद इन्हें आगे का काम करने के लिए लाईसैंस दिया जाये । मैडम, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि अलडिगो कंपनी ने तो बहुत बड़ा चमत्कार किया कि उसने अपने डिवैल्पड क्षेत्र में से दूसरी कंपनी से पैसे लेकर रास्ता देने का प्रावधान कर दिया। जब हमने उनसे पूछा कि आपने दूसरी कंपनी को यहां से रास्ता किस आधार पर दे दिया तो उनकी तरफ से जवाब मिला कि नियमों के अनुसार रास्ता दिया गया है । हमने पूछा कि कौन से नियम के अनुसार यह रास्ता दिया गया है तो उनकी तरफ से जवाब मिला कि नोटिस बोर्ड पर रास्ता देने के लिए नोटिस लगाया गया था और किसी ने एतराज नहीं किया । मैडम, मैं भी वहीं रहता हूं हमने कोई नोटिस नहीं देखा और न ही किसी के पास कोई नोटिस आया । अभी तीन दिन पहले अलडिगो ने पानी की टंकी की सफाई के बिल का नोटिस निकाल दिया जिसकी

जानकारी तुरंत सभी को मिल गई लेकिन रास्ता देने वाले नोटिस की जानकारी किसी को नहीं हुई । इसका मतलब उसमें गड़बड़ी की गई थी । अलडिगो कंपनी का गेट बहुत सुंदर बना हुआ है यदि वहीं से दूसरी कंपनी को रास्ता दे दिया जायेगा तो वह पूरी तरह से तहस–नहस हो जायेगा क्योंकि वहां से हैवी व्हीकल गुजरेंगे और उस सड़क पर हैवी व्हीकल जाने का प्रावधान नहीं है । जो कंपनी लाईसैंस लेकर वहां पर मकान बनाने जा रही है उसका जी.टी. रोड से रास्ता एक किले का पड़ता है और उधर से घूमकर जायेंगे तो 5 किले का पड़ता है । वहां पर कुछ लोग नांक के नीचे रहकर उल्टा–पुल्टा कार्य कर रहें हैं । इसमें बहुत बड़ा धोखा वहां रहने वाले लोगों के साथ हुआ है इसलिए इसकी स्पेशल जांच करवाकर वहां के निवासियों को न्याय देने का काम किया जाये। मैडम, अब मैं पानीपत शुगर मिल के बारे में बात करना चाहूंगा कि पानीपत शुगर मिल का निर्माण 1952 में हुआ था । हमारे क्षेत्र के किसान चौधरी बंसी लाल जी के पास इस शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने के लिए गये थे । चौधरी बंसी लाल जी ने कहा कि क्षमता बढ़ाने की बात छोड़ो मैं इस शुगर मिल को बंद करवा देता हूं । उसके बाद किसानों ने उनके सामने हाथ–पैर जोड़े तब जाकर उन्होंने इस शुगर मिल को बंद नहीं किया। मैडम, उसके बाद प्रदेश में अपने आपको किसानों की पार्टी कहने वालों की सरकार आ गई । उन्होंने वायदा किया कि उनकी सरकार पानीपत शुगर मिल को बाहर सिफ्ट करेंगी लेकिन सिफ्ट करने की बात तो दूर उन्होंने इस शुगर मिल की मुरम्मत का कार्य भी नहीं करवाया । उसके बाद हुड्डा साहब की सरकार आ गई और उन्होंने भी वहां के किसानों से वायदा किया कि वे इस शुगर मिल को बाहर सिफ्ट करेंगे लेकिन उन्होंने भी अपने दस साल के शासन काल में कुछ नहीं किया। जब हमारी सरकार आई तो हमने इसके लिए कोई वायदा नहीं किया था मगर हमारी सरकार ने एक प्रयास किया है कि इस शुगर मिल की कैपेस्टी बढ़ाई जाये और इसको शहर से बाहर शिफ्ट किया जाये। इसके लिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी अढ़ाई साल पहले पानीपत में गये थे तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि हम इस शुगर मिल की कैपेस्टी बढ़ायेंगे तथा इसको शिफ्ट भी करेंगे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हमारी इस पानीपत शुगर मिल की कैपेस्टी बढ़ा कर इसको शहर से बाहर शिफ्ट किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदयाः ढांडा जी, आप अपनी बात को समाप्त कीजिए। आपको बोलते हुये 22 मिनट का समय हो गया है। दूसरे सदस्यों को भी बोलना है।

श्री महिपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं। पानीपत में अवैध कालोनियां बहुत अधिक हैं जिसकी वजह से उन कालोनियों में कोई काम नहीं हो पा रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी इन कालोनियों को रेगूलर किया जाये। अगर ये कालोनियां वैध हो जायेंगी तो बहुत अच्छा काम हो जायेगा। मेरी अंतिम मांग यह है कि पानीपत का जो बस अड्डा है उसको भी शहर से बाहर शिफ्ट किया जाये। मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बस अड्डे को यथाशीघ्र शहर से बाहर शिफ्ट किया जाये ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़ें।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि सरकार ने पानीपत बस अड्डे को बाहर शिफ्ट करने के लिए मंजूरी दे दी है। सैक्टर 13 और 17 में सिटी बस सर्विस और वर्कशॉप बनेगी तथा बस अड्डा सिवाह गांव में शिफ्ट होगा। अप्रैल के महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम इसकी आधारशिला रखवाने जा रहे हैं।

Smt. Kiran Chaudhry (Tosham): Madam Deputy Speaker, I think that the Budget is completely vision-less and it does not lay-out a concrete road-map for the flagging economy of the State. Madam, the worst thing is that it does not address any issues of any section of society in Haryana. The BJP Government claims good fiscal management but I am sorry to say to the Hon'ble Finance Minister that the debt liability is projected to go from Rs.1,41,792 crore to Rs.1,61,159 crore. This itself shows that the fiscal management and plan of the Government is completely in doll-drums. Secondly, the revenue deficit has been projected at Rs.8253 crores for the year 2018-19 against the revised estimates of Rs.8226 crore for the year 2017-18. Madam, the fiscal deficit which is the another key, fiscal indicator has been proposed at Rs.19399 crore as against 16240

crore in 2017-18. Madam, this clearly shows that there is a slippage at both ends. It does not match at all. The worst thing is that the Government has not shown any inclination to reign in the wasteful expenditure that it has been doing on the blitzkrieg on the publicity and on other various functions which were not really required. The current example is Geeta Jayanti Programme on which about Rs.20 crore have been spent according to Government's record. Apart from that ,Madam, since the State came into existence in 1966 till 2014, the debt of the State was hardly Rs.70,000 crore but today it has become more than the double and that itself shows in where Haryana is headed. No concrete measures have been taken to make for the development of the State. Madam, the worst thing is that no concrete measure has been taken by the State to lessen the Rs. 1.6 Lakh Crore amount of debt which is piling up year after year during the past three years. And this is going to lead us on the slippery roads to bankruptcy. We are on the road to bankruptcy. And I am sorry to say Madam that the CAG Report was presented today and we had no chance of studying this CAG Report. I wish it had been presented a day earlier or may be during the weekend so that we could have seen and what exactly the Government has been upto. But unfortunately the report comes to at a time that even we cannot go through what is written in it. I would also like to say Madam, that political gimmick a very apparent in this "Vidai Budget" I would like to say because this is the "Vidai Budget" of the Government and madam, बेदी जी, आप बाद में बोल लेना । मैंने आपको बोलते हुए कभी डिस्टर्ब नहीं किया है इसलिए आप भी सुनने की क्षमता रखिये । (शोर एवं व्यवधान) Madam, the State has not done anything to take away the burden some VAT on Diesel and Petrol which was an oppressively increased from 21 per cent to 26.5 per cent on Petrol and 9.24 to a

mammoth 17.24 per cent on Diesel. So this is how the State is being managed. This is where they should have done something and brought the VAT down so that the common-man would have been given some relief. Also at the same time Madam, I was going through the Budget paper, 100 crores have been allocated to SYL. Now this is another gimmick. This year again they allocated another 100 crores. And at the same time Madam, nothing happened. The State has not even begun to start the process of digging the SYL canal from the Punjab side so that we can get SYL canal water back into Haryana. Our fields are parched, our farmers are crying. We have no water. There is no water to at the tail-end as has been time and again put forward by the treasury benches.

श्री कृष्ण कुमार बेदी : किरण जी, आपकी सरकार ने जो हांसी बुटाना नहर बनाई थी उसका क्या हुआ । एस.वाई.एल. नहर की बात तो आप कर रही हैं । यहां हरियाणा प्रदेश में 40 साल से किसकी सरकार रही है । हांसी बुटाना नहर का क्या हुआ ? आप उसका जवाब दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदया : बेदी जी, प्लीज आप बैठ जाईये ।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया, इन्होंने 100 करोड रूपये अलोकेट करके रख दिये और कहते हैं कि हजार करोड भी देंगे । आप हजार करोड कब दोगे और एस.वाई.एल. नहर का पानी कब आएगा । कब हमारे किसान को पानी मिलेगा । This is apparently, totally and completely a political gimmick. Madam, I am sorry to say but I want to put this on record that big promises have been made in the Budget and as far as our promises are concerned they are very big. But when it comes to execution I think it is a complete zilch situation. Nothing has been done for the farmers and for the youths as far as employment is concerned. Now, I start it elaborating. I do not want to elaborate on subject which have already been spoken on. Madam no provision has been made for the farmers in terms of MSP. They should talk about the Swaminathan Report. But today no provision as far as MSP is concerned is being made. Mustard is being sold in the "Mandis" at less then the MSP. I am not saying this,

the newspaper are reporting everyday. मण्डियों के अन्दर इतना बुरा हाल हो रहा है कि एम.एस.पी. के ऊपर मस्टर्ड की बिक्री नहीं हो रही है । साथ की साथ They make tall promises on employment but the actual situation is that they are completely clueless on the situation of employment and they have really not done anything according to their election manifesto promise which they had promised long time ago. Madam Government mal-administration has burdened the State with a great deal of liability. Government has to pay thousands crores of rupees in terms of interest. Madam what is the result of it? The result is that you have to cut down the allocation for the key sectors i.e. Public Health, Education, Power, Transport, Panchayati Raj etc. I do not blame him. It is a fact. What is happening is that-when you cut the allocation of the important sectors then there is no development. Nothing happens in future? The entire development system comes down to a standstill. It is actually the situation. We have reached at a complete dead-end as far as these things are concerned. Madam, I would like to pick up one or two more issues. उपाध्यक्ष महोदया, पिछले बजट में आई.टी.आईज. के बारे में लिखा हुआ था कि वर्ष 2017–18 में 15 आई.टी.आईज. स्थापित की जायेंगी वहीं इस वर्ष के बजट में कहा गया है कि 20 आई.टी.आईज. स्थापित की जायेगी जबकि असलियत में इन 20 आई.टी.आईज. में 9 आई.टी.आईज. वह शामिल हैं जिनकी पिछले साल के बजट में घोषणा हुई थी। इसका मतलब तो यह है कि बजट में केवल मात्र जगलरी ही की जा रही है और बातों को तोड़–मरोड़कर पेश किया जा रहा है। वास्तव में सरकार के पास कोई ऐसी चीजें ही नहीं बची हैं जिनको वह अमलीजामा पहनाते हुए लोगों को दिखा सके। इसके साथ ही माइनर्ज की रिहेबिलिटेशन के संबंध में जो बजट में बात कही गई है, के संदर्भ में मैं दावे के साथ बताना चाहूंगी कि हमारे इलाके में जो पंजोखरा माइनर, कैरू माइनर या जुई फीडर के लिए 150 करोड रूपये की लागत से काम शुरू करने की बात कही गई है, केवल खोखले दावे की बात है। यहां पर एक ईंट लगाने तक का काम नहीं हुआ है और रिहेबेलिटेशन का किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अनेक बार लोहारू में गए हैं और इस क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ भी है लेकिन यहां पर भी पम्प न. 1 से पम्प न. 8 तक जो सिवानी कैनाल का एरिया है, उसकी रिहेबिलिटेशन का काम शुरू नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया,

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इसका काम जल्द से जल्द शुरू करवा दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, बड़े जोर–शोर के साथ कहा जाता है कि हरियाणा प्रदेश में अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जायेगा जबकि असलियत यह है कि जब रिहेबिलिटेशन का काम पूरा ही नहीं हुआ है तो टेल तक पानी कैसे पहुंचेगा? उपाध्यक्ष महोदया, पहले इरीगेशन डिपार्टमैंट की तरफ से सिंचाई के लिए 32 दिन के अंतराल पर पानी दिया जाता था लेकिन आज इस अंतराल को बढ़ाकर 41 दिन कर दिया गया है। इसकी वजह से भी किसान भाई बहुत परेशान हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगी कि यह कौन सा रोड मैप जनता के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या इस तरह की कार्रवाई से हरियाणा प्रदेश के हर खेत को पानी उपलब्ध करवाया जा सकेगा? आज हरियाणा प्रदेश की नहरों में पानी नहीं है और सरकार कह रही है कि प्रदेश की अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जायेगा। हमारा इलाका तिसाया मर रहा है, सरकार को हमारे इलाके की तरफ ध्यान देते हुए प्रभावी कदम उठाकर बेहतरी के प्रयास करने की जरूरत है। (शोर एवं व्यवधान)

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी): उपाध्यक्ष महोदया, आज कांग्रेस की यह नेत्री इतनी बड़ी–बड़ी बातें सदन में कर रही हैं लेकिन इनकी पार्टी के नेता श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी पंजाब में जाकर कहते हैं कि एस.वाई.एल. नहर के पानी की एक बूंद तक हरियाणा को नहीं जाने देंगे और उन्हीं की पार्टी की नेता यहां पर सदन में यह बयान कर रही हैं कि हरियाणा प्रदेश के खेतों को पानी नहीं मिल रहा। उपाध्यक्ष महोदया, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का कोई स्टैंड नहीं है और मैं आपके माध्यम से किरण जी से अनुरोध करता हूँ कि आपका सैलीब्रेशन–डे आने वाला है, आप उसको सेलिब्रेट कीजिए, आपके लिए रास्ता खुल गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदया, मुझे बीच में इंट्रप्ट न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया: बेदी जी, एक बार माननीय सदस्या को अपनी बात पूरी कर लेने दें उसके बाद आप अपनी बात रख लेना।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदया, एस.वाई.एल. नहर के पानी पर हरियाणा प्रदेश का अधिकार है लेकिन इस नहर के पानी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आए हुए भी एक साल से अधिक का समय हो गया है लेकिन बावजूद इसके एस. वाई.एल. नहर के पानी को हरियाणा प्रदेश में लाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदया, एस.वाई.एल. नहर का पानी न मिलने की वजह से आपका इलाका भी इफेक्ट हो रहा है। यदि यह पानी आता है तो आपका इलाका भी इस पानी से सिंचित होगा, लेकिन अफसोस है कि आज तक सरकार ने इस संदर्भ में भी एक ईंट तक लगाने का काम नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं पब्लिक हैल्थ के संबंध में अपनी बात रखना चाहूंगी। लक्षमणपुरा, ढ़ाणी दरियापुर गांव के वाटर पंप्स निर्माण के लिए हमने वर्ष 2013–14 में पैसे दिलवाये थे लेकिन आज तक यह निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसी प्रकार बापोड़ा और दिनोद जो दो गांव हैं, इनमें सिवरेज का काम करवाने की बात कहीं गई है, अब विश्वास न हो तो सरकार की घोषणा से संबंधित दस्तावेज निकलवाकर देखा जा सकता है, परन्तु अफसोस है कि इस घोषणा को हुए तीन साल का समय गुजर चुका है लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई भी कार्य शुरू नहीं किया गया है। आज हमारे एरिया के अनेक ऐसे गांव हैं जहां लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। गांव किरावड, खानक, बिढ़ोला, छप्पार, रागड़ान, संडवा, भूसान, साल्हेवाला, पंजोखड़ा, खरकड़ी माखवान, आल्मपुर, कोहाड़, बिजलाना, छपार जोगियान तथा बादलवाला आदि अनेक ऐसे गांव हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। यह तो कुछेक गांव हैं जिनके मैंने नाम गिनाए हैं इनके अतिरिक्त भी ऐसे न जाने कितने गांव हैं जहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। आज भिवानी के किसान ढ़ोल पीट–पीट कर सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की तरफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक भी ढ़ोल बजाने की कार्रवाई में शामिल हैं लेकिन बावजूद इसके हमारे क्षेत्र में सरकार द्वारा आज तक कोई काम पूरा नहीं किया गया है। वूमन एम्पावरमैंट की बात चली है । यह बहुत अच्छी बात है और वूमन को एम्पावर किया जाना चाहिए। इसके तहत महिलाओं के लिए सप्लीमैंट्री न्यूट्रीशन प्रोग्राम चलाया गया है । अगर इसकी गहराई में देखा जाए तो इस Supplementary Nutrition Programme के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरी तरह से आहार उपलब्ध नहीं करवाया गया है । जो आंकड़े सामने आये हैं Haryana has fallen down as far as nutrition is

concerned. हम सूची में बहुत बुरी तरह से नीचे गिर रहे हैं । कुछ समय पहले हम बाकी सारे स्टेट्स से आगे थे । अब हम बहुत पीछे आ गये हैं । अब मैं जिस प्वायंट पर बात कर रही हूं उसे माननीय मंत्री जी नोट कर लें । अभी महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की गई थी – 'उज्ज्वला ग्रामीण योजना' । मैं पूछना चाहती हूं कि इस योजना के तहत कितनी गरीब महिलाओं को लाभ मिला है और कितनी गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है ? (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, मुझे इस योजना की जानकारी नहीं है । अतः माननीय सदस्या मुझे इसके बारे में डिटेल में बता दें तभी मैं इसके बारे में कुछ बता पाऊँगा । (विघ्न)

Smt. Kiran Choudhry : Hon'ble Deputy Speaker Madam, there was some NGO in Narnaul and they said that they would be doing this specific work for women empowerment.

Captain Abhimanyu: Hon'ble Deputy Speaker Madam, can I request Hon'ble CLP leader to please elaborate and give some more details about the scheme about which she is talking.

Smt. Kiran Choudhry : OK. If the Minister requires the details, I will give the details. At this moment I have a lot of other points to raise, so I will give you the details later. But I want to tell the House what exactly it is.

Captain Abhimanyu : Madam, Deputy Speaker, how can I respond on the issue of which I do not have details. She may give the details about the issue which she is raising. Only then I can respond to it. I would like to respond to each and every word of the Learned CLP Leader.

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्कीम महिलाओं को सशक्त करने के लिए बिजली की स्कीम थी । यह इसी सरकार की बनाई हुई स्कीम है । मैं जानना चाहती हूं कि इस स्कीम का क्या हश्र हुआ है ? अगर इस बारे में माननीय मंत्री जी को नहीं पता है तो उन्हें इसके बारे में अपनी सरकार से पता करना पड़ेगा । **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए ।)** अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूं कि इस बजट में बहुत–से नये–नये प्रावधान और प्रोजैक्ट्स दिखाए हुए हैं । मेरा कहना है कि इनमें से अधिकतम प्रोजैक्ट्स के केवल नाम बदलकर उन्हें नये प्रोजैक्ट के रूप में दिखाया गया है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में 3 साल पहले 'आदर्श ग्राम योजना' की घोषणा की थी । उन्होंने इसके बारे में कहा था कि हर

विधायक हर साल एक गांव अडॉप्ट करेगा । इस योजना को शुरू किये हुए 3 साल हो चुके हैं । मैंने एक गांव बापौड़ा को अडॉप्ट किया था । इस गांव के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और विभिन्न अधिकारियों को हजारों चिट्टियां लिख चुकी हूं । उस गांव के विकास कार्य करवाने के लिए मेरे पास आज तक पैसा नहीं आया है । अब सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर 'महाग्राम विकास योजना' कर दिया है । सरकार ने इस योजना का सिर्फ नाम ही बदला है बाकी सब कुछ वही है । मेरा कहना है कि आप केवल एक योजना पर ही काम कर दीजिए । हम उसी से खुश हो जाएंगे । इसके बाद सरकार ने टॉयलेट्स की बात की । इसमें कहा गया कि हम हरियाणा को ओपन डैफिकेशन फ्री स्टेट बनाएंगे । अभी हरियाणा ओपन डैफिकेशन फ्री होने से बहुत दूर है । मुझे इस बात का दुख हुआ कि इस मामले पर भिवानी के डी.सी. को राष्ट्रपति के पास ले जाकर सम्मानित करवाया गया । मैं आपको वहां के आंकड़ें बताना चाहती हूं । बाढ़ड़ा ब्लॉक में 3,202 टॉयलेट्स, बोंद ब्लॉक में 2,153 टॉयलेट्स, बहल ब्लॉक में 3,818 टॉयलेट्स, कैरू ब्लॉक में 1,534 टॉयलेट्स, लोहारू ब्लॉक में 1,352 टॉयलेट्स, सिवानी ब्लॉक में 5,96 टॉयलेट्स और तोशाम ब्लॉक में 3,650 टॉयलेट्स अभी भी पैंडिंग हैं । इन पर अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है जबकि हरियाणा सरकार का कहना है कि हरियाणा ओपन डैफिकेशन फ्री हो गया है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, अब आप सिर्फ 2 मिनट में वाइंड अप कर लीजिए ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, इसके बाद एजुकेशन की बात कही गई है । मैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहती हूं । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने ग्रामीण विकास की कई बातें कही हैं जो तथ्यों से परे हैं । उनका आपस में कोई संबंध नहीं है । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, अब माननीय मंत्री जी मेरे बोलने के समय में जितना समय ले रहे हैं मैं उतने ही ज्यादा समय तक बोलूंगी । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, 'आदर्श ग्राम योजना' अलग योजना है, छोटूराम ग्रामोदय योजना' अलग योजना है, 'श्यामाप्रसाद रूर्बन मिशन' एक अलग योजना है । ये एक जैसी दिखने वाली सभी योजनाएं अलग–अलग हैं । (विघ्न) आप एक पढ़ी–लिखी महिला लीडर हैं । आपको इन योजनाओं को समझना पड़ेगा । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्या को सही राह दिखा रहा हूं लेकिन ये झूठ बोलना चाहती हैं । यह गलत बात है । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, आप मंत्री जी को बिठाइये । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या को इन योजनाओं को मिक्स नहीं करना चाहिए । ये सदन में गलत तथ्य बता रही हैं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, माननीय मंत्री जी आपको इन योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं जिनकी आप बात कर रही थी । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष जी, जब सत्ता पक्ष के सदस्य सदन में अपनी बात रखते हैं तब भी माननीय सदस्या उन्हें बीच में डिस्टर्ब करती है । अब भी ये सदन में सरेआम गलत बात कह रही हैं । इन्हें सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए । ये सदन में ठीक जानकारी लेकर ही अपनी बात रखें । (विघ्न) अब हम जनता को गुमराह नहीं होने देंगे । अब झूठ की राजनीति बहुत हो गई । अब राजनीति सही आंकड़ों पर चलेगी । अगर सदन में कोई गलत जानकारी देगा तो हम उसे वहीं पर टोकेंगे । कांग्रेस ने 60 साल तक झूठ की राजनीति की है । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । मैं सदन में आंकड़ों के हिसाब से बात कर रही हूं । मैं माननीय मंत्री जी को एजुकेशन के बारे में कुछ सुझाव देना चाहती हूं । माननीय मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं । ये शिक्षा के बारे में बहुत बड़ी–बड़ी बातें कह रहे थे । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि वे देखें कि ग्राउण्ड लेवल पर क्या चल रहा है । प्रदेश में मैट्रिक और सैकेण्ड्री लेवल बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है । माननीय मंत्री जी प्रदेश में ओनलाइन एडमिशन की बात करते हैं । आज के दिन हमारे बच्चे they are not capable of doing online admission क्योंकि अभी उन्हें इसकी नॉलेज नहीं है । अतः मेरा आग्रह है कि उनको इसका कुछ प्रशिक्षण दिया जाए । इससे वे अपना ओनलाइन एडमिशन करवा सकेंगे । अभी उनका इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है । इसी तरह से शिक्षा बोर्ड ने एच.टी.ई.टी. करवाने के टैण्डर निकाले हुए हैं । उसमें व्यापक रूप से करप्शन किया गया है । उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि सरकार की जीरो टॉलरैंस की बात सही मायने में सामने आये । अब मैं गैस्ट टीचर्स के बारे में बात करना चाहूंगी । सरकार ने

वायदा किया था कि हम उनको समान कार्य के बदले समान मानदेय देंगे । अभी भी उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं । अतः सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए । (विघ्न) मैं अपने क्षेत्र तोशाम के बारे में बात करना चाहूंगी । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपको अपने क्षेत्र के बारे में पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी । (विघ्न) मैंने आपको बोलने के लिए 2 मिनट का समय दिया था जबकि आप 3 मिनट तक बोल चुकी हैं । अब आप बैठ जाइये । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, वैसे तो आप अन्य सदस्यों को काफी देर तक बोलने देते हो लेकिन हमारे बोलने के समय पर हमारा टाइम कट कर देते हो । मैं ठीक बात कह रही हूं, इसलिए आप मेरी बात सुन लीजिए । (विघ्न) गवर्नमैंट सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल निगाना कलां, हसान–रूडान–लोहानी, गवर्नमैंट हाई स्कूल कालेवाला, गवर्नमैंट हाई स्कूल सूरजपुर, धारीपुर, ढांगर, आलमपुर, गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल लोहानी और अन्य सारे स्कूल्स से संबंधित एक बहुत ही अहम मुद्दा है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आपने 1:22 बजे बोलना शुरू किया था और अब 1:44 हो चुके हैं । (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष जी, आज आपने हमें बोलने का समय नहीं दिया है । पहले आप कहते थे कि नेता प्रतिपक्ष ने आपका समय ले लिया है । आज तो वे भी सदन में नहीं बोले हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं (विघ्न)।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों को सदन में अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए। (शोर एवं व्यावधान)।

श्री अध्यक्षः संधू जी, नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला को सदन में बोलने के लिए समय दिया गया था और उन्होंने 30 मिनट तक सदन में अपनी बात रखी है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मेरे 3 प्वायंट ही बाकी हैं, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दूंगी (विघ्न)।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, हमें भी बजट पर अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः संधू जी, आप एक सप्ताह का काम एक दिन में करना चाहते हैं। आपने 4 दिन तक सैशन नहीं चलने दिया। इन 4 दिनों के दौरान तो आप बोले नहीं। इसलिए इन 4 दिनों का काम एक दिन में कैसे हो सकता है ? आप बैठ जाएं (विघ्न)।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, हमने सदन को चलने दिया है और कोई व्यावधान नहीं किया (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः संधू जी, बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में जो फैसला हुआ था उसी फैसले के अनुसार ही सदन की कार्यवाही चल रही है (विघ्न)।

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकों को बोलने के लिए समय दिया जाए ताकि अपने हल्के की समस्याओं के बारे सदन में अपनी बात रख सकें। (शोर एवं व्यावधान)।

श्री अध्यक्षः नसीम जी, आप बैठ जाएं। अगर माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाहते तो इस तरह से डिस्ट्रब नहीं करते। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप अपनी बात रखना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप सदन को नहीं चलने देंगे तो अपनी बात कैसे रखेंगे ? एक ही बात पर आपने 2 घंटे 5 मिनट का समय बर्बाद कर दिया (विघ्न)।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, अगर हमें सदन में बोलने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है तो हमें क्यों बुलाया गया था । (विघ्न) हमें बोलने के लिए समय दिया जाए (विघ्न)।

श्री अध्यक्षः संधू जी, आपकी पार्टी के माननीय सदस्यों को सदन में व्यावधान पैदा करने के कारण नेम किया गया था (विघ्न)।

श्री नसीम अहमदः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को बजट पर बोलने के लिए समय दिया जाए (शोर एवं व्यावधान)।

श्री अध्यक्षः नसीम जी, माननीय मंत्री जी को 2:00 बजे बजट के सवालों पर रिप्लाई देना है। (शोर एवं व्यावधान)।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, बजट का कुछ हिस्सा तनख्वाह में चला गया और कुछ हिस्सा भ्रष्टाचार में चला गया तो प्रदेश के विकास के लिए पैसे कहां से आएंगे (विघ्न) ?

श्री अध्यक्षः जगबीर जी, आपको जितने पैसे चाहिए माननीय मंत्री जी उतने पैसे आपको दे देंगे। कल भ्रष्टाचार के बारे में जो खबर छपी थी शायद आपने वह खबर नहीं पढ़ी है (विघ्न)। मलिक जी, आप बैठ जाएं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, हमें गवर्नर एड्रैस पर भी अपनी बात रखने के लिए समय नहीं दिया (विघ्न)।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): संधू जी, आपकी पार्टी के जितने माननीय सदस्य बजट पर बोलना चाहते हैं उन माननीय सदस्यों के नाम अध्यक्ष महोदय को दे दें। सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए समय दिया जाएगा। जबकि नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला और आप पहले ही बोल चुके हैं।(शोर एवं व्यावधान)

श्री अध्यक्षः जगबीर जी, प्लीज आप बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं (विघ्न)।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, जब तक हमें बोलने के लिए समय नहीं दिया जाएगा तब तक हम नहीं बैठेंगे (विघ्न)।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मुझे कन्कल्यूड करने दें। सभी माननीय सदस्यों के लिए बधाई की बात है कि यू.पी के उप चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की विजय हुई है (विघ्न)।

श्री कृष्ण कुमार बेदीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को आगे चुनावों में पता चल जाएगा कि कौन –सी पार्टी विजय होगी ?

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, यू.पी. में सभी जगह कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थन वाले उम्मीदवार चुनावों में विजयी हुए हैं। (शोर एवं व्यावधान)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जैसे आज इनैलो पार्टी के माननीय सदस्यों को सदन में बुलवाया है उनको बोलने के लिए समय दिया जाए

और कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य कल भी सदन में अपनी बात रख चुके हैं। (शोर एवं व्यावधान)

श्री अध्यक्षः जसविंद्र जी, आपके पार्टी के विधायक 2–2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें तो सही होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसविंद्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप हमारे सारे मैम्बर्ज को बोलने के लिए 5–5 मिनट का समय दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जसविंद्र जी, आप सब लोग अपनी बात 2–2 मिनट में ही समाप्त करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि मुझे अपनी बात कंक्ल्यूड करने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, आप अपनी बात कंक्ल्यूड करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कंक्ल्यूड करने जा रही हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे 3 प्वायंट्स हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भिवानी नगरपालिका है वहां पर सरकार के द्वारा औने–पौने दामों पर जमीन बेच दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त है कि वे उसके ऊपर नजर डालें और जो दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे हल्के में जो नहरे हैं जैसे– निगाना माइनर, थिलोड माइनर, बिड़ौला माइनर, दिनोद माइनर, छपार माइनर, आलमपुर माइनर, हसन माइनर और खारियावास माइनर वहां पर पानी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे अहम मुद्दा फारेस्ट का है। अध्यक्ष महोदय, जो मोरनी की पहाड़ियों पर पतंजलि योग पीठ की तकनीकी सहायता से वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार बता सकती है कि इसमें भागीदारी पतंजलि की ही है या उसमें सरकार की भी कुछ भागीदारी है और इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो कैरू का हर्बल पार्क और तोशाम का हर्बल पार्क है उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि आज हमारे पास केवल 7 परसेंट ही फॉरेस्ट कवर है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि ये जो इतने अच्छे हर्बल पार्क बने हुए हैं उनको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है ? अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी सवाल

यह है कि हमारे प्रदेश में आवारा पशुओं का बहुत ही अहम मुद्दा है और सरकार को उसके लिए हर पंचायत में पैसा पहुंचाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मेरी कुछ डिमांडस अभी कहने से रह गयी हैं इसलिए आप कृपा करके इनको मेरी स्पीच का पार्ट बनवा देना।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

***श्रीमती किरण चौधरीः**

सिंचाई एवं जल संसाधन–बजट में यह दर्शाया गया है कि 150 करोड़ रुपये कि लागत से वर्ष 2017–18 में कई माईनर/डिस्ट्रीब्यूट्री को तमींइपसपजंजपवद का काम शुरू हो चुका है। परंतु में दावे के साथ कह सकती हूं कि पिंजोखरा, कैरू, जुई फीडर का काम हतवनदक पर शुरू नहीं हुआ है। सरकार से अनुरोध करती हूं कि सिवानी कैनाल को पम्प न. 1 से पम्प न. 8 तक (लौहारू) काम शुरू किया जाए और तमींइपसपजंजपवद का काम भी इस प्लान में डाला जाए।

जन स्वास्थ्य– लक्ष्मणपुरा और ढ़ाणी दरियापुर गांव में वाटर वर्कस के निर्माण का काम 2013–14 के दौरान मंजूर किया गया था, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। सरकारी घोषणा के अनुसार बापोड़ा और दिनोद के लिए सीवरेज के काम के लिए कोई भी फंड आवंटित नहीं किया गया है।

सड़क– सिवानी से भिवानी वाया तोशाम का बाईपास बनाया जाए क्योंकि चौ. सुरेन्द्र सिंह चौंक पर सारा–सारा दिन जाम लगा रहता है जिससे नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

परिवहन– कांग्रेस सरकार के दौरान मैंने 04 करोड़ रुपये तोशाम वर्कशाप को बनवाने के लिए मंजुर किए थे परन्तु खेद का विषय है कि भाजपा सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया और तोशाम की जनता को दरकिनार कर दिया ।

ग्रामीण विकास और पंचायत– सरकार की आदर्श गांव योजना के तहत अपने राज्य के बापोड़ा गांव (तोशाम) को आदर्श गांव बनाने के लिए प्रस्ताव दिया था। मेरे द्वारा

.....

***चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया**

सरकार से बार–बार आग्रह करने पर भी गांव के विकास कार्यों के लिये इस बार के बजट से कुछ खर्च नहीं किया गया जबकि यह थ्पदंदबपंस लमंत खत्म होने को जा रहा है और वर्तमान के केन्द्रीय मंत्री भी इस गांव के निवासी है परन्तु हतवनदक समअमस पर इस और कुछ नहीं किया जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार सिर्फ दावे करती है और आगे निकल जाती है। इस के संदर्भ में मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, पंचायत राज विकास मंत्री और अतिरिक्त उपायुक्त, भिवानी को बार–बार पत्र द्वारा आग्रह किया गया था कि बापोड़ा गांव के विकास कार्य के लिए जरूरी अनुदान मंजूर किया जाये।

किसानों की समस्याएं– ओलावृष्टि के वजह से जिन किसानों की फसले बर्बाद हुई है उनके नुकसान का मूल्याकंन करके मुआवजा दिया जाए। जिसके लिए भिवानी के किसानों द्वारा सरकार के खिलाफ इसके लिए विरोध व धरना दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय, द्वारा की गई घोषणा अनुसार किसानों को भूमि सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में नहरी पानी उपलब्ध करवाया जाए तथा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने बारे जिससे किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिल सकें।

असंध उप–मण्डल को जिला घोषित करने बारे–लोगों की वास्तविक मांग को देखते हुए असंध उप–मण्डल को जिला घोषित किया जाए क्योंकि यह कैथल, पानीपत और जींद से 45 किलोमीटर की दूरी पर है तथा करनाल से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

चौकीदार संघ की मांग–गांव चौकीदार संघ की मांग है कि उनका वेतन 3500 से बढ़ाकर 10,000 किया जाये और उन्हें टार्च और छाता भी उपलब्ध करया जाए, ताकि वे अपना काम सुचारू रूप से कर सके।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि पशु आवारा नहीं, बल्कि बेसहारा होते हैं। मैं माननीय सदस्या को कहना चाहूंगा कि वे पशुओं को आवारा न कहें।

श्री अध्यक्षः जसविंद्र सिंह संधू जी, आप अपनी बात 2 मिनट में समाप्त करें। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविंद्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप हमारी पार्टी के हर मैम्बर्ज को 5–5 मिनट बोलने का समय दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जसविंद्र जी, आप लोगों को बोलने के लिए 2–2 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविंद्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि हमारी पार्टी के हर मैम्बर्ज को बोलने का मौका देंगे और आपने इसका वायदा भी किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जसविंद्र जी, मैंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया है। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविंद्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे हर मैम्बर्ज को 5–5 मिनट बोलने का समय दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सभी माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाएं, जसविंद्र जी कुछ बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं भी जानना चाहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के मैम्बर्ज को बोलने के लिए कितना समय देंगे ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जो मैम्बर्ज गवर्नर एड्रेस पर बोल चुके हैं तो उनको बोलने का समय नहीं दिया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, दुनिया में कहीं भी कट मोशन पर होने वाली डिसकसन को लेट नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, आपको अपने कट मोशन को दो दिन पहले देना चाहिए था लेकिन आपने अपने कट मोशन को दो दिन पहले नहीं दिया है।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैंने अपने कट–मोशन्ज दो दिन पहले ही दिये थे, आप रिकार्ड निकलवाकर चैक करवा लें।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, जब कट मोशन के ऊपर बात की जायेगी उस समय मैं इस बारे में स्थिति को क्लीयर कर दूंगा। अभी आप कृपया करके बैठ जायें और हाउस की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें और सरदार जसविन्द्र सिंह जी को अपनी बात कहने दें।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू (पेहवा) : स्पीकर सर, मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट इस महान सदन में प्रस्तुत किया, जो बातें बजट पर माननीय सदस्यों द्वारा कही गई और जिन बातों को हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया कि

पहले कितना कर्ज़ हरियाणा प्रदेश के ऊपर 38 वर्षों के दौरान था और उसके बाद हमारी सरकार के समय में कितना कर्ज़ हुआ, कांग्रेस के शासनकाल में कितना कर्ज़ हरियाणा प्रदेश के ऊपर हुआ और वर्तमान सरकार ने हरियाणा प्रदेश के ऊपर कर्ज़ में कितनी बढ़ोतरी की है, मैं इन सभी बातों को न दोहराते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज कर्ज़ 1 लाख 61 हजार करोड रूपये के लगभग सरकार द्वारा बताया गया है यह किस हेतु लिया गया ? जब भी इस बारे में चर्चा की जाती है तो सत्ता पक्ष द्वारा यह कहा जाता है कि इस मामले में पूर्व की सरकारों द्वारा क्या किया गया? अध्यक्ष महोदय, यह चुनाव के समय प्रदेश की जनता की पसंद होती है और अपनी पसंद के अनुसार ही वह किसी पार्टी की सरकार का चुनाव करती है। मैं यह बात मानता हूं कि जरूर हमारी सरकार ने भी कुछ गलतियां की होंगी जिनके कारण हमारी सरकार को प्रदेश की जनता द्वारा बदला गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार को भी प्रदेश की जनता ने नापसंद कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम हरियाणा प्रदेश का इतिहास देखते हैं तो महसूस होता है कि वर्तमान सरकार के समय में जो यह कर्ज़ बढ़कर 1 लाख 61 हजार करोड रूपये हो गया है तो फिर परिस्थितियों में कोई बदलाव तो मौजूदा सरकार से भी नहीं हो पाया है। वर्तमान बजट में कृषि क्षेत्र के लिए जो राशि रखी गई है उसमें सरकार द्वारा कमी की गई है। बच्चों को रोजगार देने के लिए जो धनराशि रखी गई है उसमें भी कमी की गई है। इससे यह कैसे माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार के स्तर पर कोई ठोस कदम उठाये जायेंगे। इसी प्रकार से हमारे कृषि मंत्री जी यह बात करते हैं कि उनकी सरकार वर्ष 2022 तक प्रदेश के किसानों की आय दुगुणी कर देगी। कृषि मंत्री जी से हमने पहले भी सदन में बार–बार यह पूछा है कि वे पहले प्रदेश की जनता को यह तो बतायें कि वर्तमान समय में प्रदेश के किसानों की आय कितनी है जिसको सरकार वर्ष 2022 में बढ़ाकर दुगुणी करने का प्रचार कर रही है। इस मामले में सबसे अच्छी बात तो यह होती कि कृषि मंत्री जी बात ही वर्ष 2019 तक की ही करते। अब कहने को राज्यमंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी जी भी यही कहते हैं कि हमारी सरकार तो वर्ष 2024 तक रहेगी। सरकार के मंत्रियों द्वारा ऐसी बातें कहना प्रदेश के वोटर को चैलेंज करने वाली बात है। कुल मिलाकर ये यही कहना चाहते हैं कि हम सदा हरियाणा प्रदेश की

सत्ता सम्भालते रहेंगे। मैं इनको यही सलाह देना चाहूंगा कि हर चुनाव से पहले प्रदेश की जनता ने अपना मन बनाया होता है। जो फैसला प्रदेश की जनता लेना चाहती है उसको कभी भी कोई भी पार्टी नहीं बदल सकती है और न ही प्रदेश के वोटर को किसी भी पार्टी द्वारा किसी भी स्तर पर चैलेंज ही किया जा सकता है। ऐसी बातें कहना कि हम फलां साल तक सत्ता में रहेंगे कोई मायने नहीं रखता है। अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय दुगुणी होनी है या नही होनी है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा लेकिन अगर प्रदेश की सरकार की नियत साफ हो तो वह प्रदेश के किसानों की भलाई के लिए बहुत से काम कर सकती है। सबसे पहले तो उन वस्तुओं पर टैक्स की दर कम की जा सकती है जिनकी खरीद किसान वर्ग से सीधे जुड़ी है। इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि आज ट्रैक्टर के ऊपर 12 परसैंट और टॉयर्ज़ ट्रैक्टर के स्पेयर पार्टस के ऊपर 18 परसैंट जी.एस.टी. है। इसी प्रकार से सभी कृषि यंत्रों पर 12 परसैंट और कीटनाशकों पर 18 परसैंट जी. एस.टी. है। खाद पर पहले जी.एस.टी. नहीं होता था लेकिन अब खाद पर 05 परसैंट जी.एस.टी. लगा दी गई है। वर्तमान सरकार के समय में डीज़ल जितना महंगा हुआ है वह भी अपने आप में एक रिकार्ड की बात है। यदि प्रदेश की सरकार वाकई किसानों के हितों के प्रति चिंतित है और यह चाहती है कि किसानों की आय जल्दी से जल्दी दुगुणी हो जाये तो सरकार को किसानों के खर्चे घटाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम सरकार को किसानों के खर्चे घटाने चाहिए क्योंकि यही उसके हित की बात है। उसकी आय तो जब बढ़ेगी तब बढ़ जायेगी। एक बात में यह कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी ने होर्टीकल्चर के लिए भी बजट में बहुत थोड़ी सी राशि का प्रावधान किया है। मैं उनसे यह बात कहना चाहूंगा कि वे प्रदेश में होर्टीकल्चर को बढ़ावा देने की बात बार–बार कहते हैं। सरकार द्वारा पानी के संरक्षण की बात भी की जाती है। प्रदेश की सरकार ने एक स्कीम बनाई है कि जिसके तहत नहरों और रजबाहों के ऊपर जो परमानैंट आउटलैट्स हैं वहां पर पक्के खाले बनाये जायेंगे और पाइप लाइन दबाई जायेगी। यह स्कीम अच्छी है लेकिन इस काम में जो मैटीरियल यूज़ किया जा रहा है वह इतना ज्यादा घटिया है कि आज अभी नहर का पानी बंद किया जाये तो 15 मिनट में वह पाइप लाइन पूरी तरह से खाली हो जाती है। जब यह एक बार खाली हो जाती है तो उसको भरने के लिए कम से कम दो घंटे पानी चलाना पड़ता है। इस प्रकार से जो हमें पानी की सेविंग करनी

थी इससे तो वह पानी की सेविंग नहीं होगी। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी पानी की सेविंग सही प्रकार से नहीं हो रही है। इसी प्रकार से जो पराली के प्रबंधन की बात है उस दिशा में भी सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया है। प्रदेश के किसानों को अनावश्यक रूप से तंग करने के बजाये सरकार को इस ओर भी अपने स्तर पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। इसके विपरीत सरकार द्वारा ट्रैक्टर पर भी टैक्स लगा दिया गया है। इसी प्रकार से सरकार द्वारा भावांतर योजना का भी बखान किया गया है। इस बारे में मेरा सरकार से यह कहना है कि जिस प्रकार से दूसरी जिन्सों का एम.एस.पी. सरकार द्वारा तय किया जाता है उसी प्रकार से फल, फूल, सब्जियों और प्याज का भी सरकार को एम.एस.पी. निर्धारित करना चाहिए। अगर सरकार प्रदेश के किसान की हालत को सुधारना चाहती है तो उसको ये सभी काम जल्दी से जल्दी करने होंगे। ट्रैक्टर को चौधरी देवी लाल जी द्वारा गड्डा डिक्लेयर किया गया था लेकिन केन्द्र की सरकार ने ट्रैक्टर पर अब टैक्स लगा दिया है जिसकी वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। उसके लिए भी हम केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से मिलकर आये हैं। इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है उसकी जानकारी भी सदन में दी जाये। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाये ?

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, अब मैं अपने विधान सभा हल्के की दो बातें कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए अब आप वाईंड–अप करें।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र में गये थे तो उस समय वहां पर पश्चिमी बाई–पास बनवाने की बात कहकर आये थे मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि

पेहवा में पश्चिमी बाई–पास का निर्माण करने के लिए जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाये। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने वहां पर 100 बैड का हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की थी लेकिन इस बारे में भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पेहवा में 100 बैड का हॉस्पिटल बनाने के लिए जल्दी से जल्दी कार्यवाही शुरू की जाये। मेरे पेहवा में एक लगभग 300 साल पुराना रैस्ट हाउस है, जो कि पुरातत्व विभाग को दिया हुआ है, उस रैस्ट हाउस की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब है। इस रैस्ट हाउस की हालत को सुधारने के लिए भी सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि इस रैस्ट हाउस की हालत भी जल्दी से जल्दी सुधारी जाये। ऐसे ही पेहवा का नया बस स्टैण्ड बनाने की भी बात की गई थी लेकिन इस बारे में भी अभी कोई कार्यवाही सरकार के स्तर पर नहीं हुई है। मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि पेहवा में नया बस स्टैण्ड बनाने की दिशा में जल्दी से जल्दी कार्यवाही शुरू की जाये। इसी प्रकार से मेरे गांव गुमथला गढ़ू सरकारी स्कूल में स्टॉफ की बड़ी भारी कमी है मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि इसको भी जल्दी से जल्दी दूर किया जाये। अध्यक्ष जी, मेरी आपसे एक बार फिर से प्रार्थना है कि आप पांच–पांच मिनट का समय सभी सदस्यों को बोलने के लिए जरूर दें। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

14:00 बजे

श्री जय तीर्थ (राई): स्पीकर सर, मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया? चाहे एक मिनट का ही समय आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए दिया हो। स्पीकर सर, मुझे आज एक ज्ञापन मिला था मैं सबसे पहले उसी का जिक्र करना चाहूंगा। वर्ष 2015 में हमारे सोनीपत को नगर निगम बनाया गया था। उसके बाद 26 गांवों की पंचायतों को भी इस नगर निगम में इंक्ल्यूड कर लिया गया था। उन 26 गांवों के 260 लोगों ने मेरे पास आकर मुझे आज ज्ञापन दिया है। उन्होंने अपने ज्ञापन में यह बात कही है कि उनकी ग्राम पंचायतें अब नगर निगम, सोनीपत में नहीं रहना चाहती। हमारी आदरणीय मंत्री श्रीमती कविता जैन ने पिछले सैशन में कहा था कि नगर निगम, सोनीपत को 157 करोड रूपये की आमदनी इन 26 गांवों से हुई है। नगर निगम, सोनीपत ने वे 157 करोड रूपये ले तो लिए लेकिन इन सभी गांवों में विकास के नाम पर कोई एक नया पैसा भी नगर निगम, सानीपत द्वारा खर्च नहीं किया गया है। इसी कारण से ये सभी 26 गांव नगर निगम, सोनीपत से बाहर

निकलना चाहते हैं। पहले तो उस क्राईटेरिया के बारे में जानना चाहते हैं जिसके तहत इन सभी 26 गांवों को नगर निगम, सोनीपत में मिलाया गया था। उनका यह भी कहना है कि जिन गांवों की दूरी सोनीपत से दो मिलोमीटर थी उनको तो नगर निगम, सोनीपत में शामिल नहीं किया गया लेकिन जिन गांवों की दूरी सोनीपत से 20 किलोमीटर थी उन गांवों को नगर निगम, सोनीपत में मिला लिया। इस मामले को ध्यान से देखने पर यह बात सामने आई है कि जिन ग्राम पंचायतों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी और आमदनी के दूसरे साधन भी बहुत थे उन गांवों को तो नगर निगम, सोनीपत में इंक्ल्यूड कर लिया गया और जिन गांवों में न तो जमीन थी और न ही आमदनी के दूसरे साधन थे उन गांवों को नगर निगम, सोनीपत में इंक्ल्यूड नहीं किया गया। जिन गांवों को नगर निगम, सोनीपत में इंक्ल्यूड किये इनमें मुस्तरका मालिकान की जमीन भी नगर निगम, सोनीपत में शामिल कर ली। इन सारे गांवों की जो जमीन पंचायती जमीन में शामिल नहीं होती उस जमीन को भी इन गांवों की जमीन में मिला लिया गया। अब हमारे ये सारे के सारे गांव आंदोलन की राह पर है। ये आंदोलन की रूप रेखा चला रहे हैं और इन्होंने यह धमकी दी हूई है कि वे 24 मार्च, 2018 को श्रीमती कविता जैन जी के आवास को भी घेरेंगे। इनका यह कहना है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जायेगा अर्थात् जब तक इन गांवों को नगर निगम, सोनीपत से बाहर नहीं निकाला जायेगा तब तक इनका ये आंदोलन जारी रहेगा। इन 26 गांवों में से 24 गांव मेरे हल्के में आते हैं इसलिए मैं उनको अपना पूरा समर्थन देता हूं। मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि इन सभी गांवों की नगर निगम, सोनीपत से बाहर होने की मांग को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाये। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : स्पीकर सर, माननीय सदस्य जय तीर्थ दहिया जी ने जो डिमाण्ड अभी–अभी सदन में रखी है इस बारे में मैं हाउस को आश्वस्त करना चाहती हूं और इस हाउस के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को भी बताना चाहती हूं कि जब भी कोई निगम गठित किया जाता है तो उसके लिए जो सैट प्रोसीजर होता है अर्थात जब किसी नगर पालिका या नगर परिषद् की सीमा को बढ़ाया जाता है तो सर्वप्रथम उसकी आबादी का क्राईटेरिया होता है कि नगर पालिका या नगर परिषद् की आबादी कितनी है ? जब तीन लाख से ऊपर आबादी हो जाती है तो उसको नगर निगम बनाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, इतना डिटेल में जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए आप कृपया करके शोर्ट में ही इस मामले में अपना जवाब दे दें।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, मैं इस बारे में इतना ही बताना चाहूंगी कि लिस्ट ऑफ डिमाण्ड इन सभी गांवों से मांगी गई थी और इन गांवों के लोगों ने अपनी डिमाण्ड्ज लिखकर दी थी । डी.सी. ऑफिस में इन सभी 26 के 26 गांवों की जो डिमाण्ड्ज़ हैं वे जमा हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन की गई और फिर लोगों से ऑब्जैक्शंज़ मांगी गई हैं। जब उन ऑब्जैक्शंज़ को देने का समय पूरा निकल गया, उसके बाद उसको बाकायदा तौर पर नोटिफाई किया गया। फिर भी अगर कुछ गांवों के लोगों ने अपनी कोई बात रखनी है तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वे निश्चित रूप से आकर मुझ से मिल लें। इसके साथ ही साथ मैं माननीय साथी श्री जय तीर्थ दहिया जी को यह कहना चाहूंगी कि वे यह मैमोरैंडम मुझे दे दें, मैं इन सभी गांव वालों से मिल लूंगी और अगर उनकी कोई दिक्कत होगी तो उसको प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जायेगा।

श्री जयतीर्थः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि उन 26 गांवों के लोगों ने पहले ही उपायुक्त को और मंत्री जी को ज्ञापन दे दिया है।

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहती हूं कि जब भी वह ज्ञापन मेरे पास आयेगा तो हम उस पर संज्ञान ले लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि सोनीपत जिले के इन 26 गांवों का रेफ्रेंडम करवा लिया जाये। अगर वे गांव नगर निगम में शामिल होना चाहते हैं तो उनको शामिल कर लिया जाये और यदि वे नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो उनको नगर निगम से बाहर रख दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, जब आपकी सरकार ने 9 नगर निगम बनाये थे तब क्या आपकी सरकार ने इस प्रकार का कोई रेफ्रेंडम करवाया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, इनका इन गांवों से कोई मतलब नहीं है इनको सिर्फ इसलिए दिक्कत है क्योंकि यह सोनीपत का नगर निगम हमारी सरकार ने बनाया है। पूरे प्रदेश में फरीदाबाद और गुरूग्राम के बाद सोनीपत नगर निगम ही विश्व के मानचित्र पर आने वाला है। यहां पर विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। ये

लोग सोनीपत की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वहां पर 3–3 इंडस्ट्रियल जोन आने वाली हैं, वहां पर रैपिड मैट्रो आने वाली है तथा के.एम.पी. एक्सप्रैस वे पूरा होने भी आने वाला है। अध्यक्ष महोदय, ये वहां की जनता को उनके हक नहीं मिलने देना चाहते हैं।

श्री बिक्रम सिंह यादव (कोसली) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018–19 के लिए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके तहत मंत्री महोदय द्वारा विभिन्न विभागों के लिए की गई घोषणाओं के लिए फंड उपलब्ध करवाया गया है उसके द्वारा ही मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणायें जल्दी कार्यान्वित होंगी। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार ने 3 लाख से अधिक एल.पी.जी. गैस कनैक्शन दे कर हरियाणा प्रदेश को कैरोसीन मुक्त किया है जिससे हरियाणा सरकार को प्रति वर्ष 270 करोड रुपये का फायदा होगा। यह हरियाणा में महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इस रबी सीजन के लिए गेहूं की खरीद के लिए 1735/– रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है जिसमें लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का प्रावधान किया है। यह किसानों के लिए बहुत ही हितकारी स्कीम है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से हमारी सरकार ने गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 330/– रुपये प्रति क्विंटल किया है जो पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक है जो कि हरियाणा में गन्ने की बिजाई करने वाले किसानों के लिए बहुत अच्छी पहल है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने हल्के की कुछ मांगे पूरी करने के लिए और जल्दी ही उनको क्रियान्वित करवाने के लिए विनती करता हूं । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015 में सहकारिता दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे हल्के के बारे में कुछ घोषणाएं की थी जिनको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं ताकि उनको जल्दी से क्रियान्वित किया जा सके । हमारे यहां कोसली व भाकली गांव को मिलाकर एक नगरपालिका बनाने की घोषणा की गई थी । इसलिए मेरी विनती है कि इन दोनों गांवों को मिलाकर नगरपालिका को जल्दी से बनाया जाए । दूसरी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाटुसाना गांव में हैफेड का एक कैटलफीड प्लांट लगाने की की थी उसका कार्य भी जल्दी से शुरू करवाया जाए । तीसरी घोषणा ग्राम शहादत नगर में एक नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई थी । उसके लिए भी मेरा माननीय

स्वास्थ्य मंत्री व मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उसको भी जल्दी शुरू करवाया जाए । उसी के साथ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कौसली में भिवानी बोर्ड की तर्ज पर जे.बी.टी. की कक्षाएं शुरू करवाने की घोषणा की हुई है । उसके लिए भी मेरी विनती है कि उसको भी जल्दी से शुरू करवाया जाए । इसी के साथ साहलावास रोड से नाहड़ रोड तक का बाईपास का निर्माण जो पिछली सरकार द्वारा पक्षपात करते हुए अधूरा छोड़ा हुआ है उसको बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि उस बाईपास को पूरा करवाए जाए क्योंकि इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2015 में घोषणा भी की थी । उसी के साथ मेरी एक और विनती है कि जाटुसाना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महिला कॉलेज खोलने की घोषणा की हुई है उसको भी इसी सत्र से आरम्भ करवाया जाए और उसको महिला कॉलेज की बजाए को–एड कॉलेज के नाम से खोला जाए ताकि उसमें लड़के और लड़कियां दोनों को ही फायदा हो सके । उसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2015 में हमारे भाकली गांव में एक लॉ कॉलेज खोलने की घोषणा की थी जिसकी एक बार रात्री लॉ कॉलेज खोलने की मंजूरी मिल गई थी लेकिन उसके बाद पता नहीं किस तकनीकी आधार पर वह कार्य रूकद गया है । उसको मैं माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उसको भी जल्दी से आरम्भ करवाया जाए । हमारे उसी गांव जाटुसाना में दूध का एक चिलिंग प्वायंट है जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चिलिंग प्वायंट को मिल्क प्लांट में तब्दील करने की घोषणा की हुई है जिसके लिए मैं माननीय मंत्री श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी को भी कहना चाहूंगा कि उसको जल्दी से आरम्भ करवाया जाए । इसी के साथ मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे वहां महिला फूलचन्द विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लूलाहीर गांव में एक महिला रिजनल सैंटर चल हुआ है जिसमें चार साल से कक्षाएं भी शुरू हो गई थी लेकिन उसके भवन निर्माण का कार्य अभी तक लटका हुआ है । इसलिए मेरी माननीय शिक्षा मंत्री जी से विनती है कि जल्दी ही उस भवन निर्माण के कार्य को आरम्भ करवाया जाए । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री नसीम अहमद (फिरोजपुर झिरका) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद । अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें रेलवे का जिक्र किया गया है ।

जिसमें दिल्ली से गुरूग्राम, गुरूग्राम से सोहना, सोहना से नूंह और फिरोजपुर झिरका से होते हुए अलवर के लिए रेलवे लाइन निकालने की व्यावहारिकता की एक रिपोर्ट लेनी है । लेकिन इस रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कई बार सर्वे हो चुका है । पिछली कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन के अन्दर कई बड़े वायदे किये थे कि इस रेलवे लाइन के 50 प्रतिशत खर्च को हरियाणा सरकार वहन करेगी और 50 प्रतिशत खर्च को केन्द्र की सरकार वहन करेगी और इस रेलवे लाइन को हम जल्दी ही बनवाएंगे । जब उन्होंने वह घोषणा की थी तो क्या वह घोषणा झूठी थी जिससे इसकी व्यावहारिकता दोबारा चैक करनी पड़ रही है । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन है कि मेवात की जो जनता है । मेवात की जो औरत हैं, मेवात के जो मर्द हैं उन्होंने आज तक रेल नहीं देखी है।

अतः रेलवे लाइन की केवल मात्र बात न करके, इस एरिया में रेलवे लाइन बिछाने की जरूरत है। अगर सरकार यह काम करती है तो मेवात के लोग सरकार को दुआएं ही देंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी कांग्रेस की तरह ही सिर्फ झूठा वादा किया तो यह हमारे मेवात क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ा अन्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, बजट में मेरे हल्के के एक रोड का जिक्र करते हुए कहा गया है कि फिरोजपुर झिरका से बिवान गांव तक का रोड बनाया गया है, इसके लिए मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ लेकिन साथ ही यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि इस रोड का जिक्र बजट में करने की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि यह रोड तो पहले ही बन चुका है, अगर बजट में डालना था तो इस बजट में गुड़गांव से अलवर तक के 448–ए नम्बर रोड को फोर लाईन करने बात डाली जा सकती थी। इस रोड पर हजारों की संख्या में राजस्थान से खनन व पत्थर लेकर हरियाणा व दिल्ली में आने वाले डंपर चलते हैं और साथ ही इस रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी है। इस ट्रैफिक की वजह हर रोज इस रोड पर कोई न कोई दुर्घटना होती ही रहती है जिसमें काफी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं। मेरे पास इस रोड पर दुर्घटनाओं से संबंधित एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमें दर्शाया गया है कि वर्ष 2016–17 में इस रोड पर हुई दुर्घटनाओं में 325 नौजवान मारे गए और वर्ष 2017–18 में 298 नौजवान इस रोड पर हुई दुर्घटनाओं में मारे गए है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा और साथ ही माननीय लोक

निर्माण मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस रोड को जल्द से जल्द फोर लेन बनाने का काम किया जाये ताकि मेवात के जो नौजवान इस रोड पर दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं, उन पर अंकुश लगाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र में स्थित तिगांव पी.एच.सी तथा पिनंगवा पी.एच.सी. में डॉक्टर्ज की भारी किल्लत है जिसकी वजह से लोगों को अलवर, राजस्थान, गुड़गांव, पलवल या फरीदाबाद इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त छोटी–मोटी बीमारियां जैसा कि बुखार, मलेरिया या जैसे औरतों की समस्या हैं, इनके लिए भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता को नूंह या नल्हड़ में जाना पड़ता है लेकिन यहां मेडिकल की पूरी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, इन सब बातों के मद्देनज़र मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सभी पी.एच.सीज. में मोबाईल ओ.पी.डीज. शुरू की जाये ताकि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है या जहां पर कोई डाक्टर्ज नहीं है, यदि सप्ताह में कम से कम एक दिन इन गांवों में मोबाईल ओ.पी. डीज. की यदि व्यवस्था हो जाती है तो लोग अच्छी तरह से अपना इलाज करवा पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित माडीखेड़ा गांव के स्कूल की अपग्रेडेशन करके हमारे क्षेत्र की जनता की मांग को जिस प्रकार से पूरा करने का काम किया है इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ । इसके साथ ही मैं यह भी मांग करता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित बशीरखां स्कूल की भी अपग्रेडेशन की जाये ताकि हमारी बच्चियों को एक ही जगह पर ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त हो सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित गांव नामतः लोहिना खुर्द, तिंगाव, भुचाका, मोहम्मदवास, डाणा, बुबेलहेडी, चांदढ़ाका, डुंगेजा, जयतलका, घटवासन, मल्लाका, झारपुड़ी, नीमखेड़ा, बढ़ेड, डोंडल, गोकलपुर तथा एचवाडी की तहसील पहले फिरोजपुर झिरका में थी और इनका ब्लॉक भी फिरोजपुर झिरका हुआ करता था लेकिन सरकार ने इन गांवों को पुन्हाना तहसील व पुन्हाना ब्लॉक में डाल दिया है, जबकि यहां के आम आदमी, सरपंच व पूर्व सरपंच एक तरह से सभी जन यह चाहते हैं कि वे जब फिरोजपुर झिरका विधान सभा क्षेत्र के वासी हैं तो उनकी तहसील व ब्लॉक फिरोजपुर झिरका ही रखी जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि यह मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस संदर्भ में आश्वासन

प्राप्त करना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे मेरी इस मांग को जरूर पूरा करेंगे। इसके साथ ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बिजली की बड़ी भारी समस्या है। यहां पर जो पुरानी बिजली की लाइंज है, उनको तुरन्त बदलने की आवश्यकता है। गांव शाकरस, पाटखोरी, बढेड़ व बिवान कुछ बड़े गांव हैं और कुछ छोटे गांव भी हैं जिनमें बिजली की बहुत पुरानी लाइंज बिछी हुई हैं और बहुत जर्जर हालत में है, मेरा अनुरोध है कि इनको भी तुरन्त बदलवाया जाये ताकि लोगों को सही मात्रा में और सही समय पर बिजली मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग बिजली का कनैक्शन लेने के लिए बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर काटते रहते हैं लेकिन उनको बिजली का कनैक्शन नहीं मिलता है। गांव घाघस, ढाणा और फिरोजपुर झिरका के लोगों ने पिछले एक या दो साल से घर के लिए बिजली का कनैक्शन लेने के लिए एप्लाई किया हुआ था लेकिन आज तक उनकी बिजली के कनैक्शन के लिए कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : नसीम अहमद जी, आप जल्दी से जल्दी कंक्लूड कीजिए।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ एक मिनट और बोलने का मौका दीजिए। बजट में आखरी टेल तक पानी पहुँचाने की बात कही गई है। मेरा फिरोजपुर झिरका हरियाणा का आखरी हिस्सा है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बनारसी डिस्ट्रब्यूट्री और एक लण्डवा नाला है। इस डिस्ट्रब्यूट्री और नाला में पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय पानी गया था और उसके बाद बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री में पानी नहीं गया। यह बात मैं सदन में दावे के साथ कह सकता हूँ। यदि माननीय मंत्री जी को कोई शक है तो मौके पर जाकर देख भी सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से अनुरोध है कि फिरोजपुर झिरका को भी चण्डीगढ़ की तरह समझें और यदि सरकार पानी पहुँचा देगी तो हमारे क्षेत्र के लोग सरकार को दुआ देंगे। आज लोग टैंकरों के द्वारा सिंचाई कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नसीम अहमद जी, आपका बोलने का समय समाप्त हो चुका है।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मेरी दो–तीन महत्वपूर्ण बातें और रह गई है, इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि मेरी लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

***श्री नसीम अहमदः** अध्यक्ष महोदय, खान और भूविज्ञान हरियाणा में खनन बन्द है और खासकर हमारे क्षेत्र में इस की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसका कारण है राजस्थान में उसी अरावली पर खनन चल रहा है और उसका सराकर ने जो बजट में जिक्र किया है, वह गलत ब्यान दिया गया है। बजट में रोजगार हमारे यहां पर प्याज, टमाटर, बैंगन और अलग–अलग सब्जियों की पैदावार फिरोजपुर झिरका के किसान बड़ी मेहनत से पैदा करता है और उस को मण्डी करने के लिए दिल्ली आजादपूर मण्डी में लेकर जाना पड़ता है। उसका पैसा आने–जाने में काफी लगता है। मेरी मांग है कि स्टेट लेवल पर एक बड़ी मण्डी बड़कनी या फिरोजपुर झिरका में बननी चाहिए ताकि किसान अपनी पैदावार को यही पर बेच सकें । कोल्ड स्टोर वहा पर बनवाने चाहिए।

डॉ0 हरि चन्द मिड्ढा (जीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी बजट पर बोलना चाहता हूँ लेकिन मुझसे आज बोला नहीं जा रहा है, इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि मेरी लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

***श्री हरी चंद मिड्ढाः** अध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। स्पीकर सर बजट सरकार का रोड़ मैप होता है कि आगामी एक वर्ष में सरकार किन–किन उपलब्धियों तथा विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने जा रही है, वही प्रदेश के हर वर्ग को एक उम्मीद होती है कि सरकार द्वारा क्या–क्या सुविधाएं आगामी वर्ष में प्रदान की जाएगी। स्पीकर सर वित्त वर्ष 2018–19 के बजट से प्रदेश की जनता को जो उम्मीद थी , वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट ने जहां प्रदेश की जनता के अरमानों पर पानी फेरा, वही यह साबित कर दिया कि 2014 के विधानसभा के आम चुनाव में भाजपा द्वारा जो वादे किए गए थे वो खाली जुमले साबित हुए।

वहीं बजट में जिस तरह से वर्ष 2018–19 के लिए 115198.29 करोड़ का बजट पेश करके जनता को और सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया,

.....

*** चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

वहीं प्रदेश को, जो प्रदेश हरि का प्रदेश और खुशहाल प्रदेश जिसका निर्माण जननायक स्व. चौधरी देवीलाल ने अपने अथक प्रयासों से किया था उस प्रदेश को अगर आंकड़ो का अवलोकन करूं तो कर्जदार प्रदेश बनाने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। स्पीकर सर पढ़कर आश्चर्य हुआ कि बजट का 30 प्रतिशत हिस्सा तो प्रदेश के कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ''सबका साथ – सबका विकास'' सरकार ने एक नारा दिया, मगर आज अगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो , प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं, जीन्द शहर और जीन्द ग्रामीण क्षेत्र के लिए कि गई, उनमें से किसी भी घोषणा पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यूं पिछली सरकार की तरह वर्तमान सरकार भी जीन्द को अनदेखा कर रही है।

स्पीकर सर भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की एक रैली का आयोजन प्रदेश सरकार द्वारा जींद में किया गया, जीन्द की जनता को एक आस जगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की रहनुमाई में जीन्द को कोई नई सौगात दी जाएगी मगर न तो मुख्यमंत्री जी व न ही केन्द्र सरकार द्वारा जीन्द के पिछड़ेपन को दूर करने की एक भी घोषण नहीं करना कही न कही प्रत्यक्ष रूप से ''सबका साथ–सबका विकास'' नारे पर प्रत्यक्ष चिन्ह खड़ा कर रहा है। स्पीकर सर जब हम सदन में प्रवेश करते है तो सामने बड़े–बड़े अक्षरो में लिखा होता है कि सदन में किसी भी सूरत मे झूठ बोलने पर आप पाप के भागीदार बनते है और जनता व समाज के गुनहेगार बनते हैं, मगर जिस तरह से बजट प्रस्तुत करते वक्त कोरा झूठ बोला गया, उदहारण के तौर पर क्रम संख्या 78 पेज संख्या 22 का जिक्र करता हूं, सर दर्शाया गया कि 22 जून, 2017 को खुले में शौच–मुक्त (ओ.डी.एफ) घोषित किया गया है, और अब मिशन – ग्रामीन का ध्यान (ओ.डी.एफ) प्लस पर है, स्पीकर सर मैं, सदन में मुख्यमंत्री जी व वित्त मंत्री जी से कह रहा हूं, आप मेरे साथ चले जीन्द अगर एक भी गांव खुले में शौच मुक्त हुआ हो तो, क्या सरकार उन अधिकारियों की जांच करवाएगी जिन्होंने वे आकड़ें पेश किए हैं, और इस पूरी योजना में जो–जो घोटाला हुआ है क्या उसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी।

अध्यक्ष महोदय जीन्द के मेडिकल कालेज का जिक्र किया गया है मगर निरन्तर दो वर्ष से सरकार जीन्द की जनता को गुमराह कर रही है क्योंकि आज जीन्द में स्वास्थ्य सेवाएं न के बराबर है, वहीं डाक्टरों की भारी कमी के चलते जीन्द का सामान्य हस्पताल आज रैफरल केन्द्र बन कर रह गया है, वहीं मेडिकल

कालेज का निर्माण कार्य शुरू न कर सरकार जीन्द की जनता के मौलिक अधिकारी का हनन कर रही है। स्पीकर सर वर्ष 2014 के आम चुनाव में भाजपा ने प्रदेश के युवाओं को एक सपना दिखाया कि भाजपा की सरकार बनने पर प्रति वर्ष 2 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएगें, लेकिन सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि साढ़े तीन वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा मात्र 20,000 रोजगार प्रदान किए गये है और वित्त वर्ष 2018–19 के बजट में वेतन–भते–पेंशन के बजट में कटौती साफ दर्शाती है कि आगामी वित्त वर्ष में भी सरकार कोई रोजगार नहीं देने वाली है जो प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है।

स्पीकर सर बजट में तथा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सड़क तंत्र को मजबूत करने की बात कही गई है। श्री अध्यक्ष जी जीन्द–पानीपत वाया सफीदों तथा कैथल–जींद–हांसी लोक निर्माण विभाग द्वारा डिटेल प्रजोक्ट रिपोर्ट तैयार करने की बात कही गई है। जबकि अध्यक्ष महोदय P.W.D विभाग की जीन्द में जितनी सड़के हैं सबकी हालत खस्ता हैं, तथा वित्त वर्ष 2017–18 के बजट में जिन सड़कों का निर्माण प्रस्तावित था वही आकड़े पेश कर जीन्द की जनता की भावनाओं के साथ कुठाराघात है।

स्पीकर सर जनस्वास्थ्य विभाग का जिक्र करूं तो मेरे जीन्द विधानसभा क्षेत्र में जहां शहरी क्षेत्र में नहरी जल पर आधारित कोई पेयजल घर नहीं है वही क्षेत्र में TDS 4000 से 12000 तक है मेरे जीन्द क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था का दीवाला निकल चुका है। अध्यक्ष महोदय आकड़ो का तोड़–मरोड़ कर जिस तरह से उद्योग के बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत करने की बात कही गई है, वही वर्तमान सरकार ने ''हैपनिग हरियाणा'' के नाम पर जिस तरह से प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया और निवेश के दावे किए गए वो भी धरातल पर जुमला ही साबित हुए । मेरा विधानसभा क्षेत्र इस प्रदेश का केन्द्र बिन्दु है, मगर उद्योग जगत में अति पिछड़ा होन के कारण, आज विकास के नाम की बाट जोह रहा है। महोदय 51 पेजों का अवलोकन करने के बाद अगर मैं ये कहूं कि बजट से साफ प्रदर्शित हो रहा कि यह बजट का कुप्रबंधन है।

स्पीकर सर मेरे विधानसभा क्षेत्र कि कुछ मांगे है। जो इस प्रकार है, शहरी क्षेत्र मे पीने के पानी के लिए नहरी जलघर आधारित जलघरों का निर्माण करवाया जाएगा। जीन्द के पास (आबाद) इलाके अर्बन एस्टेट, डिफेंस कॉलोनी सैक्टर 7,8,9

और 11 तथा स्कीम न. 05/6 की सड़कों का पुनिर्माण करवाया जाए। शुगर मील जीन्द की पिराई क्षमता बढ़ाई जाए। शहरी की बदहाल सीवरेज व्यवस्था, जैन नगर, विश्वकर्मा कॉलोनी, दयाल बाग, वाल्मिकी बस्ती , आरा रोड़, प्रेम नगर, भटनागर तथा दुर्गा कॉलोनी के लिए विशेष योजना तैयार की जाए। जींद शहर मुख्यालय पर अधिकारियों के आवास 150 नए बनाए जायें। बरसोला वंश–रालोचन तीर्थ को कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन लिया जाए। ठंडी राम हलवाई से एक रूपया चौंक वाया काठ मण्डी, चक्कर रोड़, रामराये गेट, शिव चौंक सड़क का निर्माण किया जाए। माननीय पुलिस अधीक्षक के निवास से सफीदों सड़क तक इस सड़क को P.W.D विभाग को स्थानातरित किया जाए। जीन्द शहर में एक इण्डस्ट्रियल सैक्टर को विकसित किया जाए। जीन्द शहर में निर्माणाधीन नंदीशाला के लिए एक विशेष राशि प्रदान की जाए। जीन्द शहर के सभी पार्कों के रखरखाव व सुधार कार्यों हेतु 10 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की जाए। जींद शहर में कृषि विश्वविद्यालय एवं रिसर्च सैंटर टरनिटी लाला लाजपतराय हिसार का रीजनल सैंटर स्थापित किया जाए। जांज कलां से दरियावाला, खूंगा से रायचन्दवाला, जलालपुर कलां से जलालपुल खुर्द, बरसाना से बोहतवाला, रूपगढ़ से बडोदी, जुलानी से अहिरका कच्चे रास्तों को पक्का किया जाए। अहिरका सीवरेज ट्रीटमैंट प्लाट से कालावा–किनाना ड्रैन के लिए विशेष लाइन दबाकर निकासी का प्रबंध किया जाए। पटियाला चौंक से ट्रैफिक थाना कैथल रोड़ को चारमार्गीय बनाया जाए तथा दिल्ली से बठिण्डा रेलवे लाइन के पुल से इक्कस तक सड़क को चारमार्गीय किया जाए। पिण्डारा–तीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपये प्रदान किए जाए। जांज कलां में धरने पर बैठे किसानों की मांग को मानते हुए उनको धरने से उठाया जाए। जीन्द में ट्रामा सैंटर का निर्माण किया जाए वहीं पर मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए।

स्पीकर सर, उम्मीद करता हूं कि जब भी वित्त मंत्री जी बजट पर जवाब दें मेरे सभी प्रश्नों का जवाब दे, वही क्षेत्र से जुड़ी इन सभी मांगों को पूरा करते हुए बजट का प्रावधान करने का कष्ट करें। सर मैं अपने हल्के की कुछ मांगे रखना चाहता हूं। सड़कें टूटी हुई हैं उन्हें बनवाया जाए, सीवरेज का बुरा हाल है जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए सीवरेज व्यवस्था को ठीक करवाया जाए। मेडिकल कालेज का कार्य शुरू नहीं हुआ है उसे शुरू करवाया जाए। मेरे हल्के जीन्द में जांज कलां में किसानों ने पीने के पानी की समस्या के

कारण धरने पर बैठे हुए हैं सरकार उनके लिए कुछ व्यवस्था करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर कार्य शुरू किया जाए। धन्यवाद सर।

श्री रणबीर गंगवा (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय वित्तमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है इस पर माननीय सदस्यों ने अपनी–अपनी प्रतिक्रिया दी हैं। किसी माननीय सदस्य ने बजट को अच्छा बताया है और किसी माननीय सदस्य ने बजट को किसी तरीके का बताया है। लेकिन मेरी इस बजट को लेकर चिंता है, वह इस बात को लेकर है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है और बढ़ते हुए अपराध में नम्बर–1 पर है। मुझे इस बात का दुख है कि इस बजट में गंभीरता बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई है। बजट में कहा गया है कि नये कॉलेज खोले जायेंगे, यह बहुत ही अच्छी बात है और नये कॉलेज खोले भी जाने चाहिए। लेकिन क्या हम उन कॉलेजिज में अपने बच्चों को पढ़ाकर एम.ए., बी.एड. व एम. टेक. आदि करवाने के बाद कोई रोजगार दिलवा पायेंगे? यदि बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो वे बच्चे अपराध के साथ जुड़ जायेंगे। हमारा हरियाणा एन. सी.आर. के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, जिसका हमें फायदा उठाना चाहिए। एन.सी. आर. के अंदर जितने भी उद्योग–धंधे लगे हुए हैं चाहे वह गुरूग्राम, फरीदाबाद और साथ लगते हुए क्षेत्रों में हों वहाँ पर हमारे बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए। हमारा देश एक है, इसलिए मैं यह नहीं कहता कि दूसरे राज्यों के बच्चों को रोजगार न मिले। लेकिन हमारे प्रदेश के अंदर उद्योग–धंधे लगे हुए हैं, इसलिए हमारे प्रदेश के बच्चों को दूसरे राज्यों के बच्चों के अनुपात में 50 प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा नौकरियां मिलनी चाहिए, जिससे उनको रोजगार मिल सके। अध्यक्ष महोदय, आज का बच्चा खेती नहीं करना चाहता है और जब उसे कोई रोजगार नहीं मिलता है तो वह क्राईम की श्रेणी की तरफ चला जाता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार अपराध बढ़े हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि क्राईम की रिपोर्ट कह रही है कि आज हरियाणा क्राईम के अंदर नम्बर–1 हो गया है। यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। यदि हमारा प्रदेश क्राईम में आगे बढ़ेगा तो प्रदेश में उद्योग–धंधे कौन लगायेगा? पहले हम यह सुनते थे कि बिहार की हालत बहुत खराब है, इसलिए वहां पर उद्योग–धंधे नहीं लगते थे लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में कानून व्यवस्था ठीक है इसलिए वहाँ उद्योग–धंधे लगते हैं। हमारे प्रदेश में उद्योग–धंधे ज्यादा लगेंगे तो

हमारे बच्चों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से हमारे प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं वह हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए और उस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। जाट आरक्षण के दौरान जिस तरह से हरियाणा जला उससे सिद्ध हो गया है कि हरियाणा सरकार किसी भी प्रकार की भीड़ को काबू नहीं कर सकती। जिस तरह से दिनांक 25 अगस्त, 2017 को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख का माननीय कोर्ट से फैसला आना था तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान देकर कहा था कि हम आस्था के ऊपर धारा 144 नहीं लगा सकते हैं। किस तरह से लाखों लोगों की भीड़ इक्ट्ठी करने के बाद गोलियां चलाई गईं। (विघ्न)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : अध्यक्ष महोदय, मंडल कमीशन के दौरान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय 26 दिन हरियाणा जला था। उस दिन को भी मेरे माननीय साथी को याद कर लेना चाहिए कि किस तरह से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि जल कर रखा हो गया था। जब तक मेरे माननीय साथी श्री गंगवा साहब को वह दिन याद नहीं आयेगा तब तक श्री मनोहर लाल सरकार की उपलब्धियां नजर नहीं आयेगीं। (विघ्न)

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, 25 अगस्त की घटना में पंचकुला में 42 लोग मारे गए और आज भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। पुलिस ने एस.आई.टी. टीम गठित की हुई है। पुलिस भोले–भाले लोगों को बुलाती है और पैसे लेकर उनको छोड़ने का काम करती है। इस तरह के हालत आज प्रदेश के अंदर है। इस बात की चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी जांच करवा लें। 25 अगस्त को जलियावालां बाग की कहानी दोहराई गई थी। यह हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है।

श्री अध्यक्ष : गंगवा साहब, जल्दी कंक्लूड कीजिए।

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने हल्के की बात सदन में रखना चाहता हूँ। मेरा निर्वाचन क्षेत्र ड्राई एरिया है और लोगों को पानी की बड़ी भारी समस्या है। आज भी ऐसे गांव है जहां पर चौधरी दुष्यंत चौटाला द्वारा पानी के टैंकर दिए गए थे और लोग उन टैंकरों से ही काम चला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय दोगुनी कैसी होगी? किसानों की फसल के ऊपर कैप लगा दिया जाता है कि किसान से केवल 10 मन बाजरा ही खरीदेंगे। इस तरह से किसान की आय दोगुनी कैसी होगी? सबको पता है कि आज सरसों की फसल किस रेट पर

बिक रही है। किसान की फसल का जब तक एम.एस.पी. फिक्स करके उसकी खरीद नहीं होगी तब तक किसान की आय नहीं बढ़ सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ओ.पी. जिन्दल माइनर जो नलवा के लिए बनाई गई है, उसमें अभी तक बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। लाइट के कारण किसानों की बारी चली जाती है। इसी तरीके से मंगाली के अंदर अनाज मण्डी है लेकिन वहाँ पर लम्बे समय से कोई भी खरीददारी नहीं होती है जिससे वहाँ के किसानों को दूसरी जगह अपने अनाज के लिए आना–जाना पड़ता है और बड़ी भारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस सीज़न के अंदर वहां पर खरीद शुरू हो जानी चाहिए। गांव मात्रश्याम से मिंगनी खेड़ा और गांव गंगवा से आर्यनगर रोड बिल्कुल टूटा हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाये। गांव गंगवा से कैमरी गांव तक सड़क बहुत ज्यादा खराब है, उसकी तुरंत रिपेयर की जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।

श्री केहर सिंह (हथीन) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । मेरा निर्वाचन क्षेत्र हथीन खेती से संबंधित वाला देहात है और सारी व्यवस्था खेती के ऊपर ही निर्भर है। हथीन में सिंचाई की बहुत भारी कमी है। इसके लिए मैंने पिछले वर्ष 21 दिन भूख हड़ताल की थी। एक बार 7 दिन की भूख हड़ताल इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मैं पिछले लगातार साढ़े तीन साल से किसानों के लिए अंतिम टेल तक पानी पहुँचाने के लिए सदन में लगातार आवाज उठाता रहा था। लेकिन सरकार ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। इसलिए मैं जनता के साथ भूख हड़ताल पर बैठा था। प्रशासन के द्वारा मुझे लिखित में आश्वासन दिया गया था कि हम 90 दिन के अंदर आपकी सारी समस्या हल कर देंगे और नियमित रूप से पानी देने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, न तो वहाँ पर बेहतर ढंग से डिस्ट्रीब्यूट्री की सफाई हुई है और न ही हथीन डिस्ट्रीब्यूट्री से जो माइनर व रजबाहे निकलते हैं उन पर गेट लगाया गया है और न ही पानी देने का कोई शिड्यूल बनाया गया है। यही हालत हमारी मानपुर माइनर, बिछौर माइनर, पुन्हाना माइनर, डाडका माइनर, कोट माइनर, भंगूरी माइनर, हथीन शाखा और पलवल शाखा की है। गुरूग्राम कैनाल से निकलनी वाली उटावड़ डिस्ट्रीब्यूट्री, चांदपुर माइनर और धतीर माइनर की है। इनके ऊपर भी कोई काम नहीं किया गया है। इन माइनरों में पंप के माध्यम से पानी डाला जाता है। अध्यक्ष

महोदय, मुझे दुख तो तब होता है जब साढ़े तीन साल में भी उन पंपों की मोटरों को नहीं बदला गया। सरकार अंतिम टेल तक पानी पहुँचाने का काम कहाँ से करेगी? अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्ष 2015 में हथीन गए थे और वहाँ पर हथीन बाईपास बनाने की घोषणा करके आए थे। लेकिन वह प्रोजैक्ट भी आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। कोई भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिनांक 09.10.2016 को हसनपुर कस्बे में गए थे और वहां पर यमुना पुल बनाने की घोषणा करके आए थे। इसके लिए लोगों ने भूख हड़ताल क्यों करनी पड़ी क्योंकि वहां पर एक आस्था का मन्दिर है और लाखों की संख्या में लोग दूर दराज से भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। जब भारी संख्या में लोग गुजरते हैं तो वहां पर हर वर्ष 10–20 श्रृद्वालुओं की मौत हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस इस पुल की डी.पी.आर. तैयार हो चुकी है और जल्दी ही पुल का निर्माण हो जायेगा। लेकिन आज तक भी इस पुल के निर्माण का कार्य नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के करीब 29 गांव क्रमशः अंधोप, नांगल जाट, बहीन आली ब्राहम्ण, आली मेव, नांगल सभा, रूपनगर नाटोली, रनियाला खुर्द, उटावड़ ढकलपुर, लखनाका, जलालपुर, गुलेसरा, हुड़ीतल, धीरणकी, स्वामिका मोहदमका विनोदागढ़ी, कलसाड़ा, गुराकसर, जरारी, दुर्गापुर, अहरवां, जलालपुर खालासा, धामाका, राखौता, गेलपुर, कलवाका और जैंदापुर गांव शामिल हैं। इन गांवों के लोगों ने अपना 10 बाई 10 का टैंक बनवा रखा है और उस टैंक में पैसे देकर टैंकरों से पानी डलवाते हैं और टैंकरों से पानी डलवाने के लिए हर सप्ताह 1,000–2,000 रूपये का खर्चा आता है लेकिन गरीब आदमी इस खर्चे को वहन नहीं कर सकता है। मेरे पलवल जिले में प्रति व्यक्ति आय 78,000/– रूपये है और हथीन हल्के में प्रति व्यक्ति 50,000/– रूपये से भी कम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। आरणीय अध्यक्ष महोदय, इस पानी की समस्या का एक ही समाधान है कि पलवल जिले के पास यमुना नदी पर बैराज बना दिया जाए ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को खेतों के लिए तथा पीने के लिए शुद्ध पानी मिल सके। अगर यू.पी. सरकार गोकुल बैराज होने के बावजूद भी शाहपुर बैराज बना सकती है तो हम भी पलवल जिले में बैराज बना सकते हैं। पूर्व माननीय मुख्य मंत्री श्री बंसी लाल जी ने पलवल जिले में बैराज बनाने की बात कही थी लेकिन पता नहीं किन कारणों से वह बैराज नहीं

बनाया गया। इसके अतिरिक्त मैंने भ्रष्टाचार के मामले में पहले भी सदन में कहा था कि मेरे हथीन हल्के में साढे 4 करोड रूपये पंचायत चुनावों के दौरान आचार संहिता लगने के बाद निकलवाये गये थे परन्तु उन पैसों से धरातल पर एक पैसे का काम भी नहीं हुआ। मैने यह बात बार–बार उठायी है कि संबंधित भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त अतिथि अध्यापकों को नियमित किया जाए और कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो आंगनवाड़ी वर्कर्ज और हैल्पर वेतन बढ़ाने तथा नियमित करने की डिमांड कर रही हैं उनकी मांगों की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरे क्षेत्र में करीब 5–6 गांव क्रमशः नांगल जाट से पावसर, जनाचोली– मठनाका से रिबड़ सोहना रोड, टहरकी से दहलाका, टहरकी से भूरजा, अहरवां से कारना और मण्डकौला से महेशपुर किशोरपुर रोड के गांवों के 6 करम के रास्तों को पक्का किया जाए।

श्री अध्यक्षः केहर सिंह जी, आप अपनी बात लिखकर दे दें।

***श्री केहर सिंहः** ठीक है जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे हथीन हल्के में सब्जी मण्डी का निर्माण करवाया जाए। इसके अलावा मेरे हल्के में पी.एच.सीज. में स्टॉफ और दवाइयों की कमी है उसको भी पूरा किया जाए। पी.एच.सी. नांगलजाट और पी.एच. सी. मण्डकोला का जीर्णोद्धार किया जाए। बहीन गांव के 33 के.वी.ए. सब स्टेशन को 66 के.वी.ए. का सब स्टेशन बनाया जाए। उटावड़ व पर्रोनी गांवों में नए 66 के. वी.ए. सब स्टेशन बनाए जाएं। इसके अलावा बहीन ग्राम पंचायत में हुए घोटाले की जांच भी की जाए। नए पलवल शुगर मिल को अपग्रेड किया जाए। नांगलजाट, अन्घोय, मानपुर, मठनाका, मण्डकोला, फुलवाडी और सैलीटी गांवों के स्कूलों को अपग्रेड करके सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बनाये जाएं।

श्री बलकौर सिंह (कालांवाली) (अ.जा.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैने पिछले सैशन में भी मेरे हल्के की बहुत सारी मांगे रखी थी और आज भी मेरे हल्के में ज्यादातर वहीं समस्याएं सामने खड़ी हैं। मेरे कांलावाली हल्के की पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में अपग्रेड किया जाए और वहां पर डाक्टर्ज की संख्या कम है, इसलिए डाक्टर्ज की

.....

*** चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

संख्या को बढ़ाया जाए। इसी प्रकार दादूपुर पी.एच.सी. और बड़ागुढ़ा पी.एच.सी. में न तो कोई डाक्टर्ज हैं और न ही लेडी डाक्टर्ज है। दादूपुर पी.एच.सी. में तो एक ए.एन.एम. ही डाक्टर्ज का काम कर रही है इसलिए वहां पर भी डाक्टर्ज की नियुक्ति की जाए। दूसरी बात यह है कि मरे हल्के के स्कूलों में अध्यापकों की बहुत ज्यादा कमी है और जो तबादला पॉलिसी सरकार ने बनायी है, उस पॉलिसी में बहुत सारी कमियां हैं। अध्यापकों की तबादला नीति तो ठीक है परन्तु बहुत सारे अध्यापक अपनी मर्जी के स्टेशन पर ट्रांसफर करवाकर संबंधित स्थान पर ज्वाईन कर लेते हैं परन्तु इससे बच्चों की पढ़ाई पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर किसी स्कूल में बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं तो वहां पर अध्यापकों की संख्या कम है और जिस स्कूल में अध्यापक ज्यादा हैं तो उस स्कूल में बच्चों की संख्या कम है। इस तबादला पॉलिसी में बच्चों की संख्या के हिसाब से तरजीह दी जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इसलिए बच्चों की संख्या के हिसाब से ही स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। मैंने अपने हल्के में सड़कें बनाने की मांग हर सैशन में रखी है कि मेरे हल्के की सड़कों की हालत ठीक नहीं है, उन सड़कों की मरम्मत करवाई जाए या सड़कों को दोबारा से बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं गुरूगोविंद सिंह मार्ग के बारे में बताना चाहूंगा कि मैं इस मार्ग से रिलेटेड क्वैश्चंज कई बार हाउस में ला चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, यह गुरूगोविंद सिंह मार्ग मेरे हल्के को टच करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं हर बार इस सड़क को पूरा करने के लिए मांग करता आया हूं और हर बार मुझे सदन द्वारा आश्वासन भी दिया जाता रहा है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज तक गुरूगोविंद सिंह मार्ग को पूरा नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसे जल्दी पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात खिलाड़ियों के बारे में कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में मलडी गांव और लकड़कली गांव हैं और उन गांवों की लड़कियों ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मैडल भी जीता है, लेकिन उसके बावजूद उन लड़कियों को आज तक कोई भी सरकारी राहत नहीं दी गई है। अध्यक्ष महोदय, वे लड़कियां गरीब परिवार से संबंध रखती हैं और मैं चाहता हूं कि उन्हें सरकार की तरफ से जल्द से जल्द सरकारी सहायता दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात 'फसल बीमा योजना' की करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार 'फसल बीमा योजना' के तहत मुआवजा देती है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के में एक देसु

मलकानां गांव है, जहां पर पिछले साल 120 एकड़ जमीन पर गेहूं की फसल बोई गई थी जो जलकर राख हो गई है। अध्यक्ष महोदय, उस समय सरकार ने उन गांव वालों को आश्वासन दिया था कि सरकार उन किसानों को 12 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देगी, लेकिन एक साल बीत गया है और आज तक उन्हें मुआवजा राशि नहीं दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि उन किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि उपलब्ध करवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के द्वारा कालांवाली को सब–डिवीजन बनाने के लिए अनाउंसमेंट की गई थी और मैं इस सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि इन्होंने उसे सब–डिवीजन बनाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कालांवाली में एस.डी.एम. साहब भी बैठने लग गए हैं, लेकिन वहां पर सरकार के द्वारा कोई भी बिल्डिंग बनाने का प्रावधान नहीं किया गया है और वहां पर एक प्राइवेट बिल्डिंग में सब–डिवीजन कार्यालय चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि वहां पर एक सरकारी बिल्डिंग बनवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि प्रदेश में कैंसर की बीमारी बहुत चल रही है और मेरे हल्के में कैंसर का प्रभाव बहुत ज्यादा है। मैंने पिछली बार भी विधान सभा में इस संबंध में एक क्वैश्चन लगाया था। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले अभी भी इस संबंध में 20,000 रुपए का चैक देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी मरीज किसी जात, धर्म और मजहब से संबंध नहीं रखता है, उसके बावजूद शिरोमणि गुरूद्वारा कमेटी वाले उन्हें 20,000 रुपए की मदद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब शिरोमणि प्रबन्धक गुरूद्वारा कमेटी वाले उनकी मदद कर सकते हैं तो हमारी सरकार उनके वास्ते कुछ क्यों नहीं कर सकती है ? अध्यक्ष महोदय, कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसका इलाज भी बहुत महंगा है और हर गरीब आदमी इसका ईलाज नहीं करा सकता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार इस तरफ जरूर ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को पानी के लिए यमुना–घग्घर लिंक के बारे में एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कई पंचायत वालों से रैजोल्यूशन और सुझाव आया है कि कालांवाली, डबवाली और रानिया हल्के को इसमें शामिल कर लिया जाए, क्योंकि यहां पर बहुत सारी जमीन हैं तो उस एरिया को भी पानी मिल सकता है, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस तरफ भी जरूर ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, नशे के बारे में मैं बताना

चाहूंगा कि मेरा इलाका नशे से बहुत प्रभावित है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के में जो स्थानीय पुलिस है, वे नशे के पदार्थ बेचने वालों को क्यों नहीं पकड़ती है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे सिर्फ सैलरी लेने के लिए ही है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार इसके लिए स्थानीय पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दे।

श्री अध्यक्षः बलकौर सिंह जी, इस मुद्दे पर कॉलिंग अटैंशन मोशन लगा था और उस पर सारे मैम्बर्ज बोल चुके हैं।

श्री बलकौर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारा इलाका नशे से बहुत प्रभावित है, इसलिए मैं चाहता हूं कि स्थानीय पुलिस इस पर एक्शन लें। धन्यवाद।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार के ऊपर वर्ष 2014 से पहले तक केवल 70 हजार करोड रुपए कर्जा था, लेकिन इन 3 सालों में सरकार के ऊपर 90 हजार करोड रुपए कर्जा और हो गया। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सरकार के ऊपर कुल 1 लाख 61 हजार करोड रुपए कर्जा है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अब सरकार को कुल बजट में से 23 प्रतिशत कर्ज के रूप में वापिस देना पड़ेगा, 37 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को वेतन–भत्ते के रूप में देना पड़ेगा, उसके बाद कुछ मिसलेनियस खर्चे होते हैं और जो बकाया पैसा बचा है वह सिर्फ 25 प्रतिशत के लगभग है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड में इम्लौयीज नहीं हैं और हॉस्पिटल्ज में डॉक्टर्ज नहीं हैं। यदि सभी को रोजगार दिया जायेगा तो उनकी तनख्वाह में ही बहुत पैसा लग जायेगा फिर विकास के कार्य कहां से होंगे ? अध्यक्ष महोदय, जो पैसा विकास के लिए यहां से दिया जाता है उसमें से कितना पैसा हकीकत में लगता है उसके बारे में सभी को जानकारी है । क्योंकि उसमें कमीशन खाया जाता है । मैं अपने सोनीपत जिले की बात करूं तो चेयरमैन ग्रांट देने से पहले 20 प्रतिशत का कमीशन मैंबर्ज से मांगता है। इस बारे में लिखित में भी शिकायतें हैं । मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जो पैसा ऊपर से दिया जाता है वह पूरे का पूरा नीचे तक नहीं पहुंचता। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि बेरोजगार युवकों को जो बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा वह पैसा कहां से आयेगा और मुख्यमंत्री जी जो घोषणाएं करते हैं उनका पैसा कहां से आयेगा ?

गोहाना का वैस्टर्न बाई पास हमारी सरकार के समय में बनाया गया था । उस पर कुछ आगे के कार्य होने थे । मुख्यमंत्री जी जब 14 अगस्त, 2016 को गोहाना पुल का उद्घाटन करने गये थे तो उन्होंने बाई पास के आगे के काम करवाने की घोषणा की थी लेकिन आज तक भी वह काम नहीं हुआ है । मैंने यह विषय 2016 के बाद अगले सैशन में भी उठाया था जिसमें मंत्री जी ने यह कार्य करवाने का आश्वासन दिया था लेकिन उस पर आज तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से किलोड़द गांव में आई.टी. इन्स्टीट्यूट बनाने के लिए पिछले बजट में 128 करोड रुपये का प्रावधान किया गया था लेकिन आज तक उसकी नींव भी नहीं भरी गई है । इसी तरह से वहां कोच फैक्ट्री बननी थी उसका भी कहीं कोई रोड मैप नहीं है । इस तरह से मेरे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी घोषणाएं की हैं उनमें एक भी पूरी नहीं की गई। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उन्होंने मेरे हल्के में जितनी भी घोषणाएं की हैं उन पर तुरंत कार्य शुरू करवाकर पूरा किया जाये । अध्यक्ष महोदय, अब मैं भ्रष्टाचार के बारे में बोलना चाहूंगा कि जो बातें कापड़ीवास जी ने कही, करनाल के एम.पी. ने कही और अग्रवाल जी ने कही मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता । मैं यहां केवल वही बातें बताना चाहता हूं जो प्रदेश की जनता ने कही हैं । सी.एम. विंडो में प्रदेश की जनता अपनी शिकायतें भेजती है । सी.एम. विंडो में सिरसा जिले की 8829 शिकायतें आई जिसमें 6094 शिकायतें भ्रष्टाचार से संबंधित थी यानि 69 प्रतिशत शिकायतें भ्रष्टाचार के बारे में आई थी । इसी तरह से भिवानी जिले से 8216 शिकायतें आई जिसमें 4247 शिकायतें भ्रष्टाचार के बारे में थी यानि 52 प्रतिशत शिकायतें भ्रष्टाचार के बारे में थी । इसी तरह से हिसार जिले से 6213 शिकायतें आई जिसमें 67.77 प्रतिशत शिकायतें भ्रष्टाचार के बारे में थी। (घंटी) इसी तरह से गुरूग्राम जिले की 70.71 प्रतिशत और फरीदाबाद जिले से 58 प्रतिशत शिकायतें भ्रष्टाचार के बारे में सी.एम. विंडो में आई थी । अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सी.एम. विंडो में इतनी ज्यादा शिकायतें भ्रष्टाचार के बारे में आ रही हैं तो प्रदेश से भ्रष्टाचार कहां कम हुआ है बल्कि पहले से बढ़ा है । इसके अतिरिक्त कुछ लोग तो पैसे देकर भी अपना काम करवा लेते हैं वह डाटा अलग है । अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं स्टेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ बातें यहां बताना चाहूंगा । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं रिकार्ड की बातें बता रहा हूं ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है । हमारे साथी मलिक साहब अखबारों की खबर पढ़ रहे हैं । इनमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सी.एम. विंडो में जितनी शिकायतें आई थी उनमें से 70 प्रतिशत का निवारण हो चुका है। इस तरह से सी.एम. विंडो की बहुत अच्छी परफारमैंस है । यह रिकार्ड की बात है और मलिक साहब पता नहीं ये बातें कहां से निकाल लाये हैं । सी.एम. विंडो से लोगों में बहुत संतुष्टि है ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, अब आप बैठें । आपका समय पूरा हो चुका है ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं । हरियाणा स्टेट सेलेक्शन कमीशन में 34 नौकरियों का रिजल्ट आया जिसमें 12 नौकरियां ऐसे कंडीडेट्स को दे दी गई जिनको इंटरव्यू के लिए नोटिस ही जारी नहीं हुआ । अध्यक्ष महोदय, यदि आप कहते हैं तो मैं उन कंडीडेट्स का रोल नम्बर पढ़ देता हूं ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, सदन में जो भी माननीय सदस्य कोई बात कहे वह जिम्मेवारी के साथ कही जाये । यदि कोई माननीय सदस्य जिम्मेवारी के बगैर कोई बात कहता है तो नोटिस लिया जाना चाहिए । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो भी सी.एम. विंडो में शिकायतें आती हैं उनका किसी तरह का वर्गीकरण नहीं होता कि कौन सी शिकायत भ्रष्टाचार के बारे में है, कौन सी शिकायत सड़क के बारे में है और कौन सी शिकायत पुलिस के खिलाफ है । इस तरह का कोई साफ्टवेयर नहीं है कि वह शिकायतों का वर्गीकरण करता हो । माननीय सदस्य जो आंकड़े सी.एम. विंडो के बारे में अभी बता रहे थे उनके बारे में या तो ये स्थिति सिद्ध करें अदरवाईज इनके खिलाफ नोटिस लिया जाये ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा स्टेट स्टाफ सेलेक्शन की बात कर रहा था ।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, प्लीज अब आप बैठें । आपने 2 बजकर 38 मिनट पर बोलना शुरू किया था और अब 2 बजगर 46 मिनट हो गये हैं । प्लीज अब आप बैठें ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा था कि स्टेट स्टाफ सलैक्शन कमीशन की वैब–साईट देख ली जाये । उस पर सारा डाटा उपलब्ध है। ऐसे कंडीडेट्स का सेलेक्शन कर दिया गया जिनका इंटरव्यू के लिए रोल नम्बर ही जारी नहीं हुआ था । (शोर एवं व्यवधान) मेरे पास आंगनवाड़ी वर्कर्ज की लिस्ट भी है इसमें भी ऐसे कंडीडेट्स का सेलेक्शन कर दिया गया जिनको इंटरव्यू के लिए रोल नम्बर जारी नहीं हुआ । अध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब दे कि इस तरह से सेलेक्शन कैसे हो रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, मलिक साहब अखबारों की खबर की बात कर रहे हैं । इनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, प्लीज अब आप बैठें । आपको बोलते हुए 8 मिनट का समय हो चुका है । (शोर एवं व्यवधान) मेरी इजाजत के बगैर जगबीर मलिक जी जो कुछ भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये । (शोर एवं व्यवधान) मलिक साहब, प्लीज आप बैठें । आपको जितना समय दिया गया था उससे आप डेढ़ गुना ज्यादा समय बोल चुके हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसबीर देशवाल (सफीदो) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं । वित्तमंत्री जी ने 2018–19 का बजट मजदूर, कर्मचारी, आम आदमी, व्यापारी, किसान यानि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए पेश किया है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश उन प्रगतिशील राज्यों में से एक है जिसने प्रत्यक्ष लाभ अर्जित किया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, प्लीज आप बैठें । आप अपनी बात कह चुके हैं । (शोर एवं व्यवधान)

*** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।**

श्रीमती शकुंतला खटक : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बजट पर बोलना है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहन जी, अभी आप बैठें । आपको भी बजट पर बोलने का अवसर दिया जायेगा । अभी जसबीर देशवाल जी को समय दिया हुआ है । (शोर एवं व्यवधान) मलिक साहब, प्लीज आप बैठे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसबीर देशवाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश 1 अप्रैल, 2017 से कैरोसिन मुक्त प्रदेश बन चुका है इससे लगभग 270 करोड रुपये की बचत हुई है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा समय विपक्ष के साथी इस तरह से खराब न करें ।

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हमारा एक मैंबर भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहा है और आप उनकी बात नहीं सुन रहे जबकि यह सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि मलिक साहब को भ्रष्टाचार पर उनकी बात कहने के लिए समय दिया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब ने जो सी.एम. विंडो का विषय उठाया था उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण बेदी : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है क्या उस भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करना चाहते हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, प्लीज आप बैठें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसबीर देशवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस तरह से कांग्रेस पार्टी के सदस्य बीच में डिस्टर्ब न करें । मैं बजट के बारे में अच्छी बातें बता रहा हूं । (शोर एवं व्यवधान) हमारी सरकार ने महिलाओं को धुएं के कलंक से मुक्त करने के लिए 3 लाख से ज्यादा कनैक्शन एल.पी.जी. के दिए हैं । इसी तरह से गन्ने का भाव भी प्रदेश 330 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है जो देश में सर्वाधिक है । इसके अलावा सूरजमुखी, मूंग, बाजरा और सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई है और भविष्य में भी की जाती रहेगी। इसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जैविक खाद और जैव उर्वरकों के उपयोग के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत 50 एकड़ प्रत्येक के 20 क्लस्टरों में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और 250 गांवों में किसानों को शिक्षित करने के

लिए नाबार्ड के सहयोग से जलवायु स्मार्ट कृषि योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य में बागवानी के तहत आने वाले क्षेत्र को 7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ा कर दुगना करने तथा उत्पादन को तीन गुणा करने के उद्देश्य से हॉर्टिकल्चर का विजन तैयार किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 140 फसल समूहों में 340 बागवानी गांव घोषित किये हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ अपने विधान सभा क्षेत्र की मांगों के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो सब–डिवीजन पिल्लूखेड़ा और सफीदों हैं। पिल्लूखेड़ा सब–डिवीजन जीन्द और सफीदों के बीच में पड़ता है जो कि 40 किलोमीटर की दूरी है। सरकार की योजना है कि 20 किलोमीटर पर कन्या महाविद्यालय खोला जायेगा इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पिल्लूखेड़ा में कन्या महाविद्यालय खोला जाये। पानीपत से जीन्द सड़क को चारमार्गी बनाने की घोषणा हो चुकी है। इस सड़क पर बीच में सफीदों पड़ता है इस प्रोजैक्ट पर यथाशीघ्र काम शुरू करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, सफीदों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। पी.डब्ल्यू.डी. की तथा मार्किटिंग बोर्ड की सड़कें दी हैं लेकिन उन पर कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है इसलिए उस कार्य को जल्दी पूरा किया जाये। मैंने दो गांव हाट और डाटरथ गोद लिये थे जिसमें से हाट गांव में तो विकास के काम हुए है लेकिन डाटरथ गांव में विकास के काम नहीं हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर जल्दी विकास के काम शुरू करवाये जायें। इसी प्रकार से खेड़ा खेमावती गांव में हाई स्कूल है उसको अपग्रेड करके 10+2 का किया जाये। यह गांव सफीदों से दो किलोमीटर की दूरी पर है लेकिन यहां बच्चों की संख्या अपग्रेडेशन के नॉर्म्स के मुताबिक है इसलिए रिलैक्सेशन दे कर इसको अपग्रेड किया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं बिजली के बारे में बताना चाहूंगा कि बिजली की तारों को बदलने का काम बहुत धीमा चल रहा है इसलिए इसको स्पीडअप करने की जरूरत है। सफीदों में 3 पॉवर हाउस बनाने का प्रोसैस बहुत धीमा है इसलिए उसको भी तेज किया जाये। गांगोली और भाग खेड़ा गांवों के खेतों में पानी भर जाता है और वह ड्रेन से नीचे चला जाता है जिसके कारण 300 एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है इसलिए वहां पर पाइपलाइन डाल कर उस पानी को निकालने के लिए इस प्रोजैक्ट को मंजूर करवाया जाये। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव डिडवाड़ा में पिछले साल लगभग 250 एकड़ गेहूं की

फसल बिजली के तारों के कारण आग लग कर जल गई थी। उसके लिए सरकार ने 12 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की घोषणा की हुई है जो अभी तक उन लोगों को नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन किसानों को जल्दी से जल्दी इनकी फसल का मुआवजा दिया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमें भी बोलने के लिए समय दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपको अलग से टाईम दे देंगे । अब आप प्लीज बैठ जाईये ।

श्री हरविन्द्र कल्याण (घरौंडा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद । अबकी बार बहुत अच्छा बजट पेश हुआ है । जिसमें कोई नया कर नहीं लगा है । उसमें चाहे टी.आर.आर. में बढ़ोतरी की बात है, चाहे कैपिटल एक्सपैंडेचर में बढ़ोतरी की बात है, चाहे फिस्कल डैफिसिट 3 प्रतिशत से कम रहने की बात है । अध्यक्ष महोदय, आज बजट पर बहुत विस्तार से बोलने की इच्छा थी लेकिन समय की कमी होने के कारण मैं बजट पर केवल अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी के वक्तव्य को ही दोहराना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मोस्ट हैंडसम फाईनैंस मिनिस्टर एण्ड ए वैरी ब्यूटीफुल बजट । मैं कहना चाहूंगा कि पूरा हफ्ता विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना अर्थात मुद्दा विहीन होने से जो गम्भीर चर्चा होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई है । उन्होंने हमारे माननीय सदन के नेता मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य में बेवजह बीच–बीच में टोका–टाकी की है । स्पीकर सर, उस संबंध में मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि यह इस तरह की परम्परा न बने इसलिए यह सबकी चिन्ता होनी चाहिए । स्पीकर सर, आज मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की दो–तीन बातें जरूर रखना चाहूंगा । उनमें मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने घरौंडा विधान सभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है । उसके साथ ही जो जरूरी विषय हैं उन पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । जैसे वहां कन्या महाविद्यालय बनाने की बात है क्योंकि हमारा घरौंडा अभी सब डिवीजन बना है इसलिए वहां पर इतनी कोई सरकारी जमीन नहीं है । अतः वहां पर सब डिवीजन लैवल का एक स्टेडियम होना

बहुत जरूरी है जिसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है । इसके अलावा केन्द्र सरकार से संबंधित मेरे हल्के की कुछ समस्याएं हैं जिनके लिए आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार केन्द्र की सरकार को लैटर लिख कर उन समस्याओं को दूर करवाने का काम करें । जैसे कि नेशनल हाई–वे नं0 1 जो जी.टी.रोड है वह मंदिर के पास अभी तक 4 लेन है जबकि सारी सड़क 6 लेन और साथ में सर्विस लाईन भी बन चुकी है । वह सड़क 4 लेन होने के कारण वहां पर बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं । उसमें मैं चाहूंगा कि वहां पर जो कम्पनी टोल वसूल करती है उसे चैक करे कि यह रोड 6 लेन होने में किस कारण से देरी हो रही है । इसके साथ ही जी.टी. रोड पर कम्बोपुरा गांव के पास एक अण्डर पास की जरूरत है क्योंकि उस गांव की लगभग आधी जमीन जी.टी. रोड के दूसरी तरफ है जिससे वहां पर लोगों को दूसरी तरफ जाने में दिक्कत होती है । जब जी.टी. रोड बन रहा था तब वहां पर एक छोटा सा अण्डर पास बनाने का प्लान था लेकिन वह अभी तक बन नहीं पाया है । स्पीकर सर, घरौंडा में रेलवे विभाग की जो जमीन लीज पर लेनी है जिसकी माननीय रेल मंत्री जी ने स्वीकृति दी थी तो मेरा निवेदन है कि उसका कार्य जल्दी से शुरू हो क्योंकि यह 22 गांवों का विषय है । यह जमीन मिलने के बाद घरौंडा की रेलवे रोड से आर.यू.बी. कनैक्ट होगा । मेरे हल्के के यह कुछ जरूरी विषय थे जिनको मैं यहां सदन में रखन चाहता था । इसी के साथ मैं आपका दोबारा से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती शकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का समय दें ।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, प्लीज आप बैठ जाईये । मैं आपको बाद में बोलने का टाईम जरूर दूंगा ।

श्री तेजपाल सिंह तंवर (सोहना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री और वित मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया है ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है ।

वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर

15:00 बजे

श्री तेजपाल तंवर : अध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारे वित मंत्री जी ने पेश किया है ऐसा बजट हमारे प्रदेश में पहली बार आया है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश की जनता इस सदन की कार्यवाही को देखने व सुनने के लिए सदन में आती है, वह जानना चाहती है कि आखिर हमारे प्रदेश की सरकार और हमारे विपक्ष के साथी हरियाणा प्रदेश के बारे में किस प्रकार के विचार रखते हैं, लेकिन सदन में जिस तरह का आचरण देखने या सुनने को मिलता है, उससे मुझे लगता है कि भविष्य में शायद ही हरियाणा की जनता इस सदन की कार्यवाही को देखने व सुनने के लिए इस सदन में आयेंगे? अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी सदन में जो भी बात रखें उन बातों में कम से कम इतना तो जरूर बताना चाहिए कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं, उनमें यह खामियां हैं और उन खामियों को दूर करने संबंधी सुझाव भी दिए जा सकते हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि विपक्ष की तरफ से केवल और केवल सत्ता पक्ष की बुराई करने के सिवाय और कोई काम नहीं किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की भी सरकार सत्ता में रही थी और इन भाईयों ने भी प्रदेश में बहुत काम किए थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस तरह के काम किए कि जैसे इन्होंने जो प्रदेश में रोड बनाये थे, जैसे ही बारिश आती तो यह रोड एक महीने की समयावधि में बह जाया करते थे। वैसे तो हमारे क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने कभी रोड बनाये ही नहीं लेकिन अगर मान लो कि कोई रोड बन भी गया तो वह रोड बारिश होते ही बह जाया करता था। हमारे नूंह जिले में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में बिल्डिंग बनाई गई उनमें बीम की जगह बल्ली डाल दी जाती थी और जहां सरियों का प्रयोग करके लैंटर डाला जाता है वहां पर झूंड की छत डाल दी गई थी। इस प्रकार के हालात हमारे क्षेत्र में हुआ करते थे। हमारे क्षेत्र के हिस्से के 70 प्रतिशत बजट को कांगेस पार्टी के लोग खा जाया करते थे। 30 परसेंट ही केवल हमारे एरिया पर खर्च होता था। आज यही लोग सदन के माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस पार्टी के लोग भी सत्ता से जाते जाते प्रदेश पर बहुत भारी कर्ज छोडकर गए थे लेकिन जब

हम प्रदेश के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं तो भी ऐसी परिस्थिति में यह लोग आक्षेप लगाते हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार में केवल और केवल पत्थर लगाने तक का कार्य तो किया जाता था लेकिन उससे आगे कुछ नहीं होता था। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार में लगे उद्घाटन पत्थरों को रेल में ढोना चाहे तो शायद यह पत्थर रेल में भी नहीं आ पायेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी भी सरकार में रही लेकिन इनके राज में भी पांच–पांच करोड रूपये की जमीन, अढ़ाई–अढ़ाई लाख रूपये में एक्वॉयर कर ली जाती थी। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। हम किसानों के हितों की बात करने वाले हैं लेकिन विपक्ष के हमारे साथी कुछ पेशेमंद किसानों को इक्ट्ठा करके सरकार के खिलाफ रोज शोर मचवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में बहुत से कदम उठाये हैं। हमारे कृषि मंत्री जी ने तो किसानों के हितों के लिए कही–कही तो 85 परसेंट सब्सिडी तक देने का काम किया है। क्या यह सब्सिडी किसानों के काम नहीं आयेगी? अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही और भी बहुत से काम हमारी सरकार किसानों के हित में करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, सदन में एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि या तो सदन में नहीं आयें और अगर आते हैं तो इस सदन में झूठ न बोले क्योंकि ऐसा करने की अवस्था में बहुत पाप लगता है, परन्तु इस सबके बावजूद सदन में 100 प्रतिशत झूठ ही झूठ बोला जाता है, सच्ची बात तो कोई कहता ही नहीं है। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता भी सदन में मौजूद हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि हर हाल में सदन की परंपराओं को बनाये रखते हुए सदन में सच्ची बात ही कही जानी चाहिए और यही नहीं अगर कोई गलत बात है तो उसको कहा भी जाये और उसके लिए सदन में सुझाव भी दिए जायें और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इन सब बातों का ध्यान रखा जायेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने प्रदेश के विकास से संबंधित जो भी काम दिए उन्होंने उन कामों को फटाफट करके दिखाया और अगर कोई एक आधा काम रह भी गया है तो वह भी जल्द पूरा हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे नसीब भाई ने मेवात क्षेत्र में रेल चलाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितनी ही बार मेवात क्षेत्र में रेल चलाने की बात कही लेकिन किया कुछ नहीं जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेवात क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने की बात को

बजट में रख दिया है। अध्यक्ष महोदय, जब रेल दिल्ली से सोहना होते हुए नूंह जायेगी तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय वित्त मंत्री जी दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसके अतिरिक्त हमारे क्षेत्र में जो रोड़ज को फोर लाईन बनाने की बात बजट में कही गई है उसके लिए भी मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज प्रदेश में विकास के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं और प्रदेश की जनता जानती है कि आज झूठ और लूट की राजनीति खत्म हो गई अब तो केवल यह बात रहेगी कि जो प्रदेश का विकास करेगा वह प्रदेश में राज करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री भगवान दास कबीर पंथी (नीलोखेड़ी) (अ.जा.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बधाई देता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी को जो वह प्रदेश व सबके हित में एक कल्याणकारी बजट लेकर आये है इससे प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे परिवहन की बात हो या चाहे कृषि की ही बात क्यों न हो, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया है और सबसे अहम बात इस बजट की यह है कि इसमें वह गरीब आदमी जो अंतिम पायदान पर बैठा है, वह किस प्रकार आगे बढ़े तथा वह खुशहाल हो इस सबके लिए भी बजट में बात रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1966 में हरियाणा प्रांत बनने के बाद प्रदेश में बहुत सी सरकारें आई, बहुत से मुख्यमंत्री बने, अलग अलग रूप से उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए व्यवस्था की और अलग–अलग योजनाएं भी बनाई, बार बार बजट लाए गए लेकिन कहीं न कहीं उन सरकारों में लचीलापन रहा और यही वजह रही कि उस लचीलेपन की वजह से भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को प्रदेश में आने का मौका मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और उनकी पूरी कैबिनेट का जिन्होंने वोट की राजनीति से उपर उठकर कठोर से कठोर फैसला लेने का काम किया है। चाहे पंचायत चुनावों में शिक्षा को अनिवार्य करने का काम हो, इस पर विपक्ष के साथियों ने बहुत शोर मचाया था। (विघ्न) आज हर पंचायत में प्रतिस्पर्धा की भावना आई है कि मैं अपने गांव को किस तरह से आगे लेकर जाऊँ । पहले शिक्षा विभाग में जिस तरीके से ट्रांसफर पॉलिसी में धांधली हुआ करती थी, उस धांधली को बंद करने का काम हमारी

सरकार ने किया है। आज गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को मैरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरह से पहले किसानों की फसल अनाज मण्डी में दो–तीन दिन तक पड़ी रहती थी, आज उनकी फसल को उठाने और पैसा भुगताने का काम समय पर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी कह रहे थे कि सरकार ने पिछले साढ़े तीन साल में क्या किया है? इसके जवाब में अगर मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करूँ तो हमारी सरकार ने नीलोखेड़ी को शिक्षा का हब बनाया है। आज वहाँ पर राजकीय कॉलेज बनने जा रहा है। जिसकी वर्षों से डिमाण्ड हुआ करती थी और इसी सत्र से वहाँ पर क्लासिज शुरू होने जा रही है। पौलिटेक्निक कॉलेज की जो पुरानी मांग थी, पिछले वर्ष से इंजीनियरिंग की क्लासिज़ शुरू हो चुकी हैं। एक बहुत बड़ी बागवानी यूनिवर्सिटी की सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमारे क्षेत्र में दी है और इस यूनिवर्सिटी के लिए 486 करोड रूपये बजट में प्रावधान किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। गुरूकुल कन्या महाविद्यालय जिसमें हमारे बच्चे केवल 10वीं व 12वीं तक ही पढ़ा करते थे, आज इस महाविद्यालय में ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के तकरीबन 7–8 राजकीय स्कूल्ज अपग्रेड हो चुके हैं। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो हमारे क्षेत्र में दो नई पी.एच.सी. गांव गंगोधर व समाना बाहु में खुलने जा रही हैं। हमारे तरावड़ी में 50 बैड का अस्पताल बनने जा रहा है और नीलोखेड़ी में 100 बैड का अस्पताल बनने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय खेल मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र के चार गांवों जम्बा, सिकरी, समाना बाहु और बस्तली में खेल स्टेडियम की सौगात दी है। नीलोखेड़ी हाइवे पर है और यहां पर अरबों रूपये का चावल का कारोबार होता है, सरकार को इतना रेवेन्यू देने के बाद भी किसी भी सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारी सरकार मेरे क्षेत्र की सारी सड़कों को ठीक करने का काम तो कर ही रही है और साथ में सड़कों की चौड़ाई भी बढ़ाने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी ने वर्ष 2018–19 के लिए लगभग 1,15,198 करोड रूपये का बजट प्रस्तुत किया है। मैं अपने हल्के की जो वर्षों से मांग है, उनकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में लगभग 118 एकड़ जमीन पर बागवानी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उस यूनिवर्सिटी में गांव के ही बच्चों को 'सी' व 'डी' कैटेगरी की भर्ती में और एडमिशन में

प्राथमिकता दी जाये । निसिंग हमारा एक कस्बा है, जो कैथल और करनाल रोड पर पड़ता है। वहाँ पर अनाज मण्डी है और मार्किट भी है। कैथल और करनाल से फोरलेन की मंजूरी मिली हुई है। लेकिन वहाँ से एक बाईपास निकाला जाये ताकि ट्रैफिक के कारण जो बड़े–बड़े हादसे होते हैं, उनसे बचा जाये। नीलोखेड़ी में चार एकड़ में एक मण्डी है। उस मण्डी में न तो कोई नया दुकानदार आता है और सीज़न के समय किसानों की फसल मण्डी के बाहर पड़ी रहती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग है कि उस अनाज मण्डी को शहर से बाहर निकाला जाये। अध्यक्ष महोदय, नई अनाज मण्डी के लिए हमने सरकार को प्रस्ताव दिया हुआ है। मेरी माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि इस समस्या को देखते हुए, इस समस्या को हल किया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।

श्री बलवंत सिंह (सढौरा) (अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2018–19 के लिए लगभग 1,15,198 करोड रूपये का बजट प्रस्तुत किया है। यह एक संतुलित बजट है। इस बजट में हर वर्ग चाहे अमीर–गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी या कर्मचारी हो सबको ध्यान में रख कर ही बजट पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश के अनुसार समय का अभाव है। अगर हम इस बजट के हर बिन्दु पर प्रकाश डाले तो पिछले वर्ष की तुलना में चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो उसमें लगभग 51 प्रतिशत की वृद्धि, सिंचाई के क्षेत्र में लगभग 20.1 प्रतिशत की वृद्धि, शहरी विकास के लिए लगभग 26.65 प्रतिशत की वृद्धि, बिजली विभाग में लगभग 10.9 प्रतिशत की वृद्धि, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 20.32 प्रतिशत की वृद्धि, कौशल विकास के क्षेत्र में लगभग 20.32 प्रतिशत की वृद्धि और पी0डब्लयू0डी0 (भवन एवं सड़क) विभाग में भी पिछले साल की तुलना में काफी वृद्धि इस बजट में सरकार ने की है। कुल मिलाकर माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2018–19 के लिए 1,15,198.29 करोड रूपये का बजट प्रस्तुत किया है जोकि बजट अनुमान वर्ष 2017–18 की तुलना में 12.6 प्रतिशत और 1,00,739.38 करोड रूपये के संशोधित अनुमान वर्ष 2017–18 से 14.4 प्रतिशत अधिक है। अध्यक्ष महोदय, बजट के हर पहलु पर यदि नजर लगाएं तो यह बजट समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी है। इस बजट की जितनी भी प्रशंसा की जाये उतनी ही कम है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात

सदन में जरूर कहूगाँ कि इस समय सदन के सम्मानित सदस्य जो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जब वे विपक्ष में होते थे तो उनको एक मिनट भी नहीं बोलने दिया जाता था और नेम करके सदन से बाहर निकाल दिया जाता था। इस बात का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपकी फिराखदिली की सभी माननीय सदस्यगण सराहना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, जिसे हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सारे विकास के काम हमारे क्षेत्र में हो जायेंगे। चाहे वह कॉलेज का काम हो, पौलिटेक्निक कॉलेज का काम हो, अस्पताल के अपग्रेडेशन का काम हो, 66 के.वी.ए. ट्रांसफार्मर देने की बात हो या फिर सारी सड़कों का उदारीकरण का काम हो। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे यहाँ जो कॉलेज है, जिसमें क्लासिज़ शुरू होनी है। वह कॉलेज को–एजुकेशन के नाम से सैंग्शन हुआ था। मुझे पता लगा है कि वह कॉलेज गर्ल्ज के लिए बनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, उस कॉलेज को को–एजुकेश ही रहने दीजिए नहीं तो हमारे हल्के के बाकी बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जायेंगे? बिलासपुर से लेकर जरनैली रोड बनाया गया है लेकिन उसमें सिर्फ जागधोली से बड़ैल का अढ़ाई किलोमीटर का रास्ता रह गया है, अगर वह रास्ता बन जाता है तो साढौरा से जब मुड़कर आते हैं तो 15 किलोमीटर का रास्ता कम हो जायेगा। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे सरस्वती नगर में को–एजुकेशन कॉलेज बनाने की घोषणा की हुई है, मैं चाहूँगा कि उस पर भी जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाये। मेरे हल्के के तीन गांव रटौली, रामपुरराईयां और कानड़ीकलां के राजकीय स्कूलों में बच्चों की संख्या पर्याप्त हैं, इन स्कूलों को भी अपग्रेड किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे हल्के के पांच स्कूल्ज पहले ही अपग्रेड कर दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं चाहूँगा कि मेरे हल्के के रामपुरछोली में 33 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर लगाया जाए, जो वहां के लोगों की बहुत जरूरी डिमाण्ड है क्योंकि लगभग 50–60 किलोमीटर के एरिया से लाइन आती है। बिजली को लेकर हर रोज वहां पर दिक्कत रहती है। इसके लिए हमने जमीन का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि समय के अभाव के कारण आपकी नजर मेरे ऊपर लगी हुई है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।

श्री घनश्याम दास (यमुनानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट अनुमान प्रस्तुत किये हैं वे अनुमान हरियाणा के समग्र विकास के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। हरियाणा प्रदेश की वर्तमान सरकार गन्ने का सर्वाधिक मूल्य देने वाली सरकार है। इसके अतिरिक्त पॉपलर और सफेदा उत्पादकों के हित में नये लाईसेंस देकर उसकी ठीक से मार्किटिंग हो सके और उद्योग को बढावा मिल सके, ऐसा निर्णय सरकार ने लिया है। यह प्रदेश की पहली सरकार है जिसने हरियाणा प्रदेश में बागवानी विश्वविद्यालय खोलने की स्थापना की है जिससे फसलों के विविधिकरण में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी और इसी सरकार ने 'भावांतर भरपाई योजना' के तहत किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ वर्तमान सरकार ने जिस अनुपात में कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाएं हैं, उस अनुपात में आज से पहले किसी भी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढाए थे। इसके लिए सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर जिला हरियाणा प्रदेश के अग्रणी जिलों में एक विशेष स्थान रखता है। यमुनाननगर जिले में माईनिंग हो रही है और जो वाहन अपना मैटिरियल लेकर जाते हैं तो उन वाहनों से टपकता हुआ पानी सड़कों पर गिरता जाता है जिसके कारण सड़कें टूट जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे वाहन रेत लेकर जाते है तो उन वाहनों से रोडज के ऊपर टपकता हुआ पानी जाता है और उस पानी के कारण सड़कें टूटती रहती हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिन स्थानों से माईनिंग का मैटिरियल लेकर वाहन निकलते हैं वे सड़के पानी के कारण खराब हो जाती हैं तो उन स्थानों पर इस प्रकार की सड़कें विकसित की जाएं जो टपकते हुए पानी का सामना करते हुए लम्बे समय तक लोगों को सेवा दे सकें। इसके साथ ही माननीय कृषि मंत्री, माननीय उद्योग मंत्री और सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार ने जो कार्ड बोर्ड और प्लाई के लाईसेंस दिये थे उसके फलस्वरूप यह इंडस्ट्री बड़ी मात्रा में विकसित हो रही है। विश्वस्तरीय प्रोडैक्शन के लिए पॉपलर और सफेदे की फसल के लिए कोई रिसर्च नहीं हुआ है और पॉपलर और सफेदे की जो प्रजातियां पहले से चली आ रहीं हैं उन्हीं प्रजातियों का उत्पादन किया जा रहा है। इसलिए ऐसी प्रजातियों को विकसित किया जाए जो जल्दी तैयार हों और अधिक बॉयोमास दे सकें। इसके लिए कोई अनुसंधान केन्द्र या विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। इसके

साथ ही एक विश्व स्तरीय गुणवता वाला कार्ड बोर्ड, प्लाई और प्लास्टर तैयार करने में अनुसंधान केन्द्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसा अनुसंधान केन्द्र निश्चित रूप से अच्छे कार्ड बोर्ड और प्लाई को मैन्यूफैक्चर करने में सहायक सिद्ध होगा और निश्चित रूप से यमुनानगर का क्षेत्र विश्व के मानचित्र पर लकड़ियों के उद्योग में स्थापित हो चुका है इस उद्योग को और आगे बढाये जाने की जरूरत है। इसके साथ नगर निगम में जितने कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं उतने कर्मचारी कार्यरत नहीं है इसलिए स्वीकृत पदों की संख्या के हिसाब से कर्मचारी नियुक्त किए जाएं ताकि विकास के काम को गति मिल सके। इसके अतिरिक्त निगम पार्षदों के प्रतिनिधि प्रायः कहते रहते हैं कि उनको वर्तमान सरकार से यह अपेक्षा है कि उनके वेतन बढाए जाने चाहिए। एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि नगरों में शाम के समय जाम की स्थिति बन जाती है इस जाम की स्थिति से निपटने के लिए कोई रिंग रोड हर नगर में विकसित किया जाए ताकि शहर के लोग शाम के समय बन्धक बनकर अपने घरों में न बैठे रहें। यदि उनको अपने बच्चों की परीक्षा दिलवाने के लिए सुबह जाना है और कारोबार करने के बाद शाम को जब वे घर वापिस आते हैं तो उनको जाम की स्थिति का सामना न करना पड़े। इन बातों पर ध्यान दिया जाएगा तो हरियाणा प्रगति के पथ पर अग्रसर है उसको और गति मिल जाएगी और हम हरियाणा प्रदेश को भारतवर्ष का अग्रणी प्रदेश बनाने में सफल हो सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, क्या मेरी तरफ आपकी सख्त नजर है ?

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी तरफ कोई सख्त नजर नहीं है। सभी माननीय सदस्य बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. रविन्द्र बलियाला (रतिया) (अ.जा.): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां तक इस 2018–2019 के बजट का सवाल है यह केवल मात्र आंकड़ों का खेल है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में आंकड़ों को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि यह देखने में बहुत अच्छा बजट लगता है, लेकिन एक कहावत है कि नई बोतल में पुरानी शराब है ''old wine is in new bottle.'' अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बजट में पिछले बजट की उन सारी योजनाओं और स्कीमों को ही रिपीट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी

डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन मैं केवल मात्र केवल जो मेरे हल्के से संबंधित है उन बातों की व्याख्या करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले बजट में मेरे हल्के की सड़क फतेहाबाद, रतिया और बुडलाडा तक बननी थी उसकी बात कही गई थी, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई काम शुरू नहीं हुआ और इस बार फिर से इस बजट में उन्हीं सड़कों के बारे में दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार सिर्फ घोषनाएं करती रहेगी और बजट में केवल लिखती रहेगी या उसके ऊपर काम भी करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट में अर्बन डेवल्पमेंट के अंदर एक AMRUT(अमरूत) यानी अटल मिशन फॉर रिजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोरमेशन स्कीम का जिक्र किया गया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारे रतिया और जाखल–दादरी के अंदर नगरपालिका ने 250 लोगों को बेघर करने का नोटिस दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि जो अर्बन डिवैल्पमेंट का 5626.84 करोड रुपए का बजट है उसके तहत जिन लोगों को बेघर करने का नोटिस दिया गया है क्या उन लोगों के घर बनाए जाएंगे ? अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को बेघर करने का नोटिस दिया गया है उनकी जमीन पहले पंचायत के अंडर में थी, लेकिन अब वह जमीन नगरपालिका के अंडर में आ गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि उन लोगों की 3–3 पीढ़ियां आगे आ गई, लेकिन अब उनको बेघर करने का नोटिस दे दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से मेरा एक सवाल घग्घर नदी के पॉलुशन के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा हर साल बजट में कहा जाता है कि हम इस पॉलुशन को ठीक करेंगे, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी का लिखित में जवाब है, जिसमें यह कहा गया था कि 31 दिसंबर, 2016 तक घग्घर नदी को पॉलुशन मुक्त कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार पब्लिक हैल्थ के ऊपर बहुत पैसा खर्च कर रही है और बजट स्पीच में कितनी ही बीमारियों का जिक्र किया गया, लेकिन घग्घर के अंदर जो पॉलुशन से बहुत सी बीमारियां हो रही हैं उसका क्या होगा ? अध्यक्ष महोदय, रतिया के अंदर हैपेटाइटस–सी और कैंसर जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर पानी बहुत ज्यादा जमा रहता है और जाखल तक पानी भरा रहता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक बराला साहब जी को भी पता ही होगा कि वहां पर कितना पानी भरा रहता है और उससे कितनी बीमारियां फैल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि

सरकार पब्लिक हैल्थ के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रही है तो क्या पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पौल्यूशन के ऊपर कुछ–न–कुछ संज्ञान लेगा कि आखिर पौल्यूशन को कैसे ठीक किया जाए ? अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इस बजट में मेडीकल एजुकेशन और हैल्थ की बात की गई है और सरकार हर बजट स्पीच में यह कहती है कि हर जिले में हम एक मेडीकल कॉलेज खोलेंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उसके लिए क्या किया है? अध्यक्ष महोदय, सरकार पंचकुला और गुरूग्राम की बात करती है, जो कि चण्डीगढ़ के नजदीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार पंचकुला और गुरूग्राम वाले हॉस्पिटल्ज को फैसिलिटी देने के बजाए, रूरल एरिया के अंदर जो हॉस्पिटल्ज हैं उनको थोड़ा अपग्रेड करें ताकि जहां से हॉस्पिटल्ज काफी दूर हैं उनको अच्छी फैसिलिटी मिल सके। अध्यक्ष महोदय, रतिया के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए हिसार, बठिण्डा या फिर पटियाला जाना पड़ता है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि रतिया क्षेत्र जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहां के लोगों के लिए मेडीकल फैसिलिटी उपलब्ध करवाएं। अध्यक्ष महोदय, सरकार गुरूग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला जो पहले से डिवैल्प शहर हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी देने की बात करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार ने बजट में इतना पैसा हैल्थ के लिए रखा हुआ है उसके अंतर्गत क्या ये ऐसा कोई प्रोविजन करेंगे, जिससे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए ? अध्यक्ष महोदय, इस बजट स्पीच में थोड़ी सी नई टर्म्स एण्ड कंडीशन जोड़ दी गई है, जैसे पहले के बजट में लिखा हुआ था कि केवल गवर्नमेंट ही मेडीकल कॉलेज खोलेगी लेकिन इस बजट में यह लिख दिया गया है कि मेडीकल कॉलेज को गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी में से कोई भी बना सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो पराली के जलाने की बात थी तो सरकार ने पराली से रिलेटेड फतेहाबाद के लिए जो एक प्रोजेक्ट दिया है, क्योंकि रतिया क्षेत्र में पराली की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पैडी होती है। अध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपने लैवल पर इस तरह का कोई–न–कोई प्रोजेक्ट लगाए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कुछ सवाल और भी पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आदरणीय मंत्री जी इसे नोट भी कर लें। स्पीकर सर, सरकार द्वारा बजट में फिस्कल मैनेजमैंट के ऊपर काफी लम्बी–चौड़ी बातें लिखी गई हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि यह जो मानदण्ड दिया गया है यह लिमिट के अंदर दिया गया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बलियाला जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए अब आप कृपया करके बैठ जायें। अब श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी बोलेंगी।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला (डबवाली) : धन्यवाद स्पीकर सर। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वह पूरे प्रदेश के लिए एक रोड मैप होता है। जब सरकार द्वारा बजट पेश किया जाता है तो प्रदेश के सभी लोगों की उसके ऊपर निगाह होती है कि उनके लिए बजट में क्या होगा? मैं एक महिला होने के नाते यह कहना चाहूंगी कि हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उससे प्रदेश की सारी की सारी महिलायें बहुत निराश हैं क्योंकि बजट में प्रदेश की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया है। सर्वप्रथम मैं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहूंगी। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के बारे में बात की जाये कि जब गर्भवती महिलायें हॉस्पिटल जाती हैं तो सरकारी हॉस्पिटल्ज़ और सी.एच.सीज़. में शाम चार बजे के बाद कोई ए.एन.एम. और डॉक्टर नहीं मिलता। इस कारण चार बजे के बाद गरीब महिलाओं को प्राईवेट हॉस्पिटल्ज़ में जाना पड़ता है। उनकी समस्या यह है कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वे प्राईवेट हॉस्पिटल्ज़ की फीस चुका सकें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि आज हरियाणा में कुपोषित महिलायें 58 परसैंट हैं। इसी प्रकार से 42 परसैंट कुपोषित बच्चे हैं। इन बच्चों में से 14 परसैंट बच्चों की स्थिति बहुत खतरनाक स्टेज़ पर है। इन कुपोषित बच्चों में से आये दिन बहुत से बच्चों की डैथ हो रही है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश में जो हॉस्पिटल्ज़ हैं उनमें गर्भवती महिलाओं के लिए यह कंडीशन है कि अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जाता। इस प्रकार के मामले भी सामने आये हैं कि जब हॉस्पिटल्ज़ में आधार कार्ड के अभाव में गर्भवती महिलाओं को एडमिट नहीं किया गया तो उन महिलाओं की डिलीवरी मजबूरीवश पार्क में भी करवानी पड़ी है। मैं एक घटना बताना चाहूंगी कि दिनांक 11 फरवरी, 2018 को एक चोट लगी हुई महिला को पहले तो पंचकूला से कालका भेजा गया और फिर कालका से वापिस उसको पंचकूला लेकर आया गया। इसी प्रकार से मैं महिलाओं की सुरक्षा की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी। मेरा यह कहना है कि हरियाणा प्रदेश में हॉस्पिटल्ज़ में ईलाज के लिए आने वाली महिलायें भी पूरी तरह से सुरक्षित

नहीं हैं। कुरूक्षेत्र के लोक नायक जय प्रकाश जनरल हॉस्पिटल में सिविल सर्जन का ऑफिस व निवास स्थान भी है, इस हॉस्पिटल में 17 नवम्बर, 2017 को एक महिला से डॉक्टर द्वारा किये गये बलात्कार का मामला सामने आया था। इसी प्रकार से आई.सी.यू. का भी एक मामला है। अब मैं शिक्षा के मामले में बात करना चाहूंगी। मेरा डबवाली हल्का राजस्थान से सटा हुआ है जिसके कारण डबवाली हल्का शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्री जी ने वित्त मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत करने के उपरांत ब्यूटीफुल बजट कहकर बजट की सराहना की थी। इस प्रकार से उनके कहे अनुसार यह बजट फीमेल बजट हो गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहूंगी कि बजट के अंदर डबवाली हल्के के लिए कितने महिला महाविद्यालय खोलने का प्रावधान रखा है। इसी प्रकार से सरकार डबवाली हल्के में कितने स्कूल खोलने जा रही है यह भी मैं सरकार से जानना चाहूंगी। शिक्षा मंत्री जी ने ब्यूटीफुल बजट कहा तो इसलिए इस दिशा में उनको ये सब काम डबवाली हल्के के लिए करने ही पड़ेंगे। अब मैं अपने डबवाली हल्के में पानी की समस्या के बारे में बात करना चाहूंगी। आज मेरे डबवाली हल्के में पीने के पानी की भयंकर समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि गांवों में जो पानी की डिग्गियां हैं उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में गाद भरी हुई है। मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रिकवैस्ट है कि आने वाले गर्मी के मौसम से पहले इन पानी की डिग्गियों की गाद जल्दी से जल्दी निकाली जाये ताकि गर्मी के मौसम में मेरे डबवाली हल्के के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उनको निर्बाध रूप से पीने का साफ पानी उचित मात्रा में मिल सके। मेरे डबवाली हल्के में बिजली की भी बड़ी भारी समस्या है। सरकार द्वारा जगमग योजना में सिरसा जिले को भी काउंट किया गया है। पूरे सिरसा जिले में सबसे ज्यादा कम बिजली डबवाली हल्के को मिलती है। सरकार को इस ओर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और मेरे डबवाली हल्के की बिजली की समस्या को दूर करना चाहिए। अब मैं स्वच्छता के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगी। सरकार की योजना है स्वच्छ हरियाणा और इसी प्रकार से केन्द्र सरकार की योजना है स्वच्छ भारत। अगर आप हाईवे पर जायें तो हाईवे के ऊपर आपको सबसे ज्यादा गंदगी डबवाली में मिलेगी। सिरसा जिले को सफाई के लिए जो अवॉर्ड दिया गया है इस बारे में मेरा यह कहना है कि जिस अधिकारी ने इस अवॉर्ड के लिए सिरसा जिले को सिलैक्ट किया है उस अधिकारी की जांच होनी चाहिए। वहां पर स्कूल्ज़ में सबसे ज्यादा गंदगी

है। इसी प्रकार से सबसे ज्यादा गंदगी हाईवे पर भी होती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि हाईवे के ऊपर जितनी भी सब्जी मण्डियां लगती हैं सरकार एक विशेष आदेश जारी करके उनको हाईवे से दूर कहीं दूसरी जगह पर लगवाये क्योंकि हाईवे पर सबसे ज्यादा गंदगी इन सब्जी मण्डियों के पास ही होती है। वहां पर ज्यादा गदंगी होने की वजह से वहां पर हर वक्त आवारा पशुओं का भी जमावड़ा लगा रहता है जिसके कारण वहां पर बहुत सी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसी के साथ मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगी कि हमारे वहां पर जो हाईवे बना है उस हाईवे पर चोरमार नाम का एक गुरूद्वारा आता है। उस गुरूद्वारे में जब हम एंटर करते हैं तो हमें बहुत लम्बी दूरी तय करके देर से घूम कर आना पड़ता है क्योंकि इस गुरूद्वारे के पास हाईवे में कोई कट नहीं है। अभी–अभी मेरे पास आस–पास के क्षेत्रों से बहुत से सिख भाई इक्ट्ठे होकर आये थे कि गुरूद्वारे में जब संगत लगती है तो उनको भी पांच किलोमीटर दूर स्थित कट से होकर आना पड़ता है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर गुरूद्वारे के सामने या तो अण्डरपास बनवाया जाये या फिर हाईवे पर एक कट दिलवाया जाये जिससे गुरूद्वारे में आने वाली संगत को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। अब मैं हरियाणा प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात करना चाहूंगी। डबवाली हल्के में एक व्यापारी भाई को आये दिन बहुत सी धमकियां मिलती हैं। आये दिन उनके दरवाज़े पर गोलियां चलाई जाती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगी कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा तो नहीं कर सकती लेकिन कम से कम प्रदेश के व्यापारियों को तो सरकार को एक सुरक्षित वातावरण में जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा बहुत ही कम संख्या में महिला सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की हुई है। अगर सीनियर महिला पुलिस कर्मियों की संख्या देखी जाये तो उनकी संख्या तो जीरो के बराबर है। मैं डबवाली के उस व्यापारी भाई की सुरक्षा के लिए सरकार से विशेष आग्रह करूंगी क्योंकि जब भी मैं डबवाली जाती हूं तो उस घर की महिलायें मुझसे मिलने आती हैं और कहती हैं कि आप हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए सरकार से कोई पुख्ता इंतजाम करवायें। मेरा सरकार से बार–बार यही आग्रह है कि डबवाली के सभी व्यापारी भाईयों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाये। सर, मेरी एक छोटी सी डिमाण्ड और है मेरा यह कहना है कि मेरे डबवाली हल्के में एक गर्भवती महिला डिलीवरी

के लिए आई तो सबसे पहली बात तो यह हुई कि उस हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए महिला डॉक्टर नहीं थी। उस महिला को सिर्फ ब्लड बैंक की व्यवस्था न होने के कारण वहां पर एडमिट नहीं किया गया। उसके पश्चात् उस महिला को सिरसा रैफर किया गया। सिरसा पहुंचते–पहुंचते उस महिला की हालत बहुत सीरियस हो चुकी थी जिसके कारण उसे सिरसा से हिसार रैफर किया गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि शेरगढ़ गांव में 40 एकड़ जगह हमारे पास है अगर सरकार वहां पर हॉस्पिटल बनवाने की कार्य योजना तैयार करवा दे तो हम वह पंचायती जमीन को तुरन्त स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा सरकार को हैंड ओवर कर देंगे इसलिए मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि वहां पर एक मेडीकल कॉलेज जल्दी से जल्दी बनवाया जाये। सर, ऐसे ही मैं चौटाला गांव के हॉस्पिटल के बारे में कहना चाहूंगी। वहां पर कोई डॉक्टर्ज नहीं है। मुझे चौटाला गांव के हॉस्पिटल में स्टॉफ की नियुक्ति के लिए कहते हुए लगातार साढ़े तीन वर्ष हो चुके हैं। मेरा अपना यह मानना है कि अगर इतनी बार और इतने लम्बे समय तक भगवान को भी कहा जाये तो वे भी इंसान की बात मान लेते हैं लेकिन मेरे इतना कहने के बावजूद भी चौटाला गांव के सरकारी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है। इस प्रकार से यह एक पूरी तरह से सोई हुई सरकार है। (विघ्न) यह हॉस्पिटल चौधरी देवी लाल जी की बनाई हुई धरोहर है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब ने उसका रखरखाव किया। 10 साल कांग्रेस के शासनकाल के दौरान इस हॉस्पिटल में कभी डॉक्लर्ज की नियुक्ति नहीं की गई। इसी प्रकार से साढ़े तीन साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन अभी तक भी वहां पर एक भी डॉक्टर नहीं है। मेरी यही रिकवैस्ट है कि सरकार वहां पर दूसरे डॉक्टर्ज चाहे भेजे या न भेजे लेकिन वहां पर महिलाओं के लिए तो डॉक्टर्स की नियुक्ति अवश्य की जानी चाहिए। वहां की महिलायें इलाज के लिए बठिण्डा जाती हैं। वर्तमान सरकार में बाल विकास मंत्रालय एक महिला के पास है। मेरा महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से निवेदन है कि आंगनवाड़ी केन्दों पर जो भोजन बनता है अगर माननीय मंत्री जी वहां पर मौके पर जाकर देखें तो ये पायेंगी कि वहां पर कितना गंदा भोजन बनाया जाता है। उस भोजन में कीड़े निकलते हैं जिससे आये दिन बच्चे बिमार होते हैं। मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह् जो कमल का निशान है इसको महिलायें ही ऊपर

लेकर आई थी और महिलायें ही इसको नीचे गिरायेंगी। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश बरवा (लोहारू) : स्पीकर सर, मेरे हल्के लोहारू का सबसे ज्वलंत मुददा पानी है। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी पांच बार हल्का लोहारू में जाकर आये हैं। मेरे लोहारू हल्के के जिन माइनर्स की टेल पर अभी तक पानी नहीं पहुंचा है मैं उन माईनर्स का नाम आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। ईस्सरवाल सब–डिस्ट्रीब्यूट्री, ईस्सरवाल डिस्ट्रीब्यूटरी, ढ़ाणी भाकरा माइनर, भ्राहलू माइनर, मण्डौली खुर्द माइनर, नक्कीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी, सलेमपुर माइनर, सिधनवा माइनर, गुरेरा माइनर, सिधनवा सब–माइनर, कासनी कलां माइनर, तलवानी सब–माइनर, सूरपुरा खुर्द माइनर और गोकुलपुरा माइनर – ये सभी वे माइनर्स हैं जिनकी टेल पर अभी तक पानी नहीं पहुंचा है जबकि सरकार द्वारा सभी टेल्ज़ पर पानी पहुंचाने के बहुत से दावे किये जाते हैं। सरकार द्वारा ये दावे बार–बार किये जाते हैं कि सभी टेल्ज़ तक पानी पहुंचा दिया गया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे हल्के लोहारू में एक जनसभा की थी उस जनसभा में उन्होंने ढिगावा बाई–पास की घोषणा की थी लेकिन ढिगावा बाई–पास का अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से नम्र निवेदन है कि ढिगावा बाई–पास का काम जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाये। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सिवानी ब्लॉक को हिसार में मिलाने की घोषणा भी की गई थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा पर भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यहां तक कि किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। ओलावृष्टि के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया गया है कि वे ओलावृष्टि से तबाह हुई फसल की गिरदावरी दोबारा से करवायेंगे। एक बात मैं और यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहल को उप–मण्डल का दर्जा देने की भी घोषणा की थी लेकिन इसके ऊपर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरे लोहारू विधान सभा में खेतों में ढ़ीले तारों को कसने के लिए मैंने क्वैश्चन भी लगाया था। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि मेरे लोहारू हल्के के किसानों के खेतों में जो ढ़ीले तार हैं उन सभी को जल्दी से जल्दी कसवाया जायेगा लेकिन इस मामले में भी विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ढ़ीले तारों की वजह से वहां पर

आये दिन किसानों की मौतें हो रही हैं इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिकवैस्ट है कि मेरे लोहारू हल्के में खेतों की ढ़ीली तारों को जल्दी से जल्दी कसवाया जाये ताकि प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। इसी प्रकार से मेरे सिवानी ब्लॉक का रबी की फसल का वर्ष 2017 का मुआवजा आया हुआ है वह 5 एकड़ की सीलिंग बांध कर दिया जा रहा है जबकि मुआवजा पूरे रकबे का आया हुआ है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मुआवजा पूरे रकबे का दिया जाये। इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र के 5 गांवों वीतवान, ढाणी, भाकरा तथा पातवान इत्यादि का रबी की फसल खराब होने का वर्ष 2015 का मुआवजा है वह आज तक नहीं दिया गया है इसलिए वह भी जल्दी से जल्दी जारी किया जाये। इसी प्रकार से मेरी मांग है कि जो लोहारू का रोडवेज डिपो है उसको दादरी की बजाय भिवानी में शामिल किया जाये। मैंने पहले भी निवेदन किया था और अब फिर यह निवेदन करता हूं कि लोहारू से हिसार और बहल से हिसार रोडवेज की नई बस लगाई जायें क्योंकि वहां पर रोजाना बहुत लोग सफर करते हैं। इसी प्रकार से कुड़ल गांव में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कॉलेज की कक्षाएं शुरू करवाने की बात कही थी लेकिन इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है इसलिए मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर जल्दी से जल्दी कॉलेज की कक्षाएं शुरू की जायें। इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि रूपाना गांव जो कि सिवानी ब्लॉक में पड़ता है उसके हाई स्कूल को 10+2 में अपग्रेड किया जाये। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा सरसों की पैदावार लोहारू और बहल में होती है लेकिन वहां पर कोई खरीद सैन्टर नहीं है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पर सरसों की खरीद के लिए एक खरीद सैन्टर बनाया जाये ताकि लोगों को अपनी सरसों को बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो पशु बीमा बंद हो चुका है उसको दोबारा से चालू किया जाये ताकि किसानों को कोई नुकसान न हो। इसी प्रकार से किसानों को ड्रिप सिंचाई योजना के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मैंने जो मांगें सदन में रखी हैं उन पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाये। इसके साथ ही साथ मंत्री जी हमेशा कुछ कविताएं सुनाते हैं इसलिए मैं भी कुछ लाइनें सुनना चाहूंगाः–

असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो,

कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो,

जब तक सफलता हासिल ना हो, दिन रात चैन का त्याग करो तुम,

संघर्षों के मैदानों से मत भागो तुम,

ऊंची लहरों से जो डरते हैं उनकी नैया पार नहीं होती,

कुछ किये बिना जय–जयकार नहीं होती,

कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार को काम करना ताकि जनता का कुछ भला हो सके। सरकार के पास सिर्फ एक साल का समय बचा है इसलिए इनको कुछ काम करके दिखाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथी श्री ओम प्रकाश बरवा जी बहुत विद्वान विधायक हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं क्योंकि ये बरवा गांव के हैं और मैं कैरू गांव का हूं। मैं माननीय साथी से पूछना चाहता हूं कि क्या कई सालों के बाद अब पाजू माइनर में पानी आया है या नहीं आया है?

श्री ओम प्रकाश बरवाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अधिकारिक तौर पर टेल पर कितना पानी होना चाहिए? आपने ट्यूबवैल चलवा कर टेल पर पानी तो दिखा दिया लेकिन आप यह भी बतायें कि टेल पर कितना पानी होना चाहिए?

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी से कहना चाहूंगा कि ये अपनी भूमिका में हैं और हम अपनी भूमिका में है। मैं इन पर 100 फीसदी विश्वास करके यह पूछना चाहता हूं कि इनको कितने सालों बात पाजू माइनर में पानी दिखाई दिया है?

श्रीमती शकुन्तला खटक (कलानौर) (अ.जा.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं। वित्त मंत्री जी जब अपना छोटा सा बैग विधान सभा में लेकर आये तो उस बैग से

ही मुझे अंदाजा लग गया था कि इस बजट में कुछ नहीं मिलेगा और जब बजट प्रस्तुत किया तो पता लग गया कि इस बजट में वाकई किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं मिला। वित्त मंत्री जी ने कहा कि मुझे लगातार चौथा बजट प्रस्तुत करने की सौगात मिली और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह पूछती हूं कि वित्त मंत्री जी ने लगातार 4 बजटों में हरियाणा की जनता को क्या दिया? हरियाणा की जनता को इन सभी बजटों में कुछ नहीं मिला है। बजट बुक में किसान, मजदूर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, युवा, महिला, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग, कर्मचारी, प्रधानमंत्री जन–धन योजना तथा व्यापारी किसी के लिए भी कुछ नहीं दिया गया है।

स्पीकर सर, किसान रोड पर आ गये हैं । किसानों को उनकी फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं । खेती के लिए बिजली पानी नहीं है । पहले किसान डीजल के टयूबवैल से काम चला ले लेते थे लेकिन अब डीजल के रेट भी रोजाना बढ़ रहे हैं । अब डीजल का रेट 64 रूपये प्रति लिटर हो गया है और सरकार कह रही है कि हम वर्ष 2022 में किसान की इन्कम दोगुनी कर देंगे । स्पीकर सर, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार–बार नहीं । इसलिए वर्ष 2022 को तो भूल जाईये। स्पीकर सर, मजदूरों की अगर हम बात करें तो आज मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है । वह सारा दिन चौंक पर बैठ कर चले जाते हैं लेकिन उनको मजदूरी नहीं मिलती । हुड्डा साहब, के समय में चौंक पर कोई मजदूर नहीं मिलता था । स्पीकर सर, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आज स्कूलों का बहुत बुरा हाल हो रहा है । आज स्कूलों में टीचर्ज नहीं हैं । अतः शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह कहावतों को छोड़कर स्कूलों की तरफ ध्यान दें क्योंकि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं । अगर आप स्कूलों की तरफ ध्यान देंगे तो गरीबों के बच्चों का भला हो जाएगा । स्पीकर सर, अगर हम अस्पतालों की बात करें तो आज अस्पतालों का भी बहुत बुरा हाल है । अस्पतालों में आज न डॉक्टर्ज हैं और न दवाइयां हैं । मंत्री जी आपने रोहतक में ट्रामा सैंटर चालू किया है जिसमें ज्यादातर एक्सीडैंटल केसिज जाते हैं । जिसमें सी.टी.स्कैन मशीन की जरूरत होती है। एम.आर.आई. मशीन की नहीं । लेकिन वहां पर सी.टी.स्कैन मशीन नहीं है । जिसके लिए मरीज को एक किलोमीटर दूर ट्रॉली पर सी.टी.स्कैन करवाने जाना पड़ता है जोकि बहुत दुर्भाग्य की बात है । मैं विज साहब, को कहना चाहूंगी कि अखबारों में गब्बर शेर, बब्बर शेर लिखवाने से काम नहीं चलेगा । अस्पतालों में

डॉक्टर्ज और दवाइयां देने से काम चलेगा । उनमें सुविधाएं देने से काम चलेगा । स्पीकर सर, अगर हम नहरों की बात करें तो सरकार जो टेलों पर पानी पहुंचाने की बात करती है । मैं अपने हल्के की बात करती हूं मेरे हल्के के लगभग 10 गांव टेल पर हैं । लेकिन जब से बी.जे.पी. की सरकार आई है तब से किसी टेल पर पानी नहीं गया है । हरियाणा में पानी तो है ही नहीं । हरियाणा में लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिलता तो फिर टेलों पर कहां जाएगा । सरकार साफ झूठ बोल रही है । अगर यकीन नहीं आता तो मंत्री जी आप मेरे साथ चलें मैं आपको दिखा सकती हूं कि टेलों पर पानी नहीं गया है । बी.जे.पी की सरकार ने नहरों के पानी को एक सप्ताह से घटाकर तीन दिन कर दिया है यानी अब केवल तीन दिन ही पानी किसानों को मिलता है। स्पीकर सर, अगर युवाओं की बात करें तो आज के दिन सभी युवा रोड़ों पर घूम रहे हैं । आज युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है और न ही कोई बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है जबकि बी.जे.पी. सरकार को लाने में युवाओं का अहम रोल है । आज युवा वर्ष 2019 का इन्तजार कर रहे हैं कि कब इलैक्शन आए और हम बी.जे.पी. की सरकार को भगायें । आपने देखा होगा कि युवा हुंकार रैली में सारी कुर्सियां खाली थी । इससे ही बी.जे.पी की सरकार को समझ जाना चाहिए । स्पीकर सर, अगर हम महिलाओं की बात करें तो आज जब महिलाएं अपना हक मांगती हैं तो सरकार उन पर लाठी चार्ज करवाती है । पानी की बौछारें करवाती है। इस सरकार में महिलाओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं है । इसलिए बी.जे.पी. सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ,' के नारे को बन्द कर देना चाहिए । जब महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं । रोजाना बलात्कार हो रहे हैं तो इस नारे का कोई महत्व नहीं है । स्पीकर सर, अगर मैं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की बात करूं तो उनके लिए वित मंत्री जी ने अपने बजट में कोई नई योजना नहीं दी है । इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि बी.जे.पी. की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में एस.सी.–ए. के लोगों को आरक्षण देने की बात की है । इसलिए जो लोग अपने हक के लिए दो साल से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनको सरकार आरक्षण दे कर उनको भूख हड़ताल से उठाने का काम करें । बेदी साहब, आज आपकी वह जुबान कहां गई ? वह ज्यौं के त्यौं हड़ताल पर बैठे हुए हैं ।

श्री जयवीर बाल्मीकीः स्पीकर सर, मैं भी इस मुद्दे पर माननीय सदस्या शकुंतला जी का समर्थन करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जयवीर जी, मैं आपको भी बोलने का समय दूंगा। अभी आप बैठिए और शकुंतला जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें। (शोर एवं व्यवधान)

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बैदी) : अध्यक्ष महोदय, शकुंतला जी ने मेरा नाम लेकर कुछ बात कही है इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं। अतः मुझे आपके माध्यम से उनकी बात का जवाब देना जरूरी हो गया है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से पूछना चाहूंगा कि जींद में अनुसूचित जाति के लोग किस बात के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि जींद जिले में अनुसूचित जाति के 'ए' कैटेगरी के लोग भूख हड़ताल करते हुए अपनी उन मांगों को पूरा कराने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में की थी अर्थात इस जाति का जो वर्गीकरण समाप्त करने का काम किया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस वर्गीकरण को फिर से बनाने का वायदा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी को इस वर्गीकरण को फिर से बनवाने में सहयोग करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदीःभारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषण पत्र में अनुसूचित जाति 'ए' कैटेगरी के लोगों के लिए जो वायदे किए थे, वह हमें अच्छी तरह से याद हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अनुसूचित जाति के 'ए' कैटेगरी के अधिकार खत्म करने वाली आपकी कांग्रेस पार्टी ही थी। (शोर एवं व्यवधान) आपको इस बात को हुड्डा साहब से पूछना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बेदी जी, आप मंत्री हैं आपको चेयर को एड्रैस करके बात करनी चाहिए। आपको सीधी किसी सदस्य से बात नहीं करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) मंत्री का मतलब यह नहीं है कि आप सदन की सभी मर्यादाओं से उपर हो गए। मंत्री को सदन की मर्यादाओं के हिसाब से बात करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, हमने अगर 'ए' ब्लॉक का नुकसान किया था तो हमारी पार्टी ने उस नुकसान को भुगता भी तो है। आज हम विपक्ष में बैठे

हैं। अगर हमारे समय में 'ए' ब्लॉक टूटा था तो आज हम विपक्ष में बैठे हैं और उसका नुकसान भुगत रहे हैं।

श्री अध्यक्षः शकुंतला जी, आपका समय अब समाप्त होता है अतः आप जो अन्य डिमांड रखना चाहती हैं उनको हमारे पास भिजवा दें, निश्चित रूप से उनको सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जायेगा।

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, ठीक है मैं विभिन्न विषयों पर आधारित लिखित दस्तावेज आपको दे देती हूं, आप इनको प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनवा देना ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

***श्रीमती शकुंतला खटकः**स्पीकर सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साथ सबका लिया लेकिन विकास केवल मंत्री और आर.एस.एस. वालों का किया है। हरियाणा की जनता के विकास की जगह उसकी रे–रे माटी कर दी गई है। स्पीकर सर, हरियाणा के सारे कर्मचारी रोड्ज पर हड़ताल पर बैठे हैं। जब विज साहब विपक्ष में होते थे तो कहा करते थे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आयेगी तो हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन मान देंगे। उन वादों का क्या हुआ? स्पीकर सर, केवल पानी की टंकियों को चैक करने से ही काम नहीं चलेगा। कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन दोगे तभी काम चलेगा। स्पीकर सर, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते तो बहुत खुले पर आज तक 15–15 लाख रूपये किसी के खाते में नहीं आये। पता नहीं 15–15 लाख रूपये कौन ले गया। स्पीकर सर, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यापारियों की बुरी हालत कर दी है। एक बार दुकान पर एक भिखारी भीख मांगने आया तो दुकानदार ने भिखारी को देखकर पुराना अखबार पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि उसके गल्ले में एक सिक्का भी नहीं था। भिखारी इंतजार करके चल दिया, तब व्यापारी ने अखबार मुंह के आगे से हटाया और कहने लगा कि जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो नोटों से गल्ले भरे रहते थे और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है एक सिक्का भी हमारे गल्ले में नहीं है। आज व्यापारियों की यह हालत हो गई है। स्पीकर सर, मेरे हल्के की भी कुछ मांगे हैं। मैं

*** चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

पहले भी इनके बारे में सदन में आवाज उठाती रही हूँ लेकिन सरकार द्वारा आज तक भी इन डिमांड को पूरा नहीं किया गया है। कर्मचारियों की भी कुछ मांगे हैं। उन्होंने मुझे अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दे रखा है, मेरा निवेदन है कि इनको मांगों को भी पूरा करने का काम किया जाना चाहिए। स्पीकर सर, आज किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलने का टोटा हो रहा है, मजदूरों को मजदूरी का टोटा है, स्कूलों में टीचर्ज का टोटा है, नहरों में पानी का टोटा है, युवाओं को रोजगार का टोटा है, महिलाओं को सम्मान का टोटा है, व्यापारियों को ग्राहकों का टोटा है, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को अपनी वैलफेयर के लिए बनाई गई योजनाओं का टोटा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि यह टोटा कब पूरा होगा। स्पीकर सर, मैंने सरकार के असली विकास के चेहरे को दिखाने का काम किया है। स्पीकर सर, पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार ने कलानौर को सब तहसील का दर्जा दिया था, मेरे अनुरोध है कि यहां की जनता की डिमांड पर इसको सब डिवीजन का दर्जा दिया जाये, दस दस करोड रूपये गांवों के विकास के लिए पंचायतों को दिए जायें, नगर पालिका, कलानौर को 25 करोड रूपए दिए जायें, रोहतक नगर निगम में कलानौर हल्के में पांच गांव और पैसठ कालोनियां आती हैं उनके लिए 50 करोड रूपये दिए जायें, खोखराकोट के बारे में मैं विधान सभा में दो बार प्रश्न लगा चुकी हूँ पर आज तक यहां पर विकास नहीं हुआ है, निवेदन है कि यहां पर तुरन्त विकास कार्य शुरू करवाया जाये, कलानौर के लाइन पार एरिया के लिए अंडर पास बनाया जाये ताकि बाहरी कालोनियां को शहर से जोड़ा जाये, कलानौर और आउटर कालोनियों की बिजली की तारों को घरों पर से हटाया जाये, कलानौर के किसानों के खेत जो टेल पर हैं, उनमें पानी पहुंचाने का कार्य किया जाये। राजीव गांधी आवास योजना के तहत जो पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार में पैसा मंजूर हुआ था, उसके तहत अभी तक मकान की किस्त बाकी है, वह पूरी किस्त तुरन्त संबंधित परिवारों का उपलब्ध करवाई जाये। पूरे कलानौर हल्के के अन्दर दो साल से जो बिजली, पानी, सीवरेज की समस्या आ रही है उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाये। किसानों को बिजाई–बुआई के समय कम से कम 18–20 घंटे बिजली प्रदान की जाये। पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के कलानौर में सामान्य हस्पताल बनाया था लेकिन अब इसमें मशीनों, उपकरणों और डाक्टरों व स्टॉफ की कमी है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाये और इसमें नई बिल्डिंग, डिजिटल एक्स रे मशीन व अल्ट्रासाउंड मशीन

जल्द से जल्द लगाई जाये। इसके अतिरिक्त नियमित व अनुबंधित अनुदेशकों की समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, निर्माण के कार्य में लगे मजदूरों समस्याओं की तरफ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। स्पीकर सर, मेरा निवेदन है कि मेरी इन डिमांड्स को जल्द से जल्द पूरा करते हुए मेरे हल्के की जनता की समस्याओं को दूर करें। धन्यवाद।

सरदार बख्शीश सिंह विर्क (असन्ध) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री कैप्टन साहब ने जो बजट पेश किया है मैं उसकी सराहना करता हूँ और साथ ही अपने हल्के की दो–चार बातें रखना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में नगरपालिका के अधीन जो अन–एप्रूव्ड कालोनियां हैं और जहां पर लगभग 50–60 परसेंट मकान बन भी चुके हैं, उन अन–एप्रूव्ड कालोनियों को एप्रूव्ड किया जाये। मेरे क्षेत्र के सालवन में मन्दिर के पास ड्रेन पर एक पुल है । वह एक तीर्थ स्थान भी है । उस ड्रेन के पुल के नीचे पाइप्स दबे हुए हैं । जब पीछे से इसमें गन्दा पानी आता है और बरसात होती है तो ये पाइप्स जाम हो जाते हैं । इस वजह से वहां पर किसानों को फसलों का भी बहुत नुकसान होता है । अतः मेरा कहना है इस ड्रेन के पुल को दोबारा बनाया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के मुनक में लड़कियों का एक कॉलेज बनाया जाए । वहां की लड़कियों को शिक्षा प्राप्ति के लिए 20–25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है । मेरा कहना है कि मुनक के नजदीक जहां भी स्कूल के नॉर्म्स पूरे होते हों वे वहां पर लड़कियों के लिए एक कॉलेज का निर्माण करें । इसके साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जुण्डला को सब–तहसील का दर्जा दिया जाए । इसके न होने की वजह से हमारे किसानों को बहुत दूर के शहर करनाल और अन्य शहरों में जाना पड़ता है । इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र की मण्डियों/ परचेज सैन्टर जैसे मूणक और सालवन की न तो चारदीवारी की गई है और न ही उनमें गेट लगाए गए हैं । अतः माननीय मंत्री जी इनमें गेट लगवाने, चारदीवारी करवाने और अच्छे प्लेटफॉर्म का निमार्ण करवाने का काम करें । इसके अतिरिक्त सालवन के पास बोंद गांव में एक खेल स्टेडियम बनवाया जाना है । इसके साथ ही सदन में पानी की बात चली है । माननीय सदस्या किरण जी ने पानी को लेकर एक बहुत अच्छी बात कही है । मेरा कहना है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है । अतः आदरणीय किरण जी को

पंजाब से हरियाणा में पानी लाने के लिए पंजाब सरकार से बात करनी चाहिए । इसके साथ–साथ हम सभी को भी हरियाणा में पंजाब से पानी लाने के लिए जोर लगाना चाहिए । अगर ऐसा हुआ तो हरियाणा में पानी ही पानी हो जाएगा और पानी की कोई कमी नहीं रहेगी । अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्रीमती बिमला चौधरी (पटौदी) (अ.जा.) : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं । मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया है । यह बजट किसान के हक का है । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हमने अपने क्षेत्र के 6 स्कूल्स को 10+2 स्तर पर अपग्रेड के लिए कहा था । इनमें से अभी तक केवल 2 स्कूल्स को ही अपग्रेड किया गया है । अभी भी नानू, हेली मण्डी, पटौदी और बलेवा के 4 स्कूल्स को 10+2 तक अपग्रेड किया जाना बाकी है । अभी माननीय कृषि मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं । मेरे क्षेत्र में एक अनाज मण्डी है । मेरा उनसे अनुरोध है कि उसमें शैड बनाया जाना बहुत जरूरी है । आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती सीमा त्रिखा (बड़खल) : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं । हमारे प्रदेश के संवेदनशील और विवेकशील वित्त मंत्री जी ने आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत ही बढ़िया बजट पेश किया है । यह बजट हमारी सरकार के मूल मन्त्र, अन्त्योदय और एकात्म मानववाद को साथ लेता हुए चलता है । यह बजट एक तरफ हमारी बेटियों के स्वावलम्बन को, गृहणियों की रसोई को, बुजुर्गों की पैंशन को और गरीब की 10 रूपये में मिलने वाली भोजन की थाली को पूरा करता हुआ चलता है । इस बजट ने हमारे राज्य के हर वर्ग को छूआ है । इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय वित्त मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं । मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र बड़खल में घोषणाएं करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समूचे मंत्रिमण्डल को धन्यवाद देती हूं । इन घोषणाओं के माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता को विकास के नये रास्ते मिले हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र बड़खल को सब–डिवीजन घोषित किया गया है । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र बड़खल के कई स्कूल्स को अपग्रेड किया है । हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने अपने क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी की मांग रखी थी । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस

मांग को पूरा करते हुए दुधोला गांव में एक विश्वकर्मा स्किल डिवैल्पमैंट यूनिवर्सिटी बनाई है । मैं एक पार्षद भी रही हूं, इसलिए मुझे पता है कि पहले तो सड़कों के निर्माण के लिए हम पैसा मांगते थे । उस समय हमारी बात कोई नहीं सुनता था परंतु अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से हमारे क्षेत्र की एक सड़क के निर्माण का काम चल रहा है । उस सड़क की लागत लगभग 110 करोड रूपये आएगी । हमारे फरीदाबाद को एशिया का मैनचैस्टर कहा जाता था । प्रदेश में कई सरकारें आई और चली गई लेकिन फरीदाबाद में पासपोर्ट बनाने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाई । हमने फरीदाबाद की रैली में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज जी के सामने यह मांग रखी । माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय केन्द्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने हमारी इस मांग को स्वीकार कर लिया । इसके बाद हमारे क्षेत्र में एक पासपोर्ट ऑफिस की सुविधा भी दी गई । इसके अलावा हमारे क्षेत्र में बहुत–से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट्स अप्रूव किये गये हैं । हमारे क्षेत्र में राजा नाहर सिंह स्टेडियम को सैंग्शन किया गया है, सीवरेज के लिए 100 करोड रूपये सैंग्शन किये गये और एक 66 के.वी.ए. सब–स्टेशन मंजूर किया गया है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग को पूरा किया है । उन्होंने सैनिक कॉलोनी और ग्रीन फील्ड को नगर निगम के अंतर्गत लाने की घोषणा की है । इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं । इसके अलावा मैं अपने क्षेत्र की दो–तीन समस्याओं का जिक्र करना चाहूंगी । इनको मेरे क्षेत्र की डिमांड के रूप में कंसीडर किया जाए । इस समय सदन में टूरिजम मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं । बड़खल झील और सूरजकुण्ड विश्व के मानचित्र पर चमक रहे हैं । ये दोनों धरोहर हमारे क्षेत्र की पहचान है । अतः मेरी विनती है कि बड़खल झील और सूरजकुण्ड को टूरिजम कॉरीडोर घोषित किया जाए । इसके अलावा मेरा अनुरोध है कि बड़खल से सूरजकुण्ड तक मैट्रो से कनैक्टिविटी की जाए । इससे इन दोनों शहरों में कनैक्टिविटी बढ़ेगी और सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा । गुरूग्राम भी हमारे क्षेत्र के साथ लगता है । गुरूग्राम और फरीदाबाद दोनों एकसम चलते हैं । फरीदाबाद के बहुत–से बच्चे मेडीकल फैसिलिटीज और नौकरियों के लिए गुरूग्राम जाते हैं । इन दोनों शहरों में काफी आवाजाही है । अतः मेरा अनुरोध है कि इन दोनों शहरों के लिए भी मैट्रो की कनैक्टीविटी दी जाए । इससे इन दोनों शहरों को काफी लाभ होगा । अंत में मैं कहना चाहूंगी कि सरकार का धर्म होता है कि

वह प्रदेश की धरोहर को सम्पूर्ण तरीके से सुरक्षित रखे । इसके लिए मेरा एक सुझाव है । सरकार को एक बोर्ड का गठन करना चाहिए और ड्रोन्स की सहायता से पहाड़ों, माइन्स और फॉरेस्ट एरिया की हर 3 महीने की रिकॉर्डिंग की जाए । इससे पता चल जाएगा कि कहां क्या गलत काम हो रहा है । यह सरकार प्रदेश हित के कार्यों के लिए बधाई की पात्र है । आज इस सदन में वे माननीय सदस्य भी बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत लम्बे समय तक प्रदेश पर राज किया है । वे माननीय सदस्य आज भी प्रदेश में पानी की कमी की बात करते हैं । इस बात से यह पता चलता है कि उन्होंने 47 सालों में प्रदेश के लिए कैसे काम किये हैं । धन्यवाद ।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास (रिवाड़ी) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मुझे इसका बहुत हर्ष और गर्व है कि हमारे प्रिय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने एक कल्याणकारी और जनता की नब्ज और प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए एक सम्पूर्ण बजट पेश किया है । इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । कैप्टन अभिमन्यु जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है । इस काम को अच्छे ढंग से करने का एक कारण यह भी है कि इनकी रगों में चौधरी मित्रसेन जी का खून दौड़ रहा है । एक सैनिक, एक वित्त मंत्री, एक फाइनैंस एक्सपर्ट और एक युवा नेता से हम ऐसी ही आशा करते हैं । इनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पूरा सहयोग प्राप्त है । हमारी सरकार इस सोच से चल रही है कि हरियाणा प्रदेश को किस तरह से सम्पूर्ण विकास की तरफ बढ़ाया जा सकता है । आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सभी विधायक जनता द्वारा चुनकर इस सदन में आये हैं । हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं । जब मैं देखता हूं कि हम सदन में हमारे सभी सदस्य किन चीजों को प्रफ्रैंस दे रहे हैं और किस तरह से समय को नष्ट कर रहे हैं तो मुझे बहुत दुःख होता है । सदन में जिस तरह से सदस्य एक–दूसरे पर छींटाकशी करते हैं और सदन में एक बहुत ही निम्न स्तर का वातावरण पैदा होता है तो इस बातों को देखकर प्रदेश की जनता को बड़ा दुख होता है। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश की जनता को आस बंधी है कि अब हमारा प्रदेश तरक्की करेगा। अध्यक्ष महोदय, वैसे ही आपके जैसे अध्यक्ष के होते हुए ऐसी एक परम्परा बननी चाहिए कि पूरे भारत में हरियाणा विधान सभा की शालीनता का एक आदर्श प्रस्तुत हो सके। हरियाणा प्रदेश एक गौरवपूर्ण राज्य है। माननीय सदस्यों का आचरण अच्छा होना चाहिए।

16:00 बजे

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 30 मिनट के लिए और बढा दिया जाये ?

आवाजें: ठीक है, जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, हाउस का समय 30 मिनट के लिए बढाया जाता है।

वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवासः अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल ने एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव नशे के बारे में पेश किया था। क्या हम भी नशे में हैं ? (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्यों का आचरण नशा करने वालों की तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह का आचरण विपक्ष के माननीय सदस्य कर रहे हैं वह आचरण नशे का है। इसलिए माननीय सदस्यों का आचरण नशे का नहीं होना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की जनता विपक्ष के माननीय सदस्यों का आचरण देख रही है। विपक्ष के माननीय सदस्य जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। विपक्ष के माननीय सदस्य जो आचरण कर रहे हैं इस आचरण को प्रदेश की जनता देख रही है और प्रदेश की जनता इस आचरण के परिणाम विपक्ष के माननीय सदस्यों को देगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों को सुखद, प्यार और मोहब्बत का वातावरण तैयार करना चाहिए। इसलिए माननीय सदस्य अपनी–अपनी भूमिका में ठीक रहकर ही जनता की सेवा करेंगे तभी विधान सभा की मार्यादा बनी रह पाएगी। इसके अतिरिक्त कानून, व्यवस्था और अनुशासन की बात की जाती है अगर कानून व्यवस्था को बनाने वाले ही व्यवस्था के प्रति ठीक आचरण नहीं करेंगे तो कानून और व्यवस्था ठीक नहीं बनी रह सकती है। मैं माननीय सदस्यों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अगर किसी माननीय सदस्य को मेरी बात बुरी लगती है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन माननीय सदस्य इस बात का घर पर जाकर आत्म चिन्तन करें कि क्या हम सचमुच इन्हीं बातों के लिए ही विधायक चुनकर आते हैं। विधायक बनना कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि विधायक बनने के बाद ही माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री भी बनते हैं और फिर हम क्या काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से क्षमा याचना

करते हुए अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में पिछली सरकार के समय में 27 एकड़ जमीन मेडीकल कॉलेज बनाने के लिए स्योराज माजरा गांव में दी गयी थी परन्तु वहां पर अभी तक मेडीकल कॉलेज नहीं बनाया गया है। हमारी सरकार की योजना है कि हर जिले में मेडीकल कॉलेज खोले जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि संबंधित गांव की 27 एकड़ जमीन में मेडीकल कॉलेज बनवाने की सिफारिश की जाए। दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे हल्के में एक ब्वॉयज कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणाएं करते हैं उन घोषणाओं को पूरा भी करते हैं परन्तु इस घोषणा में थोड़ा विलम्ब हो रहा है इसलिए इस घोषणा को जल्दी पूरा करवाया जाए। इसके अतिरिक्त 2 बातें पूरे हरियाणा के महत्व की है पहली बात यह है कि हमारे प्रदेश की जमीनों में ज्यादा खाद्य, पैस्टिसाईड्स तथा रसायन डालने से बंजर होती जा रही हैं तो जमीन की मृदा को टेस्ट करने के लिए मशीनें उपल्बध करवायी जाएं और इस मशीन की कीमत लगभग 50,000–60,000/– रूपये ही होती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री और वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि आप बजट से यह छोटा सा प्रावधान कर दें तो हर गांव में यह मशीन खरीदकर लगायी जा सकती है क्योंकि अगर मृदा की जांच हो जाएगी तो संतुलित खाद्य डाली जाएगी, जिससे मृदा की ऊपजाऊ ताकत बढ़ जाएगी और उससे किसानों को लाभ होगा। दूसरी बात स्वास्थ्य से संबंधित बात है जिसमें वायरल होने से मलेरिया तथा दूसरी तरह की बीमारियां होती हैं। इसकी रोकथाम के लिए एक फोगिंग मशीन हर गांव में उपलब्ध करवा दी जाए तो लोगों को इस तरह की बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा और इस मशीन की कीमत भी ज्यादा नहीं हैं। इसलिए प्रत्येक गांव में एक–एक मशीन लगाने का प्रबन्ध किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने हमारे क्षेत्र के आग्रह पर 3 जिलों के कॉलेजों को मीरपुर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, मीरपुर के साथ जोड़ दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारा एक साहलावास गुजर गांव है जो हाईवे से बहुत दूर पड़ता है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि उस गांव के स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाए, क्योंकि उस गांव के लड़कियों को कॉलेज में आने–जाने में बहुत दिक्कत होती है। अध्यक्ष महोदय, मेरी तीसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से

गवर्नमेंट गर्ल्ज कॉलेज की बिल्डिंग बनाने के लिए 9 करोड रुपए मंजूर हो चुके हैं, लेकिन उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि उस काम को गति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से धारूहेड़ा में एक 50 बैड का हॉस्पिटल बनाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी उसका काम नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, धारूहेड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है और उसकी सड़कें सन् 1977 में बनी थी जो अभी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने उस सड़क को बनाने का काम शुरू तो किया, लेकिन उसका काम फिलहाल बंद है और मैं चाहता हूं कि उस काम को गति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं हर बार एक मांग उठाता आया हूं कि धारूहेड़ा जो कि भिवानी से लगता हुआ क्षेत्र है लेकिन उसमें राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र का गंदा पानी आता है। अध्यक्ष महोदय, एन.जी.टी. ने यह आदेश दिया है कि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र से जो गंदा पानी आता है उसे वह साफ करके भेजें। अध्यक्ष महोदय, वहां से जो साफ पानी आता है उसके लिए हमने नाला भी बना दिया है, लेकिन वह पानी आगे जाकर फैल जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और माननीय मंत्री डॉ. बनवारी लाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पानी वहां से आता है, वह हर जगह दूर–दूर तक न फैल उसके लिए सरकार कुछ प्रयास करे ? उस पानी का दोनों जगहों के बीच मात्र 2 किलोमीटर का फासला है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जो लिक्विड ट्रीटमैंट प्लांट खरखड़ा में है उस पानी को वहां ट्रांसफर करके साहिबी नदी में डाल दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि धारूहेड़ा में एक सब डिवीजन ऑफिस बी.डी.ओ. लैवल का खोला जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राव नरबीर सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने पूरे हरियाणा में बड़ी डीसैंट और फटा–फट चमकती हुई सड़कें बनाई हैं। (मेजें थप–थपाई गईं) लेकिन अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक कंजूसी कर रखी है सारे हरियाणा में तो सड़कें बना दीं, लेकिन मेरी रेवाड़ी की सड़कें अभी भी बननी बाकी है। अध्यक्ष महोदय, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने पहले कई समुदायों को भवन बनाने के लिए जमीन दे दी थी। अध्यक्ष महोदय, हमारी राजपूत सभा, अम्बेडकर समिति और ब्राह्मन महासभा इन तीनों ने मुझे ज्ञापन दिया है कि जैसे दूसरे समाजों को जिस रेट पर जमीन दी गई थी, इनको भी उसी रेट पर जमीन मुहैया कराई जाए और मुझे लगता है कि इनकी बात जायज है और सरकार को इनकी बात माननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद करते हुए इस

महान सदन का भी धन्यवाद करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में हम ऐसा आदर्श आचरण प्रस्तुत करेंगे कि हमारी हरियाणा विधान सभा पूरे भारत में सबसे अनुशासित और सबसे मिलनसार समझी जाएगी और यहां के प्रत्येक विधायक इस क्षेत्र को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हर तरह से प्रयत्न करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि हम आपस में ईर्ष्या और अपने नेताओं को खुश करने के लिए इधर–उधर की बात न करें तो ज्यादा ठीक होगा।

श्री घनश्याम सर्राफ (भिवानी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी ने गांव, किसान, व्यापारी, मजदूर और कर्मचारी इन सबका विकास निहित करते हुए एक अच्छे बजट का प्रस्ताव पेश किया है और जिससे इन सभी का सर्वांगीण और चहुंमुखी विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और इसलिए मैं अपने हल्के की डिमांड्स के बारे में कहना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिवानी में लड़कियों का बारहवीं तक स्कूल बनाने की घोषणा की थी जिसकी जमीन खरीदने के कागज माननीय राज्यपाल महोदय के पास आये हुए हैं इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाये । इसी तरह से भिवानी में जे.बी.टी. का सैंटर होता था जो चरखी दादरी जिला बनने के बाद उस में चला गया । मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि एक जे.बी.टी. सैंटर भिवानी में भी बनाया जाये । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय का नींव पत्थर रखे हुए 21 महीने का समय हो गया है उसका कार्य भी बहुत मंथर गति से चल रहा है । वहां पर अभी तक केवल चार दीवारी का कार्य ही हुआ है इसलिए उसका कार्य भी जल्द से जल्द करवाया जाये। इसी तरह से भिवानी में तिगड़ाना मोड़ से रोहतक रोड तक एन.एच. का निर्माण करवाया जाये । इसके लिए केन्द्रीय मंत्री जी से बात करनी पड़ेगी । **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया चेयर पर आसीन हुई।)** मैडम, इसी तरह से मान्हेरू और बामला में 33 के.वी.ए. के सब स्टेशन बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उनका कार्य भी जल्द से जल्द शुरू करवाया जाये । यदि मैं सौर उर्जा की बात करूं तो आज के दिन सौर उर्जा पर गरीब परिवारों को 30 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है । मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यह सब्सिडी 50 या 60 प्रतिशत तक की जाये ताकि गरीब परिवार सौर उर्जा के सयंत्र ज्यादा से ज्यादा लगवा सकें। मैडम, भिवानी शहर में पेय जल के लिए 4 इंच की 20 कि.मी. की पाइप

लाइन व 6 इंच की 10 कि.मी. की पाइप लाइन के लिए पाइप मुहैया करवाई जायें और वहां पर पब्लिक हैल्थ विभाग में अधिकारी बहुत कम हैं वह कमी भी दूर की जाये । मैडम, अब मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे भिवानी जिले में बड़ा कारखाना लगवाया जाये ताकि वहां की बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके । हमारी बहन कविता जैन जी ने भिवानी में ठोस कचरा प्रबंधन सयंत्र लगाने के लिए जून तक बनाने की घोषणा की थी लेकिन अब अगला जून आने वाला है उस पर जल्द से जल्द कार्य करवाया जाये । इसके अतिरिक्त भिवानी म्यूनिसिपल कमेटी में अधिकारियों की कमी है उसको भी पूरा किया जाये । मैडम, अब मैं खेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे हल्के के हालुवास व राजगढ़ गांवों में खेल स्टेडियम बनाने प्रस्तावित हैं उनका कार्य भी जल्द करवाया जाये । इसके साथ–साथ मैं मांग करूंगा कि भिवानी के खेल स्टेडियम के साथ 8 एकड़ जमीन लगती है उसको खेल स्टेडियम में शामिल किया जाये । माननीय खेल मंत्री जी ने प्रदेश में विकास के बहुत कार्य करवाये हैं इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं । मैडम, अब मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि भिवानी हास्पिटल में कैथलब व डायलासिज की सुविधा उपलब्ध करवाई जाये ताकि इन बीमारियों के मरीजों का इलाज तुरंत हो सके । बजट में भी इसके लिए प्रोविजन रखा गया है । इसके अतिरिक्त भिवानी के मेडिकल कालेज का उद्घाटन हुए 9 महीने का समय हो गया है उसका भी जल्दी कार्य करवाया जाये ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : मैडम, माननीय साथी ने भिवानी मेडिकल कालेज के बारे में बात की है । इस बारे में मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस मेडिकल कालेज का काम शुरू कर दिया गया है और हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही इसका निर्माण पूरा करवा दिया जायेगा ।

श्रीमती किरण चौधरी : मैडम, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि इस मेडिकल कालेज का आरिजनल नाम क्यों बदला जा रहा है ?

श्री अनिल विज : मैडम, किरण चौधरी जी की सरकार के समय में इस कालेज का कुछ भी काम नहीं हुआ था । इसका सारा काम हम सर्राफ साहब के कहने पर करवा रहे हैं । (विघ्न)

श्री घनश्याम सर्राफ : मैडम, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा यदि मेडिकल कालेज का कार्य मंत्री जी के कहने के बाद जल्दी करवाया जायेगा । अब मैं ग्रामीण

विकास की बात करना चाहूंगा कि देवसर, राजगढ़, बामला, नंदगांव, मान्हेरू व सांगा गांवों में कम्यूनिटी सैंटर स्थापित किए जायें । इसके अतिरिक्त एच.आर.डी. एफ. के तहत अतिरिक्त पैसा देकर कुछ गांवों की फिरनियां भी बनवाई जायें । इसी तरह से दीनबंधु सर छोटूराम योजना की राशि विकास कार्य हेतु जल्द से जल्द जारी करवाई जाये । मैडम, हमारी सरकार ने दो योजनाएं भिवानी क्षेत्र के लिए दी हैं जो कि विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगी । भिवानी–लौहारू रेल लाईन के लिए वित्तमंत्री जी ने बजट में प्रोविजन किया है और भिवानी की हवाई पट्टी का 2 कि.मी. विस्तार किया जा रहा है ताकि वहां पर हवाई जहाज खड़े हो सकें और उनकी रिपेयरिंग का काम हो सके । इन दोनों योजनाओं के लिए भी मैं सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । मैडम, अंत में मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और बजट का समर्थन करता हूं। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : डिप्टी स्पीकर मैडम, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं । वित्त मंत्री जी भी आ गए हैं मैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि बजट के पेज संख्या 2 पर review of past performances का जिक्र किया हुआ है । मंत्री जी ठीक समझें तो जो सुझाव मैं देने जा रहा हूं, इनको नोट कर लें क्योंकि यह हमारे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। रिव्यू में सरकार ने अपनी परफारमैंसिज को हाई लाईट किया हुआ है उसमें दूसरे भी पहलू हैं जिन पर चिंता करने की आवश्यकता है । मैं बताना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश का शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2014–15 में 17.7 प्रतिशत बजट रखा गया था जो कि 2017–18 में कम होकर 16.1 प्रतिशत हो गया । 2017–18 में शिक्षा का बजट दिल्ली का 25 प्रतिशत, झारखण्ड का 19 प्रतिशत, असम का 18.8 प्रतिशत, केरल का 16.7 प्रतिशत, बिहार का 17 प्रतिशत रखा गया था जबकि हमारे प्रदेश का शिक्षा का बजट इन सभी राज्यों से कम है । मैडम, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे विषय हैं यदि इन विषयों पर सरकार की नियत सही नहीं होगी तो कोई भी प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता । यह बड़ी चिंता की बात है और मैंने ये आंकड़े बजट के स्टेटिस्टिकल डाटा देखकर तैयार किए हैं । हमारे प्रदेश की शिशू मृत्यु दर भी राष्ट्रीय औसत से काफी खराब है जो तालिका संख्या 8 में नजर आती है । इसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का डाटा दिया हुआ है जो राष्ट्रीय औसत से खराब है । मैडम, यदि मैं कृषि की बात करूं तो हमारे देश में

औसतन 7 प्रतिशत बजट 2017 में कृषि पर खर्च हुआ है जबकि 5.2 प्रतिशत बजट इस क्षेत्र के लिए हरियाणा ने रखा था । यू.पी. ने 12 प्रतिशत, झारखण्ड ने 12 प्रतिशत, पंजाब ने 14 प्रतिशत, कर्नाटक ने 8.5 प्रतिशत बजट कृषि के लिए रखा था यानि इन राज्यों ने हरियाणा से कहीं ज्यादा बजट कृषि के लिए रखा था । इसी तरह से 2017 में सिंचाई के लिए देश का औसतन बजट 5 प्रतिशत था जबकि हरियाणा का सिंचाई का बजट 3 प्रतिशत था और 2014–15 में यह बजट 4 प्रतिशत था । 2017 का सिंचाई का बजट तेलंगाना का 17 प्रतिशत, कर्नाटक का 9 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश का 9 प्रतिशत, गुजरात का 7 प्रतिशत, असम का 5 प्रतिशत, महाराष्ट्र का 4 प्रतिशत था । इन आंकड़ों से पता चलता है कि सिंचाई का बजट भी दूसरे राज्यों के औसतन हरियाणा का बहुत कम रहा है । मैडम, यदि किसी राज्य में सिंचाई की सही व्यवस्था होगी तो वह राज्य अपने आपको आगे ले जा सकता है । (विघ्न) मैडम, मैंन ये आंकड़े बजट स्टेटिस्टिकल से ही निकाले हैं । इसी तरह से ग्रामीण विकास का 2017 का बजट औसतन 6 प्रतिशत है और हरियाणा का 5.4 प्रतिशत है । जबकि ग्रामीण विकास के लिए बिहार का 14 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश का 9 प्रतिशत, राजस्थान का 8 प्रतिशत, उड़ीसा का 8 प्रतिशत, बंगाल का 10 प्रतिशत था । ग्रामीण विकास का बजट भी हमारे प्रदेश का अन्य राज्यों के मुकाबले कम रहा है । मैडम, इसी तरह से जहां तक पुल एवं सड़कें बनाने के लिए औसतन बजट 4 प्रतिशत रहा है । 2014–15 में हरियाणा का पुल एवं सड़कें बनाने के लिए 4 प्रतिशत था जबकि 2017 में यह कम होकर 3.3 प्रतिशत रह गया । जबकि पुल एवं सड़कें बनाने के लिए 2017 में झारखंड का 10 प्रतिशत, उड़ीसा का 9 प्रतिशत, बिहार का 4.8 प्रतिशत, यू.पी. का 5.2 प्रतिशत, महाराष्ट्र का 4.7 प्रतिशत का बजट था। (विघ्न) मैडम, मैंनें सरकार के ही स्टेटिस्टिकल डाटाज में से ये आंकड़े निकाले हैं मैं कोई घर से नहीं लेकर आया। पुलिस के लिए हरियाणा के 2017–18 के बजट का 4.4 प्रतिशत खर्च किया जाना है जो कि वर्ष 2014–15 के 4.9 प्रतिशत से भी कम चला गया है वहीं पर छत्तीसगढ़ में यह 4.7 प्रतिशत है, महाराष्ट्र में 4.5 प्रतिशत, असम में 5.5 प्रतिशत खर्च किया जाता है। इसी प्रकार से एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के बजट में भी कटौती करके 1 प्रतिशत से भी कम कर दिया है जबकि आन्ध्रप्रदेश इस मद पर 8 प्रतिशत खर्च करता है, कर्नाटक 7 प्रतिशत खर्च कर रहा है, तेलंगाना 10 प्रतिशत तथा महाराष्ट्र अपने बजट का 5 प्रतिशत खर्च कर रहा है।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): उपाध्यक्ष महोदया, माननीय साथी जो आंकड़े सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी हमारे स्टेट से कोई रिलेवैंसी नहीं है। किसी भी डाटा की रिलेवैंसी उस स्टेट के एरिया और उस स्टेट में वह चीज कितनी है इस बात पर निर्भर करती है। हमारे राज्य में 80 प्रतिशत एरिया सिंचाई में कवर होता है वहीं दलाल साहब जिन राज्यों के आंकड़े दे रहे हैं वहां पर सिंचाई कितनी है? दूसरे राज्य में सिंचाई के अलग हालात हैं। मेरे राज्य में सड़क का घनत्व अलग है और उनकी सड़क का घनत्व अलग है। मेरे राज्य की प्राथमिकताएं अलग हैं और उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। हो सकता है उनको ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता हो इसलिए इन आंकड़ों की हमारे राज्य से कोई रिलेवैंसी नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि ये इस महान सदन का समय बर्बाद न करें।

उपाध्यक्ष महोदया: दलाल साहब, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री करण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर लेकर जा रहा हूं। हरियाणा में अपराध भी ज्यादा होते हैं और अपराधों को कोर्ट में सिद्ध करने की क्षमता भी हरियाणा पुलिस की कम है। प्रति एक लाख जनसंख्या पर जहां भारत में अपराध की दर 233 है और हरियाणा में और खराब है और वह 320 है। पंजाब में यह 137 है, राजस्थान में 246 है, गुजरात में 233 है, बिहार में 157 तथा उत्तर प्रदेश में 129 है। यह तालिका 10 में दिये गये आंकड़े हैं आप इनको देख लेना। आई.पी.सी. के तहत जहां भारत में कोर्ट में अपराध सिद्ध करने का प्रतिशत 46.8 है जो की कम है और हरियाणा में तो इससे भी कम 27 प्रतिशत अपराध कोर्ट में सिद्ध हो पाते हैं। इसी प्रकार से महिलाओं के खिलाफ अपराध का आंकड़ा देश में प्रति एक लाख पर 55 है जो कि हरियाणा में 78 है, हिमाचल प्रदेश में 35 है, बिहार में 27 तथा पंजाब में 38 है।

उपाध्यक्ष महोदया: दलाल साहब, आप अपनी बाकी की स्पीच लिखित में दे दें हम उसको सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनवा देंगे।

श्री करण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदया, मैं समाप्त ही कर रहा हूं। मैं एक आखिरी सुझाव आपके माध्यम से सरकार को देना चाहता हूं। उत्तर हरियाणा में जहां धान और गेहूं की खरीद एम.एस.पी. पर होती है तथा सरकार एक–एक दाना खरीदती है। सरकार का नारा है कि हरियाणा–एक, हरियाणावी–एक। वहीं दक्षिण

हरियाणा जो कि आपका इलाका भी है, नारनौल, भिवानी, महेन्द्रगढ़ से लेकर पलवल, होडल तथा मेवात तक के लोगों के साथ गलत हो रहा है। वहां पर पानी की कमी होने के कारण लोग सरसों की खेती करते हैं। वहां पर किसानों की सरसों मंडियों में पड़ी हुई है। सरसों की खरीद के लिए सरकार ने जो नीति बनाई है वह चिन्ता का विषय है। सरकार किसानों से फर्द की मांग करती है वह भी ठीक है लेकिन सरकार ने नीति बनाई है कि किसान जो कुल सरसों पैदा करेगा सरकार उसकी केवल 25 प्रतिशत सरसों खरीदेगी। उपाध्यक्ष महोदया, सरसों की खेती गरीब आदमी करता है इसलिए सरकार को दक्षिण हरियाणा में भी किसानों की सरसों एम.एस.पी. पर पूरी की पूरी खरीदनी चाहिए। दक्षिण हरियाणा के दम पर ही तो यह सरकार बनी है और दक्षिण हरियाणा के किसानों के साथ इस तरह की ज्यादती ठीक नहीं है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी सरसों की फसल को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदयाः दलाल साहब, आपका समय समाप्त हो गया है इसलिए अब आप बैठ जाइये।

श्री परमेंद्र सिंह ढुल (जुलाना): उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे साथियों ने बजट पर जो बातें कही हैं मैं उनको न दोहराते हुये अपनी दो–चार बातें बताना चाहूंगा। एफ.आर.बी.एम. एक्ट और चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से हमारा राजस्व घाटा समाप्त हो जाना चाहिए था। इसको समाप्त करने के लिए प्रयास भी किये जाने चाहिएं थे लेकिन अबकी बार भी यह राजस्व घाटा 1.20 प्रतिशत है। जब इस बात के लिए आदेश आये थे कि आपको अपना राजस्व घाटा समाप्त करना है उसके बावजूद भी समाप्त न होना चिन्ता का विषय है। इसी प्रकार से राजकोषीय घाटा इस बार 2.82 प्रतिशत है जो कि पिछले साल के बजट में 2.83 प्रतिशत था जो कि खत्म हो जाना चाहिए था। राजस्व घाटा जो पिछले साल 1.35 प्रतिशत था इस बार 1.20 प्रतिशत है जो कि 8253.51 करोड रुपये है जो कि चिन्ता का विषय है। एक चिन्ता यह है कि प्रदेश पर जो एक लाख 61 हजार करोड़ रूपये का कर्जा हुआ है वह किस प्रकार से हुआ है ? यह खबर आज के ट्रिब्यून अखबार में भी आई हुई है और सरकार के जवाब में भी यह आया है कि यह कर्जा गीता जयंती जैसे कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार पर खर्च करने से हुआ है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कर्जा इसलिए लिया जाता है कि वह पैसा इस तरह की जयंतियों पर

खर्च करके लुटाया जाए । आज प्रदेश का प्रत्येक बच्चा 64 हजार से ऊपर का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है । इससे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि इन आंकड़ों को बड़ी आसानी से छुपाया गया है । सरकार के जो अनुमान थे उसके आधार पर 20.72 प्रतिशत की दर से हमारा कर्जा वापिस होना चाहिए था। जबकि वह 23.1 प्रतिशत की दर से वापिस हुआ है यानि अब वह कर्जा 3 प्रतिशत की दर से 20 प्रतिशत के ऊपर बढ़ा है । इससे टोटल 15 प्रतिशत की कर्जा अदायगी बढ़ जाएगी । इसके साथ ही एक चिन्ता का विषय कर्मचारियों के वेतन व पैंशन का है । वर्ष 2014–15 में 43.87 प्रतिशत पैसा कर्मचारियों के वेतन अकाउंट व पैंशन अकाउंट में जा रहा था । अबकी बार वह पैसा घट कर के 37.56 प्रतिशत हो गया है। जो 6 प्रतिशत की कटौती वेतन व पैंशन अकाउंट में हुई है वह बहुत चिन्ता का विषय है । इसका मतलब हरियाणा प्रदेश में नौकरियां नहीं दी गई हैं। युवाओं को बेरोजगार रखा गया है क्योंकि अगर सरकार रोजगार देती तो वेतन व पैंशन अकाउंट के पैसे की प्रतिशत्ता बढ़नी चाहिए थी । अगर इसको 6 प्रतिशत घटाया है तो इसका मतलब है कि प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार बनाया गया है । मुझे इस बात की हैरानी है कि मनरेगा घोटाले के अन्दर जिन अधिकारियों को लोकायुक्त के द्वारा दण्डित किया गया है और उनके संबंध में सरकार को यह कहा गया है कि उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाए, सरकार उन्हीं अधिकारियों को प्राईड पोस्टिंग देने लगी है और रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा से नौकरियों पर रखने में लगी है । उपाध्यक्ष महोदया, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । इसके साथ–साथ बजट में जो कटौतियां हुई हैं उनको भी मैं गिनवाना चाहता हूं । रूरल डवैल्पमैंट का बजट वर्ष 2017–18 में 4.85 प्रतिशत था जो अब घट कर 3.76 प्रतिशत हो गया है, जोकि चिन्ता का विषय है ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : परमेन्द्र जी, आप इस फाईनैंस में कहां फंस गये हैं । आप बीबीपुर माइनर और बहबलपुर माइनर के बारे में बात कर लो । आपको जब टाईम मिलता है तब तो आप अपने हल्के की बात रखते नहीं हैं ।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): उपाध्यक्ष महोदया, इनको गलत सूचना लिख कर दे दी गई हैं।

श्री राम बिलास शर्मा : परमेन्द्र जी, ओमप्रकाश बरवा जी कितनी अच्छी बात कर रहे थे ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो वर्ष 2017–18 के बजट की ही बात कर रहा हूं । इसी में यह सारा खेल है इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदया : परमेन्द्र जी, आप जल्दी अपनी बात को खत्म कीजिए । आपके केवल तीन मिनट रह गये हैं ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, यह जो सी.ए.जी. की रिपोर्ट आई है उस संबंध में हमने पिछले बजट में भी प्रार्थना की थी कि जब हम वीक एण्ड में यहां से जाएं तो उससे अगले ही दिन यह रिपोर्ट आ जानी चाहिए । इस रिपोर्ट में ''डिस्कॉम'' का जो घोटाला है उस पर पिछले बजट के दौरान भी आवाज उठाई गई थी । ''डिस्कॉम'' का जो घोटाला है वह पिलर मीटर घोटाला है वह सामने आया हुआ है । अगर यह रिपोर्ट कल आ जाती तो हम आज ये डिस्कॉम के सारे के सारे घोटाले प्रदेश सरकार के सामने रख देते । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आगे से आप यह निर्देश दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब हम सदन में आएं तो यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट हमें दे दी जाए ताकि इस पर सार्थक रूप से बहस हो जाए । उपाध्यक्ष महोदया, इसके साथ ही मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे अपने हल्के की कुछ डिमांड्स हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा । मेरे हल्के जुलाना को उपमण्डल का दर्जा दिया जाए क्योंकि जो हमारे हल्के से छोटे हल्के हैं वह उपमण्डल बना दिये गये हैं इसलिए हमारे हल्के को भी उपमण्डल बनाया जाए । हमारे प्रदेश के अन्दर लगातार इवेन्ट्स के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है वह पैसा इवेन्ट्स पर खर्च न करके प्रदेश की डिवैल्पमैंट के ऊपर खर्च करें और जो युवा बेरोजगार बनाए जा रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए क्योंकि लाखों से अधिक रिक्तियां आज विभिन्न विभागों में पड़ी हुई हैं । नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी मांग रखी थी कि आप नौकरियों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को वेटेज दें ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी उसमें शामिल हो सकें । इसके साथ ही कृषि मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि अब फल्ड इरीगेशन सिस्टम को खत्म कीजिए क्योंकि फल्ड इरीगेशन सिस्टम हमारे प्रदेश के हित में नहीं है इसलिए सरकार को माईक्रो इरीगेशन सिस्टम पर जाना पड़ेगा जिसके लिए सरकार कलस्टर बनाकर इसका प्रचार प्रसार करे । इस बारे में वित मंत्री जी ने अपने भाषण में भी बताया है और कृषि मंत्री जी ने भी इस बारे में कृषि सम्मिट में बताया है । मेरा निवेदन है कि इस विषय पर इफैक्टिवली कोशिश की जाए ।

उपाध्यक्ष महोदया : परमेन्द्र जी, आप अपना बाकी लिखा हुआ मैटर सदन के पटल पर रख दें हम उसको प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनवा देंगे क्योंकि समय काफी हो गया ।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : ठीक है जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद । मैं अपनी बाकी लिखित स्पीच सदन के पटल पर रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है।

*** श्री परमेन्द्र सिहं ढुल :**

Construction of new village link roads

- Village Dhigana to Padana-3 km and Village Bhaironkhera to Dhigana-2 km.
- Village Nidana to Biroli via Nidani-10 km and Village Nidani to Radhana-4 km.
- Village Gatauli to Karsola-4km and Village Karsola to Jind-Rohtak Highway-2km
- Village Ramrai to Bibipur-3km and Ramrai Khera to Ikkas-Bhiwani Road bypass-2km
- Village Ramgarh to Ikkas-Bhiwani Road bypass-2km
- Village Sirsakheri to Nandagarh–Mehrada road – 1km and Sirsakheri to Lijwanakalan.
- Village Lakhmirwala to Brahkhurd -3km and Village Lakhmirwala to Manoharpur-2km and Village Kharkrangi Bhirtana.
- Village Sunderpur to Lohchab-3km and Village Radhana to Brahkhurd-3km
- Village Baganwala to Pokrikheri-3 km and Village Baganwala to Rajthal -2km
- Village Bibipur to Buana -4km and Village Brarkhera to Buradehar-2km

.....

***चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

- Village Kherabakhta to Julana via Rajgarh -5km and Village Assan to Bhirtana- 5km
- Village Karela to Malvi-4km and Village Karela to Gandhwali Khera-4km
- Village Radhana to Brahkhurd -4km and Village Ramkali to gattoli
- Village Ashrafgrah to Biroli-2km and Village Ashrafgarh to Radhana-2km
- Village Khera Bakhta to Jaijaiwanti Railway Station-3km
- Village Gosainkhera to Khemakheri-3km

- Village Ghimana to Bishanpura Railway Station-2km
- Village Jhamola to Kharainti -3km and Kilazafargarh to Devrar-3km
- Village Ponkrikheri to Bibipur-3km and Village Dashkhera to Devrar-4km
- Village Gadhwali to Buradehar and Buradehar to Kinana Railway Station.

- Village Brarkhera to Kinana Railway Station no land acquisition is required in the above mentioned roads

Construction of village Chaupal

- Construction of a chaupal for the Balmiki community at village Chabri approximately Rs 8 Lakh
- Construction of a chaupal for the muslim community of village Ramrai approximately Rs 10 Lakh
- Construction of a chaupal for the dhanak community of village Gatauli approximately Rs 10 Lakh
- Repair of general chaupal at village Ramrai, approximately Rs 10 Lakh
- Construction of dhanak community chaupal at village Lakhmirwala, approximately Rs 10 Lakh
- Renovation of Sinhmar chaupal at village Gosainkhera, approximately Rs 5 Lakh

- Construction of Chaupal at Bararkhera Rs 10 Lakh
- Construction of Saini chaupal at village Lywana kalana Rs 10 Lakh
- Construction of Buddakheria chaupal at Village Lywana kalana Rs 10 Lakh
- Repair of General chaupal at Village Siwaha, approximately Rs 5 Lakh
- Repair of Harijan Chaupal at Village Sunderpur, approximately Rs 10 Lakh
- Repair of Harijan Chaupal at Village Jaijaiwanti approximately Rs 5 Lakh
- Repair of the general chaupal at village Buana approximately Rs 10 Lakh
- Repair of Puniya panna chaupal at village Sindhvikhera approximately Rs 5 Lakh
- Construction of Chaupal at Village Bisampara

Construction and Refurbishment of Drain

- Repair and augmentation of the capacity of the Gatauli-Karela drain.
- Extension, repair and augmentation of the capacity to the Nandgarh-Sirsakheri darain.
- Construction of Karsola drain to benefit village karsola, Gatauli and Jaijaiwanti
- Construction of drain for village Lijwanakhurd
- To start abandoned drain on the bank of S.S.B and start new pump however at R.D 8100 as were prepared in 1996

Pertaining to irrigation water network

- Renovation of Rajbaha No 3 that include raising the level along both sides from 0 to 72428 burjis and overhaul from 72428 to 129000 burjis. Rs 9.47 crore announced a year ago but work yet to start

- Renovation and augmentation of Gatauli-Gadhwali-Karela drain, Rs 2.45 crore announced but the work is only half completed
- Construction of Bhaironkhera-Ramkali drain, Rs 6.45 crore announced but the work is not fully completed
- Construction of Ramkali- Behbalpur minor linkage, announcement made several times but nothing on the ground
- Karela minor, Announcement made in previous budget session but nothing of the ground
- Bibipur minor, Announcement made in previous budget session but nothing on the ground
- Linkage of Brarkhera 1L with Buana sub-minor, Announcement made in previous budget session but nothing on the ground
- Remolding of Ludana minor, Shadipur minor Julana Sub-minor Shamlo Sub-minor, Nidani minor, Chabri minor, Announcement made in previous budget session but nothing on the ground
- Remodelling of old Shamlo minor.

Repair of existing link roads

- Jind-Safidon Road (Highway)
- Jind-Rohtak Highway
- Jind-Bhiwani Highway
- Village Sunderpur to Paathri (Lakhmirwala)
- Gohana road to village Sunderpur via Brahkhurd
- Rohtak road to Buana via Brarkhera
- Rohtak road to Buana via Buradehar
- Village Kinana to Bibipur

बैठक का समय बढ़ाना

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अगर हाउस की सहमति हो तो सदन का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : ठीक है जी ।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, सदन का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

.....

वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर

श्री आनन्द सिंह दांगी (महम): उपाध्यक्ष महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने 9 तारीख को सदन में इस प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया और उसके बाद तीन दिन से बजट पर बहस हो रही है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी–अपनी तरफ से बजट पर विभिन्न प्रकार की बातें की जा रही हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से बजट की बड़ाई की जा रही है और विपक्ष की तरफ से बजट की खामियां बताई जा रही हैं। बजट में चाहे कितनी खामियां हैं लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता पक्ष की तरफ से बजट की केवल मात्र बड़ाई ही की जा रही है और विपक्ष बजट की खामियों को सरकार को बताने की बराबर कोशिश कर रहा है लेकिन सरकार की तरफ से उन बातों पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है और जब कोई सदस्य बोलता है तो बोलते हुए उस सदस्य को बीच में टोका जाता है। मैं समझताउ हूं कि यह अच्छी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, हम सब इस सदन में हरियाणा प्रदेश की जनता की आंकाक्षाओं को पूरा कराने के लिए आते हैं। घंटों–घंटों तक पूरा समय बर्बाद करके अगर यहां से उठकर चले जाते है, नेम होकर चले जाते हैं और जनता की आकांक्षाओं को यदि पूरा नहीं करा पाते हैं तो यह बहुत ही गलत बात है। उपाध्यक्ष महोदया, यह हम सबका बहुत बड़ा फर्ज और कर्त्तव्य बनता है कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ हमें यहां पर भेजा है, हम जनता की उस उम्मीद पर खरे उतरे। मैं समझता हूँ कि यह अच्छी परंपराएं नहीं हैं। विपक्ष का कोई भी सदस्य जब बोलता है चाहे वह ठीक बात ही क्यों न कह रहा हो तो भी ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से बोलना नहीं चाहिए, उनका बीच में बोलने व टोकने का कोई हिसाब ही नहीं बनता है। सदन की कार्य प्रणाली के हिसाब से भी बीच में बोलने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है लेकिन ऐसी सदस्य बीच में उठकर बोलने लग जाते हैं। सदस्य ही

नहीं सरकार के मंत्री तक बीच में उठकर अपने आप बोलने लग जाते हैं और सबसे बड़ी तो यह है कि विधायक तो फिर भी ठीक बोल लेते हैं लेकिन सरकार के दो–तीन ऐसे मंत्री हैं, जिनको सुबह ही चाबी भर दी जाती है कि तुमका बोलना ही बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उपाध्यक्ष महोदया, बजट के बारे में बहुत सी बातें सदन में कही गई हैं। मैं भी इस संबंध में यह बात कहना चाहूंगा कि अबकी बार वर्तमान सरकार द्वारा जो चौथा बजट सदन में पेश किया गया है और जो पहला बजट पेश किया था, अगर हम ध्यान से देखें तो पायेंगे कि इसमें किसी प्रकार का कोई ज्यादा अंतर नहीं है। डॉ. कादियान जी ने एक बात बजट के संबंध में सदन में कही थी कि पिछले साल डिपार्टमैंटवाइज मद में जो पैसा दिया गया था वह पैसा भी पूरा खर्च नहीं हो सका है तो इस प्रकार की अवस्था में एक प्रश्न उठता है कि आखिर यह सरकार कर क्या रही है। सत्ता पक्ष के सदस्य सदन में आकर तो बढ़ाई मारते हैं कि प्रदेश में यह हो रहा है या वह हो रहा है लेकिन जब प्रैस लॉबी में बैठते हैं तो सारे रोने लग जाते हैं कि हमारा यह काम नहीं हो रहा है या हमारा वह काम नहीं हो रहा है। आज इस सरकार के कारनामों की वजह से समाज का हर वर्ग दुखी है, चाहे वह किसान हैं, चाहे वह मजदूर है, चाहे वह व्यापारी है या चाहे वह कर्मचारी ही क्यों न हो, आज हर वर्ग इस सरकार से परेशान व दुखी है।

श्री आनंद सिंह दांगी : मैं किसान हूँ और खेती–बाड़ी का काम करता हूँ। इसलिए इस विषय पर मेरा सदन के अंदर बोलना बहुत जरूरी है। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने आसमान की तरफ देखकर कहा था कि किसान मेरा देवता है। मैं यह कहता हूँ कि किसान देवता नहीं भगवान है। भगवान पैदा करता है और लोगों का पेट पालता है। किसी मंदिर में चले जाते हैं तो मन्दिर में शिव जी, हनुमान या कृष्ण आदि देवता होते हैं। इस तरह से देवता तो बदलता रहता है लेकिन भगवान कभी नहीं बदलता है। आज पूरे देश का किसान दुखी है। किसान अपनी मांगों को लेकर जगह–जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने हकों के लिए आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार उनके ऊपर लाठियां बरसा रहीं हैं और पानी की बौछारें कर रही है। किसानों के ऊपर धारा 307 के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदया : दांगी जी, आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

श्री आनंद सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया, इस प्रकार की ज्यादती मेरे साथ प्लीज न करें क्योंकि मैं थोड़ा ही बोलूंगा ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैंने सदन में यह भी कह

दिया कि मैं किसी भी माननीय सदस्य की बात रिपीट नहीं करूँगा। मुझे अपनी बात सदन के अंदर कहने का हक और अधिकार भी है और मैं अपनी बात कह कर ही रहूँगा। लोगों ने मुझे इसलिए ही सदन के अंदर चुनकर भेजा है। मैं कोई तमाशा देखने के लिए सदन में नहीं आया हूँ। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : दांगी जी, आप 6 मिनट बोल चुके हैं। बाकी के माननीय सदस्यों को भी बोलने का समय चाहिए। इसलिए आपकी जो लिखित स्पीच है उसे सदन के पटल पर रख दें ताकि उस स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया जा सके। दांगी जी, आपको बोलने के लिए 2 मिनट का अतिरिक्त समय और दिया जा रहा है, इसलिए आप जल्दी करके अपनी स्पीच को कंक्लूड कीजिए।

श्री आनंद सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया, किसान दूसरा भगवान है। आज का भगवान हर तरह से दुखी और परेशान है। उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। केन्द्र सरकार ने कहा है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जायेगी। लेकिन किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे होगी? सरकार ने कीट नाशक दवाइयों पर जी.एस.टी., कृषि यंत्र पर जी.एस.टी., एग्रीकल्चर इम्पलीमैंट पर जी.एस.टी. और खाद पर भी जी.एस.टी. लगा दिया है। किसनों को जिस चीज की भी जरूरत होती है फसल पैदा करने के लिए उन सभी चीजों पर जी.एस.टी. और टैक्स लगा दिया है। आज किसानों की फसल मण्डियों में ठोकर खा रही हैं। सरसों, बाजरा और मक्का की फसल के लिए किसानों से फर्द मांगी जाती है, इन्क्वॉयरी की जाती है और किसानों से पूछा जाता है कि यह फसल कहां से लाए हो? उपाध्यक्ष महोदया, आज किसान के साथ मजाक हो रहा है। मैं यह कहना चाहूँगा कि किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? उपाध्यक्ष महोदया, माननीय कृषि मंत्री जी ने हिसार युनिवर्सिटी में एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें किसान और वैज्ञानिक इक्ट्ठे हुए थे।

उपाध्यक्ष महोदया : दांगी जी, आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है, इसलिए आप बैठ जायें।

श्री आनंद सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात सदन के अंदर जरूर कहूँगा और यह मेरा हक है। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : दांगी जी, बाकी माननीय सदस्यों को भी बजट पर बोलने के लिए समय देना मेरा हक है।

श्री आनंद सिंह दांगी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं जरूर बोलूंगा। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : प्रेम लता जी, आप बजट पर बोलिए।

श्रीमती प्रेम लता (उचाना कलां) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने इस बजट को नकारात्क कहा है। इसके लिए मैं एक मिसाल सदन में देना चाहती हूँ। जब गिलास में आधा पानी हो तो सकारात्मक सोच वाले कहते हैं कि आधा गिलास पानी का भरा हुआ है और नकारात्मक सोच वोले कहते हैं कि आधा गिलास खाली है। यह तो अपने–अपने सोचने की बात है कि बजट में कौन–कौन सी उपलब्धियां हम देखना चाहते हैं और कौन–कौन सी कमियां लोगों को दिखाना चाहते हैं। (विघ्न) जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है उसको पता ही नहीं चलता कि उसकी उम्र बढ़ रही है। इसी तरह से उसे विकास भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई हीं नहीं देता है। बार–बार विपक्ष के साथियों के द्वारा यह कहा जाता है कि यह सरकार का चौथा बजट है और इसमें कोई भी नयापन नहीं है। लेकिन विकास की प्रगति तब पता लगती है जब दूसरे प्रदेशों के लोग हमारे प्रदेश के विकास के बारे में जिक्र करते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, पिछले तीन वर्षों में हरियाणा की रैकिंग 14वें स्थान से छठे स्थान पर आ गई है। माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2018–19 के लिए 1,15,198.29 करोड रूपये का बजट प्रस्तुत किया है। जब वर्ष 1966 में हरियाणा बना था तब बजट कुछ ही करोड रूपये हुआ करता था। जो आज बढ़ता–बढ़ता इतना ज्यादा हो गया है। इससे हम अपने विकास की गति का अंदाजा लगा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक हम अपने देश की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस तरह से कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है उसका असर आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जैसे 'अटल पैंशन योजना' है । पहले पटवारी या सरपंच आदि मरे हुए लोगों की पैंशन खा जाते थे लेकिन आज वह पैंशन लाभार्थियों के सीधे खाते में जा रही है जिसे डी.बी.टी. बोला जाता है। उपाध्यक्ष महोदया, एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा था कि दुनिया में दो ही देश ऐसे हैं जहां सबसे कम टैक्स की वसूली होती है, एक हमारा हिन्दुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। बाकी देशों में ज्यादा से ज्यादा टैक्स की वसूली होती है, इसलिए वे देश हमारे देश के मुकाबले ज्यादा तरक्की करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जी.एस.टी. और विमुद्रीकरण के बारे में जो फैसला लिया है उसका हमारे देश को आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदा होगा और

इसका असर लोगों में जल्दी ही दिखना भी शुरू हो जायेगा। हमारे हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 196982 रूपये है और जबकि बाकी देशों में 112764 रूपये है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कम नहीं है। क्योंकि मैंने कल अखबार में पढ़ा था कि बच्चा पैदा होते ही कर्जवान बन जायेगा। उपाध्यक्ष महोदया, जहां पर तरक्की होगी वहां पर नफा और नुकसान भी होगा लेकिन बाद में हमें फायदा ज्यादा मिलेगा। इसी तरह से हरियाणा को 1 अप्रैल, 2017 से कैरोसीन मुक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत राज्य में बी.पी.एल. सूची के लाभानुभोगियों को एल.पी.जी. कनैक्शन देने पर 1600 रूपये की सब्सिडी देने का साहसिक निर्णय लिया है। उपाध्यक्ष महोदया, दिसम्बर, 2017 तक कुल 478000 नये एल.पी.जी. कनैक्शन जारी किए गये हैं, जिससे गृहणियों को खाना बनाते समय धुआं से मुक्ति मिल गई है और स्वस्थ वातावरण भी उपलब्ध हुआ है। इस प्रकार की योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच के कारण ही सफल हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र उचाना के बारे में सदन में कहना चाहती हूँ कि मैं उचाना विधान सभा क्षेत्र से पहली बार चुनकर सदन में आई हूँ। लेकिन मैंने यह महसूस किया है कि उचाना को कांग्रेस पार्टी के पिछले 10 साल के शासनकाल में विकास के नाम पर बहुत पीछे रखा गया था। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे वह हैल्थ का क्षेत्र रहा हो या फिर कोई क्षेत्र रहा है, सभी क्षेत्रों में उचाना को काफी पीछे रखा गया था। हमारे यहां 20 साल से बाईपास बंद पड़ा था, जिस पर काम शुरू हो गया है। इसी तरह से जीन्द से नरवाना फोरलेन बनना शुरू हो गया है। जब मैं जुलाना क्रॉस करती थी यदि मेरे हाथ में पानी या दूध का गिलास होता था तो गिलास में से पानी व दूध गिरना शुरू हो जाता था। क्योंकि सारी की सारी सड़कें टूटी हुई थीं। अब मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को बधाई देती हूँ कि हमारी कोई भी सड़क टूटी हुई नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, एक गांव से दूसरे गांव तक कनैक्टिविटी बहुत बढ़िया है और कोई भी सड़क कच्ची नहीं है। इसके लिए मैं हमारे माननीय मंत्री श्री राव नरबीर सिंह जी को बधाई देना चाहूंगी। इसी तरह से मेरे हल्के उचाना में हमारे शिक्षा मंत्री जी ने 2 साल पहले अलेवा गांव में कॉलेज खोलने की एनाउंसमैंट की थी और आज उस कॉलेज में कक्षाएं लगनी शुरू हो गयी हैं। इसके अतिरिक्त उचाना हल्के में 85 एकड़ जमीन में एक नयी मंडी बनायी गयी है।

उपाध्यक्ष महोदयाः प्रेम लता जी, आप अपनी डिमांड लिखकर दे दें। आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है।

श्रीमती प्रेमलताः उपाध्यक्ष महोदया, इसके अतिरिक्त एक मेडिकल कॉलेज बनाने की एनाउंसमैंट भी बजट में की गयी है। मुझे उम्मीद है कि इस साल हमारा कॉलेज भी बनना शुरू हो जाएगा। मेरे हल्के के बेरोजगार लड़के नौकरियों पर लगने के लिए मेरे पास आते हैं और वे लड़के कहते हैं कि हमें तो सिर्फ स्वीपर, चपरासी, चौकीदार और गेट कीपर की नौकरियों पर ही लगवा दें। वे बड़ी नौकरियों की डिमांड नहीं करते हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं है, बल्कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं तथा 12 वीं तक ही है। मेरे हल्के का मेडिकल कॉलेज और अलेवा गांव का कॉलेज शुरू होने से हमारे क्षेत्र के बच्चों का भी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और वे भी प्रदेश के दूसरे बच्चों की तरह कम्पीटीशन में आ सकेंगे। ये सभी चीजें वर्तमान सरकार में ही संभव हो पायी हैं। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः प्रेमलता जी, अगर आपकी कोई डिमांड है तो लिखकर दे दें। कम्बोज जी, आप 3 मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री राम चन्द कम्बोज (रानियां): उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज कृषि को बढ़ावा देने की बात की जा रही है और हरियाणा प्रदेश में 75 प्रतिशत से ज्यादा कृषि की जाती है। इसलिए कृषि के लिए बजट का प्रावधान भी 75 प्रतिशत से ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि प्रदेश को चलाने के लिए कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पास हरियाणा सरकार की रिपोर्ट है जिसमें सरकार ने किसानों को मारने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश के उन एरियाज को डार्क जोन में डाला गया है जिन एरियाज में धान की बहुत बड़ी खेती होती थी। मेरे हल्के रानियां में बासमती चावल की इन्टरनेशनल लेवल की वैरायटी पैदा होती है लेकिन सरकार द्वारा मेरे हल्के के एरिया को डार्क जोन में डालकर किसानों को मारने का काम किया गया है। सरकार का वाटर लेवल रिचार्ज का क्राइटेरिया 27 मीटर तक का है और कई एरियाज को तो 52 मीटर तक भी सेफ जोन में रखा गया है। सरकार का यह सिस्टम बिल्कुल किसानों को मारने वाला है इसलिए सरकार को ऐसी नीतियां नहीं बनानी चाहिए जिससे किसानों को नुकसान

हो। दूसरी बात यह है कि मेरे हल्के में घग्घर नदी से सिंचाई की जाती है और घग्घर नदी सिंचाई करने का बहुत बड़ा सोर्स हैं परन्तु इस नदी में भी विषैला पानी छोड़ा जा रहा है जिसके कारण किसानों की उपज बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त लॉ एण्ड ऑर्डर ठीक न होने के कारण प्रदेश 3 बार जला है। जब सरकार को पता है कि भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देने चाहिए था। यह बहुत बड़ी नाकामयाबी थी और मैं तो इसको बेवकूफी भी कहूंगा कि सरकार के माननीय मंत्री जिस तरह के ब्यान दे रहे थे और भीड़ को इक्ट्ठा होने दिया। इस दौरान 25 अगस्त को जिन निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं, उन लोगों की पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट सरकारी पोर्टल पर शो की जानी चाहिए। उन निर्दोष लोगों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आपकी अदालत में एक इन्टरव्यू के दौरान यह कहा था कि संबंधित लोगों के पास वृक्ष की टहनियों के सिवाय कोई हथियार नहीं था और धारा 144 के बारे में कहा था कि 5 लोग वैपन लेकर इक्ट्ठे होकर नहीं चल सकते थे, लेकिन उनके पास कोई वैपन नहीं था। यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्टरव्यू में कही थी। पंचकुला हत्याकांड में जो निर्दोष लोग मारे गये थे क्या उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और क्या उनके परिवार के एक–एक सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाएगी ? इसके अतिरिक्त जो 42 मारे गये हैं उन मृतक लोगों की पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट सरकार के पोर्टल पर डाली जाएगी। लिड टू लिड करके अलग–अलग केसों में निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। सरकार द्वारा एक एस.आई.टी. गठित की गयी है और एस.आई.टी. के द्वारा अलग–अलग तरीकों से निर्दोष लोगों को तंग किया जा रहा है। इसके लिए सरकार आश्वासन दे कि निर्दोष लोगों को तंग नहीं किया जाएगा तथा उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया जाएगा। सरकार उन लोगों के लिए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने के बारे में ब्यान दें। इसके अतिरिक्त मेरे रानियां हल्के को सन् 1987 में तहसील बनाया था उसके बाद सरकार द्वारा 25 तहसीलों को उप मण्डल का दर्जा दिया है। मेरे रानियां हल्के उप मण्डल बनाने के सभी नॉर्म्ज पूरे करता है इसलिए मेरे हल्के रानियां को उप मण्डल का दर्जा दिया जाए। उसके साथ ही साथ रानियां हल्के में पीने का पानी की कमी है, इस पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरी पानी छोड़ा जाए।

उपाध्यक्ष महोदयाः राम चंद कम्बोज जी, बाकी की डिमांड्स को आप सदन के पटल पर रख दें ताकि उनको प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया जा सके।

श्री राम चंद कम्बोजः उपाध्यक्ष महोदया, मैं बस 1 मिनट का समय लूंगा। **(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सी.एच.सी. की जो बिल्डिंग है, वह बहुत ही जर्जर हालत में है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी एक बार वहां की विजिट करके देख लें। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं थीं वे सारी की सारी अभी पैंडिंग पड़ी हुई है जैसे– चाहे रानिया का पुल की बात हो, चाहे रानिया से जीवनगर के रोड को चौड़ा करने की बात हो। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहूंगा कि रानिया शहर के बीचों–बीच एक गत्ता फैक्ट्री चल रही है और पूरे रानिया शहर के लोगों को उस गत्ता फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण को झेलना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार उस गत्ता फैक्ट्री को वहां से हटाने का काम करेगी ?

श्री अध्यक्षः राम चंद जी, आप रिटन में सारी बातें दे दें, उनको प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बना दिया जाएगा।

श्री राम चंद्र कम्बोज : ठीक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मरे हल्के की कुछ मांगे रह गई है यदि आपकी अनुमति हो तो मै लिखित रूप में दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप लिखकर दे दीजिए उसे प्रोसीर्डिंग्ज का पार्ट बनवा दिया जाएगा।

***श्री राम चंद्र कम्बोज :** रानिया को उपमण्डल का दर्जा दिया जाए। पीने का पानी नहरी उपलब्ध करवाया जाए। CHC की बिल्डिंग नई बनवाई जाए। बरसाती पानी की निकासी के लिए Storage Water की लाइन बिछाई जाए। घग्गर नदी की खुदाई और घग्गर नदी मे जाने वाले गंदे पानी पर रोक लगाई जाए। सिरसा को हौजरी का हब बनाने की घोषणा की थी उसे पूरा किया जाए। रानियां–कुताबढ़ घग्गर पुल, सिरसा जीवन नगर तक का रोड़ चौड़ा किय जाए। खैरका से ओटू घग्घर बांध पर रोड़ बनायी जाए। शहर के अन्दर गत्ता फैक्टरी है उसको हटाया जाए।

25 अगस्त को सरकार द्वारा कानून व्यवस्था के नाम पर किए गए कत्लेआम

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को प्रोसीर्डिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

पर सरकार अपना पक्ष स्पष्ट करे। इस कत्लेआम में 42 निर्दोष लागों की पुलिस की गोली से जान गई थी। सरकार अपना पक्ष निम्न तथ्यों पर स्पष्ट करें।

1. धारा 144 लगी होने के बावजूद भी इतनी संख्या में लोग कैसे एकत्रित हुए?
2. माननीय हाई कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 24.02.2017 पेज 10 रिट नं 19086 आफ 2017 में यह आदेश दिए थे कि राज्य सरकार और पंचकूला प्रशासन यह सुनिश्चित करें की जो भीड़ एकत्रित हुई है उसे वापिस भेजा जावे और उसे दोबारा पनपने ना दे।
3. राज्य सरकार या पंचकुला प्रशासन ने भीड़ को वहां से वापिस नहीं भेजा और माननीय हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया।
4. माननीय हाईकोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 24.02.2017 पेज 10 रिट नं 19086 आफ 2017 में यह आदेश पारित किया था कि कोई भी कार्यवाही करने से पहले पुलिस अधिकारी प्रत्येक दगें की घटना की वीडियोग्राफी करवाएगें और फिर उन पर मुकद्दमा दर्ज किया जावे। यह आदेश माननीय अदालत ने इसलिए दिया था कि माननीय अदालत को सरकार की मंशा पर शंका थी कि सरकार द्वारा ही भीड़ को एकत्रित किया गया है और अदालत के आदेश के बावजूद भी भीड़ को वापिस नही भेजा । माननीय हाईकोर्ट को डर था कि कहीं सरकार या प्रशासनिक अधिकरी मासूम निहत्थी भीड़ पर ज्यादती ना करे इसीलिए विडियोग्राफी करवाने के आदेश दिए गए।
5. सारा देश हरियाणा सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों पर इल्जाम लगा रहा है कि राज्य सरकार व पुलिस ने निहत्थे 42 लोगों कि हत्या की है। अगर सरकार द्वारा माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार वीडियोग्राफी करवाई गई है तो उसको सदन मे लाया जावे तथा वीडियोग्राफी को सार्वजनिक किया जावे ताकि सदन व देश की जनता देख सके कि हरियाण सरकार व पुलिस ने किस बेरहमी से निहत्थे मासूम लोगों की हत्या की । हम सदन से मांग करते है कि इन हत्याओं की जांच सिटिंग जज हाईकोर्ट से करवाई जावे।
6. राज्य सरकार दगों में मारे जाने वाले व घायल हुए व्यक्तियों बाबत अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि पूर्व में दगों में मारे गए या घायल हुए व्यक्तियो को मुआवजा व नौकरी दिए जाने के क्या आधार थे तथा 25 अगस्त को हुए दगों में मारे गए व घायल हुए व्यक्तियों को मुआवजे व नौकरी देने का आधार क्यों नही है।

7. 25 अगस्त को मारे गए व घायल हुए व्यक्तियों बाबत की गई पुलिस कार्यवाही 174 आर.पी.सी. व उनकी पोस्टमार्टम रिर्पोटस व एम.एल.आर. सदन के समक्ष लाई जावे व हरियाणा सरकार के सरकारी पोर्टल पर डाली जावे ताकि जनता उनका विश्लेषन कर सके।
8. 25 अगस्त के दगों बाबत जितने भी मुकदमा दर्ज हुए है उनमें से देशद्रोह की धारा हटाई जावे।
9. पंचकूला में मारे गए निर्दोष 42 लोगों के परिवारों को नौकरी व मुआवजा सरकार दें। सरकार सदन को आश्वस्त करे कि हरियाणा प्रदेश के किसी भी निर्दोष नागरिक को इन दंगों की आड़ में केसो में डालकर प्रताड़ित न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से माननीय हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी संलग्न कर रहा हूं।

of the society or organization;

(iv) In case of need, the Army shall be deployed and made operational.

(v) The police force shall make arrangements forthwith for capturing every moment of untoward situation through video-graphy by using video-cameras. Those who are indulging in any kind of violence, arson of breach of peace etc. shall be video-graphed and an FIR shall be registered against him/them;

(vi) In case any politician or anybody else including Ministers interferes in the enforcement of law, FIR be registered against him/them. In case of failure on the part of the police officer to register an FIR, similar action would be called against him;

(vii) No politician, leader, social-worker, spiritual leader, religious leader or any such organization shall make any provocative speech or statement, which may have the tendency to affect public order.

This order shall be applicable in the States of Haryana and Punjab as also Union Territory, Chandigarh.

We are sure that Media will play a pro-active and responsible role in this behalf.

The case be taken up today itself in post-lunch session.

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया (फतेहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है कि ''पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं।'' अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण से यह पता चल गया था कि बजट का स्वरूप कैसा होगा। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन विधान सभा में बजट प्रस्तुत होना था उस दिन मैं जब विधान सभा में आ रहा था तो मुख्य द्वार पर मुझसे एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप सफल बजट किसे मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने उस पत्रकार महोदय से कहा कि अगर आज हमारे वित्त मंत्री जी किसी गृहिणी की गुथली में, अगर आज हमारे वित्त मंत्री किसी किसान की पोटली में, अगर आज हमारे वित्त मंत्री जी किसी रेहड़ी वाले की गुल्लक में, अगर आज हमारे वित्त मंत्री जी किसी फेरी वाले के हाथ में 4 आना भी फालतू रखने में कामयाब हो गए तो मैं उसे सफल बजट मानूंगा। अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह बजट पूरी तरह से जन–विरोधी, विकास–विरोधी और भ्रामक करने वाला है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी इस बजट की बहुत तारीफ कर रहे थे कि ब्यूटीफुल बजट एण्ड वैरी हैंडसम फाइनैंस मिनिस्टर, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि this kind of budget is a serious impediment to economic improvement of State presented by very handsome Finance Minister. अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से किसानों को गुमराह करने के लिए कृषि क्षेत्र में केवल 51.22 प्रतिशत ही बजट बढ़ाया है। अध्यक्ष महोदय, इससे केवल मैं ही नहीं, बल्कि धनखड़ साहब भी नाराज है। अध्यक्ष महोदय, मैं टी.वी. पर देख रहा था कि जब धनखड़ साहब के घर पर पत्रकार महोदय बजट के बारे में उनकी प्रतिक्रिया लेने गए और पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप इस बजट में कृषि के बारे पर क्या कहना चाहेंगे तो धनखड़ साहब ने कहा कि ये मेरी गाय देखें यह 20 लीटर दूध देती है। उसके बाद पत्रकार महोदय ने दोबारा से पूछा कि आप बजट के बारे में बताएं तो इन्होंने बोला कि मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूं। अध्यक्ष महोदय, फिर से पत्रकार महोदय ने पूछा कि धनखड़ साहब आप बजट के ऊपर प्रतिक्रिया दें तो इन्होंने बोला कि यह मेरे अध्यात्म के रूम देखिए, यहां पर मैं अध्यात्म करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पत्रकार महोदय के द्वारा बार–बार फोर्स किए जाने के बाद इन्होंने कहा कि आप रोहतांग जाइए वहां पर भूस्खलन बहुत होता है और वहां के दीवार पर लिखा हुआ है कि प्रकृति पर गुस्सा मत कीजिए सबकी अपनी–अपनी भूमिकाएं हैं। अध्यक्ष महोदय,

उसके बाद मुझे पता चला कि वित्त मंत्री जी बजट पढ़ने के दौरान बार–बार पसीना क्यों पोंछ रहे थे, क्योंकि इनसे जबरदस्ती बजट पढ़वाया जा रहा था।

श्री अध्यक्षः बलवान जी, वित्त मंत्री जी बजट को बनाते हैं उनसे बजट पढ़वाया नहीं जाता है।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरियाः अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हैल्थ पर वर्ष 2017–2018 में 3168 करोड रुपए रखे थे, लेकिन उस राशि को संशोधित करके 3149 करोड रुपए की राशि दी गई। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हैल्थ के बजट में 19 करोड रुपए काटे गए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए कई योजनाएं जैसे– किशोर शक्ति योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और राजीव गांधी सबल योजना के तहत उनको पौष्टिक आहार दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में इसके लिए 288 करोड रुपए रखे गए थे, लेकिन वित्त मंत्री जी ने उसे संशोधित करके वर्ष 2018–2019 के बजट में 223 करोड रुपए कर दिए, इस तरह से 65 करोड रुपए की कटौती की गई है। अध्यक्ष महोदय, उसका असर यह हुआ कि जब भारत सरकार की कुपोषण के बारे में रिपोर्ट आई तो पता चला कि कुपोषण के मामले में हरियाणा का 14वां नम्बर आया। हरियाणा के बच्चों में ठिगना, अल्पवजनी और खून की कमी पायी गयी। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 साल से छोटे 71 परसेंट बच्चों में और 63 परसेंट महिलाओं में खून की कमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये हैल्थ के मामले में कटौती न करें। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं कानून–व्यवस्था की बात करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अगर हम वर्ष 1966 से लेकर आज तक के प्रत्येक साल का रेशो निकालेंगे तो पता चलेगा कि इन साढ़े तीन सालों में जितने क्राइम बढ़े हैं आज तक उतने क्राईम नहीं बढ़े थे। अध्यक्ष महोदय, सरकार सोचती है कि सिर्फ पुलिस स्टेशनों की लिपाई–पोताई करके लॉ एण्ड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों के साथ उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है और यह बहुत ही चिंता करने योग्य है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं एस.वाई.एल. नहर के मामले में कहना चाहूंगा कि पिछले बजट में इसके लिए पैसा दिया गया था उसको तो कहीं लगाया नहीं और इस बार 100 करोड रुपए का और प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को जहां पर काम करना चाहिए वहां पर तो करती नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार का फर्ज बनता है कि जब पिछले साल नेता प्रतिपक्ष पूरे हरियाणा को लेकर शंभू बॉर्डर पर गए। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मुख्यमंत्री जी पूरे मंत्रिमंडल को लेकर नेता प्रतिपक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर जाते तो यह एक अच्छी परम्परा कायम होती और उससे सैंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब सरकार पर दबाव बनता, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमारा मजाक उड़ाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, अगर ये लोग इसी तरह हमारा मज़ाक उड़ाते रहे तो जो आज हरियाणा प्रदेश में पानी की कमी है वह निरंतर बढ़ती ही चली जायेगी। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास जी को भी इस बारे में ज्यादा पता होगा क्योंकि पानी के मामले में उनके इलाके की स्थिति बहुत भयावह है। अध्यक्ष जी, 50 साल पहले हमारे इलाके में लोग 12 महीने बाजरे की रोटी खाते थे। हमारे इलाके के घरों में गेहूं की रोटी मेहमान के आने पर ही बनती थी। मेहमान को ही भी हमारे यहां पर आठ रोटी दी जाती थी जिनमें ऊपर की चार रोटी गेहूं की होती थी और नीचे की चार रोटियां बाजरे की होती थी। मेहमान को भी यह इंडीकेशन दिया जाता था कि उसको भी पांचवी रोटी बाजरे की ही खानी पड़ेगी। अगर एस.वाई.एल. कैनाल का पानी हमारे प्रदेश को नहीं मिला तो ऐसी ही स्थिति दोबारा से पैदा हो जायेगी। अध्यक्ष जी, राम बिलास शर्मा जी यहां पर बहुत बार रमलू वाली कहानी सुना चुके हैं मेरी उनसे रिकवैस्ट है कि वे एक बार रमलू वाली कहानी और जरूर सुना दें क्योंकि रमलू वाली कहानी वर्तमान हरियाणा सरकार पर भी 100 परसैंट सटीक बैठती है। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर अपनी बात कहने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अनूप धानक (उकलाना) (अ.ज.) : स्पीकर सर, आपने मुझे वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट पर बोलने के लिए समय दिया सर्वप्रथम तो मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, मैं आपके माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर से यह रिकवैस्ट करना चाहूंगा कि पिछले साल के बजट सत्र के दौरान मेरे विधान सभा क्षेत्र में उकलाना और भूना रोड पर आर.ओ.बी. और यू.आर.बी. बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी लेकिन एक साल के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर कोई भी कार्यवाही पी.डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा नहीं की गई है। एक बात मैं पंचायत मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के के सरसाना, सौथा, भाड्डा और पनिहारी ये चार गांव बरवाला तहसील से तोड़कर के

खेड़ी चौपटा तहसील में मिला दिये गये हैं। इससे इन सभी चारों गांवों के लोगों को बड़ी भारी तकलीफ है। मेरी मंत्री जी से रिकवैस्ट है कि मेरे हल्के के सरसाना, सौथा, भाड्डा और पनिहारी ये चार गांव खेड़ी चौपटा तहसील से तोड़कर पुनः बरवाला तहसील में मिला दिये जायें ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी मुझे बार–बार अपना गवांडी भाई कहते हैं। इन्होंने मेरे से सौथा, भाड्डा और खेडी–चौपटा तक की सड़क का निर्माण करवाने का पिछले बजट सत्र में वायदा किया था लेकिन आज तक उस सड़क के निर्माण कार्य की शुरूआत नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी की ससुराल मेरे हल्के के गांव कुलेरी में है। आदरणीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मुझे पिछले बजट सत्र में कुलेरी से खारा खेड़ी तक की सड़क बनाने का आश्वासन दिया था लेकिन इस सड़क के निर्माण का कार्य भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसी प्रकार से संदोल से बालक गांव तक जो रोड बनना था जिसके लिए मंत्री जी ने एक साल पहले स्वीकृति दी थी इस रोड पर भी अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मेरी जन स्वास्थ्य मंत्री जी से यह रिकवैस्ट है कि मेरे हल्के के ढ़ाण्ड गांव में वॉटर वर्क्स की पाईप्स में सेम का पानी मिलकर आता है जिससे वहां पर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारी पार्टी के माननीय लोक सभा सांसद श्री दुष्यंत चौटाला जी ने जगह–जगह टैंकर्स से पीने के पानी की आपूर्ति करवाने की व्यवस्था की है। मैंने इस गांव की पाईप लाईन की रिपेयर के लिए एक क्वैश्चन भी दिया था जिस पर विभाग का जवाब ष्नहींष में आया है। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस वॉटर वर्क्स की पाईप लाईन्ज़ को ठीक करवाया जाये ताकि लोगों को पीने के लिए उचित मात्रा में साफ पानी मिल सके। ऐसे ही मेरे हल्के में एक ढ़ाणी है जिसका नाम ढ़ाणी तारा नगर है। पाबड़ा रोड से इस ढ़ाणी तक एक कच्चा रास्ता जाता है। वहां पर 400 के करीब वोटर हैं और 200 से 250 की संख्या में घर हैं। बरसात के दिनों में इस ढ़ाणी में आने–जाने में वहां के निवासियों और विशेषकर जो छात्र और छात्रायें हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी माननीय कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी से प्रार्थना है कि पाबड़ा रोड से ढ़ाणी तारा नगर के इस कच्चे रास्ते को जल्दी से जल्दी पक्का करवाने के आदेश जारी करने की कृपा करें। सर, मेरे हल्के में एक ईश्शरहेड़ी गांव है। इस गांव में नई पंचायत बनी है। इस गांव में पीने के पानी का आज तक कोई प्रबन्ध नहीं हो पाया है।

वहां पर न तो कोई वॉटर वर्क्स है और न ही कोई बूस्टिंग स्टेशन है। इसलिए मेरी सम्बंधित मंत्री जी से रिकवैस्ट है कि वहां पर एक बूस्टिंग स्टेशन बनाने के आदेश जारी करने की कृपा करें। मेरे उकलाना में मार्किट कमेटी का ऑफिस खाली पड़ा है। उकलाना में कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हुआ है लेकिन कालेज की बिल्डिंग में अभी क्लॉसिज़ लगने में काफी समय लगेगा। उकलाना मार्किट कमेटी का ऑफिस खाली है इसलिए मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि जब तक इस कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार होती है तब तक उकलाना मार्किट कमेटी के खाली पड़े ऑफिस में इस कॉलेज की क्लॉसिज़ इसी शैक्षणिक सत्र से लगवानी शुरू कर दी जायें। इससे बहुत से विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। मेरे उकलाना में एक गंदे पानी का तालाब बना हुआ है और उस गंदे पानी को निकालने का अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है। इस गंदे तालाब के कारण वहां के लोगों में अनेकों बीमारियां फैल रही हैं। इसलिए मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि इस गंदे तालाब का पानी निकालकर वहां पर एक पार्क बनवा दिया जाये जिससे आस–पास के लोग बीमारियों से बच सकें और पार्क की सुविधा भी उनको प्राप्त हो सके। मेरे हल्के का पाबड़ा गांव आठ गांवों से घिरा हुआ है। पहले मेरे हल्के के इस गांव में जे.बी.टी. सैंटर होता था लेकिन माननीय श्री भजन लाल जी ने अपनी सरकार के समय में उसको मातरश्याम गांव में शिफ्ट कर दिया था। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वहां पर एक कॉलेज बना दिया जाये। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं पुनः आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरी कुछ बाते कहने से रह गयी हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हे सदन के पटल पर रख देता हूं । आप उन्हें प्रोसीर्डिंग्ज का पार्ट बनवा देना ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है जी।

***श्री अनूप धानक :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हू मेरे उकलाना में रेलवे फाटक पर भूना फतेहबाद रोड पर आर.ओ.बी. या यू.आर.बी. को मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसको बनाने का काम करेंगे अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है मंत्री जी ने सदन मैं घोषण की थी खेड़ी चोपाल से सौया तक रोड बनाने की बात कही थी अब तक इस पर भी कोई कार्यवाही नही हूई है।

.....

***चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीर्डिंग्ज का पार्ट बनाया गया**

संदोल से बालक तक रोड भी मंत्री जी ने सदन मैं घोषण की थी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कूलेरी से रवाराखेड़ी तक का रोड़ बनाने की भी सदन में घोषणा की थी अभी तक उसको भी पूरा नहीं किया गया है। मेरा प्रश्न लगा हुआ था की ढाउ गांव में वाटर वर्क्स में सेम का पानी मिक्स हो जाता है। जिससे गांव का पीने का पानी खराब हो जाता है जिससे गांव में बीमारियां फैलती है। उसको ठीक करवाया जाए लेकिन मंत्री जी ने इसका नही जवाब में दिया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हू कि इस गांव के लोगों का यही पानी पीना पड़ेगा या इस पानी को ठीक करवाया जाऐगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र मैं कन्डल गांव मैं वाटर वर्क्स का टैंक छोटा है उसमें एक टैंक और बनाया जाएं। बालक से पाबड़ा रोड पर ढाणी तारा नगर तक रास्ता कच्चा है। इस रास्ते को पक्का करवाया जाए। ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा मिल सकें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इशहेड़ी गांव है उसकी अलग से पंचायत है उस गांव में पीने का पानी नहीं है। वहा पर वाटर वर्क्स बनाया जाए। ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सकें उस गांव में अलग से अनुदान देकर अलग से सड़क बनवाई जाएं । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उकलाना में कॉलेज बन रहा है। पहले उकलाना में मार्केटी कमेटी का दफ्तर भी होता था और तहसील ऑफिस भी था अब तहसील की नई बिल्डिंग बन गई है। मार्केट कमेटी आ ऑफिस भी नयी बिल्डिंग बन गई है। वो बिल्डिंग खाली पड़ी है। इस बिल्डिंग में इस सत्र से क्लास लगाई जाए। मेरे उकलाना गांव में गन्दे पानी का तालाब बना हुआ है। उस पानी को निकाल कर उस पर पार्क या सामुदायिक केन्द्र बनवाया जाए। ताकि बीमारियों का घर बन चूका है। उससे लोगों को निजाकत मिल सकें मेरे विधान सभा क्षेत्र मैं ढाणीयां बहुत है इन ढाणियों में सरकार बिजली देने का काम करें गांव पाबड़ा में पहले जे.बी.टी. का सैन्टर हाता था जो इस गांव से तोड़ दिया था बहुत बड़ा गांव हो और सात–आठ गांव से घिरा हुआ है। यहा पर गर्ल्ज कालेज बनाने का काम करें। पाबड़ा गांव में लड़कियों के स्कूल के सामने कच्चा रास्ता है और हमारी बहनों का स्कूल आन जाने में कठिनाई होती है उस रास्ते को पक्का किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के चार गांव सौदा, माडा, पनिहारी, सरसाना बरवाला तहसील से तोड़कर खेड़ी चौपटा में जोड़ दिए है। इन गांव को वापिस बरवाला तहसील में जोड़ा जाए। मै माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हू मेरे हल्के के उकलाना सब डिवीजन जो XEN टोहाना और S.E. फतेहाबाद के अण्डर है उसको हिसार XEN और S.E. के

अण्डर किया जाए। मेरा हल्का उकलाना में एक चार साल की दलित बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई जो एक शर्मनाक हरकत थी जोकि मैं उसको ब्यान भी नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय आज तक वे दोषी पकड़े नहीं गए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में साहू गांव के एक घर में से चोर भैस खोलकर लेकर जा रहे थे, तो जिसने उनको रोकने का काम किया तो चोरो ने उसको गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के पास लगता टोहाना हल्के में एक समैन गांव है। अध्यक्ष महोदय, मैं पशुपालन मंत्री जी के सज्ञान में लाना चाहता हू कि इस गांव में लगातार भैसों की मौत हो रही है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि भैसों की मौत का क्या कारण है पता करवाया जाए तथा उसकी रोकथाम का उपाय किया जाए।

सदन का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाये?

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2018–19 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) तथा वित्तम मंत्री द्वारा उत्तर

श्री जय प्रकाश (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो 3–4 बातें सुझाव के रूप में बोलना चाहूंगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारा हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि के लिए सरकार ने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत कुछ लिखा है और ऐसे ही वित्त मंत्री जी ने भी अपने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए काफी कुछ कहा है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात विशेष रूप से कही गई है कि हम प्रदेश के किसानों को अगली खरीफ की फसल से डेढ़ गुणा लाभ देंगे। इस बारे में मेरा कृषि मंत्री जी को एक सुझाव है कि अब की बार एक महीने के बाद गेहूं की फसल आ रही है। इस बार गेहूं की फसल में जो सबसे बड़ा नुक्सान हुआ है वह मैं सारे सदन को बताना चाहूंगा मुझे उम्मीद है कि सारा सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि मंडूसी नाम की जो खरपतवार गेहूं के साथ पैदा होती है उसको गेहूं की फसल में से नष्ट करने के लिए किसानों द्वारा 4–5 स्प्रे की गई लेकिन किन्हीं कारणों से उसकी गेहूं की फसल में से वह मंडूसी नामक खरपतवार खत्म नहीं हुई। इससे

17:00 बजे

किसानों की गेहूं की फसल की कम पैदावार होने का बड़ा भयंकर अंदेशा है। ऐसे ही इस बार कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है इसलिए मेरा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि जिन किसानों की फसल इस सबसे प्रभावित हुई है उन किसानों की फसल की स्पैशल गिरदावरी करवाकर किसानों को अधिक से अधिक मुआवज़ा दिया जाये ताकि किसानों के नुक्सान की भरपाई हो सके। सरकार द्वारा किसानों को यह मुआवज़ा देने में कोई परेशानी भी नहीं होगी क्योंकि वित्त मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप में यह कहा है कि सरकारी खजाने में भरपूर धन है। वित्त मंत्री जी ने 1,15,000 करोड रूपये के लगभग का बजट प्रस्तुत किया है इसलिए अगर किसान को उसकी खराब फसल का मुआवजा नहीं दिया जायेगा तो हम समझेंगे कि वर्तमान सरकार केवल किसान के हित की बातें ही करती है और वास्तव में ग्राऊंड लैवल पर किसानों के हित के लिए सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया जाता। मैं दूसरी बात सिंचाई के मामले में कहना चाहता हूं। मैं वित्त मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा कि लखवार, ब्यासी और रेणुका इन तीनों बांधों को जल्दी से जल्दी बनाया जाये क्योंकि इन बांधों के निर्माण से हरियाणा को काफी मात्रा में अतिरिक्त पानी मिल सकता है। वर्ष 2006 में जब मैं लोक सभा का सदस्य था उस समय मैंने इस मामले को लोक सभा में भी उठाया था। उस समय यू.पी.ए. गवर्नमैंट और उससे पहले एन.डी.ए. गवर्नमैंट ने भी इन तीनों बांधों को बनाने की तरफ विशेष ध्यान दिया था इसलिए मेरा हरियाणा सरकार से निवेदन है कि वह इस मामले को केन्द्र सरकार के साथ उठाकर इन तीनों बांधों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का फण्ड तय करके इसके साथ ही साथ केन्द्र सरकार के फण्ड का भी हिस्सा तय करवाया जाये। अगर ऐसा होता है और सरकार लखवार, ब्यासी और रेणुका इन तीनों बांधों के निर्माण का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करवा देती है तो इससे हरियाणा प्रदेश को 1200 से 1400 क्युसिक अतिरिक्त पानी मिल सकता है। इससे हमारे पानी के झगड़े को भी सुलझाया जा सकता है। खासकर के जो हमारे कैथल जिले का पानी दूसरे जिलों में डाईवर्ट हो गया था वह पानी भी हमें वापिस मिल जायेगा। इसी प्रकार से मेरा एक बहुत छोटा मामला और है। सर, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया वर्ष 2018 का बजट बहुत बड़ा है। उनकी यह बात सही भी है क्योंकि उनके द्वारा जो वर्ष 2018 का बजट प्रस्तुत किया गया है उसकी राशि 1,15,000 करोड रूपये के लगभग है। हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग

की सिफारिशों के तहत वेतन का भुगतान भी किया जा रहा है लेकिन कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण भेदभाव हो रहा है। हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं हमारी विधान सभा के कर्मचारियों की तनख्वाह और पंजाब विधान सभा के कर्मचारियों की तनख्वाह में जो अंतर आया है उस अंतर को हर हाल में दूर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे पुलिस के कर्मचारी भाई जिन्होंने दिन–रात एक करके लॉ–एण्ड ऑर्डर की स्थिति को सम्भाला हुआ है, उनको पेशेवर बदमाशों से भी टकराना पड़ता है और मिलीटैंसी से भी लोहा लेना पड़ता है। उनको भी यदि सरकार द्वारा पंजाब के कर्मचारियों के समान ही वेतन दिया जायेगा तो हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी इस बात को दिल से मानेंगे कि सरकार उनका भरपूर ध्यान रखती है। यहां पर नम्बरदारी प्रथा के ऊपर बड़ी चर्चा चली। पूर्व सी.पी.एस. साहब श्री बख्शीश सिंह विर्क जी अभी सदन में मौजूद नहीं हैं वे भी नम्बरदार हैं। नम्बरदारी की प्रथा आज से नहीं है बल्कि यह बहुत पुराने जमाने से है। पुराने समय से अब तक थानेदार, एस.डी.एम., तहसीलदार या डिप्टी कमिश्नर इत्यादि द्वारा नम्बरदारों को जिम्मेदार व्यक्ति बताया जाता रहा है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं कि नम्बरदार किसी भी गांव का एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति होता है। इस सबको ध्यान में रखते हुए मेरा सरकार से निवेदन है कि नम्बरदारी प्रथा को खत्म न किया जाये बल्कि सरकार और समाज के प्रति नम्बरदारों की सेवाओं को देखते हुए उनका मानदेय बढ़ाकर उनको पुरस्कृत किया जाये। इस मामले में भी यह न कहा जाये कि यह काम उस सरकार के समय में एक प्रकार से किया गया था और दूसरी सरकार के समय में दूसरी प्रकार से किया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में हरियाणा प्रदेश की कमान है । प्रदेश के सभी नम्बरदार यही चाहेंगे कि आज वित्त मंत्री जी या फिर मुख्यमंत्री जी कल यह घोषणा कर दें कि हरियाणा में नम्बरदारी की प्रथा को कंटीन्यू रखा जायेगा। इतना ही नहीं सरबरा नम्बरदारी की प्रथा भी शुरू की जाये। जिस प्रकार से पहली सरकारों में यह सिस्टम आया था कि यदि कोई नम्बरदार रिटायर या बुजुर्ग हो जाये तो सरबरा नम्बरदार बना दिया जाये। इसके साथ ही साथ मैं अपनी दो छोटी–छोटी डिमाण्डज़ भी सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरी पहली डिमाण्ड तो यह है कि कलायत में महिला महाविद्यालय की घोषणा हो चुकी है इसलिए वहां पर क्लॉसिज़ इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू करवाने की व्यवस्था करवाई जाये। इसी प्रकार से मेरी दूसरी डिमाण्ड यह है कि राजौन्द

में महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाये। इस महिला महाविद्यालय के लिए जमीन म्युनिसिपल कमेटी, राजौन्द के पास उपलब्ध है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस जमीन को शिक्षा विभाग के नाम ट्रांसफर करवाकर राजौन्द में महिला महाविद्यालय के निर्माण का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करवायेगी। स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय प्रदान किया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री कुलवन्त राम बाजीगर (गुहला) (अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया है जिसमें हर वर्ग के बारे में सोचा गया है। शिक्षा के सुधार के लिए कदम उठाये गये हैं। उच्चतर शिक्षा के लिए 29 राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। बहुत से स्कूलों को भी अपग्रेड किया गया है। इसी प्रकार से बिजली के क्षेत्र के लिए वर्ष 2018–19 के बजट में सम्प्रेषण प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए 24 नए सब–स्टेशन स्थापित करने, 93 मौजूदा सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने और लगभग 775 किलोमीटर लम्बी सम्प्रेषण लाइनें बिछाने की योजना है। 33 के.वी.ए. के 177 मौजूदा सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाकर और 33 के. वी.ए. की 790 किलोमीटर से अधिक लम्बी नई लाइनें बिछा कर 33 के.वी.ए. सब–स्टेशन तंत्र के विस्तार के कार्य को तेज किया जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी नई सड़कें बनाने तथा गांव से गांव को जोड़ने के लिए भी बहुत सारी सड़कें बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 1443 नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए हॉस्पिटल्स में भी सुधार किया गया है इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। अध्यक्ष महोदय, मेरा गुहला विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था लेकिन अब उसमें बहुत काम हुये हैं। मेरे गुहला में भी एक लड़कियों का कॉलेज खुलवाया गया है तथा 10 स्कूल भी अपग्रेड हुये हैं इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई काम नहीं कर रही है केवह वाहवाही लूट रही है मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरा गुहला विधान सभा क्षेत्र पिछले 70 साल से पिछड़ा हुआ था उसमें 3 सालों में बहुत ज्यादा काम हुये हैं। अगर मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में पॉवर हाउस की बात करूं तो 33 के.वी.ए.

के 9 पॉवर हाउस मंजूर हुये हैं जिससे बिजली का बहुत अच्छा प्रबंध होगा उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से माननीय लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह जी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो गांवों से गांवों को जोड़ने वाली तथा 12 फुट से 18 फुट की 56 सड़कें बनाई हैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में फोरलेन कोई सड़क नहीं थी लेकिन अब फोरलेनिंग के लिए जो 4382 करोड रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से अगर नहरों की बात की जाये तो 3 नहरों नामतः मारकंडा डिस्ट्रिब्यूट्री, उरलाना माइनर तथा पहाड़पुर माइनर में कभी टेल तक पानी नहीं पहुंचता था लेकिन इनकी मुरम्मत करवा कर टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। मिट्टी–पानी की जांच के लिए 47 लाख रुपये की लागत से जो गुहला–चीका में लैब स्थापित की है उससे किसानों को बहुत लाभ होगा। इसी प्रकार से हॉस्पिटल को सुदृढ़ बनाने के लिए गुहला चीका में 4 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे मोर्चरी बनेगी, एक्स–रे मशीन तथा लैब वगैरह बनेगी उसके लिए भी मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सीवन एक बड़ा कस्बा है जिसको कांग्रेस सरकार के समय आदर्श गांव बनाया गया था लेकिन उसमें पानी निकासी का कोई सिस्टम नहीं था जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी होती थी उसके लिए हमारी सरकार की तरफ से 21 करोड रुपये पानी निकासी के लिए दिये गये हैं। वहां पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं थी और जब मैं चुनाव के दौरान प्रचार के लिए गया था तो पैदल चलने की जगह नहीं थी और मुझे ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठा कर घुमाया गया था। इसी प्रकार से सीवन में कोई पार्क नहीं था लेकिन अब वहां पर पार्क भी बनवाया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में और भी बहुत से कामों की जरूरत है मैं उनके बारे में भी कहना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र को भारत सरकार के सर्वे के बाद डार्क जोन घोषित किया गया है इसलिए गुहला में एक वाटर ट्रीटमैंट प्लांट लगाया जाये ताकि लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिल सके। मारकंडा डिस्ट्रीब्यूट्री शहर के बीच से निकलती है और वहीं पर नगरपालिका की कुछ जमीन भी उपलब्ध है इसलिए वहीं पर एक वाटर ट्रीटमैंट प्लांट लगाया जाये जिससे शहर को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल सके। इसी प्रकार से पाबसर गांव में एक 33 के.वी.ए. का सब–स्टेशन बनाया जाये जिससे

8–10 गांवों को बिजली का फायदा मिलेगा। मेरे शहर गुहला में एक सब–डिपो बनाये जाने की जरूरत है क्योंकि वहां पर 82 राईस मिल्स तथा लगभग 170 मार्बल की दुकानें हैं जिससे व्यापारी और अन्य लोगों को दिल्ली, जयपुर तथा अन्य जगहों पर जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिसके बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। इस सत्र में विपक्ष केवल आधारहीन बातें ही करता रहा है। जिस प्रकार से पिछली सरकारें काम करती थी और जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है उसको देखते हुये मैं कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी की एक मिसाल कायम की है। पहले की सरकारों में तो तानाशाही चलती थी लेकिन अब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और राज्य में इसी तरह का राज होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पहले किस प्रकार का राज होता था यह अधिकारी भी और जनता भी जानती है। इन्होंने जो कुदरत की दी हुई पॉवर थी उसमें खयानत की है। मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं :–

''अमानत में खयानत तूने किया, ताकत को जहां अपना समझा,

मनसद पर पहुंच कर भूल न जा, ये ताकत तो एक अमानत है। ''

यह अमानत आज लोगों ने इनसे छीन ली है। आज इनके पास बहस के सिवाय और कुछ भी नहीं है। आज इनसे पूछा जाये कि आपने किस प्रकार से राज किया था। आज लोग सबकुछ जानते हैं कि किसकी कैसी सोच है और किसने विकास के बारे में सोचा है। जितना विकास आज हो रहा है इतना विकास हरियाणा में आज तक कभी नहीं हुआ। मैं एक और शेर के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करूंगा:–

''साथियो विकास की असली उड़ान अभी बाकी है,

हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है,

अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन हमने,

सारा आसमां अभी बाकी है। ''

श्री अध्यक्षः कुलवन्त जी, अब आप बैठ जाईये क्योंकि आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

श्री कुलवन्त राम बाजीगरः अध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ डिमाण्डज अभी कहने से रह गयी हैं यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इनको सदन के पटल पर रख देता हूं। आप इन्हें सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनवा देना।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

***श्री कुलवन्त राम बाजीगर :**

1. गुहला में सब डिपो :–

गुहला चीका में बस सब डिपो की भी जरूरत हैं गुहला हल्के में 113 गांव व 50.000 आबादी वाला शहर और लगभग 82 राईश मिल, 200 मार्बल की दुकान व गोदाम हैं व्यापारियों को दिन राम दिल्ली, जयपूर, चण्डीगढ, या आउट स्टेट आने जाने में परेशानी ना आए इसलिए सब डिपो जरूरी हैं।

2. गुहला चीका में निम्न उप–स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की अनुमति देने बारे।

1. 04 शहरी क्षेत्र चीका में।
2. 03 गुहला में।
3. 01 गांव भागल में।
4. 01 ककराला अनायत, ककराला कुचियां, कक्योर माजरा।
5. 01 गांव खेड़ीगुलाम अली।

सामान्य हस्पताल गुहला–चीका में डिजिटल एक्सरे मशीन की मांग।

सामान्य हस्पताल गुहला–चीका में सिटी स्कैन मशीन की मांग।

एन.एच.एम. के माध्यम से 10 ए.एन.एम. के पद रिक्त पडें हैं भरवाऐं जाऐं।

3. सिंचाई के लिए डैम या छोटी नहर बनाई जाऐ।

घघर पार इलाके में लगभग 15 गांव जिसमें दाबनखेडी, चाणचक, हंसूमाजरा, भाटियां, दाबा–चाबा, रत्ताखेडा, टटियाणा, नन्दगढ, लालपूर, स्युंमाजरा, इत्यादि का

.....

*** चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

पानी तेजाबी एंव पीने योग्य व खेती योग्य नही हैं इसलिए इन गांवों में से एक छोटी नही बनाई जाए टटियाणा से उरलाना तक जो घघर एल टाईप हैं इसलिए टटियाणा से उरलाना तक 15 किलोमीटर तक छोटी नहर बनाई जाए जब घग्घर नदी बरसात के दिनों में किनारे तक भर कर चलती हैं तक इसका फायदा 15 से 20 गावों को मिल सकें और किसानों को भी अपनी फसलों के लिए इसका लाभ मिल सकें जिससे किसानों को खेती करने के लिए तेजाबी खरा पानी की बजाय फसल योग्य पानी व शुद्व पानी मिल सकें।

4. पाबसर में 33 के.वी.ए. पावर हाउस बनाया जाए लगभग 08–10 गावों पडतें हैं इन गांव में बिजली कभी समस्या ना रहें।

5. उरलाना माइनर बुर्जी न0 70,000 से 1,00,000 तक का पुनः निर्माण किए जाने बारे।

क्योंकि इस टुकडें की हालत बहुत की खस्ता हैं बैड की ईंटें उखडी हुई हैं और यह रिसती रहती हैं। जिसके कारण टेल तक पानी नही पहुंच पाता इसका निर्माण लगभग 40 वर्ष पहले हुआ था।

6. पापसर माइनर बुर्जी न0. 0 से 39,100 तक का पुनः निर्माण किये जाने बारे।

क्योकि इस टुकडे की हालत बहुत की खस्ता है बैड की ईंटें उखड़ी हुई हैं और यह रिसती रहती हैं जिसके कारण टेल तक पानी नही पहुंच पाता इसका निर्माण लगभग 40 वर्ष पहले किया गया था।

7. चीका शहर में जिम खाना क्लब बनाऐ जाने बारे।

चीका शहर काफी मात्रा में व्यापारिक सस्ंथान होने की वजय से काफी विस्तरीत हो चुका हैं और यहां भी अन्य शहरों की तरज पर जिम खाना कलब बनाया जाऐं जो कि चीका शहर की बहुत पुरानी मांग हैं।

8. गांव महमूदपूर में खेल स्टेडियम बनाऐं जाने बारे।

यह गांव घग्घर पार ऐरिया का है और इसके इर्द गिर्द लगभग 15 गांव हैं जिससे सभी को लाभ होगा घध्घर पार का गांव होने की वजय से यहां सरकारी सुविधाओं का आभाव हैं और यह ईलाका पिछड़ा हुआ है।

9. गांव दाबा में प्राईमरी हैल्थ सैन्टर बनाऐं जाने बारे।

यह गांव घग्घर पार ऐरिया का है और इसके इर्द गिर्द लगभग 15 गांव हैं जिससे सभी को लाभ होगा घग्घर पार का गांव होने की वजय से यहां सरकारी सुविधाओं का आभाव है और यह ईलाका पिछडा हुआ है।

10. गांव माजरी में पशु हस्पताल बनाऐं जाने बारे।

क्योकि यह चीका शहर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर पडता हैं यह इलाका कृषक होने की वजय से लोगों के पास काफी मात्रा में पशुधन हैं ये चीका शहर से काफी दूरी होने की वजय से पशुओं के ईलाज में दिक्कत आती है।

11. हल्का गुहला–चीका में मेडीकल कॉलेज बनाऐं जाने बारे।

यह इलाका पढाई में बहुत ही पिछड़ा हुआ हैं और इसके आप–पास 100 किलोमीटर क ऐरिया में कोई अन्य मेडीकल कॉलेज नही है ऐरिया के लोग मैडिकल कॉलेज के लिए निःशुल्क जमीन देने के लिए तैयार है।

12. गांव आंधली में खेल स्टेडियम बनाऐं जाने बारे।

गांव के लोग निःशुल्क जमीन देने के लिए तैयार है आस पास के 20–25 गांव को लाभ होगा।

13. गांव अगौंध, भूना, रत्ताखेडा, भूसंला, पपराला, हरनौली, व पापसर हेमुमाजरा, हरिगढ किंगन, दाबा में कम्युनिटी सैन्टर बनाऐ जाने बारे।

इन गांव की जनसख्ंया बहुत अधिक हैं और इन गावों के इर्द–गिर्द 5 से 6 गांवों को भी कम्युनिटी सैन्टर खोलने से सुविधा होगी।

14. गांव अगोंध में प्राईमरी हैल्थ सैन्टर बनाऐ जाने बारे।

क्योंकि यह चीका शहर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता हैं और इसके आस पास 20 गांव पडते हैं।

15. गांवों को आपस में जोडने वाली सड़कों के निर्माण बारे।

Sr.	Name of work	Length Aprox
01	Agound to Bhuna	1-5 K.M.
02	Sultania to Duserpur	2-80 K.M.

03	Mega Majra to Chakku Ladana	1-50 K.M.
04	Landaheri to Jodwa via chhana Jatan	2-25 K.M.
05	Urlana to kartarpur, Up to Punjab border Wested, Dera jaimail Singh wala	1-00 K.M.
06	Urlana to Chichadwala , up to Punjab border	2-00 K.M.
07	Rasulpur to Dohar	2-20 K.M.
08	Chaba to Shadipur	2-90 K.M.
09	Kamheri to Karhali up to Punjab border	1-50 K.M.
10	Rasulpur gamri to Malikpur	1-50 K.M.
11	Kakheri to pabsar	2-50 K.M.
12	Chanchak to Sion Majra	2-50 K.M.
13	Bopur to Up to Punjab Border	2-80 K.M.
14	Village Urlana to Dera Nishan Singh, near River in Taranwali	2-50 K.M.
15	Salempur Gamri to Nandgarh	1-50 K.M.
16	Ahmedpur Gera to Sogalpur Via kasoli	3-00 K.M.
17	(Canal Path) Hansu majra to Chanchak	3-00 K.M.
18	Dandota to Sinh (Canal Path)	2-00 K.M.
19	Mastgarh to Taranwali	3-00 K.M.
20	Sair to Bhuna Road	3-00 K.M.
21	Machhreri to kakyor majra	2-50 K.M.
22	Kallar Majra to Khushhal majra via Sadrehri 12 feet to 18 feet	
23	Repair Hansumajra to Punjab border	1-50 K.M
24	Repair Badsui to Sinh	2-50 K.M.

16. एम. एल. डी. का वॉटर ट्रीटमैन्ट प्लांट लगाने बारे।

मेरे विधानसभा क्षेत्र गुहला चीका के बारे मे अवगत करवाना चाहता हूँ कि गुहला–चीका पंजाब के साथ सटा हुआ विकसित कस्बा है जाकि तकरीबन 50 हजार की आबादी के साथ बसा हुआ है यहां पर ग्राउंड वॉटर लैवल बहुत नीचे जाने की वजह से पीने के पानी की गंभीर समस्या है जो कि केन्द्र सरकार के सर्वे के मुताबिक मेरे क्षेत्र को डार्क जोन घोषित किया जा चुका है इस खतरे को देखते हुए गुहला चीका कस्बे की जनता की पानी के लिए नहरी पानी की मांग उठानी

शुरू हो गई है इसके लिए सिचांई विभाग की गुहला से मारकंडा डिस्ट्रीब्यूट्री शहर के बीच से निकलती है जिसमे नहरी पानी की व्यवस्था तो है लेकिन इसके साथ 10 एम.एल.डी. का वॉटर ट्रीटमैन्ट प्लांट लगाया जाए ताकि शहर वासियो को पीने का साफ व शुद्ध मिल सके।

17. कोली खेडा जंगल के चारो तरफ जाल निर्माण

इस जंगल के नजदीक लगभग 10 गाँव लगते है जैसे खुशहाल माजरा, नंदगढ़, लालपुर, बुबूकपुर, हेमूमाजरा, स्यूंमाजरा, भाटियां, रत्ताखेडा लुकमान, दाबा, सरौला, जिससे इन गांवो को लाभ होगा।

18. गांव कम्हेडी के प्राईमरी स्कूल को मिडल तक अपग्रेड करवाने बारे।

गांव मे पहले से बिल्डिंग बनी हुई है और नई बिल्डिंग बनाने की कोई आवश्यकता नही है।

19. गांव चीका के प्राईमरी स्कूल को मिडल तक अपग्रेड करने बारे।

20. गांव माजरी मे खेल स्टेडियम निर्माण :–

इस गांव के इर्द गिर्द लगभग 10 गांव है जिससे सभी को लाभ होगा इस गांव की आबादी भी बहुत ज्यादा है और ग्राम पंचायत निःशुल्क भूमि देने के लिए तैयार है।

21. मीरापुर ड्रेन पर खम्बेहडा गांव मे पुल निर्माण

ठस पुल से लगभग 5 गांवो को आने जाने के लिए फायदा होगा।

22. गुहला–चीका से चण्डीगढ़ की डायरैक्ट बस सेवा शुरू करवाने बारे।

23. गांव भूना मे लिण्डारा घाट का पुनः निर्माण।

ये बहुत ही प्राचीन तीर्थ स्थान है इसकी हालत बहुत ही खस्ता है। जिसका पुनः निर्माण करवाया जाना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।

श्री पिरथी सिंह (नरवाना) : अध्यक्ष महोदय, हमारे नरवाना हल्के में नवदीप स्टेडियम के 400 मीटर सिंथैटिक और ऐथलेटिक्स ट्रैक्स बनाने के लिए सरकार ने 12 करोड़ रूपये देने का एक वायदा किया था । उसमें लगभग 3–4 करोड रूपये उपायुक्त जीन्द द्वारा कार्यकारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के पास ट्रैक बिछाने के लिए

अभी अग्रिम राशि भेज दी गई थी । ट्रैक बिछाने का काम दिल्ली की किसी एक कम्पनी को टैंडर दिया जा चुका था । टैंडर होने के बाद उस पर काम शुरू हो जाना चाहिए था लेकिन आज तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है । स्पीकर सर, ट्रैक बिछाने की फाइल का भी कोई पता नहीं है कि किस विभाग के पास अटकी पड़ी हुई है । मान्यवर, अगर मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं इसी तरह से मंद गति से चलती रही तो सरकार का स्पष्ट रूप कैसा रहेगा इसका पता नहीं है। स्पीकर सर, नरवाना शहर के वार्ड नं0 15 नई बस्ती, आजाद नगर के लोग आज भी दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं । सरकार का नारा है 'स्वच्छ भारत' लेकिन फिर भी लोग सीवरेज के गंदे सड़े पानी व कूड़ा कर्कट के ढेरों व गंदगी में जीने पर मजबूर हो रहे हैं । चाहे सरकार मेरे साथ वहां चलकर देख लें। मैं वहां पर सरकार को दिखा दूंगा, वहां पर इतनी गन्दगी है कि आप वहां से अपना मुंह बन्द कर के ही निकलेंगे । शहर का इतना बुरा हाल होने के बावजूद भी वहां के कचरा प्रबंधक उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नम्बरदार जी, आप अपनी ये सारी समस्याएं लिख कर दे दीजिए हम उनको प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनवा देंगे ।

***श्री पिरथी सिंह :** ठीक है सर, स्पीकर महोदय, नरवान विधानसभा क्षेत्र में गर्वमेंट हाई स्कूलों की संख्या 24 है जिसमें 24 पोस्टें हैड मास्टर्ज की हैं जबकि यहां अभी सिर्फ 5 ही हैड मास्टर्ज कार्यरत है बताएं बाकी बची खाली पोस्टों को कब तक भर दिया जाएगा ? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी व मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव उझाना में सीएचसी की बिल्डिंग सन् 1989 में सैक्शन हुई थी मगर आज तक यहां बिल्डिंग नहीं बनी है दूसरा यह अभी पीएचसी की बिल्डिंग में चल रही है मुझे बताऐं की उझाना में सीएचसी की बिल्डिंग कब तक बना दी जाएगी ? स्पीकर महोदय, नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव उझाना में गर्वमैंट कन्या हाई स्कूल में बच्चों की संख्या भी ज्यादा है गांव की आबादी भी काफी संख्या में है यह स्कूल सरकार की सभी शर्तों को पूरा करने में सक्ष्म है क्या सरकार द्वारा इस स्कूल को अपग्रेड करके इसे सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल का दर्जा दिये जाने की कोई परपोज़ल सरकार के विचाराधीन है अगर नहीं है तो इसे जल्द अपग्रेड किया जाए।

.....

*** चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

नरवाना सामान्य नागरिक अस्पताल अभी कुछ समय पहले सरकार द्वारा 13 डाक्टरर्ज के पदो को सैक्शन किया गया था मगर अभी तक एक भी डाक्टर ने ज्वाईन नहीं किया सरकार बताऐं कि सभी डाक्टर्ज कब तक अपनी डयूटी ज्वाईन कर लेंगे। नरवाना आई.टी.आई का निर्माण सन् 1960–63 में हुआ था जो कि 9 एकड़ में फैला हुआ है। उस समय यहां पर ट्रेडों में आए हुए सामान को लेकर बड़ी वर्कशाप बनाई थी जबकि आज पुरानी बड़ी वर्कशाप बनादई गई है। मान्यवर, आज यहां पर 51 यूनिट व 19 ट्रेडें है मेरी सरकार से मांग है कि इन ट्रेडो में आए हुए सामानों की सही तरीके से रख–रखाव के लिए आई टी आई कैम्पस नरवाना को वर्कशाप की नई व बड़ी बिल्डिंग प्रदान की जावें। माननीय स्पीकर महोदय नरवाना आई.टी.आई. कैम्पस बिल्डिंग में बनी सड़कों की हालात काफी खस्ता हो चुकी हैं और ना ही यहां स्ट्रीट लाइटों की समूचित व्यवस्था है मेरी सरकार से मांग है कि कैम्पस की सभी स्ट्रीट लाइटों व सभी सड़कों को जल्द से जल्द बनाया जावें। नरवाना आई.टी.आई कैम्पस 9 एकड़ में फैला हुआ है मेरी सरकार से मांग है कि इस कैम्पस में 2 एकड़ में पार्क बनाया जावे और इसके रखरखाव का कार्य हॉर्टिक्लचर डिपार्टमैंट को दिया जावें। नरवाना आई.टी.आई में क्लेरिकल की 5 पोस्टें है जो कि सभी पद खाली है इनका कार्य टीचिंग स्टॉफ से करवाया जा रहा है और टीचिंग स्टॉफ की भी 5 पोस्टें खाली है जिससें बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है क्या सरकार जल्द से जल्द इन पदों को भरने जा रही है। स्पीकर महोदय, नरवाना राजीव गांधी राजकीय बहुतकनीकी शिक्षा विभाग तीन मोड में कॉलेजों का संचालन कर रहा है। जो पहले से जो चल रहा है वह गवर्नमैंट मोड में है जिसका चेयरमैन विभाग का मंत्री होता है। सोशयल मोड पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप। सोशटियल मोट और पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मोड इन दानों का चेयरमैन फाइनैंस कमिशनर होता है जिसका संचालन वह अपने मनमाने तरीके से करती है। मेरी सरकार से मांग है कि इन दोनों मोड को भी सरकारी मोड मे विलय कर दिया जाये क्योंकि सरकारी मोड वाले कॉलेज बढ़िया तरीके से कार्य कर रहें हैं। जबकि उनमें एडमिशन की परसेंटेज ओर प्लेसमेंट की परसेंटेज कहीं ज्यादा है। सर, सरकारी मोड में दाखिल 90 प्रतिशत जबकि इन दोनों मोड में लगभग 50 प्रतिशत पर दाखिल हुआ है। मान्यवर महोदय, सरकार द्वारा प्रदेश के सभी प्राईमरी, हाई व सीनियर सैकेण्ड्री स्कूलों में कम्पयूटरों के साथ–साथ कम्पयूटर टीचर्ज की भर्ती तो कर दी गई है मगर बच्चों को कम्पयूटर सिखाने के लिए टीचरों को बड़ी दिक्कतों

का सामना करना पड़ता है। आज इस गर्मी के मौसम में बिजली के लम्बे–लम्बे कट लग रहें है स्कूलों में जरनेटर भी है मगर सरकार इसका डीजल नहीं दे रही। मान्यवर प्रदेश में अधिकतर प्राईमरी स्कूलों के पास स्कूल के बिजली बिल, बिल्डिंग की रख–रखाव व अन्य जरूरी कामों के लिए पर्याप्त फंड नहीं होता और जो सरकार की ओर से मिलता है उसे भी आने में काफी समय लग जाता है जिससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। क्या सरकार इस व्यवस्था को बदलकर कोई नई और ठोस व्यवस्था करने जा रही है। महोदय में आपके माध्यम से आज इस सदन को बताना चाहता हूं कि पी.एम.एस में वजीफे की दरें 01 जुलाई 2010 को रिवाईज हुई थी जबकि स्कीम में प्रावधान है कि हर दो साल के बाद वजीफे की दरों में मंहगाई को सामने रखते हुए इसे रिवाईज किया जाये लेकिन आज तक इसमें कोई रिवीजन नहीं किया गया। मेरी सरकार से मांग है कि पोलिसी को देखकर इसमें उचित व संतोषजनक कार्यवाही करें। महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारियों को 06 अप्रैल 2015 की आऊटसोर्सिंग प्रणाली/ठेकेदारी पर देने की पॉलिसी को भाग नं 2 पर दर्शाया गया था। जिसके अनुसार नगर पालिकाओं, नगर परिषदों व नगर निगमों में सफाई कर्मचारियों को सीधे इन निगमों से वेतन मिलता था। ठेकेदारों का सफाई कर्मचारियों से कोई संबंध नहीं था मगर अफसोस आज मौजूदा सरकार के 1 जनवरी 2016 के पत्र अनुसार सफाई कर्मचारियों को पॉलिसी के भाग न. 1 में ला कर रख दिया जिसके अंतर्गत ठेकेदारों प्रथा सफाई कर्मचारियों को सौगात के रूप में दी गई । जो लोग जनता को स्वच्छ रखने के कार्य में अपना जीवन लगा रहें उन्हीं सफाई कर्मचारियों को आपने अपने चुनावी घोषणा–पत्र में भी 15 हजार रुपये प्रतिमाह देने का वायदा किया था मगर आज यह वर्ग शोषण का शिकार हो रहा है । मेरी सरकार से मांग है कि इस वर्ग को हरियाणा सरकार द्वारा सौगात के रूप में दिए गए अपने उस घोषणा–पत्र को तुरंत प्रभाव से वापिस लेकर सफाई कर्मचारियों को दोबारा से निगमों के अधीन करके नई सौगात देने का काम करें। आज बिजली विभाग द्वारा व बिजली विभाग के कर्मचारियों को प्रत्येक रेड पर मोटा कमीशन दिया जा रहा है जो कि जनता के साथ सरासर ज्यादती है। आज लगभग प्रत्येक गांव व शहर स्तर पर बिजली के मीटर घरों व दुकानों के बाहर लगे हुए है शिकायतकर्ता द्वारा मीटर से संबंधित कोई शिकायत की जाती है तो उसके बाद विभाग द्वारा उस मीटर को लैब में भेजा जाता है तो वहां पर भी भोले–भाले लोगों को बिना गड़बड़ी के भी

गड़बड़ी बताकार जुर्माना लगाने का काम करते है। क्या सरकार इस पूरे मामले को संज्ञान में रखे हुए है और कब तक लोगों को इस बिना बात की पड़ रही मार से निजात मिल सकेगी। माननीय स्पीकर महोदय हरियाणा में 105 मार्किट कमेटी है बेरी हल्के की सबसे लास्ट में मार्किट कमेटी बनाई है जबकि नरवाना क्षेत्र के गांव धमतान साहिब की अनाज मंडी आज भी सब यार्ड है यह सब यार्ड काफी पुराना सब यार्ड है इस सब यार्ड की 5 साल की आमदनी 9 करोड़ रुपये है जबकि बेरी हल्के की आमदनी इससे आधी है इस अनाज मंडी से नरवाना और टोहानरा दोनों शहरों की मंडियां लगभग 15–20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। धमतान अनाज मंडी में आस–पास के लगभग 20–25 गांवों के किसान अपनी फसल बेचने के लिए प्रत्येक सीजन में यहां आते है गेहूं के सीजन में तो इस मंडी में इतना बुरा हाल है कि किसानों को अपनी फसले कच्चे में ही उतारनी पड़ती है क्योकि सरकार की अनाज मंडी में आज तक कोई फर्श नहीं लगाया गया है, यह बिल्कुल कच्ची है। यह अनाज मंडी सब यार्ड के तौर पर काफी पुरानी मंडी है मेरा संबंधित मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस मंडी को पक्की मंडी का दर्जा दिया जावें तथा मार्किट कमेटी का कार्यालय भी खोला जाये। माननीय स्पीकर महोदय नरवाना विधानसभा क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय की काफी लम्बे समय से हम मांग उठाते रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि राजकीय कन्या महाविद्यालय जल्द से जल्द बनाया जाये। माननीय स्पीकर महोदय, मेरी मुख्यमंत्री जी व शिक्षा मंत्री जी से मांग है कि नरवाना के.एम. गवर्नमैंट कॉलेज नरवाना में M.Sc Chemistry और B.Sc Chemistry Honours Courses की कक्षाएं आगामी सत्र (2018–19) से प्रारम्भ करवाई जाये। सर किसान की जमीन तकसीम की प्रक्रिया को आसान बनाया जाये व निश्चित समय सीमा में जमीन की तकसीम की जाये और जो किसान 10 साल से काश्त कर रहा है उसे वही भूमि न. अलॉट कर दिया जाये सरकार 5 एकड़ से कम के किसान की पैंशन निर्धारित करने की कोई योजना लेकर आए। सभी सराकरी कार्यालयों का कार्य दिवस 6 दिन का किया जाये। सभी सरकारी कार्यालयों के अवकाश के लिए ऑड–इवन फार्मूला अपनाया जावे। सरकार द्वारा सभी सरकारी छुट्यिों को घटाने का काम किया जावें ताकि ज्यादा छुट्यिों की वजह से बच्चों की पड़ाई पर भी बुरा असर ना पड़े और सरकारी महकमों में काम ना होने की वजह से जनता को भी परेशानी ना उठानी पड़े। स्पीकर सर, मेरे गांत कालवन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में निम्न

विषयों के अध्यापकों की कमी है कृप्या बताए इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा। प्रवक्ता अंग्रजी, प्रवक्ता संस्कृत, विज्ञान अध्यापक, सामाजिक अध्यापक, कला अध्यापक, पी.टी अध्यापक। नरवाना शहर में कचरा प्रबंधन के लिए कोई ठोस जगह नहीं है जिससे कचरा आए दिन सड़कों पर पड़ा रहने की वजह से गंदगी व महामारी के फैलने का डरा लगा रहता है क्या सरकार कचरा प्रबंधन के लिए कोई ठोस प्रणाली ला रही है। सर, नरवाना क्षेत्र से धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए हरियाणा राज्य परिवहन विभाग की और से बचों की सख्या बढ़ाई जावें। नरवाना HSIIDC कि 108 एकड़ जमीन है यहां पर लोगों की किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है जिससे आज यह क्षेत्र कोई भी तरक्की नहीं कर पर रहा है यहां की सड़के टुटी हुई है सीवरेज व्यवस्था ठप्प पड़ी हुई है पीने के लिए लोगों को खारा पानी मिल रहा है, HSIIDC की चार दीवारी टुटी हुई है जिससे अपराधिक किस्म के लोग आए दिन एक वारदात को अंजाम देते है। सरकार बताएं कि यहां के व्यापारियों को कब तक यह सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकेगी। माननीय स्पीकर महोदय, हमारी सरकार से मांग है नरवाना राजकीय के.एम. कालेज में सभी कोर्सों की सीटें बढ़ाई जावें। नरवाना हल्के में व शहर की बाहरी कॉलोनियों में भूमिगत जल का स्तर काफी दूषित हो चुका है इस पानी में टी. डी. एस. काफी मात्रा में बढ़ चुका है जिससे लोग कैंसर, काला पीलिया, जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आए हुए है लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवानें के लिए सरकार के पास क्या कोई परपोजल विचाराधीन है अगर है तो कब तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। माननीय स्पीकर महोदय नरवाना हल्के में आज कैंसर की बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है जिससे काफी संख्या में लोग मौत का ग्रास बन चुके है सरकार बताएं नरवान में लोग कैंसर की बीमारी से बचान के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस प्लान तैयार किया गया है। यह तथ्य है कि नरवाना विधानसभा में शहर की सीवरेज प्रणाली काफी पुरानी होने के चलते आए दिन ओवर फ्लो रहती है क्या सरकार नरवाना में नई सीवरेज व्यवस्था डालने बारे विचाराधीन है अगर है तो कब तक है। हल्का नरवाना मेरे गांव कालवन में एक एकड़ में खुम्बी फार्म था उस जमीदार के पास सिर्फ अढ़ाई एकड़ जमीन है जिसमें यह फार्म बना हुआ है लेकिन यह फार्म शार्ट सर्किट से जल कर राख हो गया है। मैं सरकार से मांग करता हू कि इस फार्म को 'फसल बीमा योजना' का लाभ देने काम करे। गांव कालवन का जमीनी पानी दूषित हो गया है लोगो को वही पीना पड़ता है। मैं सरकार से मांग

करता हू कि गावं में नेहरी पानी की डग्गी बनाई जाए। जिसके लिए जगह भी उपलब्ध है। हमारे नरवाना हल्के में भी NH-71 पर पड़ने वाले गांव मोहलखेड़ा, बेलरखां, उझाना, गड़ी, दातासिंह वाला, हंसडैहर आदि गावों को भी जमीन अधिग्रहण के 2012 में 32 लाख का मुआवजा मिला है जबकि बाकी जिलों में रोहतक व अन्य में 90 लाख का मुआवजा मिला है। मेरा आपसे निवेदन है कि नरवाना विधानसभा क्षेत्र के उन गांवो को भी वही मुआवजा दिया जाए।

लिंक रोड मार्किटिंग बोर्ड– गुरूसर से अम्बरसर, उझाना से खरल, सच्चाखेड़ा से दबलैन, बेलरखा से भाणा ब्राह्मान, नरवाना दबलैन–समैण फाटक से ईस्माइलपुर तक, कालवन से सुलेहड़ा, कालवन से कन्हड़ी, बेलरखा से मोहलखेड़ा, लोन से हमीरगढ़, कालवन से सोधा मेल्लां (पंजाब) लगभग 3 कि.मी. लम्बाई 27.50 चौड़ाई यह मार्किटिंग बोर्ड से बनवाई जाये यह सड़क पंजाब सरकार ने अपनी सीमा तक बनाई हुई है। धन्यवाद।

श्री वेद नारंग (बरवाला): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद । वित्त मंत्री जी ने अबकी बार चौथा बजट पेश किया है उसमें हर साल की तरह वही शब्दों का जाल और आंकड़ों का खेल खेला गया है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है जिसमें किसानों के लिए बार–बार कहा जाता है कि हम किसानों की आय बढ़ाने का काम करेंगे लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया गया । आज प्रदेश में जो भी हालात हैं उस पर मैं कहना चाहूंगा कि क्राईम बढ़ रहा है जिससे युवा भटक रहा है । क्योंकि सरकार की तरफ से युवाओं को नौकरियां नहीं दी जा रही है जिसकी वजह से आज का पढ़ा लिखा युवा भटकता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है इसमें युवाओं के रोजगार के लिए कुछ नहीं किया गया है और यही नहीं वित्त मंत्री महोदय शायद बजट में खेल नीति के बारे में भी कुछ लिखना भूल ही गए है। अध्यक्ष महोदय, हम इस महान सदन में अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात रखते हैं, जिनके संदर्भ में आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन असल में इन आश्वासनों पर भी कुछ काम नहीं होता है। इस प्रकार की अवस्था में हम विपक्ष के सदस्य अपने आपको मायूस महसूस करते हैं लेकिन जब सदन में सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े होते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्यायों के बारे में बताते हैं तो एक तरह से विपक्ष के सदस्यों का भी हौंसला

बढ़ता है कि सत्ता पक्ष में होने के बावजूद भी सत्ता पक्ष के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को दूर नहीं करवा पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो एक नारा दिया गया था कि सबका साथ–सबका विकास लेकिन आज प्रदेश में ऐसे हालात बन गए हैं कि न किसी का साथ –न किसी का विकास, बस विनाश ही विनाश।

श्री राजदीप सिंह फोगाट (दादरी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस बजट में अगर सबसे ज्यादा किसी को उम्मीद तो थी तो वह दादरी जिले को थी। दादरी को जिला बने हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और जब भी कोई नया जिला बनता है तो उसके जिले के लिए सरकार की तरफ से अलग से एक नया बजट दिया जाता है। अभी पीछे तीन महीने पहले जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिला दादरी में आए थे तो जिला दादरी के लिए 500 करोड रूपये का अलग से देने का वायदा करके गए थे लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो यह बजट पेश हुआ है इसमें दादरी जिले के लिए कहीं भी अलग से बजट देने का जिक्र नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए बड़ी ही निराशाजनक बात है। जब कोई एक जिला बनता है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट लैवल पर लगभग 51 उच्च श्रेणी के अफसर नियुक्त किए जाते हैं लेकिन दादरी जिले में आज के दिन डिस्ट्रिक्ट लैवल पर केवल पांच अफसर ही नियुक्त किए गए है। यही नहीं जब कोई एक जिला बनता है तो उस जिले की बाकायदा तौर पर बाउंड्री बनती है लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि दो साल दादरी जिले को बने हो गए हैं लेकिन आज तक इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं बनी है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनज़र मेरे दादरी जिले में डिस्ट्रिक्ट लैवल पर अफसरों की संख्या बढ़ाई जाये, इस जिले की बाउंड्री बनाई जाये और साथ ही दादरी जिले के लिए 500 करोड रूपये की राशि देने का बजट में प्रावधान किया जाये। अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि हर जिले में एक महिला कॉलेज खोला जायेगा तो मेरी माननीय शिक्षा मंत्री जी से अपील है कि दादरी जिले के अचीना क्षेत्र में एक महिला कालेज खोला जाये। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन पूरे हिंदुस्तान की यदि बात करें तो यदि सबसे ज्यादा देश को खिलाड़ी मिलते हैं तो वह केवल दादरी जिले से ही मिलते हैं लेकिन बावजूद इसके दादरी जिले में आज भी कोई डिस्ट्रिक्ट लैवल का स्टेडियम नहीं है अतः मेरा अनुरोध है कि यहां पर नैशनल लैवल का स्टेडियम बनाया जाये।

इसके अतिरिक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक फतेहगढ़ गांव है जिसके पास रेलवे स्टेशन स्थित है लेकिन दुख इस बात का है कि गांव फतेहगढ़ से लेकर रेलवे स्टेशन तक कोई रोड नहीं बनाया गया है, मेरा अनुरोध है कि इस रोड को भी बनाने का काम किया जाये। इन सबके अतिरिक्त जिला दादरी की यदि कोई सबसे बड़ी मांग है तो वह आर.यू.बी. बनाने की है। अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में लोक निर्माण मंत्री जी से भी मिला था तो मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि हम आर.यू.बी. जरूर बनायेंगे यही नहीं एक बार जब माननीय कृषि मंत्री महोदय जिला दादरी में आए थे तो यह भी कहकर गए थे कि एक साल की समयावधि में इस आर.यू.बी. को बना दिया जायेगा लेकिन आज इस बात को हुए तीन साल हो गए हैं लेकिन इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जिला दादरी में जल्द से जल्द आर.यू.बी. बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले गांव सौंफ, कासनी, लाम्बा, सांझरवास तथा कोल्हावास में पानी की बड़ी भारी किल्लत है, मेरा आपके माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इन गांवों में पानी की किल्लत को जल्द से जल्द दूर किया जाये। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से एक अनुरोध यह भी करना चाहूंगा कि जब एक बार माननीय शिक्षा मंत्री जी जिला दादरी में आए थे तो यहां के बौंध कॉलेज में साईस संकाय को भी आरम्भ करने की बात कहकर गए थे लेकिन आज तक इस दिशा में भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। अतः मेरा अनुरोध है कि बौंध में स्थित कॉलेज में साईस संकाय जल्द से जल्द शुरू किया जाये।

श्री हरि चंद मिढ़ढ़ाः स्पीकर सर, मैं भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कुछ बातें सदन में रखना चाहूंगा और सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ कॉलोनियां बहुत ही बेहाल अवस्था में हैं, इनकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे इलाके में स्थित कॉलोनियों में बेहतर जन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायें।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, यदि कोई सदस्य अभी तक बोल नहीं पाया है और यदि वह अपनी बातें प्रोसीडिंग्ज में डलवाना चाहता है तो वह अपनी बातें लिखकर दे दें, उनको प्रोसीडिंग्जस का पार्ट बनवा दिया जायेगा।

आवाजेंः ठीक है, जी।

***श्री सुभाष सुधा (थानेसर) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान गरिमामय सदन के सामने वर्ष 2018–2019 राज्य बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी व माननीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय इस प्रकार का बजट राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास लक्ष्यों का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। '' हरियाणा एक हरियाणवी एक'' की भावना, सोच व राज्य के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के हित में है। अतः कुल 1,15,198.29 करोड़ का बजट नये वर्ष के लिए पेश किया गया है। जो कि पिछले वर्ष 2017–18 की तुलना में 12.16% व संशोधित अनुमान से 14.4% अधिक है यह एक सरहानीय कार्य हैं । इसके लिए मैं एक बार फिर से राज्य सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं। **शिक्षा :** माननीय अध्यक्ष महोदय शिक्षा के क्षेत्र में कुल 13978.22 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया हैं यह पिछले वर्ष से 10.9 प्रतिशत बढ़ा है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री व माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों, छात्र–छात्राओं को शिक्षा ग्रहण के साथ–साथ हरियाणा की संस्कृति, लोक कलाओं, प्रदेश के रीति–रिवाजों से भी अवगत करवाया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं उन्होने प्रदेश में 29 राजकीय महाविद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया था और आज उस पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। इस 29 में से कुरूक्षेत्र जिले में थानेसर हल्के के गांव पलवल में राजकीय महाविद्यालय खोला गया है।

गांव हथोरा के राजकीय उच्च विद्यालय से राजकीय वरिष्ट माध्यमिक विद्यालय और गांव भिवानी खेड़ा के माध्यमिक विद्यालय से राजकीय वरिष्ट माध्यमिक विद्यालय को अपग्रेड किया गया। डिमांड– गांव बारवा के गवर्नमंट हाई स्कूल से सीनियर सैकण्डरी स्कूल।दयालपुर गवर्नमेंट मिडल स्कूल से हाई स्कूल, कुतार खेड़ी गवर्नमेंट मिडल स्कूल से हाई स्कूल, पिडांरसी गवर्नमेंट हाई स्कूल से सीनियर सैकण्डरी स्कूल इन चार स्कूलों का अपग्रेड किया जाऐ।

थानेसर शहर में राजकीय गर्ल्स वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की नई बिलडिंग बनाने के लिए फाईल शिक्षा विभाग के पास है।

.....

*** चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

गांव किरमय– गवर्नमेंट सीनियर सैकण्डर स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने की फाईल विभाग में है। इससे जल्द बनवाया जाए।

तकनीकी शिक्षाः माननीय अध्यक्ष महोदय तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष बजट कुल 482.95 करोड़ रखा गया है। इसके लिए धन्यवाद करता हू साथ ही मैं भारत सरकार व हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करता हूं जिला कुरूक्षेत्र में भारतीय डिजाइन संस्थान (National Institute of Design) NID खोला गया हो परंतु अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि दीनबंधु छोटूराम यूनिवसिटी सांइस एवं टैकनॉलोजी, मुरथल (सोनीपत) में दाखिला प्रवेश हेतु हरियाणा के बच्चों को आरक्षण दिया गया इसी तर्ज पर NID में भी हरियाणा के बच्चों को दाखिल प्रवेश हेतु आरक्षण दिया जाएं ताकि हरियाणा के बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो,

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण (I.T.I) हरियाणा कौशल विकास योजना के तहत वर्ष 2018–19 में 1.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। यह बहुत ही खुशी की बात हैं । इससे नई पीढ़ी को अपनी कुशलता दिखाने का सुनेहरा अवसर प्राप्त होगा मैं धन्यवाद करता हूं श्री विपुल गोयल मंत्री जी का 22 I.T.I में से कुरूक्षेत्र I.T.I को आदर्श I.T.I बनाने के लिए चुना गया ।

परंतु मैं यह कहना चाहता हू कि इस I.T.I में लगभग हर प्रकार की ट्रेडी से संबंधित दिया जाता है परंतु यहां पर Technical Power Electronics System ट्रैड नहीं है प्रार्थना है इसे भी यहा शुरू किा जाए ताकि युवाओ को इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए कही दूर ना जाना पड़े

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री व माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूगा कि वर्ष 2015 से लेकर नवंबर 2017 तक प्रदेश में 12,721 कि0 मी0 लग्बी सड़कों का सुधार किया गया व 184 कि0 मी0 लम्बी नई सड़को का निर्माण करवाया और वर्ष 2020 तक सभी मानव रहित रेलवे फाटको को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

सड़को का सुधार, रेलवे रोड़ का निमार्ण, के.डी.बी. रोड का निर्माण के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

मांगे– कुरूक्षेत्र बाई पास (outer Ring Road) गांव ज्योतिसर पेहवा रोड़ से G.T Road दिल्ली की तरफ मिलाने का निर्माण कार्य जल्द शुरू।

शहर के बीचो–बीच कुरूक्षेत्र–कैथल–नरवाना रेलवे लाईन जा रही है जो कि शहर को दो हिस्सों में बांटे हुए है। इस रेलवे लाईन पर 5 मानव रहि रेलवे फाटक है। जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार 2 रेलवे फाटक (पुराना बस स्टैंड के पास, थर्ड गेट–पेहवा रोड) पर आर.ओ.बी. बनाने की घोषणा की गई है। मेरा अनुरोध P.W.D मंत्री जी से बाकी बचे 3 फाटक (अम्बेडकर चौंक के पास, बिरला मन्दिर सरकारी अस्पताल के पास) मानव रहित फाटकों को भी समाप्त किया जाए।

झांसा रोड का निर्माण भी करवाया जाएं

स्वास्थ्य – माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सस्ती, सुलभ, स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए वचन बद्ध है। वर्तमान में प्रदेश में 60 अस्पताल, 500 पी.एच.सी, 8 ट्रामा सैंटर 124 नए सामुदायिक स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। मुख्यमंत्री मुफ्त ईलाज योजना के तहत 7 प्रकार की E.C.G, XRY, Ultrasound दवाईयां दंत चिकित्सा सुतिधाएं दी जा रही है। नये वर्ष के लिए 4769.61 करोड रुपये का बजट रखा गया है। इसके लिए धन्यवाद करता हूं।

200 बैड का नए भवन– LNJP बननो,

PHC बारला खोलने व

PHC अभिमपुर को CHC अपग्रेड करने के लिए,

आयुष यूनिवर्सिटी के लिए फतुहपुर में 100 एकड़ जमीन देने के लिए तथा

खेडी राम नगर में नर्सिगं कालेज खोलने के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं।

गांव बारवा में Sub Health Centre बनवाया जाए–पंचायत द्वारा इसके लिए आवश्कतानुसार जमीन देने को तैयार है।

गांब ज्योतिसर में Sub Health Centre पंचायत भवन में चलाया जा रहा है । क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की स्वयं की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। पंचायत जमीन देने के लिए तैयार है । नये भवन का निर्माण करवाया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय मै कुछ सुझाव/मांगे –थानेसर हल्के से संबंधित इस सदन में रखना चाहता हूं–थानेसर में मार्केटिंग बार्ड की नई सड़कें जो भारत आजाद होने के बाद से लेकर अभी ताक नहीं बनी है। इनको बनवाया जाए।

1. किरमय से ईशाकपुर
2. अमीन से फतुहपुर वाया रजवाटा
3. घमूर खेड़ी से लुखी रोड़ वाया शमशान घाट
4. सनेहडी खालसा से आलमपुर
5. सनेहडी खालसा से समसीपुर
6. कैथलां खुर्द से समसीपुर?
7. बगथला से सुरमी

- पिपनी (कुरूक्षेत्र) बस स्टैण्ट क निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाया जाए।
- कुरूक्षेत्र बस स्टैण्ड को आधुनिक सुविधाओं के साथ अपग्रेड करवाया जाए।
- पर्यटन की दृष्टि से बह्यमसरोवर चलते पानी के तर्ज पर सन्निहित सरोवर का भी चलता पानी किया जाए।
- अमीन बिजली सब स्टेशन को करनाल की बजाए कुरूक्षेत्र के साथ जोड़ा जाए।
- बारना पावर हाउस को मोरे सैगदां फीडर की बजाए कुरूक्षेत्र के साथ जोड़ा जाए।
- गांव, किरमच, हथीरा, बारवा, ज्योतिसर, अमीन में खेल स्टेडियम का निर्माण करवारया जाए
- ए.सी बसें जो दिल्ली से चलती है उनमें किराया चण्डीगढ़ का लिया जाता है जबकि सवारी को पिपली उतरना होता है। इस सिस्टम को भी ठीक किया जाए। धन्यवाद।

***श्री बिशम्बर सिंह बाल्मीकि (बवानी खेड़ा) (अ.जा.) :** हमारी सरकार का अब तक का सबसे शानदार एक लाख 15 हजार के लगभग का चौथा बजट पेश कर प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को ध्यान रखा गया है। बजट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र

.....

***चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया**

मोदी ने किसानों की 2022 तक आय को दोगुणा करने के संकल्प को साकार किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त दक्षिण हरियाणा के लोगों की लाइफ लाइन कही जाने वाली SYL नहर के लिए भी बजट में 100 करोड़ का प्रवाधान किया गया है। माननीय अध्यक्षा महोदय हमारी सरकार ने भिवानी, दादरी और महेन्द्रगढ़ जिलों की सभी नहरों के टेल तक पानी पहुचा रही है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यावाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से में अपने बवानी खेड़ा विधान सभा क्षेत्र की मांगे रखना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं आपके माध्यम से खरक कलिगां क्षेत्र के महिला कॉलेज का निर्माण करवाया जाए और उसका नाम शहीद गजेन्द्र सिंह के नाम पर रखा जाए । खरक कला व आस–पास के गावों की लगभग 3000 एकड़ भूमि बंजर है। जहा किसानों को पानी की बहुत जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी की 27.01.2017 की घोषणा भी है। सिरसा धोधड़ा माइनर की मैं मांग करूगां ये माइनर जल्दी से जल्द बनावाई जाए। बवानी खेड़ा कस्बे के नागरिक अस्पताल में चिकित्सको की कमी है वहा संख्या को बढ़ाया जाए एवं उनके लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ताकि लोगों को उपचार के लिए अन्य शहरों की तरफ न भागना पड़े।

अतः मैं अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री मक्खन लाल सिंगला (सिरसा) : अध्यक्ष जी, मेरे हल्के की कुछ बाते है जिसे बजट में स्थान नहीं दिया गया है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं लिखकर दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष : सिंगला जी, आप लिखकर दे दीजिए। उसे प्रोसीर्डिंगज में डलवा देंगे।

***श्री मक्खन लाल सिंगला :** पीने के पानी क व्यवस्था सुधार ने के लिए मेरे हल्के का बजट में कोई हिस्सा नहीं दिया गया है और नहरी पानी व सेम की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने कोई बजट नहीं रखा, सिरसा शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कोई बजट नहीं, सिरसा शहार में सीवरेज व्यवस्था के लिए कोई बजट नहीं, गोशाला में गऊओं के लिए कोई स्पेशल बजट नहीं, बिजली व्यवस्था सुधार के

.....

*** चेयर के आदेशानुसार प्रोसीर्डिंगज का पार्ट बनाया गया।**

लिए कोई बजट नहीं, सिरसा शहर के पार्को की व्यवस्था सुधारने के लिए बजट में प्रावधान नहीं, सिरसा ऑटो मार्किट को जो काम रूका पड़ा है उसे चालू करवाया जाए, सिरसा शहर में जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए व्यवस्था की जाए व शहर में पार्किंग की व्यवस्था की जाए ताकि जाम से शहर वासियों को निजात मिल सकें, शहर की पुरानी व नई कॉलोनियों में सीवरेज लाइन डाली जैसे विष्णपुरी कॉलोनी, डबबाली रोड चतरगढ़ पट्टी, व नई–पुरानी कॉलोनियां है। धन्यवाद।

***डा0 पवन सैनी (लाडवा) :** अदरणीय अध्यक्ष जी प्रणाम, आपके माध्यम से निम्नलिखित मांगों को सदन की कार्यवाही में जुडवाना चाहता हू। सदन में आश्वासन दिया गया है कि शिक्षा मंत्री द्वारा बबैन में महिला महाविद्यालय जल्दी शुरू करने की कृपा करें। बबैन में P.W.D Rest House बनाया जाए। नैशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ डिजाइन उमरी में हरियाणा का कोटा आरक्षित किया जाए। लाडवा हल्के के गांव सौटी में हवाई पट्टी बनाई जाए जिससे पर्यटन सूर्य ग्रहण मेले और गीता जयंती महोत्सव पर दूर प्रदेशों और देशों से आ सकें। किसान प्रशिक्षण भवन बनाया जाए। गांव कौमासपुर, मथाना चौंक से बबैन सुनारियां चौंक, बबैन चौंक से रामशरण गांव तक, हिनौरी चौंक से सब्जी मंडी लाडवा तक सड़क चार मार्गीय बनाया जाए। बिजली विभाग का उपमण्डल मथाना में बनाया जाए। लाडवा हल्के में आलु प्याज फसल बहुत होती है। इन फसलो के लिए Processing Unit लगाई जाए जिसमें किसान की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे। निम्नलिखित विद्यालयों को अपग्रेड करके वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाए जाएं

1. गांव कौलापुर का विद्यालय
2. गांव संघोर का विद्यालय
3. धनौरा जारान का विद्यालय
4. कसीथल विद्यालय

लाडवा में बाईपास का सर्वे हो चुका है उसका जल्दी मूर्त रूप देने का काम करें।
लाडवा का मास्टर प्लान 2031 जल्दी पास करके लागू करवाया जाए।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय कुरूक्षेत्र में बनाया जाये।
धन्यवाद

.....

*** चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

श्री अध्यक्षःमाननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री महोदय वर्ष 2018–2019 के लिए बजट अनुमानो पर चर्चा का उत्तर देंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि बजट पर चर्चा के बाद आपने मुझे सभी माननीय सदस्यों के जो सुझाव या प्रस्ताव आए हैं और जो उनकी एक सधी हुई समीक्षा जानने का अवसर मिला है, उस पर आपने मुझे अपना उत्तर देने का अवसर प्रदान किया है। संसदीय परंपरा में बजट एक बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और जैसाकि मैने कहा कि यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे वित्त मंत्री के नाते चौथी बार हरियाणा प्रदेश की विधान सभा में हमारी सरकार का बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला है। मैं स्वयं भी मानता हूँ कि बजट की प्रक्रिया जब तक विधान सभा के पटल पर पक्ष और विपक्ष की कसौटी पर न कसी जाये अर्थात जब तक पक्ष और विपक्ष की तरफ से बजट को न तरासा न जाये तब तक बजट की प्रक्रिया अधूरी रहती है। यह बात मैं पूरी ईमानदारी के साथ मानता हूं । कई राज्यों में यह एक बहुत परिपक्व परम्परा है कि बजट अधिवेशन लम्बा चलता है । बजट के सभी प्रस्तावों पर डिपार्टमैंटवाइज और डिमांडवाइज चर्चा होती है । बजट को वित्त मंत्री केवल पेश करता है लेकिन वह इसको अकेले बनाता नहीं है बल्कि बनाने में हर विभाग के अधिकारी अपने–अपने स्तर पर काम करते हैं । वे जिला स्तर से मुख्यालय स्तर तक पूरे साल–भर विचार करके योजनाएं बनाते हैं । इसके अतिरिक्त बजट पर माननीय मंत्रीगण भी वित्त विभाग के साथ बैठकर योजना बनाते हैं । बजट के वित्त प्रबंधन करने के लिए वित्त विभाग के अनेक अधिकारियों और पूरी सरकार ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है । मैं उन सभी का आभार और अभिनन्दन करता हूं । इस बजट पर सभी सदस्यों ने अपनी–अपनी दृष्टि से, अपनी–अपनी समझ से अपने विचार रखे हैं । यह स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष के साथियों ने बजट का पूर्ण समर्थन किया है । इसके विपरित विपक्ष के साथियों ने बजट की आलोचना की है । मैं बजट की आलोचना करने वालों का भी स्वागत करता हूं । इससे कई बातें निकलकर आती हैं जिनसे हमें काफी कुछ सीखने–समझने को मिलता है । इससे हमें अपनी बात को उत्तर के रूप में दोबारा कहने का भी अवसर मिलता है । विपक्ष के साथियों ने बजट पर बहुत–सी टिप्पणी की हैं । इससे मुझे ऐसा लगता है कि बजट को जितनी गम्भीरता से पढ़ना चाहिए था उसको उतनी गम्भीरता से नहीं पढ़ा गया है । मेरे विचार से विपक्ष के सदस्यों ने प्रि–फिक्स्ड माइंडसैट के आधार

पर ही टिप्पणी की है । ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि उस पर क्या बोलना है and some Members go over the Budget so carefull that they actually just go over it at times.

अध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से सदन में कहना चाहूंगा –

उनकी तारीफ क्या पूछते हो,
उम्र सारी गुनाहों में गुजरी,
अब बन रहे हैं वो ऐसे,
गंगा नहाये हो जैसे,
दूसरों पर अगर तफ्सील कीजिए,
सामने आइना रख लिया कीजिए ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूं कि बाकी विभागों से जो डिपार्टमैंटवाइज सुझाव आये हैं हम उनको भी कंसीडर करेंगे । सदन के सदस्यों विशेषकर विपक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से कई चिंताएं और विषय उभरकर आये हैं । कहा गया कि प्रदेश पर कर्जा बहुत बढ़ गया है । इसको लेकर अलग–अलग प्रकार की चिंताएं व्यक्त की गई हैं । कहा गया कि इस कर्ज की वजह से प्रदेश पर देनदारी बढ़ेगी, यह कर्जा अभूतपुर्व है, अप्रत्याशित है और प्रदेश में अब जो भी बच्चा पैदा होगा वह इस कर्जे के साथ पैदा होगा । सदन में फिस्कल डैफिसिट और रिवैन्यू डैफिसिट की बात की गई है । मुझे इस बात की खुशी है कि सदन के सभी माननीय सदस्य फिस्कल और फाईनैंशियल मैनेजमैंट में इतनी रुचि रखते हैं । हमारे माननीय सदस्य इन चीजों को गम्भीरता से लेते हैं । वे चाहते हैं कि हरियाणा एक जिम्मेदार राज्य के तौर पर अपनी पहचान कायम रखे । मैं सदन इस भावना को प्रमाण करता हूं । मैं इसको नमन और स्वागत करता हूं । वित्त से जुड़े हुए सारी जानकारी देना हमारा कर्तव्य है । मैं समझता हूं कि अगर मैं डिपार्टमैंटवाइज रिप्लाई देने की बजाय फाइनैंशियल और फिस्कल मैनेजमैंट से संबंधित रिप्लाई दूं तो ज्यादा उचित होगा । हमसे कहा गया कि हमने कर्ज बहुत ज्यादा ले लिया है । सदन में कई बार कहा जाता है कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश पर 70 हजार करोड रूपये कर्ज था जोकि अब बढ़कर 1 लाख 61 हजार करोड रूपये कर्ज हो गया है । मैं सदन में एक बार नहीं बल्कि अनेक बार कह चुका हूं कि इस आधार पर आंकलन करना सही नहीं है । सदन में ऐसे सदस्य भी हैं जिन्होंने सदन में आना भी उचित नहीं समझा और दिल्ली में बैठकर बजट की समीक्षा की और वहीं से बजट पर टिप्पणी दे रहे हैं । वे बता रहे हैं कि उनके समय में प्रदेश पर 70 हजार करोड रूपये कर्जा था । मैं विपक्ष के

ऐसे साथियों से कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके उन्हें उस कर्ज में 26 हजार करोड रूपये और जोड़ लेने चाहिए । मैं इस महान सदन के पटल पर कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपने समय में जिन 26 हजार करोड रूपये के कर्ज को बिजली कम्पनियों के खाते में जोड़ा हुआ था उनको हमने ऋण लेकर सरकार के खाते में जोड़ लिया है । बिजली कम्पनियों को इस कर्ज का महंगा ब्याज देना पड़ रहा था । हमने इस कर्ज को सस्ती ब्याज दर पर ऋण लेकर अपने खाते में जोड़ा है । इससे बिजली कम्पनियों को लगभग 2,750 करोड रूपये की बचत हुई है । हरियाणा सरकार को बिजली कम्पनियों के इस कर्ज का सालाना 2000–2100 करोड रूपये इंट्रस्ट देना है । इस तरह से हमने एक फैसले से 10 साल में लगभग 8 हजार करोड रूपये की बचत करने का काम किया है । मेरा कहना है कि यह कर्ज हमारा नहीं था बल्कि यह कर्ज बिजली कम्पनियों का था । जो सदस्य ऐसी बातें कहते हैं उन्हें अपनी बात कहते हुए ईमानदारी से यह बात भी बतानी चाहिए कि हमारे समय में प्रदेश पर 70 हजार करोड रूपये कर्ज था और बिजली कम्पनियों पर अलग से 26 हजार करोड रूपये कर्ज था । हमारी सरकार ने बिजली कम्पनियों के कर्ज को अपने खाते में जोड़ लिया । इससे प्रदेश पर कुल 96 हजार करोड रूपये कर्ज हो गया । आज के दिन हमारे प्रदेश पर कुल 1 लाख 61 हजार करोड रूपये कर्ज है । हरियाणा प्रदेश की समूचे हिन्दुस्तान में फिस्कल और फाइनैंशियल मैनेजमैंट के तौर पर एक जिम्मेदार राज्य की पहचान है । (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : मेरा कहना है कि बिजली कम्पनियों पर यह कर्ज भी तो वर्ष 2014–15 में ही हुआ होगा । (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सदन में काफी अच्छी बात उठाई है । इसकी जानकारी देना मेरा फर्ज है । इसका स्पष्टीकरण देना मेरा फर्ज है । यह कर्ज न वर्ष 2014–15 का है, न वर्ष 2013–14 का है, न वर्ष 2012–13 का है बल्कि यह बिजली कम्पनियों द्वारा पिछले सालों में इकट्ठा किया गया कर्ज है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कर्ज हमारी सरकार के आने से पहले का कर्ज है । सदन में कहा गया कि हमारा प्रदेश डैट ट्रैप और बैंकरप्ट होने जा रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के बारे में ऐसी शब्दावली किसने प्रयोग की ? डैट ट्रैप क्या है ? जब सरकार की किसी भी इकाई की कमाई उसकी पर मंथ इन्सटॉलमैंट से कम हो जाती है तो उस सिचुएशन को डैट ट्रैप कहा जाता है । मैं गारण्टी से कह सकता हूं कि हरियाणा सरकार जिस परम्परा और रवायत से चल

रही है उससे हरियाणा में कभी भी डैट ट्रैप की सिचुएशन नहीं आएगी । बैंकरप्सी तो बहुत दूर की बात है । हमने अपनी मर्यादा का पालन किया है । आज भी देश में कई राज्य ऐसे हैं जो डैड टू जी.एस.टी. की रेश्यो को तोड़कर चलते हैं । (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : आदरणीय अध्यक्ष जी, ... (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य धैर्य रखकर बैठें । मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा । मैं विधान सभा के पटल पर कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं । पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के वर्ष 2011–12 में जो कर्जा लिया था वह पिछले साल के मुकाबले लगभग 19.41 प्रतिशत दर से बढ़ा था । वर्ष 2012–13 में जो कर्जा लिया गया था वह पिछले साल के मुकाबले 22.37 प्रतिशत की दर से बढ़ा था । इसी तरह पिछली सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 में लिये गये कर्जे की तुलना में हमारी सरकार के समय में कर्ज की दर में कमी आई है ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 20 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है, जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 20 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मन्त्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय वर्ष 2016–17 में सालाना कर्जा 16.87 प्रतिशत की दर से बढ़ा है और वर्ष 2017–18 में 17.42 प्रतिशत की दर से कर्जा बढा है और वर्ष 2018–19 में 16.72 प्रतिशत की दर से कर्जे की वृद्धि प्रस्तावित है परन्तु कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय वर्ष 2012–13 में 22.37 प्रतिशत की कर्जा लेने की दर थी । हमारी सरकार ने सालाना कर्जा लेने की दर को घटाकर 16.72 प्रतिशत पर ला दिया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से जो चिन्ता व्यक्त की है, उस चिन्ता को दूर करना मेरा फर्ज बनता है। (शोर एवं व्यावधान)।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: कादियान जी, आय के आंकड़ों का प्रतिशत तो बताना ही पड़ता है।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने प्रति व्यक्ति को कर्जे में डूबाने का काम किया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की चिन्ता को दूर करना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार के समय में प्रदेश को कर्जे में डूबाने का काम किया गया है और हमारी सरकार ने प्रदेश के कर्जे को कम करने का काम किया है। हमारी सरकार ने प्रति व्यक्ति डैट की ग्रोथ घटाकर पर ईयर 14.44 प्रतिशत तक कम करने का काम किया है। कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2014–15 में 6.93 प्रतिशत की दर से आय बढ़ी है और कर्जा 15.34 प्रतिशत की दर से बढा है, यह बजट कांग्रेस की सरकार ने प्रस्तुत किया था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति इन्कम 6.93 प्रतिशत की दर से बढ़ी है और कर्जा 15.34 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं यह आंकड़े वित्त उदय योजना के साथ कहूं तो और भी सुंदर हो जाते हैं। कांग्रेस सरकार के समय में 22.37 प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष कर्जा बढ़ रहा था परन्तु हमारी सरकार के समय में उदय योजना के बावजूद भी वर्ष 2017–18 में 13.79 प्रतिशत की दर से कर्जा बढ़ा है और 2018–19 में 13.66 प्रतिशत की दर से कर्जा बढ़ा है। इनकी सरकार में 22.37 प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष कर्जा बढ़ा था। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बिन्दू और बताना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों में यानी वर्ष 2017–18 और वर्ष 2018–19 के बजट अनुमानों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है जिसमें प्रति व्यक्ति 11.57 प्रतिशत की दर से कर्जा बढ़ा है जो पिछले साल एचिव किया है परन्तु अगले साल इस 11.57 प्रतिशत की दर से कर्जे की तुलना में प्रति व्यक्ति 10.11 प्रतिशत की दर से आय बढ़ी है। इस साल प्रस्तावित प्रति व्यक्ति कर्जे की वृद्धि 11.44 प्रतिशत है और प्रति व्यक्ति आय 10.05 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। वर्ष 2014–15 में प्रति व्यक्ति आय 6.39 प्रतिशत थी और कर्जा बढ़ने की दर 15.34 प्रतिशत थी लेकिन हमारी सरकार ने कर्जे और आय को लगभग बराबर करने का काम किया है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार से चार साल में कोई प्रोजैक्ट नहीं लाया गया है (शोर एवं व्यावधान)।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ी है तो कर्जे की प्रतिशत घटी है। (शोर एवं व्यवधान) माननीय मंत्री जी आंकड़ों सहित जवाब दे रहे हैं। प्लीज आप बैठ जाएं।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के माननीय सदस्य बौखलाहट में हैं और सच्चाई को नहीं सुनना चाहते हैं। मैं सच्चाई पहले भी रख चुका हूं लेकिन सच्चाई को सुनना चाहते हैं। यह तो वही हालत है किः–

"अजब जुनून है, ये इन्तकाम का जज्बा"

"शिकस्त खाके, वो पानी में जहर डाल गया।"

इनको हार शिकस्त से इतनी तक्लीफ है कि इन्तकाम का जज्बा है और शिकस्त खाकर ये जहर को घोलने का काम कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं सी.एल.पी. लीडर माननीया श्रीमती किरण चौधरी जी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय सदस्या संसदीय परम्परा का निर्वहन करती हैं और अपनी बात को सदन में मजबूती से रखती हैं और हर बात को सुनने का मादा उनके अन्दर है। काश, उनकी तरह बातों को सुनने का मादा दूसरे माननीय सदस्यों को भी होता। माननीय सदस्या अपनी बात मजबूती से रखती हैं जिसके कारण हमें लाभ मिलता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को प्रणाम करता हूं। सभी माननीय सदस्य सुबह 10:00 बजे से बिना लंच ब्रेक के लगातार बैठे हुए हैं। आज एक तरह से लगभग दो सीटिंग हो गयी हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात जल्दी–जल्दी कहना चाहूंगा कि हमारे एक कांग्रेस के माननीय सदस्य द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी थी कि गुड़गाव, फरीदाबाद जिलों को छोड़कर दूसरे जिलों में पर कैपिटा इन्कम की क्या स्थिति है? तो कुछ जिलों की पर कैपिटा इनकम 100 से ऊपर है और 5 या बाकी जिलों की पर कैपिटा इनकम उससे नीचे है और अध्यक्ष महोदय, उसका जो डिफरेंस का इन्डैक्स है वह जितना बड़ा उसका फिगर होगा उतना गैप ज्यादा होगा और पर कैपिटा इनकम में डिस्पैरिटी ज्यादा होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इनका इन्डैक्स वर्ष 2013–2014 में साढ़े 8 प्रतिशत था और वर्ष 2012–2013 में 8.4 प्रतिशत था। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इस इनकम डिस्पैरिटी को 8.5 और 8.4 से घटाकर 7.6 और 7.7 प्रतिशत पर पहुंचा दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि अन्य जिलों ने भी तरक्की करने का काम किया है। (इस समय मेजें थप–थपाई गईं।) अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े हरियाणा सरकार के नहीं हैं, बल्कि ये आंकड़े भारत सरकार के स्टैटिसटिकल डिपार्टमेंट के हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री रघुवीर सिंह कादियान जी ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक कहा कि हम बजट में बहुत ही सुंदर

आंकड़े रखते हैं लेकिन उसका एक्च्युअल यूटिलाइजेशन नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. रविंद्र बलियालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ कहना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बलियाला जी, कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जैसी कि हमारे माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की थी कि हमने पिछले साल भी 1 लाख करोड रुपए का बजट दे दिया, लेकिन बजट की जो एक्च्युअल यूटिलाइजेशन थी वह कम थी। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री रघुवीर सिंह कादियान जी ने एक बहुत बड़ा वर्ड यूज किया था, उन्होंने कहा था कि बजट में इतना डाउन–फॉल हो गया, इतना डॉउन–फॉल हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने उन्हें कहा था कि यह डॉउन–फॉल नहीं है, लेकिन आप यूटिलाइजेशन में जरूर चिंता व्यक्त कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारा एक्च्युअल एक्सपेंडीचर वर्ष 2010–2011 में 84.91 परसेंट, वर्ष 2011–2012 में 87 परसेंट, वर्ष 2012–2013 में 88 परसेंट, वर्ष 2013–2014 में 85 परसेंट, वर्ष 2014–2015 में 85.86 परसेंट, वर्ष 2015–2016 में 92.51 परसेंट, वर्ष 2016–2017 में 94.08 परसेंट और अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुमान है कि वर्ष 2017–2018 में भी 31 मार्च, 2018 तक यह यूटिलाइजेशन 90 परसेंट से ऊपर रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ष 2010–2011 में जो बजट का साइज था, जो कि 40 हजार करोड रुपए से नीचे था, उस समय की सरकार ने केवल 84 परसेंट की यूटिलाइजेशन ही एचीव की थी। अध्यक्ष महोदय, वह बजट आज बढ़कर 1 लाख 15 हजार करोड रुपए हो गया है और हमने उसी मशीनरी से और उन्हीं अधिकारियों के साथ मिलकर उस बजट का यूटिलाइजेशन 90 परसेंट करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, अगर यह मानकर चला जाए कि पिछली सरकार ने 40 हजार करोड रुपए में अगर 85 परसेंट एचीव करने का काम किया है यानी 35 हजार करोड के आस–पास एचीव करने का किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हम उसी मशीनरी से और उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को साथ में मिलाकर 1 लाख 15 हजार करोड रुपए में से 90 परसेंट से ज्यादा एचीव करेंगे, इस तरह से हम डबल से भी ज्यादा एचीव करने का काम करेंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि जब बजट के पैसे का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और वह पैसा लैप्स हो रहा है, जिससे सारे बड़े विभागों के ऊपर बोझ पड़ता है। क्या माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में कुछ सोचा है ?

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि

''साहिल पर लोग यूं ही खड़े होकर देखते रहे,

दरिया में ज्यों ही हम उतरे, दरिया ही उतर गया।''

अध्यक्ष महोदय, हमने तो साबित करके दिखा दिया है कि ये 40 हजार करोड के बजट में 85 परसेंट अचीव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम 1 लाख हजार करोड के बजट में उसी मशीनरी से और उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को साथ में लेकर 90 हजार करोड रुपए का अचीव कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सरकार की मेहनत है । अध्यक्ष महोदय, कैपिटल एक्सपैंडीचर के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हम जो कर्जा ले रहे हैं उसका मुख्य हिस्सा हरियाणा के निर्माण और कैपिटल एक्सपैंडीचर के लिए खर्च कर रहे हैं । वर्ष 2013–14 के अंदर कैपीटल एक्सपैंडीचर 12787.47 करोड रुपये था जिसमें से 8 हजार करोड रुपये का पब्लिक डैट वापिस जा रहा था यानि की कैपिटल अकाउंट में केवल 4710 करोड रुपये था उसको हमने 2017–18 में अचीव करके 15374 करोड रुपये कर दिया है और इसमें तीन गुना अचीव किया है तथा इस साल 17546 करोड रुपये अचीव करने का प्रस्ताव है । अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी करण सिंह दलाल जी ने भी बजट पर बोलते हुए चिंता व्यक्त की और सवाल उठाया कि हमने कुछ महत्वपूर्ण विभागों के बजट परूसंटेज में कटौती की है । मैं उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि वर्ष 2013–14 में टोटल बजट का एग्रीकल्चर एलायड सैक्टर के लिए 2.79 प्रतिशत बजट रखा गया था जो हमने 2018–19 में बढ़ाकर 3.56 प्रतिशत कर दिया है । इसी तरह से रूरल डिवैल्पमैंट के लिए 2013–14 में 3.14 प्रतिशत बजट रखा गया था जबकि हमने 2018–19 में बढ़ाकर 3.73 प्रतिशत कर दिया है । इसी तरह से शिक्षा के लिए 2013–14 में 13. 17 प्रतिशत बजट रख गया था जबकि हमने 2018–19 में 12.52 प्रतिशत रखा है । यह कम है लेकिन मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि 2013–14 में जो 13. 17 प्रतिशत रखा गया था उसमें से खर्च 78 प्रतिशत किया गया था यानी उसका

22 प्रतिशत खर्च नहीं किया गया था । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों में सारी जानकारी दी हुई है विपक्ष के साथी उनको पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष : मैडम, वित्त मंत्री जी को तुलना तो करनी ही पड़ेगी और ये तुलनात्मक जानकारी ही दे रहे हैं । (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, बजट में सारे आंकड़े दिए हुए हैं इनको पढ़ने चाहिए । इसी तरह से हैल्थ विभाग के लिए वर्ष 2013–14 में 3.2 प्रतिशत बजट की एलोकेशन की गई थी और हमने 2018–19 में बढ़ाकर 4.14 प्रतिशत की एलोकेशन की है । अध्यक्ष महोदय, डाक्टर कादियान जी ने हमारे डाउन फाल का भी जिक्र किया था । मैं उन्हीं के समय की जानकारी देना चाहूंगा कि वर्ष 2013–14 में आर.ई. करने के बाद टोटल 79 प्रतिशत बजट खर्च किया गया यानि 21 प्रतिशत का डाउन फाल रहा । इसी तरह से 2013–14 में अर्बन लोकल बाडी का 72 प्रतिशत बजट यूज हुआ यानी 28 प्रतिशत का डाउन फाल रहा । इसी तरह से रोजगार विभाग का 75 प्रतिशत बजट यूज हुआ यानी 25 प्रतिशत का डाउन फाल रहा । इसी तरह से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का 37 प्रतिशत बजट यूज हुआ और 63 प्रतिशत का डाउन फाल रहा । इसी तरह से टैक्नीकल एजुकेशन का 79 प्रतिशत बजट यूज हुआ और 21 प्रतिशत का डाउन फाल रहा । इसी तरह से वैल्फेयर ऑफ एस.सी.,बी.सी. विभाग का बजट 69 प्रतिशत यूज हुआ और 31 प्रतिशत का डाउन फाल रहा । अध्यक्ष महोदय, डाउन फाल के ये सभी आंकड़े मैं 2013–14 के बता रहा हूं जिनमें बहुत ज्यादा डाउन फाल है और आज ये लोग हमारे डाउन फाल पर सवाल उठा रहे हैं । (विघ्न) आज इनको अपना आईना देखने में तकलीफ हो रही है । अध्यक्ष महोदय, ये लोग कभी 90 प्रतिशत का आंकड़ा छू नहीं पाये और हम 90 प्रतिशत से नीचे कभी गये नहीं यानि हमने अपना 90 प्रतिशत बजट खर्च किया है। विपक्ष के साथी करण सिंह दलाल जी ने चिंता व्यक्त की कि सिंचाई की बजट परूसैंटेज भी कम कर दी गई । मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2008–09 में सिंचाई का बजट का 2 प्रतिशत घटाया गया जबकि हमने 2017–18 में 19.23 प्रतिशत और 2018–19 में 20 प्रतिशत की बढ़ौतरी की है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के दस साल के राज में सिंचाई पर 16300 करोड रुपये खर्च किया गया यानी प्रत्येक वर्ष 1630 करोड रुपये खर्च किया गया । जबकि हमने अपने 4 साल के कार्यकाल में 12 हजार करोड रुपये सिंचाई के लिए खर्च किए हैं यानी हर साल 3 हजार करोड रुपये

हमने सिंचाई के लिए खर्च किए हैं जो कि उनके द्वारा खर्च किए पैसे से डबल है। (विघ्न) इसी तरह से कांग्रेस सरकार ने 10 साल के शासन में हैल्थ विभाग पर 8 हजार करोड रुपये खर्च किए और हमने चार साल में 16.50 करोड रुपये खर्च किए हैं । अध्यक्ष महोदय, अब मैं एग्रीकल्चर सैक्टर के आंकड़े बताना चाहूंगा और किसानों की राजनीति करने वाले मेरे सामने बैठे हैं । इनके 6 वर्ष के शासन में एग्रीकल्चर सैक्टर में केवल 2250 करोड रुपये खर्च किए गए और कांग्रेस पार्टी के 10 साल के साशन में 11 हजार करोड रुपये खर्च किए जबकि हमारे 4 साल के शासन में 11 हजार करोड रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है । (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि मंत्री जी आंकड़े बता रहे हैं कि हमारी पार्टी के शासन के दौरान एग्रीकल्चर सैक्टर में कम पैसा खर्च किया गया और उसकी तुलना आज खर्च किए गए पैसे से की जा रही है । उस समय में और आज के समय में महंगाई बढ़ गई है और सभी वस्तुओं के रेट भी बहुत हो गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : संधू साहब, प्लीज आप बैठें । मंत्री जी ने बताया है कि इनकी सरकार के समय में 90 प्रतिशत बजट खर्च किया गया है जबकि पहले कोई भी सरकार 90 प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाई । पैसा खर्च करने की परूसैंटेज पर महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त और बड़े भाई परमिन्द्र ढुल जी ने चिंता व्यक्त की थी कि कर्मचारियों की सैलरी एवं पैंशन का बिल कम हो गया है । उन्होंने कारण बताया कि कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई जिसके कारण यह बिल कम हो गया । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा देश में पहला राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग सबसे पहले दिया और यह केवल सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि बोर्ड, कारपोरेशंज आदि आटोनोमस बॉडीज को भी दिया है । वर्ष 2013–14 में सैलरी एवं पैंशन मद में 15461 करोड रुपये खर्च होते थे । (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, पिछली बात न करके कर्मचारियों और पैंशन धारकों की सैलरी पर 2017–18 में कितना पैसा खर्च होता था और 2018–19 में कितना पैसा खर्च होगा इसकी जानकारी मंत्री जी दें ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी मेरे बड़े ज्ञानी हैं और मेरे बड़े भाई हैं । इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है । विपक्ष के साथियों की यह शंका/कंफ्यूजन दूर हो जायेगा जब ये मेरी पूरी बात सुन लेंगे । मैं विपक्ष के साथियों को कोई परेशानी नहीं होने देना चाहता । अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं कि वर्ष 2013–14 में सैलरी एवं पैंशन पर 15461 करोड रुपये खर्च होते थे जो 2017–18 में बढ़कर 26732 करोड रुपये हो गये और आने वाले वर्ष के लिए इस मद में 28892 करोड यानी 29 हजार करोड रुपये का प्रस्ताव रखा गया है । इस तरह से सैलरी को हमने घटाया नहीं है । ढुल साहब को इसमें कंफ्यूजन इसलिए हो गया है क्योंकि इन्होंने ग्राफ देख लिया जिसमें पेज संख्या 12 पर सैलरी का डाटा दर्शाया हुआ है । जिसमें दर्शाया हुआ है कि 2014–15 में सैलरी एवं पैंशन पर 43.78 प्रतिशत खर्च होता था जो अब 37.56 प्रतिशत खर्च होगा । इनको लगा कि कर्मचारियों एवं पैंशनर्ज की सैलरी पर कम खर्च हो रहा है इसलिए सवाल उठाने का मौका मिल गया । इन्होंने उसके उपर की हैड लाईन नहीं पढ़ी । उसमें लिखा है Salary and Pension to total revenue receipts यानि की सरकार की टोटल रैवेन्यू की आमदनी उसकी तुलना में सैलरी/पैंशन डबल करने के बाद भी घटाई है क्योंकि हमने टोटल रैवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाने का काम किया है और यह हमने बिना किसी कर के बढ़ाया है ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाये ?

आवाजें : ठीक है, जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा तथा वित्त मंत्री द्वारा उत्तर (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि जो टोटल रिवैन्यू रिसिप्ट बढ़ी हैं उसके कारण माननीय विपक्ष के साथियों को चिन्ता हो गई कि ये तो घट गई हैं जबकि हमने टोटल रिवैन्यू रिसिप्ट बढ़ाई हैं। पी.आर.आर टू जी.एस.डी.पी. जब हमने श्वेत–पत्र जारी किया था उस समय भी कहा था कि हरियाणा प्रदेश के खजाने में जो कुल

आमदनी आ जानी चाहिए थी वह पिछली सरकार की लापरवाही के कारण नहीं आ पाई। उसी के कारण हमारी फिस्कल सिचुएशन खराब हुई है। वर्ष 2013–14 में इनकी जो जी.एस.डी.पी. की रिवैन्यू रिसिप्ट थी 9.59 प्रतिशत थी उसको हमने बढ़ाकर वर्ष 2017–18 में 11.52 प्रतिशत किया है। इस प्रकार से हमने 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह एक बहुत अच्छा परिवर्तन हरियाणा के वित्त प्रबन्धन में हुआ है। अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के साथियों द्वारा एक चिन्ता और व्यक्त की गई है कि सरकार द्वारा ब्याज अदा करने के लिए कर्जा लिया जा रहा है और प्रदेश का दिवाला निकल जायेगा, प्रदेश डैट ट्रैप में फंस जायेगा। अगर माननीय विपक्ष के साथियों को इस बात की चिन्ता है तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 2013–14 में हमारी जो कुल ब्याज की अदायगी है वह और जो टोटल आमदनी का रेशो है वह 15.39 है। आज हमने इस साल उसको घटा कर 13.93 कर दिया है जो कि पिछले साल 14.30 कर दिया था तथा अगले साल भी यह 15. 48 प्रस्तावित है। इनकी सरकार के समय में कुल आमदनी का पैसा जो ब्याज में जाता था हमने उससे बेहतर किया है। इनके समय में 15.39 जाता था जिसको घटा कर हमने 13.93 कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन यही हरियाणा प्रदेश की स्थिति है। एक और बात की तरफ माननीय विपक्ष के साथियों ने चिन्ता व्यक्ति की थी कि हरियाणा प्रदेश के सोसियो इकॉनोमिक पैरामीटर्स में हमारा जो शिशु मृत्यु दर है वह खराब हालत में है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों द्वारा इसके लिए चिन्ता नहीं की गई। एक दिन में परिवर्तन नहीं होता है लेकिन इसके बावजूद भी हमने इसमें सुधार किया है। वर्ष 2013–14 में पिछली सरकार के समय में शिशु मृत्यु दर जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति एक हजार 40 थी वह वर्ष 2016 में घट कर 35 हो गई है। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2013–14 में जो शिशु मृत्यु दर 29 थी वह घटकर वर्ष 2016 में 27 हो गई है। अगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की संयुक्त रुप से बात की जाये तो हरियाणा की जो शिशु मृत्यु दर 2014 में 36 थी वह 2016 में घट कर 33 हो गई है। हमने घटाने का काम किया है, सुधारने का काम किया है। यहां तक कहा गया कि बेटी–बचाओ, बेटी–पढ़ाओ को बंद कर दो, क्या फायदा है मैं उनको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2013–14 में प्रति एक हजार लड़कों पर 868 लड़कियां पैदा हुई थी जो वर्ष 2016–17 में वर्ष 2016 में बढ़ कर 900 बेटियां पैदा

हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों को एक शेर के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा कि :–

उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है,

मुझे यकीन है कि यह आसमां कुछ कम है,

वाकिफ है जमाना हमारी उड़ान से,

वह और थे जो हार गये आसमान से।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी यह भी बतायें कि सरकार भ्रूण हत्या कितनी रोक पाई है? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की आदत है कि ये आंकड़ों को अपनी समझ के अनुसार प्रस्तुत करती हैं। ये अभी तक सत्ता के मद से बाहर नहीं निकली हैं। मैं आई.एम.आर.(इनफैंट मोरटैलिटी रेट) के बारे में बता रहा हूं जिसके बारे में इनकी पार्टी की तरफ से बात उठाई गई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः वित्त मंत्री जी ने दोनों के बारे में बता दिया है। दोनों में सुधार हुआ है।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, यहां पर गलत आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर गलत आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक दिन और भी माननीय सदस्या को बताया था लेकिन ये सुनना ही नहीं चाहती हैं। मैंने इनको बताया था कि हमारे सारे आंकड़े इम्प्रूव हुये हैं। मैंने बताया था कि जो नीति आयोग के आंकड़े हैं वे सैम्पल सर्वे हैं तथा हमारे जो आंकड़े हैं वे एस.आर.एस. के आंकड़े हैं। वर्ष 2013–14 में हमारी शिशु मृत्यु दर 41 थी जो अब घट कर 33 हो गई है। हमने इम्प्रूव किया है । हमने सैक्स रेशो में भी इम्प्रूव किया वह पहले 868 था और अब वर्ष 2017 में यह 914 हो गया है । हर चीज में हमने इम्प्रूव किया है । हमारी अस्पतालों की ओ.पी.डी. बढ़ रही है, आई.पी.डी. बढ़ रही है । अब आपको पता नहीं किस बात की तकलीफ है ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी साथियों आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे बजट पर कुछ सुझाव दिये हैं । आज मैं उनके सुझावों को शामिल करते हुए सबका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि सभी साथियों ने अपने–अपने तरीके से बजट पर अपने विचार प्रस्तुत किये । बहुत सारी साथियों ने अपने–अपने क्षेत्र के लिए मांगे रखी हैं जिन पर हम विचार करेंगे और उनको विभागों को देंगे । डॉ0 कमल गुप्ता व श्री असीम भाई ने शुरूआत करते हुए डॉ0 कमल गुप्ता जी ने फाटक मुक्त हरियाणा का आह्वान किया है । अग्रोहा धाम के लिए और एयरपोर्ट के लिए तथा राखी गढ़ी के लिए एक इंटरनेशनल ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने की बात की है । इसके साथ ही और साथियों ने भी अपने–अपने तरीके से बहुत अच्छे–अच्छे सुझाव दिये हैं । मैं सभी साथियों के सुझाव का आभार व्यक्त करते हुए मैं बहन किरण चौधरी जी से इतना ही निवेदन करूंगा क्योंकि वह हमारी सी.एल.पी. नेता हैं । उन्होंने कहा था कि यह आपका विदाई बजट है तो वह मेरे जवाब के बाद कम से कम यह कह दें कि यह बधाई का बजट है । आने वाली बधाई का बजट है । अब मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस बजट के प्रस्ताव को पारित किया जाए । अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर कहना चाहता हूं:–

> **" हजार परत गिरे, लाख आंधियां उठे, वह फूल खिल कर रहेंगे जो खिलने वाले है । वह फूल खिलकर रहेंगे, जो खिलने वाले हैं ।"**

धन्यवाद ।

वर्ष 2018–2019 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुदानों तथा मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा ।

पिछली प्रथानुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई (डिमांड्स नं0 1 से 45) एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी । माननीय सदस्यगण किसी भी डिमांड पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नं0 बता दें, जिस पर वे बोलना चाहते हैं ।

> कि राजस्व खर्च के लिए **65,08,80,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 1–विधान सभा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **158,15,00,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 2—राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **316,48,83,200** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 3—सामान्य प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1105,74,29,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 4—राजस्व** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **238,02,46,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 5—आबकारी व कराधान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **8381,79,26,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 6— वित्त** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 58,53,55,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 410,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 7—आयोजना तथा सांख्यिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1208,64,69,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 3474,14,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 8—भवन तथा सड़कें** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 13587,43,99,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 100,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 9—शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 437,95,10,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 10– तकनीकी शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 394,16,80,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 50,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 11–खेलकूद तथा युवा कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 21,74,30,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 12– कला एवं संस्कृति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 4050,40,63,580 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 522,50,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 13–स्वास्थ्य** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 104,99,50,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1300,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 14–नगर विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 4223,60,37,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 15–स्थानीय शासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 50,10,43,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 16–श्रम** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 236,18,80,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 25,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 17–रोजगार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 504,77,87,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 68,16,17,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 18—औद्योगिक प्रशिक्षण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 722,50,60,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 15,27,25,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 19—अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 6054,80,58,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 18,92,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 20—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1217,96,87,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 159,76,15,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 21—महिला एवं बाल विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 149,31,56,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 22—भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 388,96,50,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 9451,20,70,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 23—खाद्य एवं पूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1645,20,43,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1537,06,92,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 24—सिंचाई** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 316,89,95,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 15,01,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 25—उद्योग** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 70,52,80,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 26—खान एवं भू—विज्ञान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 2667,84,73,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 27—कृषि** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 893,27,60,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 20,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 28—पशुपालन तथा डेरी विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 83,46,16,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 29—मछली पालन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 425,66,67,000 रूपये से अनधिक धनराशि, राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 30—वन तथा वन्य प्राणी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 12,42,20,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 31—परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 4510,10,39,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 100,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 32—ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 302,46,68,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 176,08,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 33—सहकारिता** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 2329,58,80,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 287,10,50,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 34—परिवहन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 3,97,75,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 47,75,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 35—पर्यटन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 4307,89,57,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 410,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 36—गृह** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 62,40,60,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 37—निर्वाचन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1952,22,48,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1759,49,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 38—लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 193,07,00,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 50,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि, राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 39—सूचना तथा प्रचार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 6614,72,75,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 5515,86,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 40—ऊर्जा तथा विद्युत** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 148,65,70,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 41—इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 692,47,82,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 42–न्याय प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 273,12,60,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 43–कारागार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 33,91,94,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 44–मुद्रण तथा लेखन सामग्री** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि पूंजीगत खर्च के लिए **1766,42,10,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 45–राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

(कोई भी सदस्य बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विभिन्न डिमांड्स सदन में मतदान के लिए रखी जाती हैं ।

कि राजस्व खर्च के लिए **65,08,80,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 1–विधान सभा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **158,15,00,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 2–राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **316,48,83,200** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 3–सामान्य प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **1105,74,29,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 4—राजस्व** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **238,02,46,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 5—आबकारी व कराधान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए **8381,79,26,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 6— वित्त** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 58,53,55,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 410,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 7—आयोजना तथा सांख्यिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1208,64,69,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 3474,14,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 8—भवन तथा सड़कें** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 13587,43,99,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 100,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 9—शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 437,95,10,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 10— तकनीकी शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 394,16,80,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 50,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 11—खेलकूद तथा युवा कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 21,74,30,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 12– कला एवं संस्कृति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 4050,40,63,580 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 522,50,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 13–स्वास्थ्य** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 104,99,50,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1300,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 14–नगर विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 4223,60,37,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 15–स्थानीय शासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 50,10,43,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 16–श्रम** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 236,18,80,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 25,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 17–रोजगार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 504,77,87,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 68,16,17,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 18–औद्योगिक प्रशिक्षण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 722,50,60,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 15,27,25,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 19–अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018–2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 6054,80,58,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 18,92,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 20—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1217,96,87,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 159,76,15,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 21—महिला एवं बाल विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 149,31,56,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 22—भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 388,96,50,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 9451,20,70,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 23—खाद्य एवं पूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1645,20,43,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1537,06,92,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 24—सिंचाई** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 316,89,95,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 15,01,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 25—उद्योग** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 70,52,80,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 26—खान एवं भू—विज्ञान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 2667,84,73,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 27—कृषि** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 893,27,60,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 20,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 28—पशुपालन तथा डेरी विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 83,46,16,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 29—मछली पालन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 425,66,67,000 रूपये से अनधिक धनराशि, राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 30—वन तथा वन्य प्राणी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 12,42,20,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 31—परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 4510,10,39,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 100,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 32—ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 302,46,68,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 176,08,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 33—सहकारिता** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 2329,58,80,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 287,10,50,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 34—परिवहन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 3,97,75,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 47,75,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 35—पर्यटन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 4307,89,57,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 410,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 36—गृह** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 62,40,60,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 37—निर्वाचन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 1952,22,48,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1759,49,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 38—लोक स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 193,07,00,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 50,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि, राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 39—सूचना तथा प्रचार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 6614,72,75,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 5515,86,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 40—ऊर्जा तथा विद्युत** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 148,65,70,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 41—इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 692,47,82,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 42—न्याय प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 273,12,60,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 43—कारागार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि राजस्व खर्च के लिए 33,91,94,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1,00,00,000 रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 44—मुद्रण तथा लेखन सामग्री** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि पूंजीगत खर्च के लिए **1766,42,10,000** रूपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 45—राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2018—2019 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन वीरवार, दिनांक 15 मार्च, 2018 प्रातः 10:00 बजे तक के लिए *स्थगित किया जाता है ।

*17:57 बजे

(तत्पश्चात सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 15 मार्च, 2018 प्रातः 10:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)